राष्ट्रीय संस्करण

CopyRight - Jagran.com

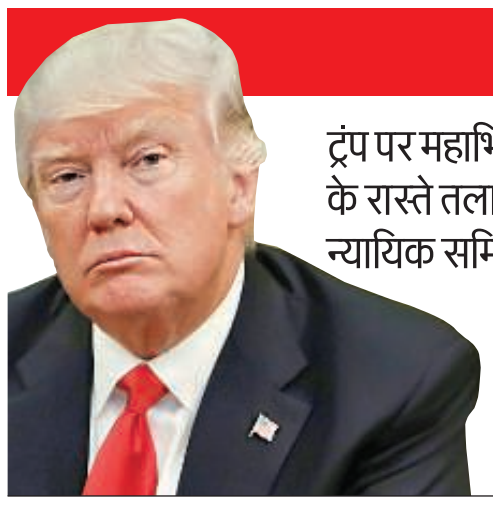

ट्रंप पर महाभियोग के रास्ते तलाश रही न्यायिक समिति >> 11

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 48

मूल्य ₹6 .00, नई दिल्ली, रविवार, 28 जुलाई 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 14

सरोकार

स्वर्ण मंदिर में अब हर रोज बचेगा सात लाख लीटर पानी

अमृतसर : विश्व को मानवता का संदेश देने वाला श्री हरिमंदिर साहिब जल बचाने

का भी संदेश रहा है। धर्मस्थल के परिक्रमा पथ की धुलाई में प्रयोग होने वाले लाखों लीटर पानी को व्यर्थ होने से बचाया जा रहा है। इसके लिए रीसाइकिलिंग और हार्वेस्टिंग प्लांट स्थापित किया गया है। (पेज-13)

रविवार विशेष

कॉफी की चुस्कियों से बनेगी झीरम घाटी की नई पहचान

रायपुर : कभी नक्सलियों के लिए कुख्यात रही झीरमघाटी नई पहचान बनाने को आतुर

है। वैज्ञानिकों ने यहां कॉफी के पौधे रोपे हैं। स्थानीय किसान इन पौधों की देखभाल कर रहे हैं। जल्द ही देश-दुनिया के लोग 'झीरम कॉफी' की चुस्कियां लेंगे। (पेज-13)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

विस स्पीकर के खिलाफ आ सकता है अविश्वास प्रस्ताव

बेंगलुरु : कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर केआर रमेश कुमार ने स्वेच्छा से इस्तीफा नहीं दिया तो येदियुरप्पा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। वहीं, सोमवार को विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश करने से पहले मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने रविवार को भाजपा विधायक दल की बैठक बुलाई है।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 5

पुलवामा का साजिशकर्ता मुन्ना बिहारी साथी सहित ढेर

श्रीनगर : कश्मीर के पुलवामा, बनिहाल समेत विभिन्न वाहन धमाकों के साजिशकर्ता पाकिस्तानी नागरिक और जैश कमांडर मुन्ना बिहारी उर्फ मुन्ना लाहौरी को उसके साथी जीनत इश्फाक मीर उर्फ जीनत उल इस्लाम तुरकवांगन (शोपियां) को सेना ने शनिवार को मार गिराया। मुन्ना पर सात लाख और जीनत पर पांच लाख का इनाम था।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 10

वंचित 43,000 गांवों में एक वर्ष में पहुंचेगी टेलीकॉम सेवा

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने साफ किया है कि वह टेलीकॉम क्षेत्र में किसी का एकाधिकार को स्वीकार नहीं करेगी। संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मौजूदा समय में देश में 43000 गांव दूरसंचार नेटवर्क के दायरे से बाहर हैं। 'मैंने कंपनियों से कहा है कि वे अपने संसाधनों को साझा करें ताकि एक साल के भीतर हम ऐसे सभी गांवों तक पहुंच सकें।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 11

ब्रिटेन की तरक्की का मौका है ब्रेक्जिट : जॉनसन

मैनचेस्टर : यूरोप के प्रमुख औद्योगिक शहर मैनचेस्टर पहुंचकर ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा, ब्रेक्जिट यानी यूरोपीय संघ से ब्रिटेन का अलग होना उनके देश के लिए आर्थिक तरक्की का बड़ा मौका है, लेकिन पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री टेरीजा मे ने इसे विपरीत हालात वाला मौका बनाकर पेश किया।

आजम के खिलाफ एक और मामले में चार्जशीट दाखिल

जागरण संवाददाता, रामपुर

सांसद आजम खां पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस उनके खिलाफ दायर मुकदमों में चार्जशीट लगा रही है तो अदालत में किसानों के बयान करा रही है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी उनके खिलाफ जांच शुरू करने जा रही है। एसपी ने ईडी को रिपोर्ट भी भेज दी है। वहीं सैफनी में विवादित बोल के मामले में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। इसके अलावा अनुसूचित जाति की जमीन बिना अनुमति खरीदने पर आजम के खिलाफ16 नए मुकदमों की भी तैयारी चल रही है।

लोकसभा चुनाव के दौरान आजम ने सात अप्रैल को सैफनी में हुई जनसभा में भड़काऊ भाषण देते हुए प्रशासन पर उनकी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया था। संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के लिए अनर्गल शब्दों का इस्तेमाल किया था। वीडियो अवलोकन टीम

अनुसूचित जाति की जमीन को लेकर 16 नए मुकदमे की तैयारी

के प्रभारी अनिल कुमार चौहान ने शाहबाद कोतवाली में आजम के खिलाफ तहरीर दी थी। अब पुलिस ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-125 व 135(2) के तहत अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) द्वितीय की कोर्ट में इस मामले में चार्जशीट दाखिल की है। इससे पहले शाहबाद पुलिस द्वारा जयाप्रदा के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में चार्जशीट लगाकर भेज चुकी है।

जिलाधिकारी की कोर्ट में दर्ज होंगे 16 वाद : आजम के खिलाफ 54 आपराधिक और जमीन से जुड़े 14 मुकदमे दायर हो चुके हैं। दर्ज कुल मुकदमों में 26 तो इसी माह दर्ज हुए हैं। अब अनुसूचित जाति के लोगों की जमीन बिना अनुमति खरीदने के मामले में 16 नए वाद दायर करने की तैयारी है।

महाराष्ट्र में बाढ़ में फंसी महालक्ष्मी एक्सप्रेस, 12 घंटे की मुसीबत के बाद बचाए गए 1050 यात्री

महाराष्ट्र में मुंबई-कोल्हापुर मार्ग पर चलने वाली महालक्ष्मी एक्सप्रेस वांगनी और बदलापुर के बीच बाढ़ में फंस गई। राष्ट्रीय आपदा राहत बल (एनडीआरएफ) की टीम ने ट्रेन में 12 घंटे से फंसे 1050 यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया। ज्ञात हो मुंबई में लगातार बारिश से ट्रेन और हवाई सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हैं (यह तस्वीर भारतीय नौसेना ने एजेंसी को जारी की है)। (खबर पेज-5 पर) प्रेट्र

कारगिल में हारने वाले आतंकवाद को दे रहे बढ़ावा

मोदी बोले ▶ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नहीं होने देंगे धन का अभाव, कारगिल विजय दिवस समारोह में शरीक हुए पीएम

समुद्र से लेकर अंतरिक्ष तक भारत के हित सुरक्षित रखने का दिया भरोसा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की ओर इशारा करते हुए कहा कि कारगिल युद्ध में पराजित लोग छद्म युद्ध के सहारे राजनीतिक मकसद पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। यही नहीं, लड़ाई अब अंतरिक्ष तक भी पहुंच गई है। यह साइबर दुनिया में भी लड़ी जा रही है। इसके लिए सेना को आधुनिक बनाना हमारी जरूरत भी है और प्राथमिकता भी है। 'मौजूदा दौर में नई चुनौतियों के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए न तो किसी दबाव में आएंगे और न प्रभाव में काम करेंगे और न ही किसी अभाव में काम होगा।'

प्रधानमंत्री मोदी ने कारगिल विजय के बीस साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में कहा, सेना के आधुनिकीकरण में धन का अभाव नहीं होने देंगे। गहरे समुद्र से लेकर असीम अंतरिक्ष तक जहां-जहां भी भारत के हितों के सुरक्षा की जरूरत होगी भारत सामर्थ्य

कारगिल विजय के 20 साल पूरे होने पर दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शनिवार को आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को फिर हरकतों से बाज आने के लिए चेताया। एएनआइ

का भरपूर उपयोग करेगा। युद्ध सरकारें नहीं लड़ती हैं, बल्कि पूरा देश लड़ता है। कारगिल के समय भी पूरा भारत एकजुट होकर वीर सैनिकों के साथ खड़ा था। पाक के साथ कारगिल समेत चार लड़ाइयों में दुश्मन को पराजित करने के साथ ही संयुक्त राष्ट्र मिशनों में भारतीय सैनिकों की बहादुरी का परचम लहराने का जिक्र करते हुए मोदी ने फिर साफ कर दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा पर हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे : राष्ट्रीय सुरक्षा के अभेद्य रहे बिना विकास भी संभव नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल पर हम किसी के भी दबाव में नहीं आएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारी सेना परंपरागत युद्ध में पारंगत है। लेकिन आज युद्ध का स्वरूप बदल गया है। आज पूरी दुनिया छद्म युद्ध की शिकार है। इसमें आतंकवाद पूरी मानवता को बहुत बड़ी चुनौती दे रहा है।

सैनिकों और उनके परिवारों से जुड़े अहम फैसले : उन्होंने बताया कि किस तरह पिछले पांच साल में सैनिकों और उनके परिवार से जुड़े अहम फैसले लिए गए हैं। इनमें वन रैंक वन पेंशन ही नहीं, नई सरकार बनने के बाद इस बार भी पहला फैसला शहीदों के बच्चों के स्कॉलरशिप बढ़ाने का लिया गया। शहीद सैनिकों के सम्मान में नेशनल वार मेमोरियल भी बना।

प्रधानमंत्री ने बताया कि सरकार सरहद पर रहने वाले नागरिकों के विकास की भी चिंता कर रही है। सीमा से सटे गांवों में आधारभूत संरचनाओं के विकास में तेजी आई है। जम्मू-कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे गांवों के लोगों को आरक्षण का लाभ इसी का हिस्सा है।

देश को बांटने की मानसिकता पर चेताया : धर्म, भाषा और जाति के आधार पर देश को बांटकर देखने की मानसिकता के प्रति आगाह करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 1947 में किसी एक भाषा बोलने वाले या एक पंथ या एक जाति के लोग ही आजाद नहीं हुए थे। बल्कि पूरा भारत आजाद हुआ था। संविधान भी पूरे भारत के लोगों के लिखा गया था। कारगिल में 500 से अधिक सैनिकों ने पूरे भारत के लिए कुर्बानी दी थी।

भारत के जवाब से पाक साजिश फेल

वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के अमेरिकी दौरे के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप के कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता की पेशकश का जिक्र नहीं किया। लेकिन यह साफ कर दिया कि पाकिस्तान शुरू से ही कश्मीर को लेकर छल करता रहा है। 1999 में भी उसने यही किया। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि युद्ध की आशंका को देखते हुए दुनिया के दूसरे देश दखल देंगे और वह कारगिल में नई रेखा खींचने में सफल होगा। लेकिन भारत की ओर से ऐसा करारा जवाब दिया गया कि उनकी साजिश धरी रह गई। पाकिस्तान को आगे भी ऐसे ही मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध में विजय देश का पराक्रम है।

प्रीति पटेल पर नस्ली टिप्पणी करने वाले को 22 माह की सजा

लंदन, प्रेट्र : ब्रिटेन की अदालत ने गृह मंत्री प्रीति पटेल के खिलाफ नस्ली टिप्पणियां करने वाले गेरार्ड ट्रायनर को 22 महीने की सजा सुनाई है। 53 वर्षीय गेरार्ड ने बीते साल अक्टूबर-दिसंबर के बीच पटेल के फेसबुक पेज पर कई नस्ली टिप्पणियां पोस्ट की थीं। उसे जनवरी में हिरासत में लिया गया था। पूछताछ के दौरान गेरार्ड ने कंजरवेटिव पार्टी की सांसद पटेल के खिलाफ टिप्पणियां करने की बात स्वीकार की थी।

मैनचेस्टर क्राउन कोर्ट के जज सिमोन ब्रायन ने शुक्रवार को अपने आदेश में कहा, 'गेरार्ड के कृत्य को न तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता माना जा सकता है और न ही किसी नेता की आलोचना। उनका पोस्ट घृणित और नस्ली भेदभाव से प्रेरित है। ऐसी भाषा के लिए कोई जगह नहीं है।'

पुलिस को दिए बयान में भारतवंशी प्रीति पटेल ने गेरार्ड की टिप्पणी को अपमानजनक बताया था। उनका कहना था कि टिप्पणियों से वह बेहद आहत थीं। इसके चलते न सिर्फ उनका सार्वजनिक बल्कि निजी जीवन भी प्रभावित हुआ था। हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने बोरिस जॉनसन ने प्रीति पटेल को गृह मंत्री नियुक्त किया है। वह ब्रिटेन में भारतीय मूल की पहली गृह मंत्री हैं।

ईडी दफ्तर से भागा कमलनाथ का भांजा

गिरफ्तारी की तैयारी में थी ईडी, वॉशरूम जाने के बहाने रितुल ने दिया चकमा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ का भांजा रितुल पुरी प्रवर्तन निदेशालय को चकमा दे गया। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद घोटाले में रितुल की गिरफ्तारी की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की तैयारी धरी की धरी रह गई। यही नहीं, वह अदालत से दो दिन की अग्रिम जमानत लेने में भी सफल रहा।

वैसे तो अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद घोटाले में रितुल पुरी से कई बार पूछताछ हो चुकी है और उसे शुक्रवार भी रामलीला मैदान के नजदीक स्थित ईडी के दिल्ली जोन के आफिस में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ में सहयोग नहीं करने के कारण जांच से जुड़े अधिकारियों ने उसे गिरफ्तार करने का फैसला लिया और मुख्यालय से इसकी इजाजत भी ले ली। लेकिन इस बीच किसी ने रितुल पुरी को ईडी की गिरफ्तारी की तैयारियों के बारे में बता दिया। इसके बाद रितुल पुरी बाथरूम जाने का बहाना बनाकर बाहर निकला तो फिर वापस नहीं आया। जांच अधिकारियों ने उसके मोबाइल पर कॉल किया तो वह भी बंद मिला।

रितुल पुरी फाइल फोटो

परेशान ईडी अधिकारियों ने रात में उस होटल की भी तलाशी ली, जिसमें रितुल रुका था, लेकिन वहां उसकी कार और ड्राइवर तो था, वह खुद गायब था। ईडी अधिकारी दिन में रितुल को ढूंढ निकालने और अगली तारीख पर पूछताछ के लिए समन भेजने की तैयारियों में ही जुटे थे कि उसने ईडी की विशेष अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी लगा दी। अदालत ने सोमवार को रेगुलर कोर्ट में मामले की सुनवाई तक अग्रिम जमानत मंजूर भी कर दी।

दरअसल अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद घोटाले के अंतिम लाभार्थियों की तलाश में जुटी एजेंसियां रितुल पुरी तक पहुंचीं। घोटाले में दलाली की रकम का एक भाग रितुल पुरी की कंपनी में मिलने के कुछ सुबूत मिले हैं और इसकी तस्दीक की जा रही है। इसी सिलसिले में उससे पूछताछ हो रही थी। रितुल पुरी मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ की बहन नीता पुरी का बेटा है। रितुल पुरी हिंदुस्तान पावर प्रोजेक्ट का चेयरमैन भी है। रितुल के पिता दीपक पुरी ऑप्टिकल मीडिया फर्म मोजर बीयर के सीएमडी हैं।

मोईन कुरैशी मनी लांड्रिंग मामले में सतीश बाबू गिरफ्तार

नई दिल्ली : ईडी ने विवादित मांस निर्यातक मोईन कुरैशी और अन्य लोगों के खिलाफ मनी लांड्रिंग मामले की जांच के संबंध में हैदराबाद के कारोबारी सना सतीश बाबू को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने उसे पांच दिन की रिमांड पर ईडी के हवाले कर दिया है। हालांकि, जांच एजेंसी ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी। पिछले साल बाबू के आरोपों के बाद ही सीबीआइ के शीर्ष अफसरों के बीच विवाद शुरू हुआ था। (पेज-3)

इलेक्ट्रिक वाहनों पर अब पांच फीसद जीएसटी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में अहम कदम उठाते हुए जीएसटी काउंसिल ने इन वाहनों पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दर घटाने का फैसला किया है। इलेक्ट्रिक वाहनों पर अब महज पांच फीसद जीएसटी लगेगा, जो फिलहाल 12 फीसद है। इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जर पर भी पांच फीसद जीएसटी लगेगा। इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी की नई दर पहली अगस्त से प्रभावी होगी।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शनिवार को जीएसटी काउंसिल की 36वीं बैठक में इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी की दर 12 फीसद से घटाकर पांच फीसद करने का निर्णय लिया गया। काउंसिल ने इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन पर जीएसटी की दर 18 फीसद से घटाकर पांच फीसद करने का फैसला भी किया। जीएसटी काउंसिल की यह बैठक शुक्रवार को होनी थी। लेकिन संसद सत्र के दौरान सीतारमण की व्यस्तता के चलते अंतिम क्षणों में यह बैठक टाल दी गई। काउंसिल ने कंपोजीशन स्कीम के तहत चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से जून की तिमाही के रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि भी 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी। उल्लेखनीय है कि

नई दिल्ली में शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई वस्तु एवं सेवाकर काउंसिल की 36 वी बैठक में इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी की दर में कटौती की घोषणा की गई। बैठक में वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर(दाएं) भी उपस्थित रहे। एएनआइ

भारत में इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग अभी शुरुआती दौर में है। सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (एसएमईवी) के अनुसार भारत में चार लाख दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन हैं, जबकि कारों की संख्या महज हजारों में है। फिलहाल देश में जितनी कारें बिकती हैं, उनमें इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी एक फीसद से भी कम हैं। यही वजह है कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रही है। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले आम बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए उपायों का एलान किया था। इसके तहत अगर कोई व्यक्ति इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए कर्ज लेता है, तो वह ब्याज के भुगतान के एवज में वह 1.5 लाख रुपये तक पर आयकर में छूट ले सकेगा। इसके अलावा केंद्र सरकार ने 10,000 करोड़ रुपये की फेम-2 योजना को भी मंजूरी दी है।

बात पते की : काउंसिल ने निकायों या प्रशासन द्वारा 12 यात्रियों से अधिक क्षमता वाली इलेक्ट्रिक बसों को भाड़े पर लेने के मामले में जीएसटी से पूरी तरह छूट का फैसला किया।

बड़ा कदम

ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए हाई कोर्ट ने उठाया बड़ा कदम, कोर्ट ने जारी किए 5 दिशानिर्देश, परीक्षाओं से 15 दिन पहले लाउडस्पीकरों पर लगाई रोक

धार्मिक स्थलों पर बिना मंजूरी अब नहीं बजेगा लाउडस्पीकर

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट आदेश दिया है कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों और अन्य धार्मिक स्थलों में दस डेसीबल से अधिक आवाज में लाउडस्पीकर नहीं चलाए जाएं। इस सीमा तक लाउडस्पीकर चलाने के लिए भी जिला प्रशासन से मंजूरी लेनी होगी। आवासीय क्षेत्रों में बच्चों की परीक्षाओं से 15 दिन पहले से लाउडस्पीकर चलाने पर कोर्ट ने रोक दी है।

पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में विचाराधीन याचिकाओं पर अपने विस्तृत आदेश में हाई कोर्ट ने कहा कि मंजूरी के लिए प्रशासन को अंडरटेकिंग देनी होगी। इसमें यह सुनिश्चित करना होगा कि लाउडस्पीकर के प्रयोग से परिसर के आस-पास के क्षेत्र में दस डेसीबल से अधिक आवाज नहीं होगी। पांच याचिकाओं को निपटारा करते हुए जस्टिस राजीव शर्मा और जस्टिस हरिन्दर सिंह सिद्धू की पीठ ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए 15 दिशा-निर्देश तय किए हैं। इनमें धार्मिक संस्थानों के लिए ध्वनि सीमा निश्चित किए जाने के साथ ही हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विशेष धार्मिक या सांस्कृतिक अवसरों पर रात दस से 12 बजे के बीच लाउडस्पीकर चलाने की अनुमति भी एक कैलेंडर वर्ष में 15 दिन से अधिक न दी जाए।

परिसर से बाहर ध्वनि पांच डेसीबल से अधिक न हो : किसी भी निजी ध्वनि यंत्र से निकलने वाली ध्वनि की सीमा निर्धारित करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि जिस परिसर में अधिक ध्वनि वाला यंत्र प्रयोग में लाया जाए उससे बाहर ध्वनि पांच डेसीबल से अधिक नहीं होनी चाहिए।

रात दस से सुबह छह के बीच हॉर्न नहीं : रात के समय रिहायशी क्षेत्रों में हॉर्न बजाने पर रोक लगाते हुए हाई कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के पुलिस अधीक्षकों से कहा कि वे सुनिश्चित करें कि रिहायशी क्षेत्रों में कोई रात दस बजे से सुबह छह बजे के बीच हॉर्न का प्रयोग ना करे। कोर्ट ने सभी पुलिस अधीक्षकों को मोटर साइकिलों पर साइलेंसर को सुनिश्चित बनाने के भी आदेश दिए हैं।

लाइव शो में भी अश्लील गीतों पर रोक : हाई कोर्ट ने नशा, हिंसा और मादकता बढ़ाने वाले गीतों पर भी नकेल कसा है। अपने आदेशों में कहा है कि पुलिस अधीक्षक सुनिश्चित करें कि किसी लाइव शो में कोई ऐसा गीत ना गाया जाए जो नशे, शराब, हिंसा या मादकता को प्रेरित करता हो।

महिलाएं बिना दुपट्टा नहीं आएं दफ्तर : डीसी

जागरण संवाददाता, फाजिल्का

फाजिल्का के डिप्टी कमिश्नर मनप्रीत सिंह ने अपने कार्यालय के कर्मचारियों पर ड्रेस कोड लागू करते हुए आदेश दिया कि कोई भी महिला कर्मचारी बिना दुपट्टे के ऑफिस नहीं आएगी। पुरुष स्टाफ पर भी टी-शर्ट पहनकर नहीं आएगा। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के कुछ कर्मचारी टी-शर्ट पहनकर आते हैं। कई की बाजू में टैटू भी बने हैं। इसी को ध्यान में रखकर डीसी मनप्रीत सिंह ने 26 जुलाई को एक आदेश जारी किया। इसमें कहा गया है कि महिलाओं के बिना दुपट्टे के आने और पुरुषों के टी-शर्ट पहनकर आने से दफ्तर जैसा माहौल नहीं लगता। डीसी कार्यालय यूनियन ने फैसले का समर्थन करते हुए सभी से निर्धारित ड्रेस कोड में आने को कहा है।

वहीं, वूमेन सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की प्रधान सुजाता नारंग ने कहा कि आज के युग में बिना दुपट्टे के कार्यालय न आने का आदेश सही नहीं है। हर जगह पर महिलाओं को पुरुषों के बराबर रखा जा रहा है। बस वह इतना ही कहेंगी कि बढ़ते युग के अनुसार यह आदेश सही नहीं हैं। हिंदू महासभा राष्ट्रवादी ने इस आदेश की सख्त शब्दों में निंदा करते हुए इसे नादिरशाही फरमान बताया है। महासभा के अध्यक्ष एडवोकेट गगन भाटिया व महामंत्री राजविंदर राजा ने कहा कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जानी चाहिए।

ओडिशा सीमा पर मुठभेड़ में मारे गए सात नक्सली

जगदलपुर, नईदुनिया

जवानों ने टिरिया के जंगल में सात नक्सलियों को मार गिराया है। यह बड़ी सफलता है। बॉडी ला रहे हैं। यहां पहुंचने के बाद उनकी शिनाख्त की जाएगी। और भी नक्सलियों के मारे जाने की संभावना है। सर्चिंग जारी है।

विवेकानंद सिन्हा, आइजी बस्तर

रविवार से नक्सलियों के शुरू हो रहे शहीदी सप्ताह के एक दिन पहले जिला बल, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड (डीआरजी) और स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की संयुक्त फोर्स को बड़ी सफलता मिली है। शनिवार शाम करीब साढ़े पांच बजे नगरनार थाना क्षेत्र के माचकोट जंगल में हुई मुठभेड़ में सात नक्सलियों को मार गिराया गया। इनमें तीन महिला व चार पुरुष हैं। घटनास्थल से सातों नक्सलियों के शव, एक इंसास राइफल, चार थ्री नॉट थ्री राइफल, और एक भरमार बंदूक बरामद किया गया है।

आइजी बस्तर विवेकानंद सिन्हा ने बताया कि मुख्यालय से करीब 40 किमी दूर ओडिशा सीमा से लगे तिरिया के माचकोट जंगल में शनिवार को नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर एसटीएफ, डीआरजी व जिला बल की संयुक्त टीम नगरनार थाने से सर्च ऑपरेशन पर रवाना हुई थी। ग्राम तिरिया से करीब चार किलोमीटर दूर जंगल में जैसे ही टीम घुसी, घात लगाए नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने भी फौरन मोर्चा संभाल लिया। दोनों ओर से करीब आधे घंटे तक फायरिंग चलती रही। इसके बाद खुद को कमजोर पड़ता देख नक्सली भाग खड़े हुए। मौके की सर्चिंग करने पर सात नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं।

दर्जन भर के मारे जाने का दावा : पुलिस का दावा है कि मौके पर 150 से अधिक नक्सली मौजूद थे। मौके पर मिले खून के धब्बों और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर एक दर्जन से अधिक नक्सलियों के मारे जाने का अनुमान है। मौके पर सर्चिंग जारी है।

32.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज हुआ दिल्ली में। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा। शनिवार को कई इलाकों में बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार रविवार के दिन भी बादल छाए रहेंगे। हल्की बारिश होने की भी संभावना है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
रविवार 28 जुलाई 2019

न्यूज गैलरी

दिल्ली सचिवालय में रुकेगा बोतल बंद पानी का उपयोग

नई दिल्ली : दिल्ली सचिवालय में बैठकों और कार्यक्रमों में प्लास्टिक के उपयोग को रोका जाएगा। इसके लिए बोतलबंद पानी, प्लास्टिक प्लेट सहित अन्य सामान का इस्तेमाल नहीं होगा। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने सर्कुलर जारी किया है। इसमें लिखा है कि प्लास्टिक बोतल, प्लेट, गिलास और कैरी बेग का इस्तेमाल कम समय के लिए होता है, लेकिन ये लंबे समय तक पर्यावरण और स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। प्लास्टिक सीवर और नाले के जाम का कारण भी बनती है। जीएडी ने सचिवालय में स्थित सभी अधिकारियों को प्लास्टिक उत्पादों का प्रयोग करने से बचने को कहा है। (जासं)

सर्वधर्म प्रार्थना सभा की तैयारी को लेकर कांग्रेस ने की बैठक

नई दिल्ली : पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को श्रद्धांजलि देने के लिए कांग्रेस चार अगस्त को सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित करेगी। इसकी तैयारी के लिए शनिवार को प्रदेश कार्यालय में बैठक बुलाई गई। बैठक में पूर्व केंद्रीय मंत्रियों, दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्रियों के साथ ही पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, जिला अध्यक्ष, निगम पार्षद एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों का भी बुलाया गया था, जिससे कि सर्वधर्म प्रार्थना सभा की तैयारी के साथ ही दीक्षित के निधन के बाद के राजनीतिक हालात व विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हो सके। कई नेता इसमें शामिल नहीं हुए। (जासं)

हवाई यात्रा भी कर सकते हैं बुजुर्ग तीर्थ यात्री

नई दिल्ली : मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत दिल्ली सरकार बुजुर्गों को हवाई यात्रा भी करा सकती है। दिल्ली सरकार ने दक्षिण भारत के पवित्र धर्मस्थलों के किराये के बारे में हवाई यात्रा करा रहीं विभिन्न कंपनियों से जानकारी मांगी है। बहरहाल, ट्रेन मार्ग से यात्रा करने वालों के आवेदन दिल्ली सरकार के पास आने जारी हैं। अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर के लिए एक हजार यात्रियों के वापस आने के बाद स्वर्ण मंदिर के लिए ही एक हजार यात्रियों के आवेदन और आ गए हैं। दिल्ली सरकार द्वारा अगला जत्था फिर से अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर को रवाना होगा। देशभर में मनाए जा रहे गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर दिल्ली से एक हजार बुजुर्ग स्वर्ण मंदिर जाकर गुरु धाम के दर्शन करेंगे। स्वर्ण मंदिर के दर्शन के बाद तीर्थ यात्रियों का जत्था वाघा बॉर्डर और आनंदपुर साहिब भी जाएगा। (जासं)

चोरी का आरोपित 23 साल बाद गिरफ्तार

नई दिल्ली : मंदिर मार्ग थाना पुलिस ने कनॉट प्लेस स्थित प्लाजा सिनेमा के कैंटीन में चोरी करने वाले आरोपित हरी भगवान शर्मा को 23 साल बाद गिरफ्तार किया गया। 1995 में हरी भगवान शर्मा पर 25 हजार रुपये चोरी करने का आरोप लगा था। उसके बाद वह फरार हो गया था। कनॉट प्लेस थाने में उसके खिलाफ चोरी का मामला दर्ज है। नई दिल्ली जिला के एडिशनल डीसीपी डॉ. ईश सिंघल के मुताबिक हरी भगवान शर्मा मूलरूप से संभल, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। उसे मार्च 2001 में कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया था। शुक्रवार को मंदिर मार्ग थाना पुलिस को सूचना मिली कि हरी भगवान शर्मा संभल स्थित अपने घर में रह रहा है। (जासं)

मेरठ हाईवे पर वाहनों का प्रवेश बंद, एनएच-9 पर दिनभर जाम

गाजियाबाद : कांवड़ यात्रा के चलते मेरठ हाईवे पर वाहनों का प्रवेश बंद किए जाने से एनएच-9 पर शनिवार को भारी जाम लगा रहा। शनिवार को छुट्टी के बाद भी सुबह से ही एनएच-9 की दोनों लेन पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। दिन में भी यहां ट्रैफिक की रफ्तार धीमी रही। कांवड़ यात्रा के चलते मेरठ हाइवे पर 22 जुलाई से भारी वाहनों का प्रवेश बंद है, जबकि 26 जुलाई से यह रोड एक लेन का हो गया है। मेरठ से आने वाला मार्ग पूरी तरह से शिवभक्तों के लिए आरक्षित कर दिया गया है। इस कारण जीटी रोड और एनएच-9 के साथ मेरठ हाईवे के एक लेन पर भी पूरे दिन जाम लगा रहा। श्रावण मास के दूसरे सोमवार यानी कल जीटी रोड पर पर डायवर्जन लागू रहेगा। कांवड़ यात्रा के चलते मेरठ रोड पहले से ही बंद है। जीटी रोड के भी बंद होने के कारण सोमवार को शहर में ट्रैफिक की हालत बदतर हो सकती है। (जासं)

सभी भ्रष्ट अधिकारियों को जबरन घर भेजने की तैयारी

सख्त रुख ▶ विभाग रिपोर्ट तैयार कर मुख्य सचिव को सौपेंगे

दिल्ली सरकार के अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन पर प्रति माह खर्च होते हैं 900 करोड़

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

भ्रष्ट और नाकारा अफसरों को जबरन रिटायर करने के नरेंद्र मोदी सरकार के निर्णय की तर्ज पर दिल्ली सरकार भी ऐसे अफसरों को घर भेजने की तैयारी में हैं। उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री से मिली हरी झंडी के बाद नौकरशाह इस पर गंभीरता से काम कर रहे हैं। सभी विभाग अपनी रिपोर्ट तैयार कर मुख्य सचिव को देने की तैयारी में हैं। 31 जुलाई से पहले यह रिपोर्ट मुख्य सचिव को सौंपनी है। इसके बाद दो अगस्त को मुख्य सचिव इसे उपराज्यपाल अनिल बैजल को सौंपेंगे। इस सूची में आइएएस और दानिक्स अधिकारी शामिल नहीं हैं। इनकी सूची केंद्र सरकार स्तर पर बन रही है।

दिल्ली सरकार में करीब 80 हजार अधिकारी पर कर्मचारी कार्यरत हैं। प्रति माह करीब 900 करोड़ की राशि इनके वेतन पर खर्च की जाती है। इनमें से कितने लोग 50 साल से ऊपर हैं और कितनों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, यह अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। मगर भ्रष्टाचार व नाकारा अधिकारियों को जबरन घर भेजने के फैसले के बाद से सरकार के सभी विभागों में गहमा-गहमी है। हर विभाग में इस बात की ही चर्चा हो रही है कि किस-किस का नंबर आता है। इसके लिए विभाग प्रमुख स्तर पर भी कमेटियां बनाई गई हैं। ये कमेटियां अपने-अपने विभाग की रिपोर्ट तैयार कर रही हैं। कमेटियां उन अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची तैयार कर रही हैं, जिनके खिलाफ पहले से ही विजिलेंस, दिल्ली पुलिस या अन्य विभाग में मुकदमे दर्ज हैं। ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को जबरन घर भेजा जाएगा।

सूत्रों का कहना है कि वित्त विभाग सहित कुछ अन्य विभागों ने अपनी रिपोर्ट मुख्य सचिव को सौंप दी है। शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने कुछ मोहलत मांगी है। इन दोनों विभागों में कर्मचारियों की संख्या अधिक है। सूत्रों का कहना है कि यदि ये विभाग 31 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट दे देते हैं तो दिल्ली सरकार दो अगस्त को फाइनल रिपोर्ट उपराज्यपाल को सौंप देगी। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए अवकाश के दिन कुछ विभागों में शनिवार को काम हुआ और रविवार को भी कुछ विभागों में काम होगा।

केजरीवाल ने उपराज्यपाल का किया खुलकर समर्थन : केंद्र सरकार की तर्ज पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी भ्रष्ट अधिकारियों को जबरन रिटायर करना चाहते हैं। यह पहला मामला है, जिसका सीएम केजरीवाल के उपराज्यपाल अनिल बैजल का खुला समर्थन किया है।

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सात जुलाई को सभी कैबिनेट सदस्यों को अपने-अपने विभागों में ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों की एक सूची तैयार करने का निर्देश दिए थे, जिससे उन्हें जबरन रिटायर किया जा सके। यह सेंट्रल सिविल सर्विसेस (पेंशन) रूल्स, 1972 के फंडामेंटल रूल 56 (जे) के तहत ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को सेवानिवृत्त करने की केंद्र सरकार की पहल की तर्ज पर होगा। इससे पहले चार जुलाई को उपराज्यपाल अनिल बैजल से इसके आदेश जारी किए थे।

भाजपा ने महिलाओं को नि:शुल्क रजिस्ट्री की सुविधा देने की मांग की

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : महिलाओं को नि:शुल्क जमीन व मकान की रजिस्ट्री करने की मांग को लेकर दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं से लिया जाने वाला चार फीसद रजिस्ट्री शुल्क खत्म किया जाना चाहिए। इससे महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा मिलेगा। महिलाओं के नाम से संपत्ति होने से उनकी सामाजिक सुरक्षा भी बढ़ेगी। उन्होंने इस दिशा में झारखंड की भाजपा सरकार द्वारा उठाए गए कदम का भी अपने पत्र में जिक्र किया है।

उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार जून 2017 से एक रुपये शुल्क लेकर महिलाओं के नाम से जमीन व मकान की रजिस्ट्री कर रही है। दिल्ली सरकार को भी महिलाओं को सशक्त करने के लिए इस तरह का कदम उठाना चाहिए। उन्होंने अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया को तेज करने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि इस काम में नौकरशाहों द्वारा उत्पन्न की गई बाधाओं को दूर करने के साथ ही इन कॉलोनियों का नक्शा तैयार करने के लिए नगर निगमों को धन मुहैया कराने की जरूरत है।

उन्होंने दिल्ली सरकार पर अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने में रोड़ा अटकाने का आरोप लगाया। मनोज तिवारी का कहना है कि वर्ष 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद ही 1797 अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी।

बड़े-बड़े भूखंडों की योजना निकालकर घोटालों को दिया अंजाम

कुंदन तिवारी, नोएडा

आनंद की बेनामी संपत्ति का मामला

- नौकरशाह और नेताओं के इशारों पर तैयार हुई थी घोटोलों की पॉलिसी
- छोटे-छोटे भूखंड में तोड़कर मनचाहे लोगों को किया गया आवंटित

बसपा सुप्रीमो मायावती के भाई आनंद कुमार ने 2007 से 2011 तक भू-आवंटन की आड़ में ही अरबों रुपये की संपत्ति जुटाकर घोटाला किया। नौकरशाह की समझ और नेताओं के इशारों पर ही घोटालों की पॉलिसी तैयार की गई व जमीनों का आवंटन हुआ। सिर्फ उन्हीं लोगों को भूखंड आवंटित किए गए, जिनकी पहुंच आनंद या उनके करीबियों तक रही। घोटालों का ताना-बाना सिर्फ काली कमाई और लाखों वर्गमीटर जमीन हड़पने के लिए बुना गया। इसकी परत दर परत अब खुलने लगी है।

सूत्र का कहना है कि यदि छोटे भूखंड की योजना आती तो इसके खरीदार अधिक होते। बड़े भूखंड के खरीदारों का बेस प्राइज भी कम होता और इसमें प्रतिद्वंद्वी की संख्या भी कम रही। इससे मनमाफिक लोगों को आवंटित कराकर शासनादेश के नाम पर विखंडित कराया गया। इसके बाद छोटे-छोटे भूखंड आपस में बांट लिए गए। यही खेल बसपा शासन काल में खेला गया।

बसपा शासन काल में प्राधिकरण में ग्रुप हाउसिंग स्कीमों की बाढ़ आ गई। ग्रुप हाउसिंग में सर्वाधिक आवंटन इसी दौरान किए गए। बड़े-बड़े भूखंडों की स्कीम निकाली गई। इन भूखंडों का आवंटन नीलामी के जरिये किया गया। बिड डालने वाली एक बड़ी कंपनी होती थी। यह कंपनी भी बसपा के करीबियों से जुड़े लोगों की होती थी। महज 10 फीसद देकर भूखंड का आवंटन कर दिया जाता था। इसके बाद इस भूखंड को छोटे-छोटे भूखंड में तोड़कर मनचाहे लोगों को आवंटित किए जाते थे। आवंटन के इस खेल में नौकरशाह और नेताओं ने अपनी जेबें खूब भरीं। सेक्टर-94 में बीपीटीपी के आवंटन में भी यही ताना बना बुना गया। इसमें 95 एकड़ के एक भूखंड को पहले चार भूखंड में तोड़ा गया। इसके बाद इन भूखंडों को विखंडित किया गया। खास यह है कि छोटे भूखंड का आवंटन मनचाहे लोगों को किया गया। ऐसे ही एक नाम नोएडा के पंडित जी का भी है। उन्होंने बसपा शासन काल में आनंद के लिए अकूत संपत्ति जुटाई थी।

सूत्र बताते हैं कि बसपा शासनकाल में आनंद के इस राजदार ने करीबियों के साथ मिलकर शहर में करीब 600 से अधिक भूखंड का हेरफेर किया। आज भी आनंद व यादव सिंह की कई संपत्तियों में पंडित जी भी शामिल है। कई औद्योगिक इकाइयों का मालिक भी है। इन्हीं जगहों से वह आनंद की अकूत संपत्तियों की देखरेख कर रहा है। सेक्टर-94 में एक बड़ा भूखंड इसी के नाम वर्ष 2012 में आवंटित किया गया है। इसे भी आनंद की संपत्ति ही बताया जा रहा है। आनंद के इस खेल ने प्राधिकरण अधिकारियों ही नहीं, बल्कि प्राधिकरण के एक माली तक को फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया है।

चुनाव समिति के खिलाफ लामबंद हुए छात्र संगठन

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) का नया सेशन शुरू होने के साथ ही छात्र राजनीति भी जोर पकड़ने लगी है। इस बार जेएनयू के छात्र संगठनों ने मौजूदा चुनाव समिति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विभिन्न संगठनों ने बैठक कर 2019 के चुनाव के लिए नई चुनाव समिति के गठन की जेएनयू प्रशासन से मांग की है।

शनिवार को जेएनयू में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी), अखिल भारतीय छात्र संघ (आइसा), ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन (एआइएसएफ), नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआइ), बिरसा आंबेडकर फुले स्टूडेंट्स एसोसिएशन (बापसा), भगत सिंह आंबेडकर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन (बासो) जैसे छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। जेएनयू प्रशासन से इस बार नई चुनाव समिति का गठन किए जाने की मांग की गई है। बैठक में तय हुआ कि 2019 के छात्रसंघ चुनाव जेएनयू के संविधान के तहत ही आयोजित किए जाएं। इस मामले में बीते साल के छात्रसंघ के प्रतिनिधि जेएनयू के छात्र डीन से मांग करेंगे कि वह छात्रसंघ के चुनाव की प्रक्रिया को जल्द शुरू करें। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि छात्रों के साथ बिना कोई विचार-विमर्श किए कोई भी फैसला छात्रसंघ चुनाव से जुड़ा नहीं लिया जाएगा। वर्ष 2018 में 16 सितंबर को जेएनयू छात्र संघ चुनाव के नतीजे आए थे।

सितंबर से देख सकेंगे सिग्नेचर ब्रिज के ऊपर चढ़कर दिल्ली का नजारा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी है कि वे वजीराबाद में यमुना पर बनाए गए सिग्नेचर ब्रिज के ऊपर चढ़कर सितंबर से दिल्ली को देख सकेंगे। सिग्नेचर ब्रिज के 154 मीटर ऊंचे मुख्य पिलर के 22 मीटर के ऊपरी बाक्स में कांच लगाने का काम पूरा हो गया है।

योजना पर काम कर रहे दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम का कहना है कि पिलर के ऊपर जाने के लिए लिफ्ट लगाए जाने का काम चल रहा है, जो अगस्त के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। इस बाक्स में जाने के लिए चार लिफ्ट लगाई जानी हैं।

600-1000 रुपये हो सकता है टिकट : ब्रिज के ऊपर से दिल्ली का शानदार नजारा देखने के लिए लोगों को छह सौ रुपये से लेकर एक हजार रुपये के बीच में चुकाने पड़ सकते हैं क्योंकि इसे बनाने के लिए भारी-भरकम खर्च हो रहा है। दिल्ली सरकार के जुड़े सूत्रों का कहना है कि पिलर पर चढ़ने के लिए संसाधन जुटाने का काम यदि अगस्त तक पूरा कर लिया जाता है, तो इसके बाद पर्यटकों को पिलर के माध्यम से दिल्ली दिखाने की सुविधा शुरू कर दी जाएगी। इस परियोजना की राशि 1518.37 करोड़ रुपये रखी गई है। ब्रिज करीब 700 मीटर लंबा है। इसमें दोनों ओर चार-चार लेन हैं। यह ब्रिज 35.2 मीटर चौड़ा है।

सिग्नेचर ब्रिज के मुख्य पिलर के ऊपरी भाग में तैयार हुआ कांच का बाक्स। संजय

ब्रिज पर पर्यटकों को ले जाने के लिए तैयारियां बाकी : पर्यटकों को ब्रिज के पिलर तक ले जाने के लिए अभी तैयारी पूरी नहीं हुई है। इसके लिए अलग से रैंप बनाए जाने हैं।

फ्लैट बुकिंग के नाम पर आम्रपाली ने 837 करोड़ के बोगस बिल बनाए

- मास्टर प्लान से अलग लोगों को दिखाए गए सपने
- प्रापर्टी डीलर्स व एजेंटों को शामिल कर बुक कराए गए फ्लैट

जागरण संवाददाता, नोएडा : आम्रपाली ने सिर्फ खरीदारों का पैसा ही डायवर्ट नहीं किया, बल्कि बोगस बिल के जरिये भी उसने काली कमाई की। एक फ्लैट की कई बार बुकिंग की गई। लोगों को वह प्लान दिखाए गए जो कभी परियोजनाओं के मास्टर प्लान में शामिल ही नहीं थे, जिनका भविष्य में अस्तित्व ही नहीं था। इसके जरिये आम्रपाली समूह ने 837 करोड़ रुपये के बोगस बिल बनाए। इसमें से अधिकांश रकम का ट्रांजेक्शन नकद में किया गया।

2009 से 2011 तक आम्रपाली समूह को नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हाउसिंग परियोजनाओं के लिए भूखंडों का आवंटन किया गया। इस दौरान आवंटन व भुगतान दोनों में लापरवाही बरती गई। इसका खामियाजा प्राधिकरण को भुगतना पड़ रहा है। समूह ने बड़ी चालाकी से खरीदार को वह सपने दिखाए जिनको उन्होंने मास्टर प्लान व एप्रूव्ड नक्शों में शामिल किया ही नहीं था। एक फ्लैट की बुकिंग होने के बाद दोबारा उसी फ्लैट की बुकिंग की गई। वह भी बाजार दर से महंगे दामों पर। अधिकांश बुकिंग प्रापर्टी डीलरों व अपने एजेंटों द्वारा नकद में कराई गई। इसकी पर्ची बनाई गई। इस तरह से आम्रपाली ने करीब 837 करोड़ रुपये के बोगस बिल बनाए।

जश्न-ए-आजादी का रंग

स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) नजदीक आ रहा है। इसे लेकर राजधानी में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसी के तहत तिलक ब्रिज रेलवे स्टेशन को जश्न-ए-आजादी के रंग में रंगा जा रहा है। फुटओवर ब्रिज पर आजादी से जुड़े चित्र बनाए जा रहे हैं। प्रेट्र

सड़क किनारे झुग्गी में सो रहे श्रमिकों पर चढ़ाई कार, दो की मौत

जासं, ग्रेटर नोएडा : एच्छर चौकी से 200 मीटर की दूरी पर तीन झुग्गियों में सो रहे लोगों पर शराब के नशे में धुत दूध कारोबारी ने स्कार्पियो चढ़ा दी। हादसे में दो की मौत हो गई, जबकि एक महिला समेत तीन अन्य घायल हो गए। आरोपित चालक मौके से भागने लगा तो वहां मौजूद लोगों ने उसे पकड़ कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने आरोपित चालक को गिरफ्तार कर उसका मेडिकल कराया। रिपोर्ट में युवक के नशे में धुत होने की पुष्टि हुई है। आरोपित की स्कार्पियो से शराब की बोतल व प्लास्टिक के गिलास बरामद हुए हैं।

मृतक सियाराम (30) और संजय (32) मूलरूप से बिहार के रहने वाले हैं। दोनों साइट फोर स्थित निर्माणाधीन साइट पर मजदूरी करते थे। एच्छर चौकी से 200 मीटर दूर स्थित साइट के समीप ही सड़क किनारे झुग्गी बनाकर एक दर्जन श्रमिक रहते हैं। उसी में सियाराम व संजय भी रहते थे। शुक्रवार रात करीब साढ़े बारह बजे झुग्गी में श्रमिक सो रहे थे। तभी दूध कारोबारी राज भाटी ने तेज रफ्तार में स्कार्पियो श्रमिकों पर चढ़ा दी। उसने भागने का प्रयास किया। लोगों ने उसको पकड़ लिया, जबकि गाड़ी में सवार अन्य दो युवक भाग निकले।

आइआइटी परिसर में फंदे से लटके मिले मां और बेटा-बहू

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- पुलिस इसे घरेलू कलह के चलते आत्महत्या की बात कह रही है

आइआइटी दिल्ली परिसर स्थित स्टाफ क्वार्टर में शुक्रवार रात मां, बेटा व बहू के शव फंदे से लटके मिले। घटना साउथ-वेस्ट जिले के किशनगढ़ थानाक्षेत्र की है। बेटे का शव ड्राइंग रूम में लोहे की पाइप से बंधे दुपट्टे, बाकी दोनों के शव अलग-अलग कमरे में पंखे से दुपट्टे से लटके मिले। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सफदरजंग अस्पताल स्थित मोर्चरी भेज दिया। तीन सदस्यीय डॉक्टरों का मेडिकल बोर्ड रविवार को पोस्टमार्टम करेगा। शुरुआती जांच में पुलिस इसे घरेलू कलह के चलते आत्महत्या की बात कह रही है। मामले की मजिस्ट्रेटी जांच भी शुरू हो गई है।

डीसीपी साउथ-वेस्ट देवेंद्र आर्या ने बताया कि हरियाणा के करनाल के रहने वाले गुलशन दास (35) आइआइटी में बायो-केमिस्ट्री विभाग में सीनियर लैब असिस्टेंट थे। वह आइआइटी परिसर स्थित तृतीय तल के स्टाफ क्वार्टर (फ्लैट) में अपनी मां कांता देवी (59) व पत्नी सुनीता (32) के साथ रह रहे थे। गत 20 फरवरी को ही गुलशन व सुनीता की शादी हुई थी। यह उनकी दूसरी शादी थी। दोनों ने अपने पहले जीवन साथी को छोड़ दिया था। पुलिस के मुताबिक, परिवार के लोगों का दावा है कि सुनीता गर्भवती थी। शादी के बाद से ही दोनों में छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा होता था।

ऐसे हुई घटना की जानकारी : सुनीता का मायका नारायणा दिल्ली में ही है। उनकी मां कृष्णा देवी ने हालचाल लेने के लिए शुक्रवार को दिनभर बेटी को फोन किया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई। इस पर रात करीब 9.40 बजे कृष्णा ने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर बेटी व दामाद के बीच घरेलू हिंसा की बात कहते हुए किसी अनहोनी की आशंका जताई। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो गुलशन के क्वार्टर का दरवाजा खुला मिला। तीनों शव अलग-अलग कमरे में फंदे से लटके थे। पुलिस का कहना है कि तीनों की मौत कैसे व किस समय हुई, मामला हत्या या आत्महत्या का है, यह सब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की जांच पड़ताल में ही स्पष्ट हो सकेगा।

40 मिनट तक लिफ्ट में फंसी एनआरआइ की 12 वर्षीय बेटी

जागरण संवाददाता, इंदिरापुरम : शक्ति खंड-तीन स्थित चार मंजिला फ्लैट की लिफ्ट में शनिवार सुबह एनआरआइ की 12 वर्षीय बेटी फंस गई। करीब चालीस मिनट बाद रखरखाव देख रहे कर्मचारियों ने लिफ्ट खोलकर बच्ची को बाहर निकाला। पीड़ित परिवार ने पुलिस में कोई लिखित शिकायत नहीं दी है। मूलरूप से सूरत के रहने वाले असीम कुमार कतर में नौकरी करते हैं। उन्होंने छह दिन पहले शक्ति खंड-तीन बिल्डर फ्लैट खरीदा है।

शनिवार सुबह उनकी 12 वर्षीय बेटी आशी गुप्ता किसी काम से नीचे गई। काफी देर तक वह नहीं लौटी, तो असीम ने उसे ढूंढ़ना शुरू किया। उन्होंने देखा कि बिल्डिंग की लिफ्ट काम नहीं कर रही है। उन्हें बेटी के लिफ्ट में फंसने की आशंका हुई तो उसे आवाज लगानी शुरू की। लोगों ने पुलिस, बिल्डर और रखरखाव कर्मियों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे रखरखाव कर्मियों ने प्रथम तल पर लिफ्ट खोलकर आशी को बाहर निकाला। आशी काफी डरी हुई है। असीम ने बताया कि वह परिवार सहित यहां छुट्टियां मनाने आए हैं। उन्होंने काफी महंगा फ्लैट खरीदा है। वह एक माह तक यहां पर रहेंगे। इसके बाद वह कतर वापस चले जाएंगे।

सुविधा

सफदरजंग अस्पताल में बुजुर्गों के इलाज के लिए जेरियाट्रिक ओपीडी सहित चार सुविधाओं का डॉ. हर्षवर्धन ने किया शुभारंभ

इमरजेंसी से इलाज बिना न लौटे कोई मरीज : डॉ. हर्षवर्धन

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने शनिवार को सफदरजंग अस्पताल में बुजुर्गों के इलाज के लिए जेरियाट्रिक ओपीडी सहित चार सुविधाओं का शुभारंभ किया। इनमें अत्याधुनिक कैथ लैब, लिथोट्रिप्सी मशीन व तीन टेस्ला की नई एमआरआइ मशीन शामिल हैं। इस दौरान डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि इस अस्पताल में मरीजों को अत्याधुनिक व गुणवत्तापूर्ण इलाज मिल सकेगा। साथ ही उन्होंने अस्पताल के डॉक्टरों और कर्मचारियों से कहा कि इमरजेंसी से कोई मरीज इलाज के बगैर नहीं लौटना चाहिए। सुनिश्चित करें कि मरीज को दूसरे अस्पताल में भी स्थानांतरित न करना पड़े।

दरअसल, सफदरजंग अस्पताल में देश का सबसे बड़ा इमरजेंसी सेंटर बना है। इसमें 500 बेड की सुविधा है। इसके अलावा 807 बेड का सुपर स्पेशयलिटी ब्लॉक शुरू हुआ है। डॉ. हर्षवर्धन ने इन दोनों सेंटरों के वार्ड, जेरियाट्रिक वार्ड, ओटी व आइसीयू में जाकर सुविधाओं का निरीक्षण किया।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने सफदरजंग अस्पताल में मरीजों से बातचीत की। प्रेट्र

इस दौरान उन्होंने मरीजों से बातचीत भी की। इसके बाद डॉक्टरों व कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सुनिश्चित करें कि इमरजेंसी में इलाज के लिए पहुंचे हर मरीज को जरूरी इलाज मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अस्पतालों में अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। सफदरजंग अस्पताल सुविधाओं के मामले में देश के श्रेष्ठ अस्पतालों में शामिल होगा। उन्होंने अस्पताल में पौधारोपण भी किया।

सफदरजंग अस्पताल में रविवार को पहली बार जेरियाट्रिक क्लीनिक चलेगा। इसमें प्रत्येक रविवार को सुबह साढ़े नौ से दोपहर 12:30 बजे तक ओपीडी होगी। इस दौरान मेडिसिन, ईएनटी, जनरल सर्जरी, नेत्र व ऑर्थोपेडिक्स विभाग के डॉक्टर ओपीडी में मौजूद रहेंगे। इस ओपीडी में पहुंचकर बुजुर्ग अपना इलाज करा सकेंगे। जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी ब्लॉक में उनकी जांच की व्यवस्था होगी। इसके अलावा अस्पताल से उन्हें दवाएं भी मिलेगी।

अस्पताल में तीन कैथ लैब मौजूद : अस्पताल में अत्याधुनिक बाईप्लेन कैथ लैब की शुरुआत होने के साथ ही तीन कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध हो गई है। इससे अस्पताल में अधिक से अधिक मरीजों के हृदय की बीमारियों का इलाज हो सकेगा।

सर्जरी के बिना निकाला जा सकेगा किडनी से स्टोन : अस्पताल में लिथोट्रिप्सी मशीन लगने से किडनी में स्टोन की बीमारी से पीड़ित मरीजों को फायदा होगा। सर्जरी के बगैर लेजर के इस्तेमाल से स्टोन को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़कर निकाला जा सकेगा।

हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर कांवड़िए की मौत, पांच झुलसे

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

गंगाजल लेने के लिए हरिद्वार जा रहे कांवड़ियों का ट्रक शुक्रवार देर रात जैतपुर इलाके में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया। करंट से झुलसने के कारण एक कांवड़िए की मौत हो गई, जबकि पांच झुलस गए हैं। पांचों का एम्स ट्रामा सेंटर में उपचार चल रहा है। मृतक की पहचान जैतपुर निवासी बिज्जू (35) के रूप में हुई है। लालू, राजन व सुशील चौधरी गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जबकि दो मामूली रूप से झुलसे हैं।

पुलिस अफसरों ने बताया कि जैतपुर इलाके के रहने वाले करीब 40 कांवड़ियों का ग्रुप हरिद्वार से गंगाजल लेने जा रहा था। देर रात सभी कांवड़िए ट्रक में सवार होकर जैतपुर से निकले। इसी दौरान जैतपुर में उनका ट्रक रास्ते में ऊपर से गुजर रही 11 हजार वोल्ट की लाइन की चपेट में आ गया। इससे ट्रक में करंट फैलने के साथ ही तेज धमाका हुआ। ट्रक सवार छह कांवड़िए करंट लगने के कारण झुलस गए। मौके पर चीख-पुकार मच गई। इसके चलते आसपड़ोस के लोग काफी संख्या में मौके पर एकत्र हो गए। हादसे की सूचना पाकर पहुंची पुलिस झुलसे कांवड़ियों को ट्रामा सेंटर ले गई। वहां उपचार के दौरान बिज्जू की मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। पुलिस अफसरों के मुताबिक जांच में पता चला है कि बिज्जू घर में अकेला कमाने वाला था।

परिजनों ने बताया कि जिस जगह हादसा हुआ, वह स्थान उनके घर से थोड़ी दूरी पर ही है। आरोप है कि क्षेत्र में हाईटेंशन लाइन के तार लटककर काफी नीचे आ चुके हैं। हादसे की आशंका जताते हुए पूर्व में इस संबंध में बिजली विभाग के अफसरों को शिकायत की, लेकिन इन्हें दुरुस्त नहीं किया गया। बिजली विभाग के अफसरों की लापरवाही को मौत के लिए जिम्मेदार बताते हुए क्षेत्रवासियों ने पीड़ित परिवार को मुआवजा दिए जाने की मांग की है।

290 परियोजनाओं का उत्तर प्रदेश में आज भूमिपूजन करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत करीब 65 हजार करोड़ रुपये है।

वायुसेना को मिली चार अपाचे की पहली खेप

हिंडन एयरबेस पर युद्धक हेलीकॉप्टर वायुसेना में किए गए शामिल

- अमेरिकी कंपनी बोइंग अगले हफ्ते सौंपेगी चार और युद्धक हेलीकॉप्टर
- सितंबर में आठों अपाचे पठानकोट एयरबेस पर वायुसेना में शामिल होंगे

भारत को मिलने हैं कुल 22 हेलीकॉप्टर। फाइल

नई दिल्ली, प्रेट्र : अमेरिकी विमान कंपनी बोइंग ने भारतीय वायुसेना को चार अपाचे युद्धक हेलीकॉप्टरों की पहली खेप सौंप दी है। भारत को मिलने वाले कुल 22 हेलीकॉप्टरों में से चार और हेलीकॉप्टर की दूसरी खेप अगले हफ्ते मिलेगी। इसके भारतीय वायुसेना में शामिल होने से भारत की दुश्मन के घर में घुसकर मारने की क्षमता और बढ़ी है।

एएच-64ई अपाचे हेलीकॉप्टर की पहली खेप की आपूर्ति शनिवार को गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर हुई है। अरबों डॉलर का यह सौदा होने के चार साल बाद भारतीय वायुसेना को पहली खेप मिली है। बोइंग के मुताबिक अपाचे की पहली खेप भारत पहुंच चुकी है। अगले हफ्ते भारतीय वायुसेना को दूसरी खेप मिलेगी। उसके बाद सितंबर में इन आठों हेलीकॉप्टरों को औपचारिक रूप से पठानकोट वायुसेना स्टेशन पर वायुसेना में शामिल किया जाएगा।

बोइंग के अनुसार वर्ष 2020 तक यानी अगले साल तक भारतीय वायुसेना के पास 22 अपाचे हेलीकॉप्टरों की पूरी फ्लीट होगी। इन हेलीकॉप्टरों को तय समय से पहले भारत को सौंपा जा रहा है।

दुनिया भर में बेचे गए हैं 2200 अपाचे : एएच-64 अपाचे दुनिया का सबसे एडवांस बहुउद्देश्यीय युद्धक हेलीकॉप्टर और इसका इस्तेमाल अमेरिकी सेना करती है। बोइंग कंपनी ने अब तक 2200 अपाचे हेलीकॉप्टरों को दुनिया भर के देशों को बेचा है। अमेरिका के अलावा इजरायल, मिस्र और नीदरलैंड की सेनाएं भी इसका इस्तेमाल करती हैं। अपाचे को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि दुश्मन की किलेबंदी को भेदकर और उसकी सीमा में घुसकर हमला करने में सक्षम है।

दो तरह की मिसाइलों से है लैस : अपाचे अटैक हेलिकॉप्टर में हेलिफायर और स्ट्रिंगर मिसाइलें लगी हैं और दोनों तरफ 30 एमएम की दो गनें हैं। इन मिसाइलों का पेलोड इतने तीव्र विस्फोटकों से भरा होता है कि दुश्मन का बच निकलना नामुमकिन होता है।

युद्ध के हर हालात में टिकने में सक्षम

इस हेलीकॉप्टर को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह युद्ध क्षेत्र की हर परिस्थिति में टिका रह सके। अपाचे का सबसे क्रांतिकारी फीचर है इसका हेल्मेट माउंटेड डिस्प्ले, इंटिग्रेटेड हेलमेट और डिस्प्ले साइटिंग सिस्टम है। इसकी मदद से पायलट हेलिकॉप्टर में लगी ऑटोमैटिक एम230 चेन गन को अपने दुश्मन पर टारगेट कर सकता है। किसी भी तरह का मौसम हो, किसी भी तरह की परिस्थिति हो, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर दुश्मनों को नहीं बख्शता।

इनमें दो जनरल इलेक्ट्रिक टी700 टर्बोशैफ्ट इंजन हैं और आगे की तरफ एक सेंसर फिट है। इस वजह से यह रात के अंधेरे में भी उड़ान भर सकता है। यह 365 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है। इसका वजन 5,165 किलोग्राम है और इसमें पायलटों के बैठने के लिए दो सीटें होती हैं।

अमेरिका ने भारत के सी-17 विमानों के लिए सैन्य बिक्री को दी मंजूरी

वाशिंगटन, प्रेट्र : ट्रंप प्रशासन ने भारत के सैन्य मालवाहक विमान सी-17 को सहयोग देने के लिए 4600 करोड़ रुपये की विदेशी सैन्य बिक्री को मंजूरी देने के फैसले से शुक्रवार को संसद को अवगत कराया। इस फैसले से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की रक्षा क्षमता में बढ़ोतरी होगी।

हाल ही में भारत ने सी-17 के लिए पुर्जे, इसकी मरम्मत संबंधी सहयोगी उपकरण, कार्मिक प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षण उपकरण आदि खरीदने का अनुरोध किया था, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। पेंटागन की रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी ने एक बयान में कहा, 'भारत को क्षेत्र में इसकी संचालनात्मक तत्परता बनाए रखने और मानवीय सहायता एवं आपदा राहत सहायता मुहैया कराने की क्षमता के लिए इन उपकरणों की जरूरत है।'

उसने कहा कि भारत को उन उपकरणों को अपने सशस्त्र बलों में शामिल करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। बयान में कहा गया है कि इस प्रस्तावित बिक्री से अमेरिका-भारत सामरिक संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। यह प्रमुख रक्षा साझेदार की गतिशीलता संबंधी क्षमताओं को मदद देकर अमेरिका की विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा को सहयोग देगी।

एफ-16 विमानों की निगरानी के लिए पाक को 12.5 करोड़ डॉलर के सौदे को मिली मंजूरी

वॉशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के लिए थोड़ी राहत की खबर है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की बैठक के कुछ दिनों बाद एक रक्षा सौदे को मंजूरी दी गई है। अमेरिका ने एफ-16 विमानों की चौबीसों घंटों की निगरानी की तकनीकी सहायता के लिए पाकिस्तान को 12 करोड़ 50 लाख डॉलर (लगभग 870 करोड़ रुपये) की सैन्य बिक्री को मंजूरी दी है।

अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि यह पाकिस्तान को सैन्य सहायता नहीं है। पाकिस्तान को अमेरिकी सैन्य सहायता जनवरी 2018 से बंद है। अधिकारियों ने कहा कि ट्रंप प्रशासन अपनी नीति में कोई बदलाव भी नहीं करने जा रहा है। पाकिस्तान को सैन्य सहायता में रोक जारी रहेगी। यह सौदा पाकिस्तान में मौजूद एफ-16 विमानों की निगरानी, उनके रखरखाव व तकनीकी सहायता से जुड़ा हुआ है।

अधिकारियों ने कहा कि पेंटागन ने पाकिस्तान को 12 करोड़ 50 लाख डॉलर की सैन्य बिक्री को मंजूरी देने के अपने फैसले से कांग्रेस को अवगत करा दिया है। एक राजनयिक सूत्र ने कहा, 'पेंटागन का यह सौदा पाकिस्तान के लिए फिर से सैन्य सहायता आरंभ किया जाना नहीं है। विमान के लिए 12 करोड़ 50 लाख डॉलर एक मामूली राशि है और यह लड़ाकू विमानों पर चौबीसों घंटे नजर रखने के लिए है। यह विदेशी सैन्य बिक्री (एफएमएस) के तहत है जिसका अर्थ यह हुआ कि पाकिस्तान को इसके लिए भुगतान करना होगा। इस धन का उपयोग पाकिस्तान में एफ-16 विमानों के प्रयोग पर नजर रखने के लिए 60 अमेरिकी ठेकेदारों के वेतन के भुगतान के लिए किया जाएगा।

रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी ने एक बयान में कहा, पाकिस्तान ने 'पाकिस्तान शांति मुहिम' उन्नत एफ- 16 कार्यक्रम के सहयोग में अभियानों पर नजर रखने में मदद के लिए अमेरिकी सरकार से तकनीकी सहयोग सेवा जारी रखने का अनुरोध किया था। पेंटागन ने कहा कि इस सहयोग के तहत प्रस्तावित बिक्री से क्षेत्र में मूलभूत सैन्य संतुलन नहीं बिगड़ेगा। बता दें कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एफ-16 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया था।

कर्नाटक विस स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर विचार

एक्शन में भाजपा ▶ विश्वास प्रस्ताव से पहले येदियुरप्पा ने बुलाई विधायक दल की बैठक

चौथी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले बीएस येदियुरप्पा शनिवार को मंड्या स्थित प्रसिद्ध सिद्धलिंगेश्वर मंदिर पहुंचे और पूजा-अर्चना कर भगवान का शुक्रिया किया। एएनआइ

बेंगलुरु, एएनआइ : कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर केआर रमेश कुमार ने स्वेच्छा से इस्तीफा नहीं दिया तो भाजपा उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। राज्य में सत्ता संभालने के बाद पार्टी इस पर विचार कर रही है। वहीं, सोमवार को विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश करने से पहले मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने रविवार को भाजपा विधायक दल की बैठक बुलाई है। पार्टी सूत्रों ने शनिवार को बताया कि स्पीकर रमेश कुमार को स्वेच्छा से पद छोड़ देने का संदेश पहुंचा दिया गया है। सूत्रों ने कहा, 'हमारा पहला एजेंडा सोमवार को विश्वास प्रस्ताव जीतना है और वित्त विधेयक को पारित कराना है। हम इंतजार करेंगे और देखेंगे कि स्पीकर अपने आप पद छोड़ते हैं या नहीं। अगर उन्होंने अपने आप इस्तीफा नहीं दिया तो हम उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे।' उन्होंने सवाल किया कि क्या विधानसभा स्पीकर विपक्षी पार्टी से हो सकता है? मालूम हो कि स्पीकर ने गुरुवार रात कहा था कि वह दो दिनों के भीतर शेष बागी विधायकों के इस्तीफों या अयोग्यता पर फैसला ले लेंगे।

अयोग्यता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे तीनों विधायक : विधानसभा स्पीकर रमेश कुमार द्वारा गुरुवार रात अयोग्य ठहराए गए तीनों बागी विधायकों रमेश एल. जर्किहोली (कांग्रेस), महेश कुमाथल्ली (कांग्रेस) और आर. शंकर (निर्दलीय) ने स्पीकर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है।

कर्नाटक विस के आसपास कल से धारा-144 : मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने 29 जुलाई को विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश करने की घोषणा की है। लिहाजा पुलिस आयुक्त आलोक कुमार ने विधानसभा की दो किलोमीटर की परिधि में 29 जुलाई की सुबह छह बजे से 30 जुलाई मध्यरात्रि तक धारा-144 लागू करने के आदेश जारी किया है।

भाजपा को जदएस के समर्थन की संभावना को देवेगौड़ा ने नकारा : पूर्व प्रधानमंत्री और जदएस सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा ने शनिवार को भाजपा को समर्थन दिए जाने की संभावना से साफ इन्कार किया और कहा कि उनकी पार्टी 'रचनात्मक' विपक्ष की भूमिका निभाएगी। दरअसल, शुक्रवार को जदएस विधायक दल की बैठक के बाद पार्टी नेता जीटी देवेगौड़ा ने कहा था, 'हम सभी ने पार्टी के साथ एकजुट रहने का फैसला किया है। कुछ जदएस विधायकों ने एचडी कुमारस्वामी को भाजपा सरकार का बाहर से समर्थन करने का सुझाव दिया जबकि कुछ विधायकों ने विपक्ष में बैठने और पार्टी को मजबूत बनाने का सुझाव दिया।' इस बयान पर देवेगौड़ा ने कहा, 'ऐसा कहने में कौन सी बड़ी बात है।

'भाजपा ने किया राज्यपाल कार्यालय का दुरुपयोग'

वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने शनिवार को दावा किया कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने असंवैधानिक तरीके से शपथ ग्रहण की है और भाजपा ने राज्यपाल के कार्यालय का दुरुपयोग किया है। पत्रकारों से बातचीत में सिद्दरमैया ने कहा कि भाजपा के पास विधानसभा में बहुमत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उन्होंने सवाल किया, '221 सदस्यीय विधानसभा में साधारण बहुमत क्या है? यह आंकड़ा 111 है। क्या उनके पास 111 विधायकों का समर्थन है? उन्हें 111 सदस्यों की सूची देनी होगी, क्या उन्होंने सूची सौंपी? भाजपा की जीत लोगों की जीत नहीं है। यह हॉर्स ट्रेडिंग की जीत है।'

सत्ता गई तो अब जदएस से चुनावी गठबंधन भी नहीं करेगी कांग्रेस

संजय मिश्र, नई दिल्ली

- कर्नाटक के अगले उपचुनावों में अलग-अलग लड़ेंगे दोनों दल

कर्नाटक में सत्ता की बाजी पलटने के बाद कांग्रेस और जनता दल सेक्यूलर (जदएस) की राजनीतिक राहें अब अलग-अलग होंगी। कांग्रेस ने इस बात का सैद्धांतिक फैसला कर लिया है कि इस्तीफा देने वाले या अयोग्य ठहराए गए विधायकों की सीटों पर होने वाले उपचुनावों में वह जदएस के साथ चुनावी गठबंधन नहीं करेगी।

कांग्रेस ने यह फैसला सूबे में येदियुरप्पा की अगुआई में भाजपा की नई सरकार बनने के बाद किया है। कांग्रेस ने हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा अभी नहीं की है, लेकिन कर्नाटक में कुमारस्वामी सरकार बचाने में लगे रहे पार्टी के एक वरिष्ठ रणनीतिकार ने कहा कि सत्ता भाजपा के हाथ में जाने के बाद जदएस से गठबंधन का मतलब नहीं रह गया है। अब यह तय हो गया है कि येदियुरप्पा सरकार बाकी बचे करीब चार साल चलेगी या कुछ समय बाद नए सिरे से चुनाव की नौबत आएगी। ऐसे में जदएस के साथ सियासी साझेदारी केवल विधानसभा में येदियुरप्पा सरकार की घेरेबंदी तक ही सीमित रहेगी। कांग्रेस रणनीतिकार ने कहा कि जदएस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का कोई भी कदम पार्टी के लिए घातक होगा। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस-जदएस के मिलकर चुनाव लड़ने से दोनों पार्टियों को हुए नुकसान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि गठबंधन हुआ तो इसका फायदा फिर भाजपा को मिलेगा। उनके अनुसार भाजपा और जदएस के मुकाबले पूरे कर्नाटक में कांग्रेस का जमीनी आधार ज्यादा मजबूत है।

मगर गठबंधन की वजह से लोकसभा चुनाव में आमने-सामने की गोलबंदी में भाजपा को जबर्दस्त फायदा मिल गया। कांग्रेस के तर्कों को सही ठहराते हुए उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के एक हफ्ते बाद स्थानीय निकाय चुनाव के परिणाम इसका प्रमाण हैं। 23 मई को लोकसभा चुनाव के नतीजे आए जबकि 29 मई को कर्नाटक के स्थानीय निकाय चुनावों में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली। जदएस ने भी इन चुनावों में अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन किया। स्थानीय निकाय चुनावों में कांग्रेस-जदएस में गठबंधन नहीं हुआ था। कांग्रेस का मानना है कि कर्नाटक में त्रिकोणीय मुकाबले से भाजपा का सियासी ग्राफ नीचे आएगा।

लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह होंगे सेना के नए डीजीएमओ

नई दिल्ली, प्रेट्र : आतंकवाद रोधी अभियानों का वृहद अनुभव रखने वाले लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह भारतीय सेना के अगले सैन्य अभियान महानिदेशक (डीजीएमओ) होंगे। वह लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान की जगह लेंगे। वह अभी नगरोटा स्थित सेना की 16वीं कोर के जनरल आफिसर कमांडिंग के रूप में तैनात हैं।

आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को बताया कि लेफ्टिनेंट जनरल सिंह 15 अक्टूबर को नए डीजीएमओ के रूप में पदभार संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल चौहान को पूर्वी कमान का नया जनरल आफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया गया है। डीजीएमओ के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल सिंह जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा सहित भारतीय सेना के विभिन्न अभियानों की निगरानी करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह 2016 में हुई सर्जिकल स्ट्राइक की योजना बनाने वाले समूह में शामिल थे। वेलिंगटन (तमिलनाडु) स्थित डिफेंस सर्विस स्टाफ और महू स्थित आमी वॉर कॉलेज के छात्र रहे परमजीत सिंह का कश्मीर घाटी में सेना की तैनाती में भी अहम योगदान रहा है। सियाचिन ग्लेशियर जैसे ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्रों में भी सिंह का लंबा अनुभव है। उन्होंने अपने करियर का अधिकांश समय जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद रोधी अभियानों का संचालन करने में बिताया है। लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह 1982 में भारतीय सेना में शामिल हुए थे और जनवरी 1984 में उनका पैराशूट रेजिमेंट में ट्रांसफर कर दिया गया था।

ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की सियासत से बिगड़ रहा सामाजिक सौहार्द : त्रिपाठी

जागरण संवाददाता, कोलकाता

बंगाल के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी का उनके पांच साल के कार्यकाल में ममता सरकार के साथ कई मुद्दों पर टकराव दिखा है। कार्यकाल खत्म होने से तीन दिन पहले शनिवार को राज्यपाल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सबसे तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की राजनीति से राज्य की सामाजिक समरसता खतरे में पड़ गई है। हालांकि, मुख्यमंत्री को सशक्त व दूरदर्शी महिला करार देते हुए उन्होंने कहा कि ममता में दूरदृष्टि है और वह अपने फैसलों को कड़ाई से लागू करने की क्षमता रखती हैं। लेकिन, उन्हें राज्य के सभी नागरिकों को बिना भेदभाव के एक निगाह से देखना चाहिए। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री को अपनी भावनाओं पर काबू रखने की सलाह दी।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के पास दूरदृष्टि है। उनके पास अपने फैसले कड़ाई से लागू कराने की क्षमता है, लेकिन कई मौकों पर वह भावुक हो जाती हैं। उन्हें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। मौके पर जब मौजूदा राज्यपाल से पूछा गया कि क्या राज्य में उन्होंने कहीं भेदभाव

> उनकी (ममता बनर्जी) तुष्टीकरण की राजनीति का राज्य के सामाजिक सौहार्द पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। मेरा मानना है कि उन्हें राज्य के हरेक नागरिक को समान भाव से देखना चाहिए।
>
> – केसरीनाथ त्रिपाठी, राज्यपाल, बंगाल

देखा तो 85 वर्षीय राज्यपाल ने बेबाक अंदाज में कहा, भेदभावपूर्ण रवैया स्पष्ट परिलक्षित है। उनके बयानों में भेदभावपूर्व रवैया साफ-साफ दिखता है। गौरतलब है कि 30 जुलाई को केसरी नाथ त्रिपाठी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। उस दिन राज्य के नए राज्यपाल जगदीप धनखड़ शपथ लेंगे और कार्यभार ग्रहण करेंगे।

राज्य में जारी हिंसा पर जताई चिंता : राज्यपाल केसरी नाथ त्रिपाठी ने राज्य में लोकसभा चुनाव के बाद जारी हिंसा पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा-मुझे लगता है कि राज्य में कानून-व्यवस्था में भारी सुधार की आवश्यकता है। मुझे नहीं पता राज्य में लोग हिंसक क्यों हो रहे हैं? इसके राजनीतिक या सांप्रदायिक कारण हो सकते हैं। संभव है कि बांग्लादेशियों व रोहिंग्याओं की घुसपैठ या फिर और भी कई कारण हों।

राष्ट्रपति शासन पर नहीं दिया सीधा जवाब : राज्य में राष्ट्रपति शासन के मुद्दे पर राज्यपाल ने सीधा जवाब नहीं दिया। जब उनसे पूछा गया कि क्या राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब है कि यहां राष्ट्रपति शासन लगाया जा सके? राज्यपाल ने कहा कि विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले सामने हैं। उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था राज्य सरकार का जिम्मा है। सिर्फ कानून-व्यवस्था की खराबी मात्र से राज्य में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता। अगर राज्य सरकार संविधान सम्मत व्यवहार नहीं करती, तब राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है।

लोकसभा चुनाव में पुलिस की भूमिका पर भी उठाया सवाल : राज्य में लोकसभा चुनाव की निष्पक्षता के बारे में पूछे जाने पर राज्यपाल ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की जमकर सराहना की। हालांकि निचले स्तर के अधिकारियों की भूमिका पर उन्होंने सवालिया निशान लगाए। उन्होंने कहा कि निचले स्तर के अधिकारी राजनीतिक पार्टियों के लिए काम करते पाए गए, जिसकी वजह से चुनाव के दौरान आम लोगों का भरोसा हिल गया था।

मानवाधिकार व मौलिक आजादी के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण साधन

जागरण संवाददाता, कोलकाता : कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि मानवाधिकार व मौलिक आजादी बरकरार रखने के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण साधन है। कोलकाता के सेंट जेवियर्स विश्वविद्यालय के पहले दीक्षा समारोह में बोलते हुए उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक संवाद और प्रभावी नेतृत्व के माध्यम से विवादों को हल करने के लिए शिक्षा की जरूरत है।

सांसद बनने से पहले संयुक्त राष्ट्र से जुड़े रहने वाले थरूर ने कहा कि समाज को नफरत फैलाने वाले और विभाजनकारी एजेंडे को चुनौती देने के लिए शिक्षा का सहारा लेना चाहिए। भारतीय शिक्षा प्रणाली के बारे में उन्होंने कहा कि हम योग्यता और नौकरियों के बीच बेमेल कौशल की प्रणालीगत समस्या से पीड़ित हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि स्नातक स्तर की पढ़ाई करने के बाद पकौड़े बेचने का कुछ नेता सुझाव देते हैं।

वर्तमान सरकार हमारे सर्वश्रेष्ठ छात्रों के लिए छात्रवृत्ति पर सब्सिडी देने में निवेश नहीं करेगी बल्कि भव्य मूर्तियों पर अपना पैसा बर्बाद करना पसंद करती हैं। थरूर का इशारा गुजरात में एकता की मिसाल कहे जाने वाले सरदार वल्लभभाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा की ओर था।

मोईन कुरैशी मनी लांड्रिंग मामले में हैदराबाद का सतीश बाबू गिरफ्तार

नई दिल्ली, प्रेट्र : ईडी ने विवादित मांस निर्यातक मोईन कुरैशी और अन्य लोगों के खिलाफ मनी लांड्रिंग मामले की जांच के संबंध में हैदराबाद के कारोबारी सना सतीश बाबू को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने उसे पांच दिन की रिमांड पर ईडी के हवाले कर दिया है। हालांकि, जांच एजेंसी ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी। बता दें कि पिछले साल बाबू के आरोपों के बाद ही सीबीआइ के शीर्ष अफसरों के बीच विवाद शुरू हुआ था।

कारोबारी को पहले इस मनी लांड्रिंग मामले में गवाह के तौर पर बुलाया गया था, लेकिन ताजा घटनाक्रम के मुताबिक उसे अब आरोपित माना गया है। अधिकारियों ने बताया कि बाबू को मनी लांड्रिंग मामले के प्रावधानों के तहत शुक्रवार देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि बाबू से कुछ घंटे तक पूछताछ की गई, लेकिन जांच में सहयोग नहीं करने पर उसे हिरासत में ले लिया गया। जांच एजेंसी कुछ वित्तीय लेनदेन समेत कुरैशी के साथ उसके संपर्क को संदिग्ध मान रही है और इसीलिए वह उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती है। सूत्रों का आरोप है कि वह रिश्वत के एक मामले में शामिल है और उसने कुरैशी को को

- गवाह के तौर पर बुलाया गया था, जांच में सहयोग नहीं करने पर किया गिरफ्तार
- विशेष अदालत ने पांच दिन की रिमांड पर ईडी के हवाले किया

हैदराबाद का कारोबारी सना सतीश बाबू की फाइल फोटो।

अवैध रूप से धन दिया है। ऐसी संभावना है कि बाबू की हिरासत का अनुरोध करने के लिए उसे जल्द ही विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। दरअसल, ईडी ने सरकारी अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके कथित भ्रष्टाचार के मामले में मनी लांड्रिंग अधिनियम के तहत कुरैशी के खिलाफ 2017 में आपराधिक मामला दर्ज किया था।

बाबू के आरोपों के बाद शुरू हुई थी सीबीआइ में उठापटक

पिछले साल सीबीआइ को दिए बयान में बाबू ने कहा था कि उसने कुरैशी से जुड़ी जांच में किसी तरह की कार्रवाई ना करने के लिए विशेष निदेशक राकेश अस्थाना को दो करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी। मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराए गए इस बयान के बाद जांच एजेंसी ने अस्थाना और कुछ अन्य अधिकारियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की थी। बाबू का आरोप था कि उसने यह धनराशि दिसंबर 2017 से लेकर 10 महीने की अवधि में दी। बाबू ने जिस दौरान अस्थाना पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया था, उस समय अस्थाना के नेतृत्व में सीबीआई का विशेष जांच दल उससे पूछताछ कर रहा था। बाद में अस्थाना ने तत्कालीन सीबीआइ निदेशक आलोक वर्मा पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया था और बाबू को बचाने और एसआइटी को कार्रवाई ना करने देने के आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

कह के रहेंगे — माधव जोशी

सियासत

पहली बार दोनों दल मिलकर सड़क पर उतरे, निकाला संयुक्त जुलूस, दोनों ही दलों के नेता गठबंधन कर संयुक्त आंदोलन करने के पक्ष में

बंगाल में माकपा और कांग्रेस आए एक साथ

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

बंगाल में माकपा और कांग्रेस एक-दूसरे का सहारा बने हैं। दरअसल, राज्य में 34 वर्षों तक शासन करने वाली माकपा इन दिनों अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, वहीं कांग्रेस भी हाशिए पर है। इसका प्रमाण हालिया संपन्न लोकसभा चुनाव के परिणाम हैं। भाजपा तेजी से माकपा व कांग्रेस को पीछे छोड़कर तृणमूल के सामने खड़ी हो गई है। यही वजह है कि दोनों एक-दूसरे के करीब आए हैं।

इस वक्त बंगाल में मुख्य सियासी मुकाबला सिर्फ दो दलों तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच केंद्रित हो गया है। ऐसे में माकपा और कांग्रेस एक दूसरे की मदद से खुद को दोबारा सशक्त करने की तैयारी में है। इसका संकेत कुछ दिन पहले ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सोमेन मित्रा ने यह कहकर दिया था कि अभी से भाजपा व तृणमूल विरोधी दलों के बीच गठबंधन की जरूरत है। वहीं माकपा में भी यह स्वर उठे हैं। इसका नतीजा यह रहा कि शुक्रवार को हिंसाग्रस्त भाटपाड़ा में संयुक्त रूप से माकपा व कांग्रेस नेताओं ने जुलूस निकाला और शांति के लिए प्रशासन से तत्काल प्रभावी कदम उठाने की मांग की। अब तक बंगाल विधानसभा में माकपा व कांग्रेस संयुक्त रूप

प्रतीकात्मक

से तृणमूल का विरोध तो करते थे, लेकिन सड़क पर साथ नहीं दिखते थे, लेकिन बदली परिस्थिति में अब दोनों ही दलों के नेता मान रहे हैं कि यदि अब भी साथ नहीं आए तो 2021 में विधानसभा चुनाव काफी मुश्किल होने वाला है। 2011 में तृणमूल से हारने के बाद माकपा अब राज्य की राजनीति में बेहद कमजोर दल बनकर रह गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की राज्य में पकड़ अब भी मजबूत है। भाजपा ने राज्य में अपने पैर जमाकर कांग्रेस व माकपा को हाशिए पर ला दिया है।

इसलिए मिलाया हाथ : लोकसभा चुनाव में माकपा के नेतृत्व वाले वाममोर्चा को प्रदेश की 42 सीटों में से एक भी सीट नहीं मिली और उसका वोट सिर्फ सात प्रतिशत रह गया।

इस स्थिति में कामरेड दो साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी संभावनाएं बढ़ाने के लिए कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर लड़ाई आग बढ़ाने को लगभग सहमत हो गए हैं। माकपा के राज्य सचिव सूर्यकांत मिश्रा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सोमेन मित्रा दोनों ही भाटपाड़ा में निकलने वाले जुलूस में शामिल रहे थे। पहले से कट्टर प्रतिद्वंद्वी रहे दोनों दलों को उम्मीद है कि संयुक्त प्रयास से वे विधानसभा चुनावों से पहले चुनावी गणित को बेहतर बना सकते हैं। सूर्यकांत ने राज्य में भाजपा और तृणमूल विरोधी ताकतों का समग्र मंच बनाने का आह्वान किया है।

2016 में किसको कितनी सीटें

माकपा की अगुआई में वाममोर्चा ने 2016 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा था। उस चुनाव में तृणमूल 44.91 फीसद वोट शेयर के साथ 211 सीटें जीत गई थी, वहीं कांग्रेस व वामदलों की झोली में महज 76 सीटें ही आई थीं। पूरे वाममोर्चा को 32 और कांग्रेस को 44 सीटें मिली थीं।

REUNION IAS
IAS V.K.TRIPATHI PCS
राजनीति विज्ञान (Optional)
29 JULY 2019
3 PM TO 6 PM
9999421659-58

IAS GS World PCS
सामान्य अध्ययन
आज
Time :- 11:45 A.M.
011-27658013, 7042772062/63

1.09 करोड़ पेड़ों को काटने की अनुमति दी गई 2014 से अब तक पूरे देश में विकास कार्यों के लिए। सबसे ज्यादा 26.91 लाख पेड़ वर्ष 2018 में काटे गए। यह जानकारी पर्यावरण राज्यमंत्री बाबुल सुप्रियो ने दी।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
रविवार 28 जुलाई 2019

कुलदीप और रेणुका के सामने आठ घंटे तक की बेटे भव्य से पूछताछ

शिकंजा कसा ▶ आयकर विभाग की टीम हिसार में कार्रवाई कर देर रात पहुंची थी दिल्ली

टीम ने तीनों के विस्तृत बयान नए सिरे से कलमबद्ध किए

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

हरियाणा के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और विधायक कुलदीप बिश्नोई के दिल्ली के रजोकरी स्थित फार्म पर आयकर विभाग की कार्रवाई शुक्रवार रात दो बजे तक चली। विभाग की टीम ने कुलदीप बिश्नोई और उनकी विधायक पत्नी रेणुका बिश्नोई के समक्ष उनके बेटे भव्य बिश्नोई से आठ घंटे तक पूछताछ की।

आयकर विभाग ने मंगलवार सुबह 7.30 बजे कुलदीप बिश्नोई के हिसार, आदमपुर, दिल्ली और गुरुग्राम स्थित निवास व संस्थानों पर एक साथ कार्रवाई की। इस दौरान कुलदीप के बेटे भव्य आदमपुर में थे, जबकि उनकी माता जसमा देवी हिसार निवास पर थीं। खुद कुलदीप और उनकी पत्नी रेणुका दिल्ली के रजोकरी फार्म हाउस पर थे। हिसार और आदमपुर में जांच पूरी करने के बाद टीम भव्य बिश्नोई को लेकर शुक्रवार सायं 5.30 बजे कुलदीप के दिल्ली स्थित फार्म हाउस पहुंची थी। करीब छह बजे से टीम ने कुलदीप, रेणुका और भव्य के बयानों की बाबत एक-दूसरे से पूछताछ की। तीनों के विस्तृत बयान नए सिरे से भी कलमबद्ध किए गए। सूत्र बताते हैं कि यह कार्रवाई रात करीब दो बजे तक चली और 2.30 बजे आयकर टीम फार्म हाउस से रवाना हो गई। विभाग की आठ गाड़ियां फार्म हाउस से बाहर निकलीं, जिनमें दो गाड़ियां दिल्ली पुलिस की थीं। आयकर विभाग की गाड़ियों में काफी दस्तावेज और दो बॉक्स भी रखे दिखे। आयकर विभाग ने भी अभी तक कुलदीप बिश्नोई के यहां सर्च की बाबत कोई अधिकृत बयान नहीं दिया है।

ट्विटर पर कुलदीप और भव्य ने भाजपा पर निशाना साधा : शनिवार दोपहर बाद कुलदीप बिश्नोई ने दो ट्वीट किए जबकि उनके पुत्र भव्य बिश्नोई ने सत्यमेव जयते को हैशटैक करते हुए ट्वीट किया।

कुलदीप बिश्नोई का पहला ट्वीट

'फूंक मार कर बुझाने की बहुत नाकाम कोशिश थी वो, अरे हम वो चिराग हैं जिसे आंधियों ने पाला है। पिछले चार दिनों से हमारे लिए चिंतित रहे मेरे प्यारे साथियों आपका दिल से आभार। आपका यह प्यार ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं भाजपा से नहीं डरता, बस आप मेरा साथ मत छोड़ना।'

दूसरे ट्वीट में ईमानदारी और सिद्धांतों की बात की

'जस प्रकार से भाजपा ने राजनीतिक द्वेष से मुझे और मेरे परिवार को चार दिन तक प्रताड़ित करने का प्रयास किया, यह उनकी छोटी सोच है। यहां तक कि मेरी बूढ़ी और बीमार मां को भी नहीं बख्शा। मैंने हमेशा ईमानदारी और सिद्धांतों का जीवन जिया है। ना मैं भाजपा से कभी डरा और ना डरूंगा।'

'वे हमें दीवार की ओर धकेल सकते हैं, वे हमें मैदान में मात दे सकते हैं, वे हमें राजनीतिक व आर्थिक नुकसान पहुंचा सकते हैं मगर वे हमारे ज्ञान, कौशल, क्षमता, कठिन परिश्रम और उद्यम क्षमता को नहीं छीन सकते। जो आपको मारना चाहते हैं, उनसे निकलकर आप और अधिक बलवान बन जाते हैं। मैं शुक्रगुजार हूं कि मुझे इस युवावस्था में ही यह सीखने को मिल रहा है।

-भव्य बिश्नोई

हुड्डा से औद्योगिक प्लाट आवंटन में हुई पूछताछ, बोले-नहीं तोड़े नियम

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अफसरों ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से चंडीगढ़ से सटे पंचकूला में औद्योगिक प्लाट आवंटन मामले में पूछताछ की है। हुड्डा पर आरोप है कि उन्होंने अपने करीबी दोस्तों, रिश्तेदारों और जान-पहचान के लोगों को 13 औद्योगिक प्लाटों का आवंटन किया, जो नियमों के अनुसार नहीं था।

अभी तक दावा किया जा रहा था कि हुड्डा से मानेसर जमीन अधिग्रहण मामले में पूछताछ हुई है, लेकिन दो दिन की पूछताछ के बाद ईडी के अफसरों ने साफ किया कि पूछताछ औद्योगिक प्लाट आवंटन मामले में हुई है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने भी कहा कि मानेसर जमीन अधिग्रहण मामले में पूछताछ की खबरें गलत हैं। हुड्डा ने पूछताछ में कहा कि प्लाटों का आवंटन पूरी तरह पारदर्शी तरीके से किया गया था। बाकायदा कमेटी का गठन हुआ, जिसने नियमों का अनुपालन किया।

पंचकूला के इंडस्ट्रीयल एरिया फेज एक व दो में इन औद्योगिक प्लाटों का आवंटन किया गया था। भाजपा सरकार ने इस आवंटन को नियमों के विपरीत मानते हुए राज्य विजिलेंस ब्यूरो से जांच कराई। विजिलेंस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि प्लाटों का आवंटन सही नहीं था। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के तत्कालीन मुख्य प्रशासक डीपीएस नागल ने उपयुक्त इंटरव्यू कमेटी का गठन नहीं किया और प्लाटों का आवंटन राजनीतिक इशारे पर किया गया। मुख्यमंत्री एचएसवीपी के चेयरमैन होते हैं। इस नाते तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास यह जिम्मेदारी थी। इस मामले में 19 दिसंबर 2015 को आठ अलग-अलग धाराओं में एफआइआर दर्ज की गई थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास जब विजिलेंस की जांच रिपोर्ट पहुंची तो उन्होंने केस सीबीआइ को सौंप दिया। सीबीआइ ने 19 मई 2016 को एचएसवीपी के तत्कालीन मुख्य प्रशासक डीपीएस नागल, रिटायर्ड चीफ फाइनेंस आफिसर एससी कंसल, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट बीबी तनेजा और सभी 13 प्लाट धारकों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की। प्रवर्तन निदेशालय ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज करने के बाद सभी संबंधित पक्षों के बयान दर्ज किए। विजिलेंस और सीबीआइ इस नतीजे पर पहुंची कि तत्कालीन सरकार ने चहेतों को लाभ देने के लिए आवेदन की तिथि समाप्त होने से एक दिन पहले नियमों में फेरबदल किया। बदले नियमों के बारे में सभी आवेदकों को पता नहीं चला। नए नियमों के बारे में केवल उन्हीं लोगों को पता चला, जिन्हें प्लाट आवंटित किए जाने थे।

भूपेंद्र सिंह हुड्डा। फाइल फोटो

प्रदेश सरकार मेरे खिलाफ राजनीतिक दुर्भावना से काम कर रही है। मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया। लोग जानते हैं। मुझसे इंडस्ट्रीयल प्लाट आवंटन मामले में जो सवाल किए गए, मैंने उनका जवाब दिया है। इन लोगों ने तो मेरे अस्वस्थ तक होने की अफवाह उड़ा दी थी।

- भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री, हरियाणा।

हुडा के पास आए थे 582 आवेदन, चयन हुआ 14 का : हुड्डा सरकार में वर्ष 2011 में पंचकूला में औद्योगिक प्लाट आवंटित करने के लिए आवेदन मांगे गए थे। यह प्लाट 496 वर्ग मीटर से लेकर 1280 वर्ग मीटर तक के हैं, जिसकी एवज में हुडा (अब एचएसवीपी) के पास 582 आवेदन आए थे।

मसूरी में आज बनेगा हिमालयी राज्यों के लिए संयुक्त मसौदा

राज्य ब्यूरो, देहरादून

आजादी के बाद देश के 11 हिमालयी राज्य अपनी साझा समस्याओं, सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरणीय महत्व और विशिष्ट भौगोलिक परिवेश की पृष्ठभूमि में विकास की दौड़ में पिछड़ेपन के ठप्पे से उबरने के लिए रविवार को पहाड़ों की रानी मसूरी में हिमालयन कॉन्क्लेव में एकजुट होंगे। मसूरी में इन राज्यों की ओर से पहली दफा संयुक्त मसौदा तैयार किया जा रहा है। इसे केंद्र सरकार के साथ ही 15वें वित्त आयोग और नीति आयोग के सुपुर्द किया जाएगा। नीति आयोग हिमालयी राज्यों के लिए अलग प्रकोष्ठ गठित कर चुका है। ऐसे में इस मसौदे को हिमालयी राज्यों के लिए पृथक नीति नियोजन की जरूरत की पैरवी की दिशा में भी अहम कदम माना जा रहा है।

कॉन्क्लेव की मेजबानी कर रहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शनिवार को मसूरी में आयोजन स्थल का मुआयना कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कॉन्क्लेव में हिस्सा लेने पहुंचे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मसूरी में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से शिष्टाचार भेंट भी की।

हिमालयी राज्यों के सामने कई चुनौतियां हैं। इनमें सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण में भागीदारी के मद्देनजर ग्रीन बोनस, पर्यटन एवं वेलनेस, आपदा प्रबंधन, पलायन आदि मुद्दों पर इस कॉन्क्लेव में चर्चा होगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कॉन्क्लेव में हिमालयी राज्यों से जुड़े विभिन्न मुद्दों और कॉमन एजेंडे पर व्यापक चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत की अधिकतर नदियों का स्रोत हिमालय है। इसलिए प्रधानमंत्री के जल संचय अभियान में हिमालयी राज्यों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। जल संरक्षण में राज्य किस तरह सहयोग कर सकते हैं, इस पर भी मंथन होगा।

कॉन्क्लेव में भाग ले रही हस्तियों में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, मुख्यमंत्रियों में हिमाचल के जयराम ठाकुर, मेघालय के केसी संगमा, नागालैंड के नेफ्यू रियो, अरुणाचल के उपमुख्यमंत्री चौना मेन, मिजोरम के मंत्री टीजे लालनंत्लुआंगाए, त्रिपुरा के मंत्री मनोज कांति देब, सिक्किम के मुख्यमंत्री के सलाहकार डॉ. महेंद्र पी लामा, जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल के सलाहकार केके शर्मा, नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार, केंद्रीय जल और स्वच्छता सचिव परमेश्वर अय्यर, एनडीएमएमए सदस्य कमल किशोर, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान के प्रोफेसर डॉ. मधु वर्मा शामिल हैं।

मप्र में दिग्गज भाजपा नेताओं की भूमिका से आलाकमान नाराज, गिर सकती है गाज

नईदुनिया, भोपाल

- संगठन व विधायक दल में जिम्मेदार नेताओं के कम किए जा सकते हैं अधिकार
- अब डैमेज कंट्रोल की चाबी भी आलाकमान अपने हाथों में रखेगा

मध्य प्रदेश में भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी और शरद कोल द्वारा कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग करने के मामले पर पार्टी आलाकमान प्रदेश के शीर्षस्थ नेताओं की भूमिका से बेहद नाराज है। लोकसभा चुनाव में सभी 28 सीटें जीतने के बाद से इन नेताओं ने न तो संगठन पर ध्यान दिया और न ही विधायकों की नाराजगी टटोली। यह भी ध्यान नहीं दिया कि क्या चल रहा है। यही वजह है कि दो विधायकों को तोड़ने में कांग्रेस कामयाब हो गई। इस घटनाक्रम के बाद माना जा रहा है कि प्रदेश के दिग्गजों की भूमिका बदलने पर भी पार्टी विचार कर सकती है। पार्टी आलाकमान डैमेज कंट्रोल की चाबी भी अपने हाथों में रखना चाहता है, ताकि विधायकों में भरोसा बना रहे। इस रणनीति के चलते ही एक अगस्त को होने वाली बैठक में पार्टी के शीर्ष नेता भोपाल आ सकते हैं।

सूत्रों के मुताबिक, मप्र भाजपा में काफी समय से सबकुछ सही नहीं चल रहा है। पहले भाजपा को विधानसभा चुनाव में पराजय मिली और अब विधानसभा में दो विधायक कांग्रेस के साथ चले जाने से बड़े नेताओं के बीच की अंतर्कलह खुलकर सामने आ गई है। पार्टी आलाकमान ने विधायकों की नाराजगी के लिए सीधे तौर पर संगठन और बड़े नेताओं को जिम्मेदार माना है। इन नेताओं की कार्यप्रणाली से भी केंद्रीय नेतृत्व नाराज है। अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने संगठन की निष्क्रियता, गुटबाजी और बड़े नेताओं की भूमिका पर रिपोर्ट तलब की है। इसकी जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के कुछ नेताओं को सौंपी गई है। पार्टी के नेता आशंका जता रहे हैं कि कई बड़े नेताओं की भूमिका बदली जा सकती है। खासतौर पर संगठन और विधायक दल के जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों के अधिकार कम किए जा सकते हैं।

सूत्र यह भी बताते हैं कि गुरुवार को प्रदेशाध्यक्ष राकेश सिंह के दिल्ली दौरे के दौरान पार्टी के आला नेताओं ने नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने कहा कि मना करने के बाद भी सरकार गिराने को लेकर बार-बार बयान क्यों दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे जनता में ऐसा संदेश जा रहा है कि हमारे नेता सत्ता के बिना तड़प रहे हैं।

छापे का मुद्दा क्यों नहीं उठाया : भाजपा में इन दिनों एक और मुद्दा उछल रही है कि लोकसभा चुनाव के दौरान प्रदेश में जो छापामारी हुई थी, उस बारे में विधानसभा में कमलनाथ सरकार से जवाब क्यों नहीं मांगा गया। पोषण आहार घोटाले और तबादलों में की गई बंदरबांट को लेकर भाजपा क्यों मौन रही। पार्टी नेताओं की मानें तो अब केंद्रीय नेतृत्व डैमेज कंट्रोल की कमान खुद अपने हाथों में रखेगा। दोनों विधायकों को भी दिल्ली बुलाया गया है, जहां राष्ट्रीय संगठन महामंत्री उनसे बातचीत करेंगे।

> मप्र विधानसभा में घटित घटनाक्रम कांग्रेस और मुख्यमंत्री कमलनाथ की शर्मनाक राजनीति को दर्शाता है। जहां तक भाजपा का सवाल है तो कांग्रेस की अनैतिक राजनीति से हमारा नेतृत्व ज्यादा सतर्कता से निपटेगा।
>
> - डॉ. दीपक विजयवर्गीय, मुख्य प्रवक्ता, मप्र भाजपा

अमित शाह आज करेंगे 292 परियोजनाओं का भूमिपूजन

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

- इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगी दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी
- देशभर के प्रमुख उद्यमियों का भी होगा समागम

प्रदेश में औद्योगिक विकास के दूसरे चरण की ओर योगी सरकार कदम बढ़ा रही है। पिछले साल इनवेस्टर्स समिट में हुए अनुबंधों को जमीन पर उतारने के लिए रविवार को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी-2 आयोजित की जा रही है। समारोह में गृहमंत्री अमित शाह 292 औद्योगिक परियोजनाओं का भूमिपूजन करेंगे।

इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हो रहे भूमिपूजन समारोह का उद्घाटन सत्र सुबह 11 से दोपहर एक बजे तक चलेगा। बतौर मुख्य अतिथि गृहमंत्री अमित शाह लगभग 65 हजार करोड़ रुपये की 292 औद्योगिक परियोजनाओं का भूमिपूजन करेंगे। देश के प्रमुख नौ उद्यमी इसी सत्र में विचार व्यक्त करेंगे। इसके बाद गृहमंत्री सहित राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम को संबोधित करेंगे।

कार्यक्रम में उद्योगों पर आधारित छह सत्र भी होंगे। दोपहर दो बजे से साढ़े तीन बजे तक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, डिफेंस एंड एयरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पर अलग-अलग हॉल में सत्र चलेंगे। वहीं, दोपहर 3.45 से शाम 5.15 बजे तक टूरिज्म एंड फिल्म, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और पावर एंड रिन्युएबल एनर्जी पर केंद्रित सत्र आयोजित किए जाएंगे। इन सभी सत्रों की अध्यक्षता विभागीय मंत्री करेंगे, जबकि स्वागत भाषण औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना का होगा।

अनुभव सुनाएंगे यह उद्यमी

अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी, पेप्सिको इंडिया होल्डिंग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अहमद अल शेख, आइटीसी लिमिटेड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संजीव पुरी, एचसीएल के चेयरमैन शिव नाडर, टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन, सैमसंग इंडिया के प्रेसीडेंट एचसी हांग, टोरेंट ग्रुप के चेयरमैन सुधीर मेहता, मेदांता के चेयरमैन डॉ. नरेश त्रेहन और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) के चेयरमैन संदीप सोमानी।

सोनभद्र नरसंहार पीड़ितों को कांग्रेस ने दी 1.09 करोड़ रुपये की मदद

जागरण संवाददाता, सोनभद्र

उभ्भा गांव में मृतकों के परिजनों को चेक देते कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव बाजीराव खड़े। जागरण

उप्र के सोनभद्र स्थित उभ्भा नरसंहार पीड़ित 19 परिवारों को कांग्रेस ने शनिवार को एक करोड़ नौ लाख रुपये की आर्थिक मदद दी। जान गंवाने वालों के परिवारों को दस-दस लाख और गंभीर रूप से घायल ग्रामीणों को एक-एक लाख रुपये का चेक दिया गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव बाजीराव खाड़े के नेतृत्व में पहुंची टीम ने उनके मान, सम्मान और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने तथा हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया।

विदित हो कि पूर्व में प्रदेश सरकार ने अपनी तरफ से मृतक के परिवारीजनों को पांच-पांच लाख रुपये की सहायता देने की घोषणा की थी। इसके अलावा एसटी/एसी आयोग सहित अन्य मद से कुल 13-13 लाख दिए जाने थे। बाद में प्रियंका द्वारा कांग्रेस की तरफ से दस-दस लाख देने की घोषणा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर मृतक के परिवारीजन को 18.50 लाख रुपये का चेक दिया। साथ ही आवास आदि की सुविधाएं भी दी गईं।

गांव में भूमि पर कब्जा करने के चक्कर में ग्राम प्रधान यज्ञदत्त की तरफ से ग्रामीणों पर हमला करा दिया गया था। उस नरसंहार में 10 लोगों की मौत हो गई थी और 28 लोग घायल हुए थे। उसमें से नौ लोग गंभीर रूप से घायल हैं। राष्ट्रीय स्तर पर इस घटना को लेकर काफी हंगामा हुआ। पीड़ित परिवार से मिलने के लिए सोनभद्र जाते समय कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा को हिरासत में लिया गया था। बाद में मीरजापुर के चुनार किले में पीड़ितों से प्रियंका की मुलाकात कराई गई थी। उसी समय प्रियंका ने मृतकों के परिवारवालों को दस-दस लाख रुपये की मदद करने के लिए कहा था। राष्ट्रीय महासचिव के निर्देश पर राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रदेश सह प्रभारी बाजीराव खाड़े के नेतृत्व में पहुंची टीम ने शनिवार को चेक दिए।

भाजपा ने मैहर-ब्यौहारी विधानसभा क्षेत्र में शुरू की चुनावी तैयारियां

नईदुनिया, भोपाल: भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी द्वारा मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस का साथ देने के बाद अब लगभग तय माना जा रहा है कि मैहर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होगा। भाजपा ने इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। पार्टी के सतना जिले के जिलाध्यक्ष नरेंद्र त्रिपाठी शनिवार को दिनभर मैहर में रहे और विधानसभा क्षेत्र में आने वाले मंडल के अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस कवायद को उपचुनाव की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है।

नरेंद्र त्रिपाठी ने दैनिक जागरण के सहयोगी प्रकाशन नईदुनिया से कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह बना रहे, उनमें नेतृत्व का अभाव महसूस न हो, इसलिए सभी लोगों को सक्रिय कर रहे हैं। उधर, नारायण त्रिपाठी ने भी साफ संकेत दिए हैं कि वे अब भाजपा में नहीं लौटेंगे। शहडोल के ब्यौहारी में भी सदस्यता अभियान के बहाने पार्टी ने उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। त्रिपाठी ने दावा किया कि नारायण को कांग्रेस के लोग ही नहीं पचा पा रहे हैं, ऐसे हालात में उन्हें उपचुनाव में मुंह की खानी पड़ेगी। पार्टी के जिलाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह छाबड़ा ने बताया कि पार्टी शरद कोल को भी सबक सिखाएगी। उधर, नारायण त्रिपाठी ने भाजपा में उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ नेताओं ने पार्टी को धरोहर बनाया हुआ है।

दिवालिया कंपनी में निवेश मामले में सहकारिता उपायुक्त निलंबित

नईदुनिया, भोपाल

- मध्य प्रदेस का सहकारिता विभाग ईओडब्ल्यू को सौंप रहा है मामला
- 2017 में आइएलएंडएफएस समूह की दो कंपनियों में निवेश का है मामला

असुरक्षित निवेश मामले में मध्य प्रदेश शासन ने सहकारिता विभाग के उपायुक्त और भोपाल सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के तत्कालीन प्रबंध संचालक आरएस विश्वकर्मा को निलंबित कर दिया है। इसे आर्थिक अनियमितता मानते हुए मामला आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) को सौंपा जा रहा है। विश्वकर्मा ने बैंक के प्रबंध संचालक रहते हुए वर्ष 2017 में मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (आइएलएंडएफएस) समूह की दो कंपनियों (आइटीएनएल और आइईटीएस) में 110 करोड़ रुपये 9.5 फीसदी ब्याज दर पर निवेश किए थे। यह कंपनी दिवालिया हो गई और अब बैंक का ब्याज सहित 118 करोड़ रुपये फंस गया है।

दिवालिया घोषित हो चुकी कंपनी में 110 करोड़ रुपये निवेश करने का मामला खुलने के बाद जांच रिपोर्ट के आधार पर विभाग उपायुक्त विश्वकर्मा के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी में था। इससे पहले ही विश्वकर्मा हाई कोर्ट से स्थगन ले आए। बाद में विभाग ने हाई कोर्ट में सारे तथ्य रखे तो वहां से याचिका खारिज हो गई। इसके बाद विभाग के मंत्री डॉ. गोविंद सिंह ने मुख्यमंत्री कमलनाथ और मुख्य सचिव सुधिरंजन मोहंती को पत्र लिखकर मामला ईओडब्ल्यू को सौंपने की सिफारिश की है। वहीं विभाग ने शनिवार को विश्वकर्मा के निलंबन आदेश भी जारी कर दिए हैं। निलंबन अवधि में विश्वकर्मा आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं कार्यालय में पदस्थ रहेंगे।

> मामले में कार्रवाई जारी है। विश्वकर्मा को निलंबित कर दिया है और मामला ईओडब्ल्यू को सौंपा जा सकता है। वहीं अन्य बैंकों और कंपनियों में निवेश राशि भी वापस लेने के निर्देश दिए गए हैं।
>
> - अजीत केसरी, प्रमुख सचिव, सहकारिता

कंपनी दिवालिया हुई, पर कार्रवाई नहीं की : विश्वकर्मा पर नियमों को दरकिनार कर कंपनियों में राशि निवेश और 94 हजार करोड़ रुपये की पूंजी वाली कंपनी के दिवालिया होने की जानकारी मिलने के बाद भी राशि निकालने के प्रयास नहीं करने के आरोप हैं जबकि राशि वापसी के लिए कानूनी कार्रवाई करने की जगह बैंक प्रबंधन ने एक साल के लिए अक्टूबर 2018 में फिर से 118 करोड़ रुपये की एफडी उसी कंपनी में कर दी थी।

अडानी और छोटे बैंकों से भी दो दिन में राशि निकालने की तैयारी : मुंबई के आइएलएंडएफएस समूह के अलावा भोपाल सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक ने जिन कंपनियों और छोटे बैंकों में बतौर एफडी राशि निवेश की है। उसे भी असुरक्षित मानते हुए सहकारिता विभाग दो दिन में वापस लेने की तैयारी कर रहा है। इनमें अडानी की कंपनी और पिछले कुछ सालों में शुरू हुई बैंक शामिल हैं। इनमें से कई बैंकों की कुल पूंजी दो हजार करोड़ रुपए है और को-ऑपरेटिव बैंक ने उनमें दो सौ करोड़ या उससे भी ज्यादा राशि निवेश कर दी है। ऐसे में संबंधित बैंकों से जल्दी राशि वापस मिलने में आशंका है। सूत्र बताते हैं कि को-ऑपरेटिव बैंक ने अलग-अलग बैंकों में करीब 1500 करोड़ रुपये निवेश किए हैं।

दांव

सिद्धू, सोनी व सरकारिया के मंत्री बनने से वेरका का कट गया था पत्ता, मंडी बोर्ड के चेयरमैन लाल सिंह को कैबिनेट रैंक दिया गया है।

सिद्धू के कैबिनेट से हटते ही कैप्टन ने बढ़ाया वेरका का कद

इन्द्रप्रीत सिंह, चंडीगढ़

कैबिनेट से इस्तीफा दे चुके नवजोत सिंह सिद्धू एक सप्ताह से अमृतसर में हैं। इसी बीच शुक्रवार को अचानक कैप्टन सरकार ने अमृतसर से ही एक अन्य विधायक डॉ. राजकुमार वेरका को कैबिनेट रैंक का दर्जा दे दिया। इस फैसले ने सभी को हैरत में डाल दिया है। चर्चा है कि ऐसा अमृतसर में वेरका का कद बढ़ाने के लिए किया गया है। उधर, वेरका ने शनिवार को सिद्धू से मुलाकात भी की। उन्हें मार्च में वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन का चेयरमैन बनाया गया था। सिद्धू सहित अमृतसर से तीन मंत्री थे, लेकिन अब ओपी सोनी व सुखबिंदर सिंह सरकारिया ही यहां से कैबिनेट मंत्री हैं।

हालांकि वेरका को कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया गया है, लेकिन उन्हें कैबिनेट रैंक देकर उनकी नाराजगी को दूर करने की कोशिश की गई है। दरअसल इससे पहले पूर्व मंत्री अमरजीत सिंह समरा जिन्हें मार्कफैड का प्रमुख बनाया गया था, को कैबिनेट रैंक दिया गया था। इसी तरह मंडी बोर्ड के चेयरमैन लाल सिंह को कैबिनेट रैंक दिया गया। वेरका भी मंत्री पद की दौड़ में शामिल थे, लेकिन अमृतसर से सिद्धू, ओपी सोनी और सरकारिया को कैबिनेट मंत्री पद मिलने के कारण वेरका का पत्ता कट गया।

कैप्टन ने साधे एक तीर से दो निशाने : सिद्धू के इस्तीफा देने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश की है। कैप्टन सिद्धू के इस्तीफा देने के बाद खाली हुए मंत्री पद पर अपने किसी खास को बिठाना चाहते हैं। दूसरी ओर वाल्मीकि समुदाय और पिछड़े वर्ग के लोग यह मांग करते आ रहे हैं कि कैबिनेट में उनको भी प्रतिनिधित्व दिया जाए। साफ है कि वेरका को कैबिनेट का रैंक देकर वाल्मीकि समुदाय को शांत करने की कोशिश की गई है, साथ ही सिद्धू के मुकाबले में उन्हें अमृतसर में मजबूत भी किया गया है।

नवजोत कौर ने कर दिया था इंकार : राजकुमार वेरका से नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी डॉ. नवजोत कौर को वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन का प्रमुख लगाया गया था, लेकिन उन्होंने यह पद लेने से इंकार कर दिया। पिछड़े वर्ग से आते संगत सिंह गिलजियां को भी इस कार्पोरेशन का चेयरमैन लगाने की बात चली, लेकिन वह भी सिरे नहीं चढ़ पाई। जैसे ही राजकुमार वेरका को यह पद मिला, उन्होंने तुरंत संभाल लिया।

डॉ. राजकुमार वेरका। फाइल फोटो

- कैप्टन ने कैबिनेट रैंक देकर उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश की
- मार्च में वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन का चेयरमैन बनाया गया था

वेरका कांग्रेस के पहले बड़े नेता जिन्होंने सिद्धू से की मुलाकात

मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर 'एकांत' में चले गए नवजोत सिंह सिद्धू से शनिवार को डॉ. राजकुमार वेरका अमृतसर स्थित उनके आवास पर मिलने पहुंचे। सिद्धू का इस्तीफा मंजूर होने के बाद वेरका कांग्रेस के पहले बड़े नेता हैं जो सिद्धू से मिलने उनके आवास पर पहुंचे हैं। एक सप्ताह में कोई भी मंत्री या पार्टी का बड़ा नेता उनके पास नहीं पहुंचा था। वेरका का सिद्धू ने स्वागत किया और बंद कमरे में दोनों के बीच आधा घंटा तक बातचीत हुई। एक सवाल के जवाब में वेरका ने कहा कि सिद्धू से उनका मिलना व्यक्तिगत निर्णय था, पार्टी की ओर से उन्हें कोई दिशा-निर्देश नहीं थे। सिद्धू से पंजाब के हालातों पर चर्चा की है। सिद्धू ने कहा है कि जनता की लड़ाई में हम भी उनके साथ होंगे।

माकपा की तर्ज पर पूर्णकालिक सदस्य बनाएगी तृणमूल कांग्रेस

जागरण संवाददाता, कोलकाता

- तीन लाख कार्यकर्ताओं को पूर्णकालिक सदस्यता देने की तैयारी
- प्रशांत किशोर की रणनीति पर वूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने पर जोर

बंगाल में भाजपा के बढ़ते वर्चस्व से लोहा लेने के लिए सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस ने अब बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का फैसला किया है। इसके लिए माकपा की तर्ज पर तृणमूल में पूर्णकालिक सदस्य बनाने का निर्णय लिया गया है। खबर यह भी है कि सोमवार को नजरूल मंच में होने वाली पार्टी की बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसकी घोषणा कर सकती हैं।

एक बात तो साफ है कि लोकसभा चुनाव में सीटों के लिहाज से भारी नुकसान उठाने वाली तृणमूल 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती। इसके लिए तृणमूल ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर (पीके) को नियुक्त किया है ताकि पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत किया जा सके। इस दिशा में पार्टी ने काम करना भी शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक 29 जुलाई को नजरूल मंच में होने वाली बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पूर्णकालिक सदस्यों को नियुक्त करने की घोषणा कर सकती हैं। राज्य में लगभग 77 हजार बूथ हैं। प्रत्येक बूथ पर चार पूर्णकालिक सदस्यों की तैनाती की जाएगी। इसके लिए राज्यभर में तीन लाख से अधिक कार्यकर्ताओं को नियुक्त करने लक्ष्य है, जो सोशल मीडिया पर पार्टी की गतिविधियों को बढ़ावा देंगे। वहीं बूथ पर तैनात सभी सदस्यों में से प्रत्येक सदस्य को अलग-अलग जिम्मेदारी दी जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि यह पीके की रणनीति का ही हिस्सा है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री इन दिनों बदली-बदली सी नजर आ रही हैं। इससे पहले एक बयान में उन्होंने भाजपा को रोकने के लिए कांग्रेस और वामदलों से मदद की अपील की थी। पीके का आइडिया है कि ताकतवर हो रही भाजपा को रोकने के लिए सभी विपक्षी दलों का एकजुट होना जरूरी है।

3.17 लाख श्रद्धालुओं ने अब तक किए बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा के दर्शन। यात्रा के 27वें दिन शनिवार को 3,142 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में शिवलिंग के दर्शन किए।

बाढ़ में 12 घंटे फंसे रहे महालक्ष्मी एक्सप्रेस के 1,050 यात्री

राज्य ब्यूरो, मुंबई

मुंबई से कोल्हापुर जा रही महालक्ष्मी एक्सप्रेस (17411) के बाढ़ में फंस जाने के कारण करीब 1,050 यात्री लगभग 12 घंटे ट्रेन में अटके रहे। बचाव दलों के प्रयासों से शनिवार शाम चार बजे तक सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि पूरे अभियान पर हम बेहद करीब से निगाह रख रहे थे। बचाव दलों को उनके अनुकरणीय प्रयासों के लिए बधाई।

मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में शुक्रवार सुबह से ही रह-रहकर भारी बारिश हो रही थी। इस कारण मुंबई से करीब 100 किमी दूर स्थित बदलापुर स्टेशन और वांगणी गांव के बीच उल्हास नदी का पानी अचानक रेल की पटरियों पर आ गया और पटरियां डूब गईं। मध्य रेलवे के वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी एके जैन के मुताबिक, ट्रेन तड़के 3.53 बजे बदलापुर से आगे बढ़ी तो वांगणी पार करने से पहले ही पटरियों के पानी में डूब जाने के कारण उसका आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। खतरा यह भी था कि जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा था।

सुबह होते ही ठाणे आपदा प्रबंधन, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), नौसेना, वायुसेना, थलसेना, स्थानीय पुलिस, आरपीएफ और स्थानीय ग्रामीणों ने मिलकर बचाव कार्य शुरू कर दिया। नौ सेना ने अपने विशेषज्ञ गोताखोरों को भी बचाव अभियान में लगाया तो वायुसेना के दो एमआइ-17 हेलीकॉप्टर अभियान में जुटे थे। सेना के 130 जवानों ने यात्रियों तक खाद्य सामग्री, पेयजल और अन्य राहत सामग्री पहुंचाई।

एके जैन के अनुसार कोल्हापुर जा रहे यात्रियों को अब 19 कोच की एक विशेष ट्रेन के जरिये निकटतम स्टेशन कल्याण से मडगांव एवं दौंड होते हुए कोल्हापुर भिजवाने की व्यवस्था की जा रही है।

नीचे नहीं उतरने की दी हिदायत : बचाव अभियान शुरू होने तक ट्रेन के अंदर मौजूद मध्य रेलवे की टीम यात्रियों को लगातार नीचे नहीं उतरने और धीरज रखने की सलाह देती रही। आरपीएफ, बदलापुर से ट्रेन तक पहुंचा रेलवे स्टाफ और ग्रामीण यात्रियों को खाद्य सामग्री इत्यादि देकर राहत पहुंचाते रहे।

यात्रियों में नौ गर्भवती महिलाएं भी शामिल : मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुनील उदेसी के अनुसार आठ हल्की नौकाओं के जरिये यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर लाया गया। पहले महिलाओं और बच्चों को, उसके बाद पुरुषों को निकाला गया। सुरक्षित निकाले गए यात्रियों में नौ गर्भवती महिलाएं भी शामिल थीं। ट्रेन से निकाले गए यात्रियों को 14 बसों और तीन टैंपों से बदलापुर स्थित सह्याद्रि मंगल कार्यालय नामक बारात घर में शरण दी गई।

हेलीकॉप्टरों से भी निकाला गया: मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस के निर्देश पर नौसेना की टीमें और उसके दो हेलिकॉप्टर भी बाढ़ में फंसी ट्रेन पर मंडरा रहे थे। कुछ लोगों को सी-किंग हेलीकॉप्टर से भी बाहर निकाला गया।

▶ अमित शाह ने बचाव दल को अनुकरणीय प्रयासों के लिए दी बधाई

11 उड़ानें निरस्त, नौ डायवर्ट

मुंबई में भारी बारिश की वजह से विमान सेवाओं पर भी असर पड़ा है। शनिवार को 11 उड़ानें निरस्त करनी पड़ीं और नौ के मार्ग बदलने (डायवर्ट) पड़े।

वायुसेना ने 124 लोगों को बचाया

भारी बारिश के कारण आई बाढ़ की वजह से राज्य में विभिन्न स्थानों पर फंसे 124 लोगों को वायुसेना ने शनिवार को बचा लिया। इनमें से 70 लोग मुंबई से 65 किलोमीटर दूर ठाणे जिले के बदलापुर कस्बे में एक पेट्रोल पंप की छत पर फंसे थे। 45 लोग ठाणे के ही शाहद में एक निजी रिजॉर्ट में फंस गए थे। नौ लोग कल्याण के पास उल्हास नदी के पास एक इमारत की छत पर फंसे थे।

मुंबई में शनिवार को बाढ़ में फंसी महालक्ष्मी एक्सप्रेस से यात्रियों को सुरक्षित निकालते राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के जवान। एएनआइ

बारिश से कई राज्यों में बिगड़े हालात, 19 की जान गई

जागरण टीम, नई दिल्ली

▶ उत्तर भारत में बढ़ रहा बारिश और बाढ़ का कहर

▶ राजस्थान में लगातार चौथे दिन तेज बारिश का दौर जारी रहा

देश में असम, बिहार और मुंबई के बाद अब राजस्थान में भी बाढ़ से परेशानी बनी हुई है। इसके चलते लाखों लोग जहां गांव-घर छोड़ने का मजबूर हुए वहीं सैंकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर बिहार में शनिवार को भी भारी बारिश से बाढ़ से घिरे लोग परेशान रहे। वहीं, अलग-अलग स्थानों पर बाढ़ के पानी में डूबने से नौ लोगों की मौत की खबर है। इनमें पश्चिम चंपारण और शिवहर के दो-दो, पूर्वी चंपारण के चार और दरभंगा के एक व्यक्ति शामिल हैं। वहीं, एक व्यक्ति लापता है।

राजस्थान में भी आई आफत की बारिश, अब तक 10 की मौत : राजस्थान में लगातार चौथे दिन तेज बारिश का दौर शनिवार को भी जारी रहा। बारिश के कारण अब तक 10 लोगों की मौत होने की बात सामने आई है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में एक दर्जन बांध टूटने के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया है।

बारिश के चलते कई ट्रेन हुई रद : राजस्थान समेत विभिन्न इलाकों में हो रही भारी बारिश के कारण ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने शनिवार को आठ ट्रेन को रद्द करने के साथ ही आधा दर्जन ट्रेनों का मार्ग बदला है। रेलवे के अनुसार जो ट्रेन रद्द हुई हैं उनमें 54085 दिल्ली-रेवाड़ी, 45086 रेवाड़ी-दिल्ली, 74003 दिल्ली-रेवाड़ी,51973 मथुरा-दिल्ली, 51974 जयपुर-मथुरा, 71903 ईदगाह-बादीकुई और 71904 बांदीकुई-ईदगाह शामिल है।

मप्र में शुरू हुआ तेज बारिश का दौर : मध्य प्रदेश के मंदसौर के मल्हारगढ़ में 12 घंटे में साढ़े आठ इंच बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। निचली बस्तियों में 30 से अधिक मकानों और दुकानों में पानी भर गया। तीन कच्चे मकान धराशायी हो गए। 10 से अधिक मवेशियों की मौत हो गई। वहीं, श्योपुर में शुक्रवार रात से शनिवार दोपहर यानी 12 घंटे में 40 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं। खातौली पुल दूसरे दिन भी डूबा रहा, जिससे श्योपुर का कोटा से संपर्क कटा हुआ है। सरारी नदी में उफान के कारण नैरेगेज ट्रेन का पुल शुक्रवार से ही डूबा हुआ है। गिरधरपुर-खोजीपुरा रेलवे स्टेशन के पास बारिश में रेलवे ट्रैक के नीचे से मिट्टी का कटाव हो गया, जिससे दूसरे दिन भी इस रूट पर ट्रेनों का संचालन बंद रहा।

पुलवामा समेत कई वाहन धमाकों का साजिशकर्ता मुन्ना साथी सहित ढेर

बड़ी कामयाबी ▶ बनिहाल और अरिहाल वाहन बम धमाके में भी शामिल था मुन्ना बिहारी

शोपियां में हुई मुठभेड़, मुन्ना पर सात और जीनत पर पांच लाख रुपये का था इनाम

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

कश्मीर के पुलवामा, बनिहाल और अरिहाल समेत पिछले छह माह के दौरान हुए विभिन्न वाहन धमाकों के साजिशकर्ता जैश कमांडर मुन्ना बिहारी उर्फ मुन्ना लाहौरी को उसके एक साथी समेत शनिवार को सेना ने मार गिराया। दक्षिण कश्मीर के शोपियां में हुई मुठभेड़ में मारा गया मुन्ना पाकिस्तान का रहने वाला था, जबकि उसका साथी जीनत इश्फाक मीर उर्फ जीनत उल इस्लाम तुरकवांगन (शोपियां) का निवासी था। जीनत को जैश ने शोपियां-पुलवामा का डिवीजनल कमांडर बनाया था। कुख्यात मुन्ना पर सात लाख और जीनत पर पांच लाख का इनाम था। मुन्ना और जीनत सुरक्षाबलों पर विभिन्न हमलों के अलावा पंच-सरपंचों से मारपीट और छह नागरिक हत्याओं में वांछित थे। मुठभेड़ के बाद तनाव को देखते हुए प्रशासन ने पूरे इलाके में मोबाइल इंटरनेट सेवा पर रोक लगाने के साथ ही सभी शिक्षण संस्थानों को भी बंद कर दिया है।

सुरक्षाबलों को जानकारी मिली कि जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी शोपियां के बोनबाजार में छिपे हुए हैं। उन्हें पकड़ने के लिए सेना की 44 आरआर, सीआरपीएफ और पुलिस के एक संयुक्त कार्यदल ने 23 पैरा के कमांडो दस्ते के साथ तड़के तलाशी अभियान चलाया। जवान जैसे ही बांडे मोहल्ले में एक मकान के पास पहुंचे, वहां छिपे आतंकियों ने उनपर फायर कर दिया। जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। आतंकियों ने मुठभेड़ के दौरान अपना ठिकाना छोड़ निकटवर्ती एक शेड में शरण ली। बताया जाता है कि यह शेड सज्जाद नामक व्यक्ति का है। कुछ लोगों के मुताबिक, आतंकी उसके ही घर में रुके थे, लेकिन पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की। सुबह साढ़े आठ बजे आतंकियों की तरफ से अंतिम गोली चली। इस दौरान आतंकी समर्थक तत्वों ने भड़काऊ नारेबाजी करते हुए मुठभेड़स्थल पर जमा होकर सुरक्षाबलों के अभियान में व्यवधान भी डालने का प्रयास किया, लेकिन जवानों ने उन्हें नाकाम बना दिया। लगभग आधे घंटे तक आतंकियों की तरफ से फायरिंग न होने के बाद सुरक्षाबलों ने मुठभेड़स्थल की तलाशी ली तो उन्हें वहां गोलियों से छलनी आतंकी मुन्ना और जीनत के शव मिले। मुन्ना और जीनत के मारे जाने की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में युवक घरों से बाहर निकले और पथराव शुरू कर दिया। उन्हें काबू करने के लिए सुरक्षाबलों को भी हल्का बल प्रयोग करना पड़ा।

वाहन बम और आइईडी बनाने में माहिर था मुन्ना : मुन्ना बिहारी के मारे जाने से कश्मीर में वाहन बम और आइईडी धमाकों को अंजाम देने के जैश-ए-मोहम्मद के नापाक मंसूबों को तगड़ा झटका लगा है। वह कश्मीर में सक्रिय उन गिने-चुने आतंकियों में एक था, जो वाहनबम और आइईडी बनाने में माहिर हैं। मुन्ना ने ही 14 फरवरी को पुलवामा हमले में इस्तेमाल वाहन बम को तैयार करने में अहम भूमिका निभाई थी। इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। इसके बाद 30 मार्च को जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर बनिहाल के पास हिजबुल मुजाहिदीन द्वारा सीआरपीएफ काफिले पर हमले के लिए जिस कार बम का इस्तेमाल किया गया था, उसे तैयार करने में भी मुन्ना शामिल था। पिछले माह 17 जून को अरिहाल (पुलवामा) में सैन्य वाहन को उड़ाने में जिस वाहन को आतंकियों ने इस्तेमाल किया था, वह भी उसने ही तैयार किया था। इस धमाके में दो जवान शहीद और करीब 14 सैन्यकर्मी और दो नागरिक जख्मी हुए थे। बनिहाल हमले में लिप्त आतंकी उवैस ने पूछताछ में बताया था कि मुन्ना हिज्ब कमांडर रियाज नायकू के कहने पर तीन से चार और वाहन बम तैयार करने में जुटा हुआ है। इसकी पुष्टि आइजी जम्मू रेंज एमके सिन्हा ने भी की थी। उन्होंने कहा था कि मुन्ना बिहारी ने कार बम तैयार किया है।

आतंकवादियों को वाहन बम बनाने की ट्रेनिंग भी देता था

अधिकारियों के मुताबिक, मुन्ना ने बीते छह माह के दौरान शोपियां, पुलवामा, कुलगाम और अनंतनाग में करीब एक दर्जन युवकों को जैश और हिज्ब में भर्ती होने के लिए तैयार किया है। वह नए आतंकियों को आइईडी तैयार करने और वाहन बम बनाने की ट्रेनिंग भी देता था।

जम्मू-कश्मीर में 10 हजार अतिरिक्त सुरक्षाबलों की तैनाती पर सियासत तेज

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

जम्मू-कश्मीर में 10 हजार अतिरिक्त सुरक्षाबलों की तैनाती पर कश्मीर में सियासत तेज हो गई है। उमर अब्दुल्ला के बाद पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती समेत विभिन्न कश्मीर केंद्रित सियासी दलों ने विरोध तेज कर दिया है। उनका आरोप है कि केंद्र भय और विमुखता की भावना पैदा कर रहा है। गौरतलब है कि इसे 35ए पर संभावित किसी निर्णय से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं, भाजपा ने कश्मीरी दलों पर लोगों में बेवजह डर पैदा करने का आरोप लगाया है और इसे विधानसभा चुनाव की तैयारी का हिस्सा बताया है।

गौरतलब है कि पिछले महीने कश्मीर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की थी। इस बैठक में राज्य पुलिस और सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से आतंकरोधी अभियानों और कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए 100 अतिरिक्त कंपनियों की मांग की थी। तर्क दिया गया था कि राज्य में बीते साल भेजे गए अर्द्धसैनिक बल आतंकरोधी अभियानों और कानून व्यवस्था की स्थिति को संभालने के लिए पूरी तरह प्रशिक्षित नहीं हैं। उन्हें सिर्फ पंचायत और निकाय चुनाव के लिए यहां भेजा गया था। गृह मंत्रालय ने राज्य प्रशासन के इस आग्रह को स्वीकार कर 100 कंपनियां भेजने का फैसला किया।

बदली जा रहीं अर्द्धसैनिक बलों की 100 कंपनियां : मुनीर अहमद

राज्य पुलिस में सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था विंग के अतिरिक्त महानिदेशक मुनीर अहमद खान ने कहा कि घाटी में अर्द्धसैनिक बलों की 100 कंपनियां बदली जा रही हैं। ये कंपनियां पहले से तैनात उन केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों का स्थान लेंगी, जिन्हें बीते साल प्रशिक्षण के दौरान ही देश के विभिन्न हिस्सों से जम्मू-कश्मीर में पंचायत व निकाय चुनावों के दौरान भेजा गया था। ऐसे में कंपनियों के आगमन को लेकर कुछ तत्व अफवाहें फैला रहे हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है।

महबूबा बोलीं-इससे दिल्ली के प्रति अविश्वास बढ़ेगा : पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि केंद्र सरकार के फैसले ने जम्मू-कश्मीर के लोगों में भय पैदा कर दिया है। इससे लोगों में व्याप्त नई दिल्ली के प्रति अविश्वास और विमुखता की भावना और बढ़ेगी।

सज्जाद गनी लोन ने कहा-फैल रही है अफवाह : पीपुल्स कांफ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने कहा कि किसी को पता नहीं कि यहां क्या हो रहा है? राज्य के विशेष दर्जे और अनुच्छेद 35ए को हटाने की अगर केंद्र की कोई मंशा है तो वह असहनीय है। इसके परिणाम खतरनाक होंगे।

फैसल बोले, पर्यटक छोड़ रहे हैं कश्मीर : जम्मू-कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट के चेयरमैन डॉ. शाह फैसल ने कहा कि श्रीनगर एयरपोर्ट पर कश्मीर छोड़कर जाने वाले पर्यटकों की स्थिति को देखा जा सकता है। यहां विभिन्न प्रकार की अफवाहें चल रही हैं।

बेवजह डर पैदा कर रहे हैं : भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र रैना ने सीधा हमला बोला कि उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती अफवाहें और डर पैदा कर रहे हैं। उन्होंने लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यह सुरक्षा बल निकट भविष्य में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर ही तैनात किए जा रहे हैं।

डोभाल के पहुंचने से मिला अटकलों को मिला बल : अनुच्छेद 35ए पर जारी अटकलों के बीच हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अचानक श्रीनगर पहुंचकर केंद्रीय खुफिया एजेंसियों, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, स्थानीय पुलिस व सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अलग-अलग बैठकें कीं। इससे भी चर्चाएं गति पकड़ने लगी हैं।

जागरण की 'आधा गिलास पानी' मुहिम से जुड़ी आइटीबीपी

जासं, देहरादून : पानी की बर्बादी रोकने के लिए चलाई गई जागरण की मुहिम 'आधा गिलास पानी' को हर स्तर पर अपार समर्थन मिला है। इससे प्रेरित होकर तमाम शिक्षण और व्यापारिक प्रतिष्ठानों ने पानी की फिजूलखर्ची रोकने का संकल्प लिया है। अब इस फेहरिस्त में आइटीबीपी (भारत तिब्बत सीमा पुलिस) भी शामिल हो गई है। देहरादून स्थित 23वीं वाहिनी के कमांडेंट अशोक कुमार गुप्ता ने दैनिक जागरण को पत्र लिखकर आधा गिलास पानी मुहिम की सराहना की। इसके साथ ही भरोसा दिलाया कि वह हर स्तर पर बहुमूल्य संपदा पानी का संरक्षण करेंगे।

शनिवार को जागरण को भेजे गए पत्र में आटीबीपी के कमांडेंट अशोक कुमार गुप्ता ने कहा कि 'आधा गिलास पानी' मुहिम के साथ जुड़कर उन्होंने अपने सभी जलपान गृहों में इस व्यवस्था को लागू कराने के निर्देश दिए हैं। पीने के लिए गिलास में उतना ही पानी परोसने को कहा गया है, जितना पीना हो। इसके साथ ही आइटीबीपी भी अपने स्तर पर पानी को बचाने के लिए अभियान चलाएगा। इसमें अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया जाएगा।

कश्मीर में आतंकी घुसपैठ नाकाम, लांस नायक शहीद

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

▶ भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को भी भारी नुकसान पहुंचने की सूचना

पाकिस्तानी सेना ने शनिवार को उत्तरी कश्मीर के मच्छल सेक्टर (कुपवाड़ा) में नियंत्रण रेखा पर भारत के अग्रिम सैन्य और नागरिक ठिकानों पर गोलाबारी कर आतंकियों की घुसपैठ कराने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने इस प्रयास को नाकाम बना दिया। इस दौरान आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में लांस नायक राजेंद्र सिंह शहीद हो गए। वहीं, भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को भी काफी नुकसान पहुंचने की सूचना है।

सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तानी सैनिकों ने तड़के मच्छल सेक्टर में अचानक गोलाबारी शुरू कर दी। इस दौरान पाकिस्तान ने भारत के सैन्य और नागरिक क्षेत्रों पर मोर्टार भी दागे। भारतीय जवानों ने पहले इसे उकसावे की कार्रवाई और घुसपैठ करवाने के लिए गोलाबारी समझते हुए संयम बरता। यह गोलाबारी करीब एक घंटे तक चली।

पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी बंद होने के बाद अग्रिम इलाकों में गश्त कर रहे जवानों और नाका पार्टियों ने घुसपैठ की आशंका के चलते तलाशी अभियान शुरू कर दिया। इस दौरान अमर पोस्ट के आगे के इलाके में जवानों ने घुसपैठियों को देखते ही ललकारा। घुसपैठियों ने खुद को फंसते देख जवानों पर फायरिंग करते हुए वापस गुलाम कश्मीर की तरफ भागना शुरू कर दिया। जवानों ने भी जवाबी फायर किया। इस दौरान लांस नायक राजेंद्र सिंह गोली लगने से जख्मी हो गए। उन्हें उपचार के लिए निकटवर्ती अस्पताल ले जाया गया, जहां वह शहीद हो गए।

रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने मच्छल सेक्टर में संघर्ष विराम उल्लंघन की पुष्टि नहीं की, लेकिन यह जरूर स्वीकार किया कि तड़के घुसपैठ के एक प्रयास को नाकाम बनाते हुए सेना की 57 आरआर के लांस नायक राजेंद्र सिंह शहीद हो गए। वहीं, घुसपैठिए वापस भाग गए। गौरतलब है कि पुलवामा पर हमले के बाद से पाकिस्तानी सेना कई बार घुसपैठ की कोशिश कर चुकी है लेकिन सेना ने हर बार उसे नाकाम कर दिया है।

पढ़े फारसी, बेचे तेल... का ताना सुन शहर आए थे संप्रदा बाबू

जागरण संवाददाता, जहानाबाद

जहानाबाद के ओकरी गांव से निकलकर देश के प्रमुख उद्योगपति बनने वाले एल्केम दवा कंपनी के संस्थापक संप्रदा सिंह का शनिवार को मुंबई में निधन हो गया। वह 94 वर्ष के थे। लीलावती अस्पताल में सुबह 9 बजकर 20 मिनट पर उन्होंने आखिरी सांस ली। तबीयत खराब होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बिहार और गृह जिले से हमेशा जुड़े रहे संप्रदा सिंह के निधन से उद्योग जगत में शोक की लहर है।

फोर्ब्स की भारत के 100 सबसे अधिक धन वालों की सूची में वह शामिल थे। उन्हें फार्मा उद्योग के ऑस्कर अवॉर्ड के समकक्ष एक्सप्रेस फार्मा एक्सीलेंस अवॉर्ड से नवाजा गया था। वे 1.85 बिलियन डॉलर की निजी संपदा के मालिक होने का दर्जा हासिल करने वाले पहले बिहारी उद्यमी थे। उन्हें बिहार का कुबेर कहा जाता था। जानने वाले उन्हें संप्रदा बाबू कहते थे। शनिवार को उनके निधन की खबर आई, तो उनके संघर्ष की कहानियां गर्व से सुनाई जाने लगीं। लोग याद करने लगे कि यह वही संप्रदा बाबू हैं जिन्हें गांव में ताना सुनना पड़ा था कि पढ़े फारसी, बेचे तेल, देखो रे संप्रदा का खेल...।

1953 में खोली थी दवा की दुकान : जहानाबाद जिले के मोदनगंज प्रखंड के ओकरी गांव में 1925 में जन्मे संप्रदा सिंह के पिता श्रीनारायण सिंह साधारण किसान थे। इकलौती संतान संप्रदा सिंह ने गांव के ही प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा हासिल की। घोसी हाईस्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद गया कॉलेज, गया से उन्होंने बीकॉम की डिग्री ली। स्नातक करने के बाद वह कुछ दिनों के लिए गांव आ गए। प्रगतिशील किसान बनना चाहते थे। सिंचाई की दिक्कत थी तो ऋण लेकर डीजल पंपसेट लिया। सब्जियों की खेती से पैसा कमाना चाहते थे। गांव के लोगों को लगता था कि बीए पास करने के बाद कोई खेती करता है क्या? तो ताना मारने लगे लोग। इस बीच अकाल पड़ा और संप्रदा बाबू ने खेती से नाता तोड़कर कुछ दिन एक निजी स्कूल में पढ़ाया। लेकिन वेतन कम होने के चलते एक दवा दुकान पर काम किया। फिर पटना में 1953 में दवा की दुकान खोल ली थी। करीब सात वर्ष बाद 1960 में पटना में ही उन्होंने मगध फार्मा के नाम से फार्मास्युटिकल्सडिस्ट्रीब्यूशन फर्म की स्थापना की। अपनी मेहनत और मिलनसार स्वभाव के कारण वे जल्द ही कई बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। उन्होंने आठ अगस्त, 1973 में मुंबई में एल्केम लेबोरेटरीज नामक दवा कंपनी की स्थापना की। जल्द ही इस कंपनी का नाम अग्रणी दवा कंपनियों में शुमार हो गया।

संप्रदा सिंह फाइल फोटो

▶ छोटी सी दवा दुकान से सफर शुरू कर खड़ी की 26 हजार करोड़ की कंपनी

▶ 1973 में मुंबई में एल्केम लेबोरेटरीज नाम से खोली थी दवा कंपनी

ताने को दरकिनार कर गांव से लगाव रखा

मुंबई में रहने के बावजूद संप्रदा बाबू का गांव से गहरा लगाव था। वे यहां से हरेक साल अपने लिए गुलर तथा मकई मंगवाते थे। अधिकांश लोगों का नाम उन्हें याद रहता था। जैसे ही गांव के लोगों को शनिवार को सवेरे उनके निधन की जानकारी मिली वहां मातम छा गया। वह 25 साल पहले तक गांव आते थे। गांव के लोगों के साथ बधार जाते थे और खेत से चना उखाड़ कर खाते थे। उन्हें गांव खूब भाता था। उनके साथी तपेशर सिंह को जैसे ही उनकी मृत्यु की जानकारी मिली वे शोक में डूब गए।

परिवार को रखा एक साथ, अपनों को अपनाए रखा : संप्रदा बाबू की खासियत यह भी रही कि उन्होंने अपने पूरे परिवार को समेट कर रखा। खुद कंपनी के चेयरमैन थे तो भाई वासुदेव प्रसाद सिंह को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया। संप्रदा बाबू के पिता श्रीनारायण सिंह भाइयों में सबसे छोटे थे। उनके सबसे बड़े चाचा कृत नारायण सिंह और मंझले चाचा प्रसिद्ध नारायण सिंह थे। उन लोगों का परिवार भी मुंबई में ही रहता है। इस परिवार की एकता और कर्मठता ने एल्केम कंपनी को पीछे नहीं जाने दिया। आज उनका कारोबार 30 देशों में फैला हुआ है।

मिसाल

कुवैत में फंसी पंजाब की महिला को कराया मुक्त, पीड़ित परिवार ने सरकार व अधिकारियों से मांगी थी मदद, लेकिन नहीं हुआ था कोई फायदा

जो कार्य सरकार 11 माह में नहीं कर पाई, हरनेक ने 11 दिन में कर दिया

पोपीन पंवार, यमुनानगर

हरियाणा के थाना छप्पर गांव के हरनेक सिंह रंधावा ने कनाडा में फिर नेकी का बड़ा काम किया है। 11 माह से कुवैत में पाकिस्तानी शेख की कैद मे फंसी पंजाब की महिला को मुक्त कराकर सुरक्षित वतन पहुंचाया है। एजेंट ने जून में महिला को हाउस कीपिंग की जॉब के लिए कुवैत भेजा था। आरोप है कि उसने महिला को 1200 दीनार में पाकिस्तानी शेख को बेच दिया था। जब यह बात परिवार को पता चली तो सरकार व अधिकारियों से गुहार गई। सरकारी व्यवस्था से परेशान होकर गुरदासपुर (पंजाब) के धारीवाल निवासी महिला के पति सुरेंद्र की हृदयघात से मौत हो गई। बाद में महिला के बेटे रोहित ने हरनेक रंधावा हेल्पलाइन कनाडा से संपर्क किया। उनके प्रयास से 11 महीने बाद महिला शेख की कैद से मुक्त हुई और स्वदेश लौटकर अपने बच्चों से मिली।

हेल्पलाइन ने 13 जुलाई से काम शुरू किया था। 11 दिन में सफलता मिली। महिला का कहना है कि अपने घर पर आधा पेट खाना ही बहुत अच्छा है। कोई भी वतन छोड़कर दूसरे मुल्क न जाए। वहां पर वह घर के काम के अलावा शेख के बच्चों को संभालती थी। इसके बावजूद मारपीट होती थी। उसको भूखा रखा जाता था। जब वह विदेश गई तब उसका वजन 60 किलो था। अब 38 किलो रह गया है।

कनाडा में रह रहे हरनेक सिंह रंधावा का फाइल फोटो।

▶ एजेंट ने पाकिस्तानी शेख को 1200 दीनार में बेच दिया था

▶ महिला के पति सुरेंद्र की हृदयघात से हो गई थी मौत

एजेंट पर दर्ज हुआ केस

गुरदासपुर के एसपी शरणदीप सिंह का कहना है कि एजेंट मुख्तार सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। महिला फिलहाल बयान देने की हालत में नहीं है, उसके बयान के आधार पर कार्रवाई होगी।

गुरदासपुर की डिस्ट्रिक लीगल अथॉरिटी के सेक्रेटरी राणा कंवरदीप कौर ने हरनेक सिंह रंधावा हेल्प लाइन कनाडा को महिला को मुक्त कराने के लिए प्रशस्ति पत्र दिया है।

रंधावा हेल्पलाइन चलाने वाले हरनेक रंधावा ने बताया कि विदेश में भारतीयों की मदद के वह काफी समय से हेल्पलाइन चला रहे हैं। इसके चार हजार सदस्य है, जो अलग अलग देशों में काम करते हैं। पीड़ित महिला के परिवार के माध्यम से पता चला कि कुवैत में उसे बंधक बनाकर रखा है। 11 माह से महिला को वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। पति की मौत पर भी भारत नहीं आने दिया। बातचीत में शेख ने बताया कि 12 सौ दीनार में महिला को खरीदा है। जब खरीद लिया तो वेतन क्यों दिया जाए।

हेल्पलाइन ने ऐसे किया काम : हरनेक ने महिला को बंधक बनाकर रखने वाले शेख का नंबर हेल्पलाइन के ग्रुप पर छोड़ दिया। नंबर आते ही सभी सदस्यों ने बारी-बारी से शेख से बात करना शुरू कर दिया। जब चार हजार लोगों की कॉल शेख पर पहुंचने लगी तो उसका दिन का चैन और रात की नींद उड़ गई। तंग आकर शेख महिला को लौटाने के लिए तैयार हो गया। इस बीच सदस्यों ने 1200 दीनार का इंतजाम भी कर लिया, लेकिन बाद में 300 दीनार के खर्च में काम चल गया। कुवैत से हेल्पलाइन के सदस्यों ने महिला का एयर टिकट कराकर इंडिया भिजवाया।

तारिक लोन, सीए व ट्रांसपोर्टर से पूछताछ करेगी एनआइए

नवीन राजपूत, अमृतसर

आइसीपी अटारी पर पकड़ी गई 584 किलो हेरोइन के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) तीन आरोपितों को दिल्ली ले जाकर पूछताछ करने की तैयारी में है। एनआइए मुख्य आरोपित जम्मू कश्मीर के तारिक अहमद लोन, अमृतसर के सीए अजय गुप्ता और ट्रांसपोर्टर जसबीर सिंह को सोमवार मोहाली की एनआइए कोर्ट में पेश करेगी। पंजाब पुलिस की खुफिया शाखा के एक अधिकारी के अनुसार एनआइए की जांच वरिष्ठ अधिकारी आशीष चौधरी की देखरेख में होगी। लंबे समय तक जम्मू-कश्मीर में तैनात रहे आशीष को तीनों आरोपितों से पूछताछ का जिम्मा सौंपा गया है।

सूत्रों के अनुसार तीनों आरोपितों को रविवार दोपहर अमृतसर से मोहाली ले जाया जाएगा और सोमवार सुबह एनआइए कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट ने अनुमति दी तो तीनों को दिल्ली ले जाकर उनके कारोबार, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ से संबंध, पाक तस्करों से सांठ-गांठ के अलावा कई अन्य पहलुओं पर पूछताछ की जाएगी। एनआइए गुरपिंदर सिंह से भी पूछताछ करना चाहती थी लेकिन जेल में उसकी मौत हो चुकी है।

सूत्रों का कहना है कि एनआइए द्वारा सीए अजय गुप्ता, तारिक लोन और गुरपिंदर से उनके फेसबुक अकाउंट और ई-मेल के पासवर्ड पूछे, लेकिन उन्होंने पासवर्ड बताने से मना कर दिया। 584 किलो हेरोइन तस्करी मामले में गैंगस्टर के लिंक भी सामने आने लगे हैं। स्टेट स्पेशल आपरेशन सेल ने शुक्रवार को फतहपुर जेल में बंद गैंगस्टर शुभम सहित सीए अजय गुप्ता, ट्रांसपोर्टर जसबीर सिंह और तारिक अहमद लोन को प्रोडक्शन वारंट पर लिया है। चारों आरोपितों को ज्वाइंट इंटेरोगेशन सेंटर में रखा गया है। इस मामले के आरोपितों के साथ गैंगस्टर को प्रोडक्शन वारंट पर लिया जाना इस बात की ओर इशारा करता है कि कहीं न कहीं इन मामले में गैंगस्टर भी शामिल हैं।

1.5 अरब टायर हर साल बेकार हो जाते हैं। इनमें से अधिकांश को जला दिया जाता है। विश्व भर में प्रदूषण की समस्या बढ़ते जाने के पीछे यह भी एक बड़ी वजह है। ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि में भी इसका योगदान है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
रविवार 28 जुलाई 2019

समय के साथ रेस में आगे गोल्डन गर्ल हिमा दास

असम के नौगांव जिले के छोटे से गांव ढिंग में धान के खेतों में माता-पिता के साथ बोआई करने वाली दुबली-पतली लड़की आज खेल के मैदान पर भारत का परचम फहरा रही है। लड़कों संग फुटबाल खेलने वाली यह लड़की एथलेटिक्स (दौड़) में कदम रखने के महज तीन साल के भीतर ही एक के बाद एक स्वर्ण पदक अपने नाम करती जा रही है। हर किसी की जुबान पर उसी का नाम और उपलब्धियों की चर्चा है? जी हां बात हो रही है हिमा दास की। भारत की इस गोल्डन गर्ल ने महज 19 दिनों के भीतर यूरोप के विभिन्न शहरों में आयोजित ट्रैक एंड फील्ड प्रतियोगिताओं की विभिन्न स्पर्धाओं में पांच स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं...

नेशनल डेस्क, नई दिल्ली

गरीब किसान रंजीत दास के घर नौ जनवरी 2000 को जन्मीं हिमा की कहानी बेहद दिलचस्प है। दो बीघा खेत और धान की खेती ही परिवार की आय का जरिया रहा, जिससे हिमा का बचपन अभावों में बीता। पांच भाई-बहनों में सबसे छोटी हिमा ने दो वक्त के भोजन की व्यवस्था के लिए उस उम्र में खेतों में परिजनों के साथ काम करना शुरू कर दिया था जिस आयु में अमूमन बच्चियां गुड्डे- गुड़ियों के साथ खेलती हैं। गांव के लड़कों को फुटबाल खेलते देखने वाली यह मस्तमौला बच्ची भी उनकी टीम में शामिल हो गई। गेंद को लेकर भागने की गति के कारण कुछ ही समय में वह प्रसिद्ध हो गई। जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ाई के दौरान विद्यालय के पीटी टीचर ने हिमा की गति देख रेसर बनने की सलाह दी। आर्थिक तंगी इतनी थी कि दौड़ लगाने के लिए अच्छे जूते भी नहीं खरीद सकती थी। स्थानीय कोच निपुन दास की सलाह पर हिमा ने जिला स्तर की 100 और 200 मीटर की स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके बाद निपुन ने हिमा के पिता से बात की और उन्हें बताया कि बिटिया खेल के मैदान में देश का नाम रोशन करने की क्षमता रखती है। उसे उचित प्रशिक्षण की जरूरत है। इसके लिए गुवाहाटी जाना होगा। परिजन अकेले बेटी को भेजने में हिचक रहे थे। अतः हिमा ने कुछ दिन गांव से गुवाहाटी जाना शुरू किया, लेकिन कई बार देर शाम घर लौट पाती थी। आखिरकार पिता ने बेटी को गुवाहाटी में अकेले रहने की इजाजत दे दी, लेकिन समस्या धन के बंदोबस्त की थी। निपुन ने खर्च का जिम्मा अपने ऊपर लिया और हिमा ने गुवाहाटी में प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। शुरू में उन्हें 200 मीटर की रेस के लिए तैयार किया गया। बाद में वह 400 मीटर की स्पर्धा में भी दौड़ने लगीं। यहीं से उनके पदक जीतने का क्रम शुरू हो गया। हिमा किसी भी जीत के समय अपने परिवार के संघर्षों को याद करती हैं और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। उन्होंने असम के बाढ़ पीड़ितों के लिए अपना आधा वेतन दान दिया है। साथ ही अन्य लोगों से मदद करने का अनुरोध किया है।

चैंपियन की कहानी

गोल्डन पंच

2 जुलाई को पोलैंड में पोजनान में एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में 200 मीटर रेस में 23.65 सेकंड के साथ पहला स्वर्ण

7 जुलाई को पोलैंड में कुटनो एथलेटिक्स मीट में 200 मीटर रेस को 23.97 सेकंड में पूरा किया। 13 जुलाई को चेक रिपब्लिक में हुई क्लांदो मेमोरियल एथलेटिक्स में 200 मीटर रेस में 23.43 के साथ तीसरा स्वर्ण पदक

17 जुलाई को ताबोर एथलेटिक्स मीट में 200 मीटर रेस को 23.25 सेकंड के साथ चौथा स्वर्ण हासिल किया। चेक रिपब्लिक में 400 मीटर की रेस 52.09 सेकंड में पूरी की।

राष्ट्रपति-पीएम के साथ ही सचिन भी हुए मुरीद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमा की सफलताओं से बेहद खुश हैं। उन्होंने ढिंग एक्सप्रेस के नाम से विख्यात हिमा को बधाई दी है। मोदी ने ट्वीट किया, भारत को हिमा पर बहुत गर्व है। उन्हें बधाई और भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर ने भी हिमा की सफलता को सलाम किया है। सचिन ने हिमा को किए ट्वीट में कहा है कि तुम्हारी जीत की भूख युवाओं के लिए प्रेरणा है। सचिन के संदेश से हिमा बेहद उत्साहित हैं।

सफलता का नतीजा: हिमा की उपलब्धियों का ही नतीजा है कि उनकी ब्रैंड वैल्यू तीन हफ्तों के भीतर दोगुनी हो गई। जहां पहले एक ब्रैंड के लिए उन्हें सालाना 30-35 लाख रुपये मिलते थे, वहीं अब यह राशि 60 लाख रुपये पहुंच गई है। हिमा फिलहाल, एडिडास स्पोर्ट्सवियर, एसबीआइ, इडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज और नॉर्थ-ईस्ट की सीमेंट ब्रैंड स्टार सीमेंट के लिए विज्ञापन करती हैं। अब हिमा के लिए वॉच ब्रैंड, टायर, एनर्जी ड्रिंक ब्रैंड, कुकिंग ऑयल और फूड जैसी कैटेगरी के ब्रैंड से नई डील के लिए बात हो रही ह।

चुनौतियां और भी हैं : दमदार प्रदर्शन के चलते हिमा से सितंबर में दोहा में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप में उम्मीदें बढ़ गई हैं, लेकिन मंजिल अभी दूर है। हिमा ने अभी तक जिन प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया है, वह इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन के मानक पर ई और एफ श्रेणी में आती हैं, जबकि ओलंपिक और ए श्रेणी में उन्हें अपनी प्रतिभा साबित करना बाकी है। हिमा का 400 मीटर की रेस में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 51.46 सेकंड रहा है, जो मौजूदा विश्व विजेता से कहीं पीछे है।

असाधारण है इस ज्योति की चमक

मास्टर स्ट्रोक

रसिक द्विवेदी, रायबरेली

रायबरेली शहर के शक्तिनगर मोहल्ले में रहने वाले शिक्षक सुरेश कुमार की पुत्री ज्योति प्रियदर्शी ने वर्ष 2017 में हाईस्कूल और 2019 में इंटर की परीक्षा पास करने के बाद अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) को चुना है। छोटी सी ज्योति के बड़े से लक्ष्य के पीछे रोचक कहानी है। 22 अप्रैल 2004 को जन्मीं ज्योति जब ढाई साल की थी तो पिता की तैनाती वाले ब्लॉक के बेतौरा गांव में रहती थी। पड़ोस में एक स्कूल था। एक दिन वह घूमते- घूमते स्कूल पहुंच गईं। परिजन खोजने निकले तो वह स्कूल में बच्चों के बीच बैठी मिलीं। सुरेश गांव से शहर आ गए और तीन साल की बिटिया का स्कूल में दाखिला करा दिया। बेटी के हर कक्षा में अव्वल आने के साथ साथ माता-पिता की आंखों में सपने भी बड़े होते गए। हाईस्कूल और इंटर की मार्कशीट जब घर आई तो परिवार चहक उठा। माता-पिता चाहते थे कि बेटी डॉक्टर बने लेकिन उसने पहली बार में ही जेईई एडवांस मेंस में कामयाबी हासिल कर ली। ज्योति ने कभी कोचिंग या ट्यूशन का सहारा नहीं लिया।

जिस उम्र में बच्चे हाईस्कूल (दसवीं) और इंटरमीडिएट (12वीं) की परीक्षा को लेकर आशंकित रहते हैं, उस उम्र में उसने सफलता की हैट्रिक लगा दी। जेईई एडवांस मेंस जैसी कठिन परीक्षा में देश भर में 342वां स्थान (ऑल इंडिया रैंकिंग) हासिल किया। इसके बाद पढ़ाई के लिए सौ फीसद प्लेसमेंट वाले आइआइटी धनबाद का रास्ता पकड़ लिया। यह उसकी लगन का नतीजा है, जिस आइआइटी में प्रवेश की औसत आयु 18 वर्ष है, वो वहां की छात्र बनकर इंजीनियरिंग की दुनिया में कमाल करने को तैयार है। देश की दूसरी सबसे कम उम्र की आइआइटियन (माइनिंग मशीनरी) बनीं इस होनहार का नाम है ज्योति, जो उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले की मूल निवासी है।

यूं तो पढ़ने का वक्त तय नहीं था, लेकिन जेईई एडवांस की परीक्षा की कोचिंग के बाद रोज 7-8 घंटे पढ़ाई की। मेंस के लिए 4-5 घंटे रोजाना पढ़ाई करती थी। वैसे इंजीनियरिंग के लिए 11वीं और 12वीं की पढ़ाई काफी है। तैयारी के दौरान वह सोशल मीडिया व ध्यान भटकाने वाली अन्य चीजों से बिलकुल दूर रही। -**ज्योति, आइआइटियन**

फटी ड्रेस और मोजे में भी मगन

मां मंजू चौधरी बताती है कि ज्योति सामान्य हालात में रहने की आदी है। उसे कभी भी किसी तरह की शिकायत नहीं रही। जो कुछ भी मिला, उसे खुशी-खुशी स्वीकार कर लिया। यह एक सच्चाई है कि पारिवारिक स्थितियों के चलते हम बच्चों को ड्रेस भी मुकम्मल तरीके से नहीं दिला पाते थे। फटे मोजे पहनकर बेटी स्कूल जाने को तैयार होती तो मां का चेहरा लटक जाता था, मगर ज्योति कह उठती- मां जूते में मोजे छिप जाएंगे। आप परेशान मत हो। इसी तरह ड्रेस जब कभी गड़बड़ हुई तो घरवालों को ही तसल्ली देती थी। ऐसा था पढ़ाई-लिखाई के प्रति ज्योति का जज्बा। आज वह कामयाबी की दहलीज पर खड़ी है। ज्योति की मां बताती हैं कि एक बार जब वह करीब तीन साल की थी तो रात में अचानक उठी और जनरल नॉलेज की पतली सी किताब लेकर पापा के पास पहुंची। और तोतली भाषा में बोली डैडी...पिहाओ (पढ़ाइए)।

15 साल से नहीं देखा टेवी

शायद आप यकीन न करें, लेकिन सुरेश के घर में पिछले 15 वर्षों से टेलीविजन नहीं चलाया गया। सुरेश के घर में यूं तो घर में टेलीविजन 2002 में ही आ गया था, लेकिन बच्चों की पढ़ाई के चलते 2004 में उसे बांधकर रख दिया गया। घर में सिर्फ समाचार पत्र और कॉपी किताबें ही मिलेंगी। मनोरंजन का कोई साधन नहीं है। भोजन करने के समय ही मोबाइल छूने की अनुमति है। वह भी थोड़ी देर बहन और फिर छोटे भाई दिव्यांश को। मां के मुताबिक, न्यूज पेपर पढ़ने के लिए पिता-बेटी में किचकिच हो जाती थी। पहले बेटी अखबार पढ़ना चाहती थी, जबकि स्कूल जाने से पहले पिता। वह बताती हैं कि मायके में एक रिश्तेदार के पुत्र की पीलिया से मौत हो गई थी। इसीलिए बेटी को डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन उसको इंजीनियरिंग अच्छी लगी। हमें खुशी है कि वह अपने सपने को साकार करने के करीब है। इंजीनियरिंग ही उसका सपना था।

छत्तीसगढ़ के नक्सली क्षेत्र के होनहारों ने भी दिखाया प्रतिभा का दम

धनबाद : 17 वर्ष के छात्र योगेंद्र नाथ सिंह, विवेक कुमार दीवान और अमरनाथ ने एक साथ पढ़ाई की। साथ-साथ खेले और आज एक साथ आइआइटी आइएसएम में दाखिला भी लिया। छतीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों के आदिवासी बहुल जिलों के दूर-दराज क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवार के इन प्रतिभावान छात्रों ने आइआइटी में सफलता प्राप्त कर अपने जैसे छात्रों के लिए रोल मॉडल के रूप में उभरे हैं। योगेंद्र नाथ सिंह का कैटेगरी रैंक 516 है। योगेंद्र को मैथ एंड कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग में दाखिला मिला है। वहीं विवेक कुमार दीवान का रैंक 554 है और उन्हें पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में दाखिला मिला है। अमरनाथ पैकरा को मिनरल इंजीनियरिंग मिली है।

प्रयास आवासीय विद्यालय रायपुर के छात्र योगेंद्र ने बताया कि हमारे विद्यालय से कुल आठ छात्रों को आइआइटी में सफलता मिली है। चार को आइएसएम तथा एक-एक को आइआइटी दिल्ली, रुड़की, मंडी तथा बीएचयू में एडमिशन मिला है। योगेंद्र ने बताया कि चार में एक छात्रा ने भी यहां नामांकन कराया है। योगेंद्र ने बताया कि नौवीं से ही हमलोगों ने तय कर लिया था कि आइआइटी परीक्षा पास करना है। विवेक बताते हैं कि विद्यालय में आइआइटी परीक्षा को लेकर विशेष तैयारी कराई जाती है। कक्षा के अलावा सात से आठ घंटे सेल्फ स्टडी भी करते थे। योगेंद्र, विवेक,और अमरनाथ के पिता पेशे से किसान हैं। उन्होंने बताया कि इंजीनियरिंग क्षेत्र में और बेहतर कर देश सेवा करना चाहते हैं।

14 साल की उम्र में आइआइटियन

जागरण संवाददाता, धनबाद

आइआइटी आइएसएम में इस बार बीटेक का नया बैच खास है। यहां विलक्षण प्रतिभा के धनी 10 छात्र-छात्राओं ने इंजीनियरिंग में दाखिला लेकर सबसे कम उम्र में आइआइटी आइएसएम में दाखिला लेने का रिकार्ड बनाया है। ये सभी छात्र साधारण परिवार से जरूर तालुक रखते हैं, पर इनका परिचय असाधारण है। चतुर्भुज, योगेंद्र, विवेक, अमरनाथ समेत देश के अलग-अलग हिस्सों से आए 10 मेधावी 14-15 साल की कम उम्र में ही आइआइटियन कहला रहे हैं। इनमें सबसे कम उम्र के हैं राजस्थान के अलवर जिले के निवासी चतुर्भुज सिंह किराल। उन्हें महज 14 वर्ष 11 महीने की आयु में आइआइटी में दाखिला मिला है।

इंजीनियरिंग के बाद आइएएस बनकर करूंगा देश की सेवा: चतुर्भुज बचपन से इंजीनियर बनने का सपना पालने वाले चतुर्भुज सिंह किराल के पिता लाल चंद राजस्थान के अलवर जिले में कबाड़ बेचकर परिवार का पालन पोषण करते हैं। छह भाई बहनों में पांचवें नंबर के चतुर्भुज की पढ़ाई के प्रति बेटे की लगन को देखते हुए पिता ने बेटे के सपने पूरे करने में कभी गरीबी को आड़े नहीं आने दिया। चतुर्भुज ने महज 13 बरस की उम्र में दसवीं की परीक्षा आठ सीजीपीए अंक के साथ पास की थी और अब 14 वर्ष 11 माह में 12वीं के साथ-साथ आइआइटी की प्रवेश परीक्षा भी पास कर ली। वह भी पहले ही प्रयास में। उन्हें पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में दाखिला मिला है।

चतुर्भुज कहते हैं कि मैने गरीबी देखी है। इंजीनियर बनने के बाद आइएएस बन कर देश की सेवा करना चाहता हूं। बकौल चतुर्भुज, आइएसएम का नाम काफी सुना था। यहां दाखिला लेने के बाद एक आइआइटीयन बनने का सपना पूरा हो गया। पिता लाल चंद ने कहा, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है लेकिन बेटे की पढ़ाई के सामने दिक्कतों को कभी रोड़ा नहीं बनने दिया। उनका कहना है कि उनके लिए बेटे की पढ़ाई ही सब कुछ है। चतुर्भुज ने अच्छे संकेत दे दिए हैं कि वह एक कामयाब इंसान बनने जा रहे हैं। हालांकि उन्हें यह अहसास भी है कि अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी है।

इंजीनियर ही बनना चाहते हैं चतुर्भुज।

मशीनों की अपार क्षमता करेगी मानव का कल्याण

10^120 होता है शतरंज के एक मुकाबले में संभावित नतीजों का मोटा-मोटा अनुमान। यह ब्रह्मांड में मौजूद कणों का कई अरब गुना है।

आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के इस जमाने में हर क्षेत्र में मशीनें मानव को चुनौती देती दिख रही हैं। हालिया शोध बताते हैं कि मशीनों की बढ़ती क्षमता मानव का कई तरीके से कल्याण करने में समर्थ है। ये जटिल और अबूझ रोगों से लेकर जोखिम के कामों तक सब चुटकियों में सुलझा देंगी। मशीनों को मानव के बरक्स रखने की पटकथा आज से बहुत पहले तब रख दी गई थी जब आइबीएम के डीप ब्लू कंप्यूटर ने 1996 में तत्कालीन विश्व चैंपियन गैरी कास्परोव के खिलाफ बहुचर्चित मुकाबले का पहला गेम जीत लिया। कास्परोव ने जबरदस्त वापसी की और सीरीज 4-2 से जीत ली। हालांकि एक साल बाद ही अपग्रेडेड डीप ब्लू ने सीरीज जीती। आज शतरंज खेलने वाले कंप्यूटरों को प्रशिक्षण के लिए एक साल की आवश्यकता नहीं होती। डीप ब्लू ने अद्भुत गणना शक्ति के आधार पर लाखों संभावित चालों का आकलन किया था, जबकि आज के कंप्यूटर इंसानों द्वारा चली जाने वाली चालों के पैटर्न के आधार पर खेलते हैं। विश्व विजेताओं को हराने के लिए कंप्यूटरों को केवल कुछ घंटों की ट्रेनिंग की जरूरत होती है। आइए, ऐसे ही कंप्यूटरों की क्षमता पर डालते हैं एक नजर:

अलग है सीखने का तरीका

जटिल गणना शक्ति का सहारा लेने के बजाय अल्फा जीरो कंप्यूटर अभ्यास के जरिये संभावित चालों का अनुमान करता है। यही तकनीक बिना ड्राइवर वाली आटोमैटिक कारों में ट्रैफिक का अंदाज लगाने में इस्तेमाल की जाती है।

4 घंटे लगते हैं अल्फा जीरो को शतरंज का मुकाबला सीखने में।

4.4 करोड़ अभ्यास मुकाबले खेले जा चुके हैं अब तक इस कंप्यूटर द्वारा।

स्टाकफिश 8 कंप्यूटर के खिलाफ उसने अब तक 100 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से किसी में भी उसे अब तक हार का सामना नहीं करना पड़ा। अल्फा जीरो ने 28 मुकाबले जीते और 72 बाजियां ड्रा खेलीं।

नए कंप्यूटर कम शक्ति लगाते हैं और ज्यादा अच्छे नतीजे देते हैं। अब इंसानों के लिए उनका मुकाबला करना मुश्किल होता जा रहा है।

20 करोड़ चालें एक सेकेंड में एनालाइज कर सकता था डीप ब्लू कंप्यूटर 1996 में।

7 करोड़ चालें एक सेकेंड में चल सकते हैं स्टाकफिश 8 जैसे सबसे अच्छे चेस प्रोग्राम।

80000 चालें अल्फाजीरो कैलकुलेट कर सकता है प्रति सेकेंड। इस कंप्यूटर ने दिसंबर 2017 में स्टाकफिश 8 को हराया था। इन दोनों कंप्यूटरों को शतरंज के मामले में महारथी माना जाता है।

बादशाहत और भी जगह है

शतरंज सरीखे खेल और भी हैं। ऐसा ही एक खेल है जापान का बोर्ड गेम शोगी। शोगी में संभावित नतीजों का अनुमान कई अरब होता है, लेकिन अल्फाजीरो को शोगी सीखने में केवल दो घंटे लगते हैं।

90 मुकाबले अब तक शोगी के खेल में जीत चुका है अल्फा जीरो सबसे प्रमुख शोगी प्रोग्राम एल्मो के खिलाफ। दोनों के बीच कुल 100 मुकाबले खेले गए। इसे काफी प्रसिद्धि मिली।

10^360 होती है चीन के एक परंपरागत स्ट्रेटजी गेम में संभावित परिणामों का अनुमान।

8 घंटे लगते हैं अल्फा जीरो को यह खेल सीखने में।

शोध में हो सकता है इस्तेमाल

अल्फा जीरो सरीखे कंप्यूटर शतरंज के मुकाबले जीतने में प्रसिद्ध बन गए हैं। उनके डिजाइनरों को उम्मीद है कि इन कंप्यूटरों का इस्तेमाल वैज्ञानिक शोध के लिए किया जा सकेगा। माना जा रहा है कि पर्किंसन और अलजाइमर जैसी बीमारियों के अध्ययन में इन कंप्यूटरों की सीखने की क्षमताओं का प्रयोग किया जा सकता है।

ब्रिटेन की राजनीति में ताजनगरी का आलोक

चर्चित शख्सियत

आगरा के कोठी मीना बाजार स्थित शिव निवास में जन्मे एक बच्चे की छोटी आंखों ने बड़ा सपना देखा और उसे लगन व जुनून से साकार कर दिखाया। शहर के प्राइमरी स्कूल में ककहरा सीखने वाले आलोक शर्मा छोटी सी ही उम्र में सात समंदर पार ब्रिटेन पहुंच गए। उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद सियासत की ओर कदम बढ़ाए और ब्रिटेन के मंत्रिमंडल में शामिल हो ताजनगरी का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। ब्रिटेन के नए पीएम बोरिक जॉनसन ने आलोक को हाउसिंग एंड प्लानिंग (आवास एवं योजना) का कैबिनेट मंत्री बनाया है। आलोक शर्मा की कहानी बयां करती **विनीत मिश्रा** की रिपोर्ट।

कोठी मीना बाजार के सामने हवेलीनुमा शिव निवास में सात सितंबर 1967 को आलोक का जन्म हुआ। बाबा बालमुकुंद शर्मा पुलिस अधीक्षक (एसपी) के पद से सेवानिवृत्त हुए, तो चाचा गणेश दत्त शर्मा भी एसपी बने। पिता प्रेम शर्मा ब्रिटेन में वेटनरी सर्जन थे। संयुक्त परिवार था, सो पिता से दूर रहकर भी आलोक को उनकी कमी नहीं खली। घर के पास ही नार्मल कंपाउड के प्राइमरी स्कूल में उनका दाखिला हुआ। करीब एक साल तक नार्मल स्कूल में पढ़ाई की। आलोक के मन में भी समाजसेवा का जज्बा पलता रहा। फिर उनका दाखिला देहरादून के वेल्हंस स्कूल में करा दिया गया। 1972 में पिता स्वदेश आए और आलोक को ब्रिटेन लेकर चले गए। देश छूटा, धरती छूटी,लेकिन समाजसेवा का जो जज्बा मासूम आंखों ने देखा था, उम्र बढ़ने के साथ-साथ वह भी जवां होता रहा। चचेरे भाई विश्वनाथ शर्मा बताते हैं कि बचपन से आलोक की रुचि सियासत के जरिये समाज सेवा करने की थी। पिता की इच्छा के अनुरूप आलोक ने सीए की पढ़ाई की और प्रैक्टिस शुरू कर दी, लेकिन इसी बीच कंजरवेटिव पार्टी में शामिल होकर राजनीति के क्षेत्र में भी कदम बढ़ा दिए। पहली बार महज 43 बरस की उम्र में वह रीडिंग वेस्ट शहर से सांसद बने।

अपनी माटी से कम न हुई मोहब्बत : भले ही आलोक ब्रिटेन में बस गए, लेकिन भारत और आगरा की माटी से मोहब्बत कम न हुई। हफ्ते में कम से कम एक बार परिजनों से फोन पर बात करते हैं। चचेरे भाई विश्वनाथ बताते हैं कि वर्ष 2010 के पहले उनका आगरा आना-जाना रहता था,बाद में व्यस्तता के कारण नहीं आ सके। आलोक भले ही ब्रिटेन में बसे हैं, लेकिन खुद भारतीय संस्कारों का मोह नहीं छोड़ पाए। बच्चों को भी भारतीय सभ्यता और परंपराओं से बखूबी जोड़ रखा है। पत्नी इंग्ला के साथ ही दोनों बेटियों को भी भारतीय संस्कारों की बेहतर जानकारी है।

ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन ने हाल में पीएम पद संभाला है और अपनी कैबिनेट में तीन भारतवंशियों को शामिल कर उन्होंने संकेत दे दिया है कि उन्हें भारत की मेधा पर कितना भरोसा है। इन्हीं तीन में शामिल हैं आलोक शर्मा, जिनकी जड़ें आगरा से जुड़ी हैं। आलोक अपनी व्यस्तता के बाद भी इस नाते को बनाए हुए हैं....

ब्रिटेन में चचेरे भाई विश्वनाथ शर्मा और अन्य परिजनों के साथ आलोक शर्मा (बाएं से दूसरे)।

बस्तर की बेटी का सियोल तक का सफर

छत्तीसगढ़ में बस्तर का इलाका नक्सलवाद से ग्रस्त है, यहां से आम तौर पर अशांति की ही खबरें आती हैं, लेकिन इसी इलाके की प्रतिभाएं समय-समय पर देश-दुनिया को अपनी काबिलियत दिखाती रही हैं। ऐसा ही एक नाम है यहां की बेटी पुष्पलता साहल का, जिसने इसी सप्ताह दक्षिण कोरिया में भारत का प्रतिनिधित्व किया है...

हौसले की उड़ान

योगेंद्र ठाकुर, दंतेवाड़ा

दंतेवाड़ा जिले के कोंडागांव ब्लॉक के छोटे से गांव बारसूर की पुष्पलता साहल इन दिनों दक्षिण कोरिया के सियोल शहर में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। उन्होंने सामाजिक संवाद विषय के जरिये भारत में बढ़ती बेरोजगारी और उसके समाधान पर प्रजेंटेशन दिया है। उन्होंने सामूहिक अनुबंध विषय पर भी दुनिया को अपने विचारों से अवगत कराया।

श्रमिकों की आवाज हैं पुष्पलता : नक्सल प्रभावित जिले के छोटे से गांव बारसूर के सामान्य परिवार में जन्मीं पुष्पलता के मन में कमजोर लोगों के दर्द को महसूस करने के बीज बचपन से ही पड़ गए थे। पिता अनूपधर नाग पहले शिक्षक थे, फिर एनएमडीसी (नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन) में नौकरी करने लगे। वह गरीबों के हक की आवाज बुलंद करते थे। पिता को गरीबों-मजदूरों की समस्याएं सुनते, उनके हक के लिए आंदोलन करते देख नन्हीं पुष्पलता के मन में भी लोगों के लिए संघर्ष करने और उन्हें न्याय दिलाने की भावना प्रबल होने लगी। मां सुकुलदई ने भी बेटी को हमेशा कमजोरों के साथ रहने को प्रेरित किया।

शिक्षक की भूमिका से शुरू हुआ जिंदगी का नया सफर : पुष्पलता ने गांव में प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद दंतेवाड़ा, किरंदुल और जगदलपुर से हाईस्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। वनस्पति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएट करने के दौरान साथियों को साथ लेकर चलना व उनके हित की बात करना उनके व्यवहार में शामिल था। इसके बाद उन्हें शिक्षक की नौकरी मिल गई। बच्चों के साथ साथ सहकर्मियों के बीच लोकप्रिय होने के कारण कुछ ही अंतराल में वह शिक्षक संघ के कुआकोंडा ब्लॉक की पदाधिकारी बन गईं।

एनएमडीसी में नौकरी की: पुष्पलता विवाह के बाद किरंदुल में रहने लगीं। इसी दौरान उन्हें भी एनएमडीसी में नौकरी मिल गई। उन्हें लगा कि यह उनके लिए बेहतर अवसर है, जहां वह अपनी अलग पहचान बना सकती हैं और रोजगार जैसे गंभीर विषय पर सार्थक बहस को आगे बढ़ा सकती हैं। इसी दौरान उन्हें समझ आया कि बेरोजगारी भी बड़ी समस्या है। इसका समाधान कैसे हो, इस विचार ने उनके मन में उथल-पुथल मचा दी। आज सामाजिक संवाद के जरिये वह इस समस्या का समाधान खोजने में जुटी हैं।

20 देशों के बीच बेबाकी से दिया प्रजेंटेशन : पुष्पलता के जीवन में बदलाव उस समय आया, जब नवंबर 2018 में उन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कंफेडरेशन द्वारा दिल्ली में आयोजित एशियन पैसिफिक रीजनल कांफ्रेंस में 12 देशों के प्रतिनिधियों के समक्ष प्रजेंटेशन दिया। इसी दौरान उन्हें सियोल कांफ्रेंस के लिए चुना गया। पुष्पलता का ऑनलाइन प्रजेंटेशन इंडियन लेबर आर्गेनाइजेशन के इटली स्थित कार्यालय भेजा गया, जिसे सराहा गया। इसके बाद 20 देशों के 31 लोगों में से पुष्पलता समेत 18 लोगों को इंडस्ट्रीज ऑफ ग्लोबल यूनियन के कार्यक्रम के लिए चुना गया। यह इंडस्ट्रीज ऑफ ग्लोबल यूनियन एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जो 143 देशों में काम करता है। पुष्पलता को राजनीति में लाने का श्रेय छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा (अब दिवंगत) को जाता है, जिन्होंने उन्हें एक कार्यक्रम में भाषण देते सुना और प्रभावित हुए।

राज्य	बहुसंख्यक आबादी	हिंदू	अन्य
जम्मू कश्मीर	68.31 (मुस्लिम)	28.43	3.26
पंजाब	57.68 (सिख)	38.48	3.84
अरुणाचल प्रदेश	30.26 (ईसाई)	29.04	40.7
नगालैंड	87.92 (ईसाई)	8.74	3.34
मणिपुर	41.28 (ईसाई)	41.38	17.34
मिजोरम	87.16 (ईसाई)	2.74	10.1
मेघालय	74.59 (ईसाई)	11.52	13.89
लक्षद्वीप	96.57 (मुस्लिम)	2.77	0.66

(सभी आंकडें फीसद में)

दुरुपयोग का बना आधार

अश्विनी उपाध्याय
राज्य की आबादी के आधार पर अल्पसंख्यक को परिभाषित करने की मांग के याचिकाकर्ता

जम्मू-कश्मीर में 68 फीसद जनसंख्या मुसलमानों की है, लेकिन वहां, अल्पसंख्यकों को मिलने वाली सारी सहूलियतें इन्हें मिलती हैं। जबकि वास्तविक रूप से अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय उन सुविधाओं से महरूम है।

भारत में अल्पसंख्यक शब्द की अवधारणा ब्रिटिशकालीन है। सन 1899 में तत्कालीन ब्रिटिश जनगणना आयुक्त द्वारा कहा गया था कि भारत में सिख,जैन, बौद्ध, मुस्लिम को छोड़कर हिंदू बहुसंख्यक हैं। यहीं से अल्पसंख्यकवाद और बहुसंख्यकवाद के विमर्श को बल मिलने लगा। संविधान निर्माण के लिए जब संविधान सभा बैठी तब 'अल्पसंख्यक' के मुद्दे पर जोरदार बहस हुई। 26 मई 1949 को संविधान सभा में अल्पसंख्यक आरक्षण पर बहस के दौरान अनुसूचित जातियों को आरक्षण देने के प्रश्न पर आम राय थी लेकिन अल्पसंख्यक आरक्षण पर आम राय नहीं बन पा रही थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने साफ किया कि पंथ/आस्था/मजहब/धर्म आधारित आरक्षण गलत है। उस समय तक अल्पसंख्यक का मतलब मुसलमान हो चुका था। बिहार के वरिष्ठ नेता और संविधान सभा के सदस्य तजम्मुल हुसैन ने जोर देकर कहा था कि 'हम अल्पसंख्यक नहीं हैं'। अल्पसंख्यक शब्द अंग्रेजों का निकाला हुआ है। अंग्रेज यहां से चले गए, अब इस शब्द को डिक्शनरी से हटा दीजिए। अब हिंदुस्तान में कोई अल्पसंख्यक वर्ग नहीं रह गया है।' तजम्मुल हुसैन के भाषण के इस अंश पर सभा में खूब वाहवाही हुई थी।

संविधान निर्माताओं ने संविधान के अनुच्छेद 29 और30 के तहत उन लोगों के लिए कुछ अलग से प्रावधान किया जो भाषा और धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक श्रेणी में आते हैं। इस अनुच्छेद में 'अल्पसंख्यक' कौन है, इसकी परिभाषा नहीं निकलती। यहां पर एक तथ्य और गौर करने लायक है कि संविधान निर्माताओं को अल्पसंख्यक आयोग के गठन की जरूरत नहीं महसूस हुई थी। लेकिन राजनीति को इसकी जरूरत थी, लिहाजा सरकार ने 12 जनवरी 1978 को अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की। इस आयोग के गठन का आधार अल्पसंख्यकों से भेदभाव, उनकी सुरक्षा, देश की धर्मनिरपेक्ष परंपरा को बनाए रखने और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना था। संसद द्वारा 1992 के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम के तहत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग बनाया गया। इस एक्ट में भी अल्पसंख्यक की परिभाषा नहीं तय की गई। यह आयोग सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए लागू की जाने वाली योजनाओं और नीतियों को प्रभावी तरीके से लागू करने पर नजर रखता है। इसी अधिनियम की धारा 2(सी) के तहत केंद्र सरकार को किसी भी समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित करने का असीमित अधिकार है।

यह भी जानना रोचक है कि किसी जाति समूह को अनुसूचित जाति या जनजाति घोषित करने की विधि बहुत जटिल है और यह काम केवल संसद ही कर सकती है (अनुच्छेद 341-342)। लेकिन किसी समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित करने का काम सरकारी दफ्तर से भी हो सकता है। इसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार ने 23 अक्टूबर 1993 को एक अधिसूचना के जरिये पांच समुदायों मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, सिख और पारसी को अल्पसंख्यक घोषित किया। 27 जनवरी 2014 को तत्कालीन संप्रग सरकार ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इसी कानून के तहत जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित कर दिया।

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2006 में राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में कहा था, 'यह सुनिश्चित करने के लिए कि अल्पसंख्यक, खासकर मुसलमान विकास में बराबरी से फायदा ले सकें, हमें मौलिक योजना बनानी पड़ेगी। संसाधनों पर उनका पहला हक होना चाहिए'। मनमोहन सिंह ने तो 'अल्पसंख्यक' का मतलब ही मुसलमान मान लिया था लेकिन आजादी के सात दशक बाद भी देश में अल्पसंख्यक कौन है यह तय नहीं हो पाया है।

'अल्पसंख्यक' की सटीक व्याख्या और परिभाषा नहीं होने की वजह से इसका बड़े स्तर पर दुरुपयोग हो रहा है। मिसाल के तौर पर 2011 की जनगणना के मुताबिक जम्मू-कश्मीर में 68 फीसद जनसंख्या मुसलमानों की है। अतः जनसंख्या के आधार पर इस राज्य में मुसलमान किसी भी दृष्टिकोण से अल्पसंख्यक नहीं कहे जा सकते हैं। लेकिन वहां, अल्पसंख्यकों को मिलने वाली सारी सहूलियतें इन्हें मिलती हैं। जबकि वहां हिंदू समुदाय जो वास्तविक रूप से अल्पसंख्यक है, उन सुविधाओं से महरूम है। हालांकि ऐसा नहीं है कि यह मामला केवल जम्मू-कश्मीर तक ही सीमित है। अगर ध्यान से देखें तो भारत के तमाम हिस्सों में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किए जाने की वजह से किसी न किसी समुदाय के साथ अन्याय हो रहा है। 2011 के जनसंख्या आकड़ों के मुताबिक देश के आठ राज्यों लक्षद्वीप, मिजोरम, नगालैंड, मेघालय, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और पंजाब में हिंदू अल्पसंख्यक हैं लेकिन उनके अल्पसंख्यक के अधिकार बहुसंख्यकों को मिल रहे हैं।

अल्पसंख्यक का दर्जा मिलने के बाद उसके सदस्यों को अल्पसंख्यकों के लिए कल्याण कार्यक्रमों और छात्रवृत्तियों में केंद्रीय मदद मिलती है। वे अपने शैक्षिक संस्थान भी चला सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर में वर्ष 2016-17 में अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप का फायदा जिन छात्रों को मिला है उनमें 1 लाख 5 हजार से अधिक छात्र मुसलमान समुदाय से आते हैं जबकि सिख, बौद्ध, पारसी और जैन धर्म के 5 हजार छात्रों को इसका फायदा मिल सका है। इसमें भी हिंदू समुदाय के किसी भी छात्र को इसका फायदा नहीं मिला है। जम्मू कश्मीर में तकनीकी शिक्षा में 20,000 रुपये छात्रवृत्ति दी जाती है। राज्य में मुसलमानों के बहुसंख्यक होने के बावजूद सरकार ने वहां 753 में से 717 छात्रवृत्ति मुस्लिम छात्रों को आवंटित की हैं एक भी हिंदू को छात्रवृत्ति नहीं दी गई है। ऐसे में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के मायने और उसकी परिभाषा को दुरुस्त किया जाना अपरिहार्य हो जाता है।

टीएमए पई मामले में संविधान पीठ कहा है कि अल्पसंख्यक की पहचान राज्य स्तर पर की जाए न कि राष्ट्रीय स्तर पर। क्योंकि कई राज्यों में जो वर्ग बहुसंख्यक हैं उन्हें अल्पसंख्यक का लाभ मिल रहा है। यह विषमता तभी दूर होगी जब अल्पसंख्यक की पहचान राज्य स्तर पर हो। दूसरा उपाय यह है कि अल्पसंख्यक की परिभाषा और अल्पसंख्यकों की पहचान के लिए दिशानिर्देश तय हों, ताकि यह सुनिश्चित हो कि सिर्फ उन्हीं अल्पसंख्यकों को संविधान के अनुच्छेद 29-30 में अधिकार और संरक्षण मिलेगा जो वास्तव में धार्मिक और भाषाई, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली न हों और जो संख्या में बहुत कम हों।

सुप्रीम कोर्ट के 11 जजों की संविधान पीठ ने 2002 में निर्देश दिया था कि अल्पसंख्यक की पहचान राष्ट्रीय स्तर की बजाय राज्य स्तर पर की जाए। क्योंकि कई राज्यों में जो वर्ग बहुसंख्यक हैं उन्हें अल्पसंख्यक का लाभ मिल रहा है और जो वास्तव में अल्पसंख्यक है उसे बहुसंख्यक माना जा रहा है। 2005 सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने कहा था कि धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक-बहुसंख्यक की अवधारणा देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक है इसलिए जितना जल्दी हो सके, अल्पसंख्यक आयोग को भंग कर देना चाहिए। 2007 में पंजाब हाईकोर्ट ने पंजाब में सिखों को अल्पसंख्यक का दर्जा समाप्त कर दिया था और वह मामला भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।

संविधान में सभी नागरिकों को बराबर अधिकार मिला हुआ है, इसलिए अब समय आ गया है कि अल्पसंख्यक-बहुसंख्यक के आधार पर समाज का विभाजन बंद किया जाए अन्यथा दूसरा उपाय यह है कि अल्पसंख्यक की परिभाषा और राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान के लिए दिशा निर्देश तय हों और यह सुनिश्चित किया जाए कि केवल उसी समुदाय को संविधान के अनुच्छेद 29-30 का संरक्षण मिले जो वास्तव में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से प्रभावहीन हो और संख्या में नगण्य अर्थात एक फीसद से कम हों।

देश के संविधान में सभी नागरिक समान हैं। धर्म, लिंग और संप्रदाय के आधार पर उनमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं बरता जा सकता है। उनके अधिकार-कर्तव्य भी एक जैसे हैं। वसुधैव कुटुंबकम् की अवधारणा को साकार करने वाले देश में अलबत्ता अल्पसंख्यक शब्द ही बेमानी लगता है। फिर भी अगर अपने राजनीतिक हितों और सियासी जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ राजनीतिक दलों ने इस शब्द का अस्तित्व बरकरार रखा है तो उसके मानदंडों को हर जाति, धर्म, समुदाय पर लागू करना चाहिए। 23 अक्टूबर 1993 को एक अधिसूचना जारी करके राष्ट्रीय स्तर पर आबादी के आधार पर पांच समुदायों मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी को अल्पसंख्यक घोषित किया गया है। देश का भूगोल अब बदल चुका है। कई राज्यों में परिभाषित अल्पसंख्यक अब बहुसंख्यक हो चुके हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में राष्ट्रीय आंकड़े की जगह राज्यवार जनसंख्या के आधार पर अल्पसंख्यक समुदायों के निर्धारण की मांग की गई है। याचिका में केंद्र की 26 साल पुरानी इस अधिसूचना की वैधता को चुनौती देते हुए कहा गया है कि यह स्वास्थ्य, शिक्षा, शरण और जीवनयापन के बुनियादी अधिकार का उल्लंघन है। अब गेंद सरकार के पाले में हैं, लेकिन यह तो जनमानस का हर हिस्सा मानेगा ही कि एक देश में दो तरह के नियम नहीं हो सकते हैं। कई राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं, जबकि दूसरे संप्रदाय बहुसंख्यक बन गए हैं। ऐसे में किसी अल्पसंख्यक को दी जाने वाली समस्त सुविधाओं और सहूलियतों के हकदार वे क्यों नहीं?

अल्पसंख्यक

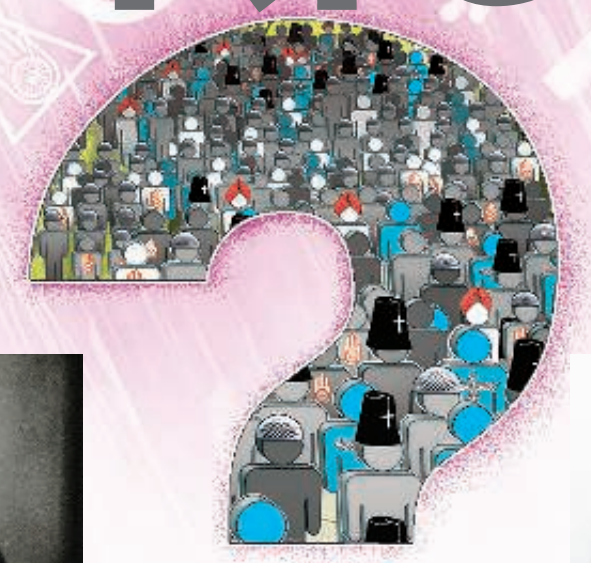

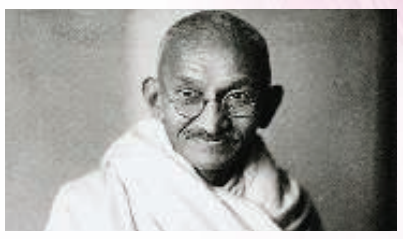

आपकी अल्पसंख्यक आवाज को भी खारिज नहीं किया जा सकता। सच हमेशा सच रहेगा।
महात्मा गांधी

हमेशा से ही रचनात्मक और समर्पित अल्पसंख्यकों ने दुनिया को बेहतर बनाया है।
मार्टिन लूथर किंग जूनियर

संविधान में विधान

भारतीय संविधान में 'अल्पसंख्यक' शब्द का इस्तेमाल सिर्फ चार बार ही किया गया है। खास बात यह है कि संविधान में इस शब्द के मायने नहीं तय किये गए हैं। नीति-निर्माण करने वाली देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद और विधानसभाओं में होने वाली बहस से यह समझा जा सकता है कि अल्पसंख्यक उस समुदाय को कहते हैं जो संख्या में उस क्षेत्र विशेष के बहुसंख्यक लोगों से कम होते हैं। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के मुताबिक अल्पसंख्यक उन समूहों को कहते हैं जिनकी उत्पत्ति का स्थान, भाषा या धर्म एक जैसे हैं, लेकिन उस क्षेत्र के रहने वाले लोगों से अलग हैं। 1950 में संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार पर आधारित पुस्तक में अल्पसंख्यक को गैर प्रमुख समूह बताया है जिनका धर्म और भाषाई संस्कार वहां के बहुसंख्यक लोगों से अलग है।

देश के अल्पसंख्यक

नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज एक्ट, 1992 के अनुच्छेद 2(सी) के मुताबिक मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन समुदायों को देश में अल्पसंख्यक का दर्जा मिला है।

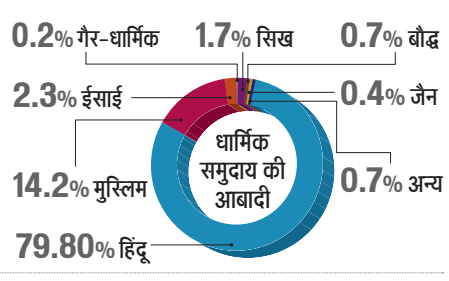

सुनिश्चित हैं विशेषाधिकार

अनुच्छेद 29 और 30 की शुरुआती भूमिका और अनुच्छेद 30 की धारा (1) और (2) में इसका जिक्र मिलता है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है। इसके मुताबिक देश के किसी भी क्षेत्र में रहने वाले किसी भी समुदाय को अपनी भाषा, शैली और परंपराओं के संरक्षण का अधिकार होगा। किसी नागरिक को अपने धर्म, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर राज्य सरकार द्वारा संचालित या राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश देने से मना नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30(1) में अल्पसंख्यकों को दो अधिकार दिए गए हैं। ये हैं अपनी मर्जी के शिक्षण संस्थान का निर्माण करना और उन्हें संचालित करना। अनुच्छेद 30(2) यह सुनिश्चित करता है कि कोई सरकार शिक्षण संस्थानों को मदद देने में इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगी कि वह संस्थान किसी भाषागत या धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित है। इस अनुच्छेद के तहत देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दी गई है।

अदालतों की व्याख्या

देश के संविधान, कानून या किसी भी उपबंध में अल्पसंख्यक की कोई परिभाषा नहीं तय की गई है। सिर्फ अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। शायद व्यापक स्तर पर अल्पसंख्यक के शाब्दिक मायने को ही सब जगह आत्मसात किया गया हो। लेकिन बदली परिस्थितियों में जब इसे परिभाषित करने की दरकार जताई जा रही है तो कई मामलों में इसके निहितार्थ की बात की गई।

केरल शिक्षा बिल, 1958 में सुप्रीम कोर्ट ने मुद्दा उठाया कि यह कहना आसान है कि अल्पसंख्यक समुदाय उसे कहेंगे जिसकी संख्या 50 फीसद से कम है, लेकिन यहां सवाल उठता है कि यह 50 फीसद कितने में से गिना जा रहा है। क्या यह पूरे देश की आबादी है या किसी राज्य का भाग या किसी छोटे इलाके का? देश में ऐसा मुमकिन है कि कोई समुदाय किसी राज्य में बहुसंख्यक है, लेकिन पूरे देश के अनुपात में वह अल्पसंख्यक हो जाए। कोई समुदाय किसी शहर में बहुसंख्यक हो, लेकिन राज्य में अल्पसंख्यक हो जाए।

केरल शिक्षा बिल में उठे सवाल का जवाब पंजाब की गुरु नानक यूनिवर्सिटी मामले में मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय को पूरे देश की आबादी के अनुपात में अल्पसंख्यक नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने कहा कि किसी समुदाय को उस क्षेत्र के कानून के हिसाब से अल्पसंख्यक तय किया जाएगा, जिस पर इसका प्रभाव पड़ेगा। अगर राज्य के कानून पर असर पड़ता है, तो राज्य की आबादी के अनुपात में समुदाय का अल्पसंख्यक होना या न होना तय किया जाएगा।

2002 के टीएम पाई फाउंडेशन मामले में सुप्रीम कोर्ट की आठ जजों की पीठ ने यह निर्णय दिया कि राज्य की आबादी के अनुपात में ही किसी समुदाय को अल्पसंख्यक मानने या ना मानने का फैसला किया जाएगा। कोई भी समुदाय जो उस राज्य की आबादी में पचास फीसद से कम हिस्सेदारी रखता है, उसे अल्पसंख्यक माना जाएगा। लिहाजा नगालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू और कश्मीर और पंजाब में हिंदुओं की संख्या के हिसाब से उन्हें अल्पसंख्यक माना जाना चाहिए।

किसी समुदाय की अधिकारहीनता या समाज से उन्हें अलग-थलग किए जाना, यह अल्पसंख्यक स्टेटस तय करने के दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इसी के चलते सच्चर कमेटी ने मुस्लिमों के गैर-प्रभावी अस्तित्व की बात रखी। इसके जवाब में इलाहाबाद कोर्ट ने 2006 में फैसला दिया कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं हैं।

1971 के डीएवी कॉलेज मामले में कोर्ट ने फैसला दिया कि पंजाब में हिंदुओं को अल्पसंख्यक माना जाए। लेकिन पंजाब और हरियाणा ने यह नहीं माना कि वहां सिख बहुसंख्यक हैं।

अहमदाबाद सेंट जेवियर्स कॉलेज बनाम गुजरात सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही किसी शिक्षण संस्थान को किसी खास समुदाय ने स्थापित किया है और संचालित कर रहा है, वह संस्थान किसी दूसरे समुदायों के छात्रों को दाखिला देने से मना नहीं कर सकता।

जैन समुदाय को पहले ही उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में अल्पसंख्यक का दर्जा मिला है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक समिति ने भी दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव रखा था। जब इस समुदाय ने केंद्र सरकार से भी यही दर्जा मांगा तो 2005 के बाल पाटिल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय का सिद्धांत बनाते समय संविधान निर्माताओं ने सोच विचार नहीं किया। हमारा समाज जो कि समानता को मौलिक अधिकार मानता है, उसमें से अल्पसंख्यक-बहुसंख्यक और तथाकथित अग्रणी और पिछड़ी जातियों को खत्म कर दिया जाना चाहिए।

जनमत

हां 95% | 05% नहीं

क्या राष्ट्रीय की जगह राज्यवार आबादी के आधार पर अल्पसंख्यकों को परिभाषित करने का समय आ चुका है?

हां 92% | 08% नहीं

क्या जिन राज्यों में हिंदुओं की संख्या बहुत कम है, वहां वे भी अल्पसंख्यकों की सहूलियतों-सुविधाओं के हकदार हैं?

आपकी आवाज

बहुसंख्यक-अल्पसंख्यक की राजनीति ने देश को बर्बाद कर दिया है। राजनीतिक लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से इसका प्रयोग करते रहे हैं। हमारा संविधान बराबरी की बात करता है। फिर भेदभाव क्यों। **राकेश कुमार**

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। जब देश का प्रधानमंत्री ऐसी बात कहकर खाई पैदा करेगा तो इस देश का भगवान ही मालिक है। **निहाल सिंह**

बहुसंख्यक हिंदुओं की किसी भी नेता को चिंता नहीं है। अपनी राजनीति चमकाने के लिए हर कोई अल्पसंख्यकों का राग अलापता रहता है। लेकिन पाकिस्तान जैसे देश में हिंदू अल्पसंख्यक हैं उनकी चिंता किसी को नहीं है। **संग्राम सिंह**

कायदे से अल्पसंख्यक-बहुसंख्यक के पचड़े में पड़े बगैर आर्थिक आधार पर लोगों की जरूरतों और सुविधाएं तय की जाएं **विभूति पांडे**

यह सही है कि कई मामलों में मुसलमान बहुत पीछे हैं। और अल्पसंख्यक के नाम पर दी जाने वाली सुविधाएं जरूरतमंदों तक नहीं पहुंचती हैं, जिससे इस समुदाय में भी समानता की खाई बढ़ रही है। **जफरुद्दीन**

जिले के साथ शुरू होता बहुसंख्यक बनने का खेल

हरेंद्र प्रताप
पूर्व सदस्य, बिहार विधानपरिषद

प्रशासन की दृष्टि से राज्य के बाद जिला एक महत्वपूर्ण इकाई है। जिस क्षेत्र विशेष में ईसाई और मुस्लिम बहुमत में होते है, दबाव डालकर पहले उसे जिला बनवाते है और फिर अपने पंथ वालों को महत्वपूर्ण पदों पर बैठा देते है। जो उनके ही हिसाब से रीति-नीति तैयार करते हैं।

अल्पसंख्यक शब्द की कोई परिभाषा या व्याख्या संविधान में नही है। इसका शाब्दिक अर्थ है, 'संख्या बल के आधार पर दूसरे की तुलना में कम संख्या वाला'। वर्तमान में देश में अल्पसंख्यक शब्द का ज्यादातर इस्तेमाल मुसलमान और ईसाइयों के लिए ही होता है। आपातकाल के समय श्रीमती इंदिरा गांधी का 20 सूत्रीय कार्यक्रम मुसलमानों को ध्यान में रखकर ही तैयार हुआ था। 1986 की नई शिक्षा नीति में प्रस्तावित अल्पसंख्यक बहुल 40 जिलों की सूची भी मुसलमानों की जनसंख्या को ध्यान में रखकर तैयार हुई थी।

2011 की जनगणना के अनुसार 28 राज्यों में से सात (जम्मू और कश्मीर, पंजाब, अरुणाचल, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम तथा मेघालय) और सात केंद्र शासित प्रदेशों में से एक लक्षद्वीप में हिंदू अल्पमत में है। हिंदू अल्पमत वाले इन आठ में से तीन (नगालैंड, मिजोरम तथा मेघालय) में ईसाई और दो (जम्मू और कश्मीर, लक्षद्वीप) में मुस्लिम जबकि पंजाब में सिख बहुमत में है। 2011 की ही जनगणना के अनुसार देश के कुल 640 जिलों में से 110 में हिंदू अल्पसंख्यक हो चला है।

1961 में मेघालय में ईसाई जनसंख्या 35.21 प्रतिशत थी जो 2011 में बढ़कर 74.59 प्रतिशत हो गयी है। 1971 में अरुणाचल प्रदेश में ईसाई कुल जनसंख्या में 0.78 प्रतिशत थे जो 2011 में बढ़कर 30.26 प्रतिशत हो गये है।

अरुणाचल की तरह ही 1951 में मणिपुर में हिंदू 60.12 तथा ईसाई 11.84 प्रतिशत थे । 2011 की जनगणना में हिंदू 60.12 प्रतिशत से घटकर 41.38 तथा ईसाई 11.84 प्रतिशत से बढ़कर 41.28 प्रतिशत हो गये हैं। ईसाई जनसंख्या में हो रही इस अप्रत्याशित वृद्धि के आधार पर कहा जा सकता है कि निकट भविष्य में मेघालय, मिजोरम नगालैंड के साथ ही साथ अरुणाचल और मणिपुर भी ईसाई बहुल प्रदेश होने वाले है।

देश में मुस्लिम और ईसाई बहुल्य प्रांत/जिला/प्रखंड बनाने हेतु कई षड्यंत्र चल रहे है। उसमें प्रमुख है क्षेत्र विशेष में योजनाबद्ध तरीके से पंथ परिवर्तन कराना, बाहर से मुसलमानों और ईसाइयों को लाकर बसाना या हिंदुओं को भागने हेतु मजबूर करना।

हरियाणा में गुरुग्राम और फरीदाबाद के मुस्लिम बहुल हिस्से को काटकर पहले मेवात जिला बनवाया और अब नाम बदलकर उसे नूंह कर दिया। 1990 में बिहार में श्री लालू प्रसाद जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने मुस्लिम बहुल अनुमंडल किशनगंज को जिला बना दिया। पश्चिम बंगाल में दिनाजपुर जिले को उत्तरी और दक्षिणी में विभाजित कर दिया गया। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तरी दिनाजपुर जिले की मुस्लिम आबादी 49.92 प्रतिशत थी जो इन आठ वर्षों में मुस्लिम बहुल में बदल गई है।

नए मुस्लिम बहुल जिले बनाने का खुला खेल असम में खूब चला। 1961 में असम में कुल 7 जिले थे और सभी जिलों में हिंदू बहुमत में थे। 2001 में असम में जिलों की संख्या बढ़कर 23 हो गयी, जिसमें मुस्लिम बहुल जिले 6 हो गये। 2011 की जनगणना में असम के 27 जिलों में से 9 जिले मुस्लिम बहुल हो गये है। असम में मुस्लिम घुसपैठ के कारण जहां मुस्लिम बहुल्य जिलों की संख्या बढ़ रही थी, वहीं हिंदू बहुल जिलों को काटकर नये जिले कैसे बन रहे थे इसका सबसे प्रमाण बोंगाईगांव जिला है। 2001 की जनगणना में बोंगाईगांव जिले में हिंदू आबादी 59.17 प्रतिशत थी जो 2011 में घटकर 48.61 प्रतिशत रह गयी यानी बोंगाईगांव भी अब मुस्लिम बहुल जिला हो गया है। मुसलमान ही नही, ईसाई लॉबी ने भी झारखंड प्रदेश के रांची जिला के सिमडेगा अनुमंडल को प्रथम ईसाई बहुल जिला बनवाने में सफलता प्राप्त कर ली है।

मुस्लिम और ईसाई बहुल प्रांत/जिला/प्रखंड में हिंदुओं की स्थिति कैसी होती है, इसका ताजा मामला पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आ रहा है। मेरठ में मुसलमानों से भयभीत हिंदुओं ने अपने मकान के बाहर 'मकान बिकाऊ है' की तख्ती लटका दी।

जो लोग जम्मू-कश्मीर में कश्मीरियत और इंसानियत की बात करते हैं, उन्हें यह पता होना चाहिए कि 1990 में घाटी से लाखों हिंदुओं के पलायन के बाद भी घाटी के अल्पसंख्यक हिंदू और सिख भय से अपने साथ घर की महिलाओं को रखने का साहस नहीं जुटा पाते हैं। 2011 में घाटी में कुल हिंदू जनसंख्या 1,68,833 थी जिसमें महिलाओं की संख्या 15764 यानी मात्र 9.33 प्रतिशत ही थी।

1990 में मुस्लिम बहुल जम्मू-कश्मीर से जैसे हिंदुओं का पलायन हुआ उसी प्रकार मुस्लिम बहुल केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप से भी हिंदुओं का पलायन हुआ है। लक्षद्वीप में 1991 में 2339 हिंदू थे जो 2011 में घटकर 1788 रह गये है। इस 1788 में भी महिलाओं की संख्या मात्र 185 है। मुस्लिम बहुल ही नही, ईसाई बहुल मिजोरम से भी अल्पसंख्यक हिंदुओं का पलायन हुआ है। मिजोरम में 1981 में 35,245 हिंदू थे जो 2011 में घटकर 30,136 हो गये हैं।

समय आ गया है कि 'अल्पसंख्यक कौन' का आधार कम से कम प्रखंड की जनसंख्या को मानकर तय किया जाये। भारत में जिस तरह मुसलमानों की स्थिति के अध्ययन हेतु सच्चर आयोग गठित किया गया था उसी प्रकार प्रदेश/जिला/प्रखंड में गैर मुस्लिम और गैर ईसाई अल्पसंख्यक के ऊपर हो रहे मुस्लिम और ईसाई जुल्म की जांच के लिए एक आयोग का गठन हो। और उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए।

देश के 640 जिलों में से 110 में अल्पसंख्यक हुआ हिंदू

राज्य		2011 की जनगणना							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	जे एंड के	22	4	16			1		1
2	हिमाचल	12	11				1		
3	पंजाब	20	3			15			2
4	हरियाणा	21	20	1					
5	उत्तर प्रदेश	71	70	1					
6	बिहार	38	37	1					
7	सिक्किम	4	3				1		
8	अरुणाचल	16	3		1		1	3	8
9	नगालैंड	11			11				
10	मणिपुर	9	4		5				
11	मिजोरम	8			8				
12	मेघालय	7			7				
13	असम	27	18	9					
14	प बंगाल	19	16	2					1
15	झारखंड	24	18		1			2	3
16	लक्षद्वीप	1		1					
17	केरल	14	9	1					4
18	तमिलनाडु	32	31						1
19	अंडमान	3	2		1				
देश		640	530	32	34	15	4	5	20

1.प्रदेश में कुल जिले; 2.हिंदू बहुल; 3.मुस्लिम बहुल; 4.ईसाई बहुल; 5.सिख बहुल; 6.बौद्ध बहुल; 7.अन्य (यहूदी,पारसी तथा जनजाति/आदिवासी); 8.किसी को बहुमत नही।

Downloaded from: www.iascgl.com

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
रविवार 28 जुलाई 2019

दैनिक जागरण

विचार कर्म का बीज है

सत्ता के प्रयोग

लंबे समय तक राजनीतिक अस्थिरता से जूझते कर्नाटक में आखिरकार येदियुरप्पा के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बन गई। येदियुरप्पा ने चौथी बार कर्नाटक की सत्ता संभाली है। चूंकि वह अभी तक एक बार भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके हैं इसलिए यह सवाल उनका पीछा कर रहा है कि आखिर उनकी सरकार कब तक चलेगी? यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है, क्योंकि भाजपा की सरकार तब बन सकी जब कांग्रेस और जद-एस के एक दर्जन से अधिक विधायकों ने इस्तीफा दिया। भाजपा को आगे इन विधायकों को उपकृत करना पड़ सकता है और ऐसी स्थिति में उसके अपने नेताओं में असंतोष व्याप्त हो सकता है। स्पष्ट है कि येदियुरप्पा सरकार को न केवल अस्थिरता की आशंका को दूर करना होगा, बल्कि जनता की अपेक्षाओं पर खरा भी उतरना होगा। यह आसान काम नहीं, क्योंकि कुमारस्वामी सरकार ने कुल मिलाकर राज्य का अहित ही किया है। वास्तव में वह बनी ही इसलिए थी ताकि उसके और साथ ही कांग्रेस के संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति हो सके।

कुमारस्वामी सरकार के पतन और येदियुरप्पा सरकार के गठन के बाद जद-एस और कांग्रेस की ओर से ये संकेत दिए जा रहे हैं कि दोनों दलों की दोस्ती भी समाप्त होने जा रही है। ऐसे संकेत यही बताते हैं कि जद-एस और कांग्रेस की दोस्ती केवल सत्ता की साझेदारी के लिए ही थी। अब यह और अच्छे से स्पष्ट हो रहा है कि कर्नाटक में 14 महीने पहले कुमारस्वामी सरकार के गठन के बाद तमाम विपक्षी दलों की ओर से एकजुटता का जो प्रदर्शन किया गया था वह वास्तव में अवसरवादी राजनीति का उदाहरण ही था। शायद इसी नकली एकजुटता के कारण ही राष्ट्रीय स्तर पर महागठबंधन नहीं बन सका। कांग्रेस और जद-एस ने जो कुछ कर्नाटक में किया वही उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा ने भी किया। इसके पहले बिहार में जद-यू और राष्ट्रीय जनता दल ने भी ऐसा ही किया था। ये बेमेल गठबंधन थे और इन्हें कामयाब नहीं होना था। समस्या यह है कि ऐसे बेमेल और अवसरवादी गठबंधन बनने का सिलसिला कायम रह सकता है, क्योंकि कई राजनीतिक दलों के लिए सत्ता ही सब कुछ है। इसी कारण आज देश के अधिकांश राजनीतिक दलों की विचारधारा का कोई अता-पता नहीं। इसे राजनीति नहीं कहा जा सकता कि राजनीतिक दल सत्ता पाने के लिए एक साथ आ जाएं और सत्ता से वंचित होने पर छिटक जाएं। यदि यह सोचा जा रहा है कि दलबदल रोधी नियम और सख्त करने से अवसरवादी राजनीति का सिलसिला थम जाएगा तो यह सही नहीं। यह सिलसिला तो तब थमेगा जब मूल्यों और मर्यादा की राजनीति को महत्व मिलेगा।

जवाबदेही की जरूरत

उत्तराखंड में सरकारी महकमों पर सरकार का नियंत्रण नहीं है या फिर उन्हें मनमानी की खुली छूट मिली हुई है। यह यक्ष प्रश्न बना हुआ है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस और कामकाज में पारदर्शिता के दावे को सरकार लगातार दोहरा रही है, लेकिन जो तस्वीर सामने आ रही है, वह इस चर्चा को जन्म देती दिख रही है कि सरकार के दावों में वाकई में कितना दम है। उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में खुला अनियमितताओं का पिटारा इसका ताजा उदाहरण है। नियुक्तियां, सामान की खरीद फरोख्त और दूसरी गड़बड़ियों को लेकर विवि चर्चाओं में है। निजी कॉलेजों के संबद्धता शुल्क को लेकर भी बड़े पैमाने पर खामियां सामने आई हैं। अधिकांश निजी संस्थानों से अपेक्षाकृत कम शुल्क जमा कराने की बात सामने आई है। यही नहीं, परास्नात्तक कक्षाओं के लिए विषयों के हिसाब से शुल्क जमा नहीं कराया जा रहा है। बात यहीं खत्म नहीं होती, एक रोज पहले एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ कि आयुर्वेद विवि में कुल सचिव पद पर मृत्युंजय मिश्रा की ताजपोशी नियम-कानून ताक पर रखकर की गई। इस 'चहेते' अधिकारी पर इतने मेहरबान कि ग्रेड पे भी 6000 से सीधे 10000 कर दिया। राज्य कैबिनेट में इस मसले को रखा ही नहीं गया। कार्मिक, वित्त, गोपन, न्याय तक से इस प्रस्ताव पर राय लेने की जरूरत नहीं समझी गई। यानी एक शख्स के लिए राजकाज व्यवस्था की ही बलि चढ़ा दी गई। हैरानी इस बात कि राज्य सरकार को तीन साल बाद इसका पता चला। सहज ही समझा जा सकता है कि आयुर्वेद विभाग में कामकाज किस तरह चल रहा है और मककमों पर सरकार की कितनी पकड़ है। यह दीगर बात है कि अब सरकार ने इस अधिकारी की कुल सचिव पद पर की गई नियुक्ति को निरस्त कर उन्हें मूल विभाग में वापस भेज दिया है, लेकिन सवाल अपनी जगह खड़ा है कि अभी तक क्यों इस पर पर्दा पड़ा रहा? सरकार ने किरकिरी से बचने के लिए अधिकारी को मूल तैनाती पर वापस भेजने का आदेश तो कर दिया, लेकिन यह जानने की कोशिश अभी भी नहीं की कि आखिर यह सब कैसे हुआ और किसने किया? यह व्यवस्था पर सीधे-सीधे प्रहार है, फिर क्यों सरकार इतने बड़े घपले के बाद भी जिम्मेदारों को बेनकाब करने से परहेज कर रही है? यह सच भी सामने आना चाहिए कि ऐसा करना सरकार की मजबूरी है या फिर जनता की आंखों में धूल झोंकना चाहती है।

खतरों से खेलता अमेरिका

संजय गुप्त

अमेरिका को यह समझना होगा कि सेना के दबदबे वाले पाकिस्तान को प्रोत्साहन देने से दक्षिण एशिया में शांति का मार्ग प्रशस्त होने वाला नहीं है

अवधेश राजपूत

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान से मुलाकात के समय जब यह दावा किया कि दो सप्ताह पहले भारतीय प्रधानमंत्री ने उनसे कश्मीर पर मध्यस्थता करने को कहा था तो देश-विदेश में जोरदार प्रतिक्रिया हुई। ट्रंप के इस बेबुनियाद दावे पर भारत की अंदरूनी राजनीति में भूचाल सा आ गया। यह भूचाल इसके बावजूद आया कि 1972 के शिमला समझौते के बाद से ही कश्मीर पर देश की यही नीति रही है कि यह भारत-पाक के बीच का द्विपक्षीय मसला है। भारत अपनी इस नीति पर बार-बार जोर देता रहा है, क्योंकि पाकिस्तान और साथ ही कुछ कश्मीरी नेता इसके लिए तत्पर रहते हैं कि कश्मीर पर कोई देश मध्यस्थता करे। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र के साथ अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर का मसला उठाता रहता है, जबकि लाहौर समझौते में भी इस मसले को आपसी बातचीत से ही सुलझाने की बात की गई थी। अमेरिका कई बार यह इच्छा जता चुका है कि अगर भारत-पाक चाहें तो वह कश्मीर पर मध्यस्थता करने को तैयार है। खुद ट्रंप ने 2016 में ऐसी मंशा जाहिर की थी, लेकिन इस बार वह जरूरत से ज्यादा बोल गए। इस पर हैरानी नहीं, क्योंकि वह असत्य और अर्द्धसत्य बयान देने के लिए ही जाने जाते हैं। वह राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मसलों पर न जाने कितनी बार झूठ बोल चुके हैं। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ट्रंप एक दिन में औसतन 12 झूठ बोलते हैं। वह इमीग्रेशन, विदेश नीति, अर्थव्यवस्था आदि पर भ्रामक बयान देने के लगभग आदी हो चुके हैं। एक बार वह यह कह गए थे कि जर्मनी नाटो को मात्र एक प्रतिशत अंशदान देता है जबकि उसका अंशदान 15 प्रतिशत है। ट्रंप 172 बार यह दावा कर चुके हैं कि वह अमेरिका-मेक्सिको के बीच दीवार बनाने का काम शुरू कर चुके हैं जबकि वहां पहले से मौजूद फेंसिंग की मरम्मत भर हो रही है। ट्रंप के बड़बोलेपन के चलते अमेरिकी विदेश विभाग को कई बार असहज होना पड़ा है। ऐसा बीते दिनों भी तब हुआ जब ट्रंप ने यह कह दिया कि मोदी ने उनसे कश्मीर पर मध्यस्थता का आग्रह किया था। इस पर अमेरिकी विदेश विभाग को यह स्पष्टीकरण देना पड़ा कि कश्मीर पर उसका नजरिया वही है जो पहले था। इसके बावजूद संसद में हंगामा मचा। कांग्रेस समेत कुछ अन्य दलों ने प्रधानमंत्री से बयान देने की मांग की। इन दलों ने विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से ट्रंप के दावे को खारिज किए जाने के बाद भी यह मांग की। इन दलों ने इसकी भी अनदेखी की कि विदेश मंत्रालय ने तत्काल ही ट्रंप के दावे का खंडन कर दिया था। इसके अलावा अमेरिका के विपक्षी दल के एक प्रमुख सांसद ने ट्रंप के दावे को लेकर भारतीय राजदूत से माफी भी मांगी थी।

ऐसा नहीं हो सकता कि विपक्षी दलों को इसका अहसास न हो कि ट्रंप झूठे बयान देते रहते हैं और उनके ऐसे बयानों को इसलिए गंभीरता से नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वह कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। विपक्षी दलों ने ट्रंप के बयान को तूल देकर यही स्पष्ट किया कि वे सरकार को असहज करने की ताक में रहते हैं। इसमें हर्ज नहीं, लेकिन कम से कम उन्हें विदेश नीति पर तो दलगत राजनीति से परे रहना चाहिए। संसद में हंगामा करने वाले दल इससे अनभिज्ञ नहीं हो सकते कि ओसाका में ट्रंप और मोदी की मुलाकात के बाद जारी वक्तव्य में उस बात का कोई जिक्र नहीं था जिसका दावा अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया। ट्रंप ने इमरान से बात करते हुए यह दावा भी किया कि वह एक करोड़ अफगानियों को मारना नहीं चाहते, नहीं तो दस दिन के अंदर अफगानिस्तान युद्ध जीत सकते हैं।

9-11 के बाद अलकायदा के खिलाफ हमले के बाद से ही अमेरिकी सेनाएं अफगानिस्तान में हैं। अल कायदा तो पस्त पड़ चुका है, लेकिन उन्हें संरक्षण देने वाला तालिबान अफगानिस्तान की स्थिरता के लिए खतरा बना हुआ है। तालिबान को पाकिस्तान का संरक्षण और समर्थन हासिल है। अमेरिका में अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सियासी सक्रियता बढ़ गई है। ट्रंप दोबारा यह चुनाव जीतना चाहते हैं। इसके लिए वह अमेरिकी जनता को लुभाने का हर संभव जतन कर रहे हैं। ट्रंप चाहते हैं कि पाकिस्तान तालिबान को समझौते के लिए राजी करे ताकि अमेरिकी सेनाएं अफगानिस्तान से लौट सकें। अपने इस चुनावी वादे को पूरा करने के लिए ट्रंप अफगानिस्तान के साथ दक्षिण एशिया को खतरे में डाल रहे हैं। अगर तालिबान को अफगानिस्तान में हावी होने का मौका मिला तो वहां की सरकार को सत्ता छोड़नी पड़ सकती है और वहां वैसी ही अस्थिरता व्याप्त हो सकती है, जैसी 2000 के दशक में थी। पता नहीं अमेरिका का तालिबान से समझौता हो पाता है या नहीं, लेकिन इसका अंदेशा अवश्य है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सेनाओं की वापसी के बाद वहां वैसी ही स्थिति बन सकती है जैसी इराक या फिर लीबिया में बनी। एक व्यापारी होने के नाते ट्रंप मात्र अपना हित देख रहे हैं। चूंकि अमेरिकी जनता का एक बड़ा तबका इससे खुश नहीं कि अमेरिका अब तक अफगानिस्तान में उलझा हुआ है इसलिए ट्रंप यह जानते हुए भी जल्दबाजी दिखा रहे हैं कि अफगान-पाक सीमा पाकिस्तानी संरक्षित आतंकियों का गढ़ बनी हुई है।

इमरान खान के समक्ष ट्रंप ने कश्मीर को लेकर जो बयान दिया उसे पाकिस्तान भले ही अपनी जीत के तौर पर देखे, लेकिन यह तय है कि भारत अपने रवैये से डिगने वाला नहीं। कश्मीर, अफगानिस्तान जैसे मसलों पर चर्चा के कारण ही इमरान खान के साथ पाक सेना प्रमुख और आइएसआइ प्रमुख भी अमेरिकी यात्रा पर थे। यह पाकिस्तानी शासन पर सेना के दबदबे का प्रमाण है। अमेरिका से लौटने पर इमरान खान का जोरदार स्वागत इसीलिए हुआ ताकि आम पाकिस्तानी जनता को यह संदेश दिया जा सके कि वह कश्मीर और अफगानिस्तान जैसे मामलों पर अमेरिका का रुख एक हद तक अपने पक्ष में करने में कामयाब रहे। यह संदेश देने की भी कोशिश की गई कि कश्मीर पर भारत को झटका लगा और साथ ही अफगानिस्तान में उसका प्रभाव कम होने वाला है।

पाकिस्तान कुछ भी जाहिर करे, अमेरिका और अन्य देशों को यह समझना होगा कि सेना के दबदबे वाली पाक सरकार को प्रोत्साहन देकर दक्षिण एशिया में शांति का मार्ग प्रशस्त होने वाला नहीं है। आज जो कश्मीर में अशांति है उसके पीछे पाकिस्तान पोषित आतंकी ही हैं। पाकिस्तान ने अभी तक खुद को आतंकवाद से अलग नहीं किया है। इसकी पुष्टि खुद इमरान खान के इस बयान से होती है कि पाकिस्तान में अभी भी 30-40 हजार आतंकी मौजूद हैं। उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि इतने आतंकियों पर वह कैसे काबू पाएंगे? अमेरिकी राष्ट्रपति अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण पाकिस्तान की हकीकत से मुंह मोड़ सकते हैं, लेकिन भारत के हित में यही है कि वह न केवल सतर्क रहे, बल्कि अमेरिका को इसके लिए आगाह भी करे कि पाकिस्तान समर्थित तालिबान से समझौता आतंकवाद को नए सिरे से उभारने का काम कर सकता है।

response@jagran.com

चमत्कारी असर वाला झूठ

हास्य-व्यंग्य

संतोष त्रिवेदी

यह झूठ के बढ़ते प्रभाव का ही परिचायक है कि वह 'ग्लानि' को भी 'ग्लैमर' में तब्दील कर देता है

हमें झूठे लोग बेहद पसंद हैं। वे बड़े निर्मल-हृदय होते हैं। कभी भी अपने झूठे होने का घमंड नहीं करते। ये तो सच्चे लोग हैं जो अपनी सच्चाई की डींगें मारते फिरते हैं। झूठा अपने झूठे होने का स्वांग नहीं करता। खुलकर और पूरे होशो-हवास में बोलता है। वह खुद इस बात का प्रचार नहीं करता। उसके 'प्रशंसक' ही कर देते हैं। कहते हैं सच बोलने के लिए बड़े कलेजे की जरूरत होती है, पर झूठ बोलने के लिए महज एक भेजे की। यह भेजा बिना शोर किए अपने नित्य-कर्म में तल्लीन रहता है।

झूठ बोलने वाला बिल्कुल तनाव-रहित होता है। मौका पड़ते ही अतिरिक्त लचीला हो जाता है। सच की तरह उसमें अकड़ नहीं होती। इसीलिए सच टूटता है और झूठ कायम रहता है। कहते हैं कि झूठ के पांव नहीं होते, पर झूठ एक दांव तो हो ही सकता है। जिस तरह झूठ के चलने की संभावना होती है, वैसे ही दांव की भी। चल गया तो चल गया नहीं तो रणनीति तो है ही। झूठ अपने सच होने के लिए संदेह को साथी बनाता है। शायद इसीलिए 'बेनीफिट ऑफ डॉउट' सच के बजाय झूठ को मिलता है। वैसे भी सच कड़वा होता है। न उगलते बनता है न निगलते। झूठ बेहद सुविधाजनक होता है। जुबान पर रखते ही मिसरी-सा घुल जाता है। सुनने में भी अच्छा लगता है। झूठ बोलने का लंबा अनुभव होने पर जुबान लड़खड़ाने का खतरा नहीं होता।झूठ को किसी के समर्थन की दरकार नहीं होती। सच जहां सबूत ढूंढता फिरता है, झूठ खुद ही सबूत होता है। झूठ के पास अपनी ताकत होती है। कमजोर आदमी उसे संभाल भी नहीं सकता। सच डरा-सहमा रहता है जबकि झूठ खुलेआम दहाड़ता है। इसीलिए सच को उगलवाने की जरूरत होती है जबकि झूठ को केवल बोलने की। महाबली जो बोलता है, वही सच होता है। झूठ बोलना राजसी लक्षण है। झूठा होना शर्म का नहीं योग्यता का प्रतीक है। यदि आप अपने तईं झूठ भी नहीं बोल सकते तो कतई नाकारा हैं। अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो एक बार बोलकर रुकें या ठिठकें नहीं। लगातार बोलते रहें जब तक वह सच के रूप में स्थापित न हो जाए। इससे एक फायदा यह भी होगा कि सच और झूठ के बीच जो बरसों से खाई बनी है, वह टूटेगी। समाज से भेदभाव भी दूर होगा।

राजनीति में अपनी भारी सफलता से उत्साहित होकर झूठ ने सिनेमा और साहित्य में भी अपनी स्थायी शाखाएं खोल दी हैं। सिनेमा से जहां एक 'चिट्ठी' का रूप धरकर वह क्रांति का बिगुल बजाता है, वहीं भाषा की 'ग्लानि' मुंह पर थोपकर वह साहित्य में संवेदना ले आता है। ऐसे में सच कहीं कोने में दुबका हुआ अपने होने की 'ग्लानि' को छिपाता फिरता है। यह झूठ के बढ़ते प्रभाव का ही परिचायक है कि वह 'ग्लानि' को भी 'ग्लैमर' में तब्दील कर देता है। झूठ इतना चमकदार होता है कि सड़क पर छुट्टा घूमते हुए घोड़े भी उसके अस्तबल में जा घुसते हैं। वहीं सच बड़ा अकेला और खाली-खाली होता है। इसमें किसी भी तरह की रचनात्मकता की गुंजाइश नहीं होती। सच के साहित्य में प्रवेश करते ही कविता अपठनीय हो जाती है। कहानी उदासी और ऊब पैदा करती है। जबकि झूठ के साथ मनचाहे प्रयोग किए जा सकते हैं। वह कल्पनाशक्ति को विस्तार कर साहित्य को समृद्ध करता है। झूठ को साहित्य, राजनीति और सिनेमा हर जगह से निकालकर देखिए, इतिहास मिटने की नौबत आ जाएगी। इसीलिए सच ठिकाने लगा है और झूठ के सब जगह ठिकाने हैं। यहां तक कि अब झूठ बोलने पर 'कौआ' भी नहीं काटता। उसे भी अपनी जान प्यारी है।

अब झूठ बोलना एक कला है। यह सबको आती भी नहीं। हो सकता है जल्द ही इसके 'अभ्यास केंद्र' खुल जाएं। वहां पर नई 'टेक्निक' पर काम हो। झूठ पर शोध-कर्म किए जाएं। इसके लिए समीक्षाओं और आलोचनाओं के रूप में बहुत बड़ा कच्चा माल हमारे साहित्य में पहले से ही उपलब्ध है। इस तरह साहित्य के 'बेगारों' को भी रोजगार की रोशनी दिखेगी और हमारे साहित्यकार 'चेलों' से भरपूर होंगे। झूठ की महिमा में हमने जो कुछ कहा, निरा झूठ है। झूठ इससे कहीं बहुत आगे पहुंच गया है। पहले झेंपकर झूठ बोला जाता था, अब पूरे सलीके के साथ। शायर वसीम बरेलवी ने इसी मौके को ताड़ते हुए कहा है, 'वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं ऐतबार न करता तो क्या करता!'

आप भी उनके कहे का एतबार क्यों नहीं करते?

response@jagran.com

तथ्य-कथ्य | इंस्टाग्राम पर प्रचार संबंधी प्रति पोस्ट से होने वाली कमाई

(आंकड़े करोड़ रुपये में)

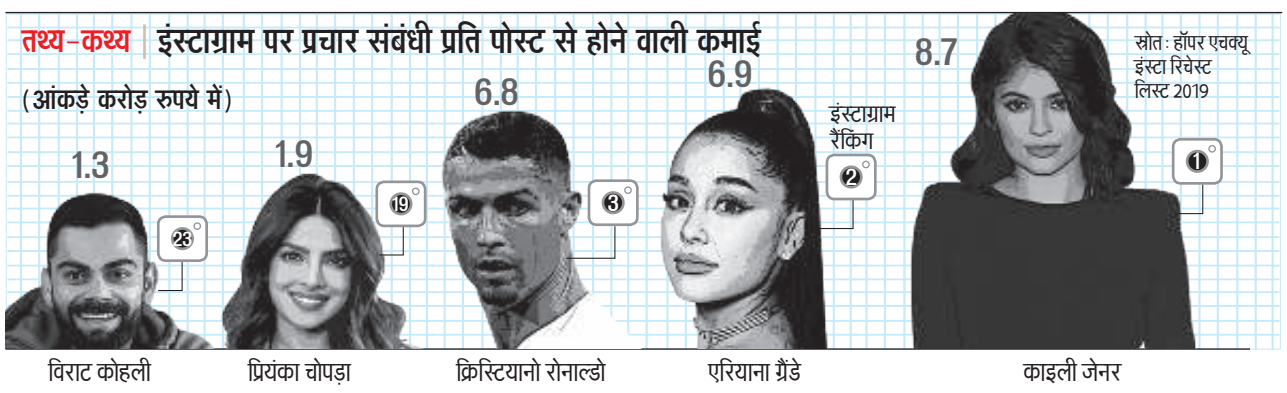

विराट कोहली | प्रियंका चोपड़ा | क्रिस्टियानो रोनाल्डो | एरियाना ग्रैंडे | काइली जेनर

ऊर्जा

संकट में अवसर

जिंदगी है तो सुविधाएं भी होंगी और असुविधाएं भी। मुश्किलें भी होंगी और आरामदायक स्थितियां भी। आरामदायक स्थितियां जहां अवसर समाप्त करती हैं, वहीं संकटपूर्ण स्थितियां अवसर की उत्पत्ति का मुख्य स्रोत होती हैं। विचारक स्टैनली अरनॉल्ड भी यह मानते हैं हर समस्या में उसके समाधान के बीज निहित होते हैं। प्रत्येक संकट में एक अवसर और नई खोज छिपी हुई होती है। बस इसके लिए संकट के समय धैर्य और सूझबूझ की आवश्यकता होती है, हालांकि यह काम मुश्किल है, क्योंकि परेशानी के समय अधिकांश लोग हड़बड़ा जाते हैं और अर्थ का अनर्थ कर लेते हैं। विरले लोग ही संकट से पार पाते हैं और जो इन्हें सुलझाना सीख लेते हैं, वे इतिहास रच देते हैं।

यह कोई नई बात नहीं है कि संकट से अवसर निकलते हैं। जब भी आपके सामने कोई संकट आए तो कागज कलम लेकर बैठ जाएं। अपने संकट को कागज पर लिखें। इसके बाद लाइन खींचकर एक जगह पर संकट से होने वाले बुरे परिणामों को लिखें और दूसरी ओर ये लिखें कि उस संकट में से क्या बेहतर आप निकाल सकते हैं। यह नीति अत्यंत कारगर है। एक बार अपनी इस नीति को अपनाने का प्रयास कीजिए, यकीन मानिए कागज पर लिखने के साथ-साथ आपका संकट न केवल बहुत कम हो जाएगा, बल्कि आप उन्हीं संकटों से नए अवसर निकाल लेंगे। संकट केवल उनके लिए ही परेशानी उत्पन्न करते हैं जो उनमें समस्याएं देखते हैं। जीवन में किसी भी कार्य एवं वस्तु को दो तरह से देखा जा सकता है-एक उनमें अच्छाई देखकर और दूसरा उनमें बुराई देखकर।

प्रत्येक कार्य में अच्छाई देखने वालों के लिए संकट सदा ही सफलता का मार्ग बनते हैं। यदि आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा कार्य करें जिसकी सराहना पूरे विश्व में हो तो अभी से संकट के मार्ग को तलाशना आरंभ कर दें, अवसर उसका अगला पड़ाव हैं और प्रगति मंजिल। जो लोग संकटों के बीच में रहकर मुस्कराना जानते हैं, वही आने वाले समय में बड़ी सफलता के हकदार होंगे।

रेनू सैनी

मंगल मिशन से बंधी उम्मीदें

मुकुल व्यास

मंगल पर मौजूद क्यूरिऑसिटी रोवर की तुलना में नासा के नए रोवर में और उन्नत उपकरणों से अहम सुराग मिल सकते हैं

एक नए अध्ययन के अनुसार अरबों वर्ष पहले मंगल पर जीवन था। तब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई थी। इस अध्ययन के अनुसार लाल ग्रह पर उल्कापिंडों का प्रहार बंद होने के बाद करीब 4.48 अरब वर्ष पहले मंगल पर हालात जीवन के लिए अनुकूल थे। 'नेचर जियोसाइंस' में प्रकाशित अध्ययन के लेखक डेसमंड मोसेर ने कहा कि संभव है कि 4.5 अरब से 3.5 अरब वर्ष के बीच वहां जीवन पनपा हो। करीब 4.2 से 3.5 अरब वर्ष पहले मंगल की सतह पर उल्कापिंडों के जो जबर्दस्त प्रहार हुए थे, उन्होंने ग्रह के भीतरी भागों से पानी बाहर निकालने की प्रक्रिया को तेज किया होगा।

इससे जीवन-निर्माण में सहायक क्रियाओं के लिए आधार तैयार हुआ होगा। इस अध्ययन से मंगल पर नमूने एकत्र करने के लिए उपयुक्त स्थल चुनने में मदद मिलेगी। इसके शोधकर्ताओं ने मंगल पर मौजूद प्राचीनतम खनिजों का विश्लेषण किया। उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और एटम प्रोब टोमोग्राफी के जरिये मंगल के उल्कापिंडों में मौजूद जिरकॉन और अन्य कणों की छानबीन की। यह माना जाता है कि मंगल की उत्पत्ति 4.6 अरब वर्ष पहले हुई और करीब छह करोड़ वर्ष बाद पृथ्वी अस्तित्व में आई। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत 3.5 अरब वर्ष पहले हुई थी। मंगल पर जीवन चिन्हों की तलाश के लिए नासा अगले वर्ष गर्मियों में एक नया 'रोवर' लाल ग्रह पर भेजेगा।

फिलहाल मंगल पर मौजूद क्यूरिऑसिटी रोवर की तुलना में इस नए रोवर के सभी उपकरण अधिक शक्तिशाली होंगे। नासा के इंजीनियर इस रोवर को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। पिछले दिनों उन्होंने रोवर में सुपरकैम मास्ट यूनिट फिट किया जो कि रोवर का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। सुपरकैम क्यूरिऑसिटी रोवर पर लगे केमकैम का उन्नत रूप है। इसमें रमन स्पेक्ट्रो-फोटोमीटर, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रो-फोटोमीटर और एक टेलीफोटो कैमरा शामिल है। इसे अमेरिका, फ्रांस और स्पेन के शोधकर्ताओं ने मिलकर तैयार किया है। नासा के विशेषज्ञों का कहना है कि सुपरकैम की मदद से रोवर मंगल के नमूनों का विश्लेषण करके उनमें जीवन के संकेत खोजने का प्रयास करेगा, भले ही ग्रह के जीवाणु लाखों वर्ष पहले मर चुके हों। सुपरकैम की विशेषता यह है कि वह छह मीटर की दूरी पर भी किसी नमूने पर फोकस कर सकता है। इससे पृथ्वी स्थित रोवर के नियंत्रकों को नया नमूना स्कैन करने के लिए रोवर में बार-बार समायोजन करने की जरूरत नहीं होगी।

उम्मीद है कि जल्द ही नासा शोधकर्ता रोवर पर नमूना एकत्र करने वाला सिस्टम लगाएंगे। यह उपकरण मंगल की मिट्टी से नमूने एकत्र करने के लिए 17 मोटरों का प्रयोग करेगा। ये नमूने रोवर में संभाल कर रखे जाएंगे। भविष्य में एक ऐसा मिशन मंगल पर भेजा जाएगा जो इन्हें एकत्र करके पृथ्वी पर लाएगा। मार्स 2020 रोवर फरवरी 2021 में मंगल पर पहुंचने के बाद जजीरो क्रेटर पर उतरेगा। लाल ग्रह की सतह पर सक्रिय होने के बाद यह रोवर उन जैविकों की तलाश करेगा, जिन्हें क्यूरिऑसिटी रोवर के उपकरण अभी तक पकड़ नहीं पाए हैं।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

राजरंग

सुरक्षा के लिए मंडराते नेताजी

राजनीति में नेताओं के इर्द-गिर्द अमला-फौज की मौजूदगी उनकी ताकत और प्रभाव का अहसास कराती है। इसमें जब नेता के पास केंद्र की ओर से मुहैया कराई गई कुछ विशेष श्रेणियों की सुरक्षा हो तो फिर बात ही एकदम अलग हो जाती है? कई नेता तो इस विशेष सुरक्षा श्रेणी को अपनी सियासत चमकाने का खास हथियार बनाने से गुरेज नहीं करते। सुरक्षा की समीक्षा के बाद हाल में केंद्र सरकार ने कई नेताओं की सुरक्षा हटा या घटा दी है। अब जब सियासत चमकाने का यह हथियार अचानक छिन जाए तो नेताजी का परेशान होना लाजिमी है। इसीलिए सुरक्षा से वंचित किए गए उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और बंगाल सरीखे कई राज्यों के ऐसे नेता इन दिनों गृहमंत्री अमित शाह से मिलने के लिए संसद भवन स्थित उनके कार्यालय के बाहर मंडराते नजर आते हैं। बहरहाल कमांडो के लिए गृहमंत्री के बाहर खुद कमांडो की तरह मंडराते रहने की नेताजी की कसरत कितनी कामयाब होगी यह तो वक्त ही बताएगा।

पहचान का संकट

सत्रहवीं लोकसभा में भारी बहुमत से जीतकर आई भाजपा में कई ऐसे सांसद भी हैं जो चुनावों से ठीक पहले अपनी मूल पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए और चुनाव भी जीत गए। इनमें से कुछ विधायक रहे हैं तो कुछ पहले भी लोकसभा में रह चुके हैं, लेकिन भाजपा के टिकट पर जीतकर आने के बावजूद संसद में उनके सामने पहचान का संकट बना हुआ है। चूंकि भाजपा में भी कई नेता पहली बार चुनाव में जीत कर आए हैं इसलिए ऐसे सांसदों में आपसी जान-पहचान नहीं के बराबर हैं। दूसरे दलों से भाजपा में आए ये नेता अपनी ही पार्टी में उपेक्षित सा महसूस कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने भी अब पार्टी में अपनी जान-पहचान बढ़ाने का तरीका निकाल लिया है। ये लोग अपनी पुरानी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मदद से भाजपा में अपनी पहचान के संकट को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं।

फिटनेस फ्रेंड्स

राजनीति के मंच पर सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्य भले ही एक दूसरे पर तीखी टिप्पणी करते हों, लेकिन एक जगह ऐसी भी है जहां वे आपस में प्रतिस्पर्धा कर एक दूसरे के मित्र बन रहे हैं। सत्रहवीं लोकसभा के कई ऐसे सदस्य हैं जो अपनी फिजिकल फिटनेस को लेकर बेहद संजीदा रहते हैं। यही वजह है कि आजकल इन सदस्यों ने लोदी गार्डन से लेकर कांस्टीट्यूशन क्लब तक हर जगह फिटनेस के मामले में अनौपचारिक ग्रुप बना लिए हैं। ये समूह पार्टी लाइन से बाहर हैं और इनमें चर्चा राजनीति की नहीं, बल्कि इस बात की होती है कि किसने कितने किलोमीटर वॉक किया और कितने मिनट तक स्विमिंग की। इनमें ज्यादातर ऐसे सदस्य शामिल हैं जो पहली बार सदस्य चुनकर आए हैं। कुछ सदस्यों ने तो अपने आशियाने में ही कुछ व्यवस्था कर ली है। एक सदस्य महोदय ने बाकायदा क्रिकेट पिच बना रखी है। बताते हैं वह खुद भी बॉलिंग करते हैं। बहरहाल, राजनीति न सही कम से कम फिटनेस के मामले में वे एक दूसरे के मित्र हैं।

अध्यक्ष जी का डर

अमित शाह के राज्यसभा से लोकसभा में आने के बाद निचले सदन के कई पुराने सांसदों की सांसें अटक गई हैं। पिछली लोकसभा में हर मुद्दे पर बढ़-चढ़कर बोलने वाले और टोका-टोकी करने वाले ये सांसद अब किसी तरह बच निकलने की कोशिश करते दिख रहे हैं। इनमें एक सांसद ने तो अपनी सीट ऐसी जगह अलॉट करा ली थी कि सत्ता पक्ष की ओर से किसी भी मंत्री के बोलने की स्थिति में कैमरे के फ्रेम में वह खुद-ब-खुद आ जाया करते थे। जाहिर है कि खुद को प्रचार दिलाने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता था, लेकिन इस बार यह सांसद महोदय पीछे दीवार के साथ बैठे नजर आते हैं। वैसे लोकसभा में अभी तक सांसदों को बैठने के लिए सीटें आवंटित नहीं हुई हैं, लेकिन लग यही रहा है कि इस बार ये सांसद अपनी सीट पीछे की दीवार के साथ रखने की कोशिश करेंगे ताकि अध्यक्ष की नजरों के सामने पड़ने से बच सकें।

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

60 से भी अधिक देशों में प्लास्टिक की थैली के उपयोग पर आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से पाबंदी है। अनेक विकसित देशों से लेकर विकासशील देशों के विभिन्न इलाकों में इसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है।

आजकल

निजी कुंठा को चिंता में बदलने की चाल

अनंत विजय

कोई साहित्यकार जिस भाषा में जिंदगी भर लिखता रहा हो, और लेखन में ठहराव सा आने पर वह यह लिखे कि जिस भाषा में वह लिखता आया है, उसके लिए उसे ग्लानि है तो क्या इससे उसकी कुंठा प्रदर्शित नहीं हो रही है? साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता हिंदी के एक साहित्यकार ने कुछ ऐसा कहा है जिससे उनकी कुंठा झलकती है, लेकिन बेहद चतुराई से उन्होंने इसे अपनी चिंता के रूप में दर्शाने का प्रयास किया है

एक हैं मंगलेश डबराल। हिंदी के कवि हैं। जन संस्कृति मंच से गहरे जुड़े रहे हैं। कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। पुरस्कार वापसी कर चुके हैं। लेकिन रायपुर में एक साहित्यिक कार्यक्रम में जब इनका परिचय साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता कवि के रूप में दिया गया, तो मंच पर मुस्कुरा रहे थे। इन दिनों कलावादियों के खेमे में भी उपस्थित रहते हैं। अभी उन्होंने लिखा है, 'हिंदी में कविता, कहानी, उपन्यास बहुत लिखे जा रहे हैं, लेकिन सच यह है कि इन सबकी मृत्यु हो चुकी है। हालांकि ऐसी घोषणा नहीं हुई है और शायद होगी भी नहीं, क्योंकि उन्हें खूब लिखा जा रहा है। लेकिन हिंदी अब सिर्फ 'जय श्रीराम' और 'वंदे मातरम' तथा 'मुसलमान का एक ही स्थान- पाकिस्तान या कब्रिस्तान' जैसी चीजें जीवित हैं। इस भाषा में लिखने की मुझे बहुत ग्लानि है। काश इस भाषा में न जन्मा होता!'

मंगलेश की इस टिप्पणी पर विचार किया जाना आवश्यक है, क्योंकि वो हिंदी के कवि हैं, हिंदी में लिखते रहे हैं और पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार पाकर, फिर लौटाने का स्टंट कर सुर्खियां बटोर चुके हैं। अब उनका हिंदी को लेकर इस तरह की टिप्पणी करना एक सुचिंतित राजनीति का परिणाम है। इसकी दो-तीन वजहें हो सकती हैं। पहली यह कि मंगलेश काफी समय से कुछ लिख नहीं पा रहे हैं। अपने न लिख पाने की कुंठा ने उनको उपरोक्त टिप्पणी लिखने को मजबूर किया होगा। उम्र के इस पड़ाव पर पहुंच जाने, हिंदी के वरिष्ठ कवि होने के विशेषण के बाद पाठकों की यह अपेक्षा तो होती ही है कि वो कविताएं लिखें। जब पाठकों की इस अपेक्षा का बोझ वे नहीं उठा पाए तो कुंठित होते चले गए और अपनी कुंठा को उन्होंने एक खूबसूरत बहाना का आवरण पहनाया और हिंदी को अपमानित करने व उसको तीन नारों की भाषा घोषित करने की चाल चली। खुद की कुंठा को छिपाने के लिए हिंदी में लिखने को लेकर ग्लानि का ऐलान कर दिया। अगर उनको मौजूदा केंद्र सरकार से कोई दिक्कत थी, जय श्रीराम के नारों से तकलीफ है तो उनको कविता लिखकर अपना विरोध दर्ज करवाना चाहिए था।

दूसरी वजह ये हो सकती है कि उन्होंने अपने कलावादी आका के इशारे पर एक नई रणनीति के तहत ये टिप्पणी लिखी हो। इस टिप्पणी को लिखने का समय देखा जाए तो ये वही समय है जब मॉब लिंचिंग को लेकर 49 कलाकारों

> **सीधे तौर पर कहें तो मंगलेश ने अपनी कुंठा को दर्द के रूप में दर्शाने की कोशिश की है जिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है**

ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खत लिखा। उसमें भी धर्म के नाम पर हिंसा की बात कही गई है। मंगलेश की टिप्पणी में भी जय श्रीराम, वंदे मातरम और हिंदू मुसलमान की बात की गई है। तो इन दोनों घटनाओं में एक साम्य नजर आता है। मंगलेश की इन दिनों अशोक वाजपेयी से नजदीकी और उनके प्रकल्पों में काम करने की बात किसी से छुपी नहीं है। 49 कलाकारों के खत का जिस तरह से अशोक वाजपेयी ने स्वागत किया और उसके बाद मंगलेश ने ये टिप्पणी लिखी तो इससे तो साफ है कि वो भाषा को राजनीति का औजार बनाना चाहते हैं। पहाड़ पर लालटेन जलाने वाले मंगलेश को ये नहीं पता कि लालटेन की लौ कब की बुझ चुकी है और उसमें चाहे वो कितना भी तेल डाल लें आग नहीं पैदा कर सकते हैं, प्रकाश तो दूर की बात है।

अब आते हैं मंगलेश की टिप्पणी पर जहां वो हिंदी कविता, कहानी और उपन्यास की मृत्यु की घोषणा कर रहे हैं। मृत्यु की इस घोषणा में मंगलेश कई दोष के शिकार हुए हैं। जब वो हिंदी कविता, कहानी और उपन्यास के मृत्यु की घोषणा करते हैं तो लगता है कि समकालीन साहित्य से उनका सरोकार ही नहीं रहा। संपर्क भी नहीं बचा। और सरोकारहीन और संपर्कहीन समझ के आधार पर निर्णय सुनाने के दोष के शिकार हो रहे हैं। आज हिंदी में युवा और नवोदित वृद्ध लेखकों की पूरी पीढ़ी सृजनरत है और बेहतरीन रचनाएं सामने आ रही हैं। मंगलेश को हो सकता है नहीं पता हो, लेकिन अगर लोकप्रियता और बिक्री के लिहाज से देखा जाए तो ये हिंदी के लिए स्वर्णकाल है। अलग अलग क्षेत्रों में हिंदी के लेखकों के लिए नए अवसर पैदा हो रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में साहित्योत्सव हो रहे हैं और इन सभी में हिंदी और उसके लेखकों की उपस्थिति निश्चित रूप से होती है। कहीं कम कहीं ज्यादा। मंगलेश को हिंदी भाषा को लेकर ग्लानि हो सकती है, लेकिन हिंदी के कई बड़े लेखकों को अपनी भाषा पर न केवल अभिमान है, बल्कि वो इसकी समृद्धि के लिए काम भी कर रहे हैं। मंगलेश कहते हैं उनको इस भाषा (हिंदी) में पैदा होने पर भी ग्लानि है।

उनकी इस टिप्पणी पर बगैर नाम लिए वरिष्ठ व्यंग्यकार प्रेम जनमेजय ने बहुत सटीक लिखा है, 'मुझे आज भीष्म साहनी की कहानी चीफ की दावत की मां याद आ रही है। उपयोग के बाद अनुपयोगी मां स्टोर रूम में और हिंदी भी शायद स्टोर रूम में।' कितने सलीके से जनमेजय ने अपनी बात रख दी और मंगलेश पर प्रहार भी कर दिया। दरअसल मंगलेश ने पर्याप्त यश और पैसा हिंदी में लिखकर ही तो कमाया। अभी भी हिंदी में ही लिख रहे हैं, भले ही कविता न लिख पा रहे हों, लेकिन फाउंडेशन आदि के लिए लेखन तो कर ही रहे हैं। अब जब हिंदी से सबकुछ हासिल कर लिया तो उसी हिंदी से प्रचार हासिल करने के लिए उसको ही स्टोर रूम में डालने की जुगत में लग गए। मंगलेश ये भूल गए कि काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती है। अकादमी पुरस्कार लौटाकर प्रचार मिला, क्योंकि उन्हें पता था कि साहित्य अकादमी एक बार दिए पुरस्कार की न तो राशि स्वीकार कर सकती है और न ही स्मृति चिन्ह आदि। यह सब जानते बूझते अकादमी पुरस्कार लौटाया था। उस समय भी प्रचार मिला और अब भी सभा गोष्ठियों में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त कवि का यश लूट रहे हैं। यानी दोनों हाथों मे लड्डू। दरअसल मंगलेश ने ये टिप्पणी एक विशेष राजनीति के तहत की है। सवाल उठेगा कैसे?

तीन चार साल पहले तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन की कृति 'मधोरुबगन' को लेकर विवाद उठा था। जब यह उपन्यास तमिल में छपा था तो उसको लेकर थोड़ी सुगबुगाहट हुई थी, लेकिन जब उसका अंग्रेजी अनुवाद 'वन पार्ट वूमन' के नाम से छपा तो विवाद बढ़ गया था। उस उपन्यास में मुरुगन ने तमिल समाज में व्याप्त लैंगिक और सामाजिक असमानता को कसौटी पर कसा था। उपन्यास प्रकाशन के चार साल बाद सबसे अधिक विरोध मुरुगन के गांव तिरुचेनगोडे में ही हुआ था। जब विवाद काफी बढ़ गया था तब मुरुगन को पीस कमेटी के दबाव में माफी मांगनी पड़ी थी। उस वक्त मुरुगन ने एक लेखक की मौत की घोषणा की थी। इसके बाद ये मामला तमिलनाडु से निकलकर पूरे देश में फैल गया था। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की ध्वजा पताका लिए घूमनेवाले लोगों ने 2016 में काफी शोर मचाया था और इसको भी असहिष्णुता से जोड़ने की कोशिश की थी। मुरुगन को पर्याप्त प्रसिद्धि भी मिली थी। अनुवाद का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी देने की घोषणा हुई थी और अब वो लिख भी रहे हैं।

ऐसा प्रतीत होता है कि मंगलेश जब हिंदी कविता, कहानी और उपन्यास के मृत्यु की घोषणा कर रहे होंगे तो उनके मन के किसी कोने में मुरुगन को मिली प्रसिद्धि की बात रही होगी। ज्यादा प्रसिद्धि की चाहत में वो मुरुगन से भी आगे चले गए और हिंदी की विधाओं के अवसान की घोषणा कर दी। मंगलेश को पता था कि अगर वो एक लेखक की मौत की बात करेंगे तो कोई नोटिस भी नहीं लेगा, क्योंकि मुरुगन तो निरंतर लिख रहे थे जबकि मंगलेश का लिखना कब का बंद हो चुका है। उन्होंने अपनी कुंठा के प्रकटीकरण के लिए हिंदी और साहित्य की विधाओं के अंत की घोषणा को चुना।

मंगलेश को समझना होगा कि इन हथकंडों से हिंदी कविता, कहानी या उपन्यास का नुकसान नहीं होगा। ये विधाएं व हिंदी भाषा सुरक्षित हाथों में हैं और युवा लेखक इसे बढ़ा रहे हैं। अपनी कुंठा निकालने के लिए, प्रचार के लिए, राजनीति चमकाने के लिए युवा लेखकों का अपमान अनुचित है और मंगलेश को इसके लिए उनसे माफी मांगनी चाहिए। जिनको मंगलेश की टिप्पणी में दर्द दिखता है उन्हें समझना होगा कि मंगलेश ने बेहद सधे तरीके से कुंठा को दर्द बनाने की कोशिश की है।

फिर से

जूट से बना ग्रीन प्लास्टिक

दुनिया भर के देश प्लास्टिक के थैलों को घटाने के लिए मुहिम चला रहे हैं। दरअसल प्लास्टिक से वैश्विक पर्यावरण को बहुत अधिक नुकसान हो रहा है। ऐसे में बांग्लादेश के लिए इस समस्या के समाधान के रूप में एक बड़े मुनाफे का कारोबार भी छिपा हुआ है, जिसके जरिये यह देश बहुत कमाई कर सकता है। दरअसल यहां बनने वाले जूट के थैले प्लास्टिक का उपयोग कम करने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।

भारत के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा जूट बांग्लादेश में पैदा होता है। गोल्डेन फाइबर के नाम से विख्यात इन रेशों की कीमत भी कभी बहुत ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ मांग घटी तो उसकी चमक फीकी पड़ गई। अब एक बांग्लादेशी वैज्ञानिक ने जूट के रेशों को कम कीमत में जैविक रूप से अपघटित होने वाले सेल्यूलोज की शीट में बदलने का तरीका ढूंढ निकाला है। इसका फायदा यह है कि दिखने में यह प्लास्टिक जैसा होने के साथ ही पर्यावरण के अनुकूल और आसानी से नष्ट होने वाला होगा।

बांग्लादेश की सरकारी जूट मिल्स कॉर्पोरेशन (बीजेएमसी) के वैज्ञानिक सलाहकार और जूट के नए बैग बनाने वाली टीम के मुखिया मुबारक अहद खान का कहना है, 'इसके भौतिक गुण लगभग एक जैसे ही हैं।' उनका कहना है कि ये थैले तीन महीने मिट्टी में दबा कर रखने के बाद पूरी तरह से अपघटित हो जाते हैं और इन्हें रिसाइकिल भी किया जा सकता है। बांग्लादेश अब प्रायोगिक तौर पर हर दिन करीब दो हजार थैले बना रहा है। हालांकि इसके कारोबारी उत्पादन को तेजी से बढ़ाने की योजना है। इसके लिए एक विदेशी कंपनी से करार भी हो गया है।

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इसी साल मार्च में इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे लोगों से 'गोल्डेन बैग के व्यापक इस्तेमाल को तेज करने में मदद' का अनुरोध किया था। अप्रैल में सरकार ने बांग्लादेश के क्लाइमेट चेंज ट्रस्ट फंड से नौ लाख डॉलर धन भी मुहैया कराया ताकि इन थैलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो सके। बीजेएमसी के जेनरल मैनेजर ममनूर राशिद इस संबंध में कहते हैं, 'एक बार प्रोजेक्ट पूरी तरह से चलने लगा तो हम सोनाली बैग को छह महीने के भीतर कारोबारी रूप से बनाने की उम्मीद कर रहे हैं।'

बांग्लादेश दुनिया के उन पहले देशों में है जिसने प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर रोक लगाई। वर्ष 2002 में यह काम स्थानीय जलमार्गों में जमा होने वाली प्लास्टिक को रोकने के लिए किया गया। हालांकि तब इस रोक को बहुत कामयाबी नहीं मिली थी। आज भी बांग्लादेश की राजाधानी ढाका में हर महीने करीब 41 करोड़ प्लास्टिक थैले उपयोग में लाए जा रहे हैं। बूढ़ी गंगा नदी में तीन मीटर की गहराई तक प्लास्टिक कचरे की परत जमा हो गई है।

दुनिया के 60 से ज्यादा देशों में

प्लास्टिक की थैली के इस्तेमाल पर रोक है। फ्रांस से लेकर चीन तक ने कुछ इलाकों में ही सही, यह रोक जरूर लगाई है। बांग्लादेश में प्लास्टिक की थैली पर रोक का विस्तार मिलने के बाद 100 से ज्यादा बांग्लादेशी अंतरराष्ट्रीय कंपनियों ने नए जूट वाले बैग का इस्तेमाल करने की बात कही है।

मुबारक अहमद खान बताते हैं, 'हर दिन मुझे अलग अलग देशों के खरीदारों से ईमेल और फोन कॉल आ रहे हैं। इनमें ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, जापान और फ्रांस जैसे देश शामिल हैं। उम्मीद की जा रही है कि हर महीने कम से कम एक करोड़ थैले का निर्यात होगा। कारोबारी तौर पर थैले का उत्पादन इस साल के आखिर तक शुरू हो जाएगा। मुबारक अहमद खान का कहना है कि अगर बांग्लादेश के सारे जूट उत्पादन को इन थैलों के निर्माण में लगा दिया जाए तो भी मांग का एक तिहाई ही पूरा हो सकेगा।

(डीडब्ल्यू से संपादित अंश, साभार)

ट्वीट-ट्वीट

समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के केवल दो शब्द माफी कहने से उन्हें लोकसभा में माफ किए जाने पर गलत मिसाल बनेगी। जब सभी राजनीतिक दलों ने उनके गंदे शब्दों और व्यवहार को निंदनीय अपराध माना है तो संसद से निष्कासन उचित होगा। वरना लोग महिलाओं का अपमान करने के बाद सुविधानुसार दो शब्द का ड्रामा करेंगे।
आलोक मेहता@alokmehtaeditor

एक सड़क की खराब हालत को लेकर किए गए ट्वीट पर आई प्रतिक्रियाओं के बाद यही कहूंगी कि मिस्टर गडकरी को देश की उन तमाम सड़कों पर यात्रा करनी चाहिए जिनके निर्माण का वह श्रेय लेते हैं। करदाताओं का पैसा ऐसी सड़कों को बनाने पर बर्बाद किया जा रहा है जो एक बरसात तक नहीं झेल पातीं।
तवलीन सिंह@tavleen_singh

भारत की आत्मा धार्मिक और उसका चरित्र लोकतांत्रिक है। बेवजह के पत्र लिखकर उसका तमाशा बनाना बंद करें।
चित्रा सुब्रमण्यम@chitraSD

गौ तस्कर मवेशी चुराने के लिए हत्याएं कर रहे हैं। जो लोग छाती पीट- पीटकर यह चिल्लाते हैं कि गाय के नाम पर हिंसा फैलाई जा रही है, वे लोग कानून तोड़ने वाले गौ तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग क्यों नहीं करते? गौ तस्कर कानून तोड़ना बंद कर दें तो देश में हिंसा अपनेआप ही थम जाएगी।
अशोक श्रीवास्तव@ashokshrivasta6

रचनाकर्म

दो 'दुश्मनों' की दोस्ताना दास्तान

प्रणव सिरोही

कुछ किनारे सिर्फ कल्पनाओं में ही मिला करते हैं, लेकिन एक किताब ने यह करिश्मा भी कर दिखाया है। अगर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के पूर्व प्रमुख और उसकी कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ के दो पुराने दिग्गज एक साथ आएं तो यह दो ध्रुवों के मिलने से कम बड़ा वाकया नहीं। रॉ के पूर्व प्रमुख एएस दुलत और आइएसआइ के पूर्व मुखिया असद दुर्रानी ने अपनी किताब 'रॉ, आईएसआई और शांति का भ्रम-एक जासूसी वृत्तांत' में कुछ ऐसा ही किया है। संवाद शैली में पेश इस किताब में लेखक एवं पत्रकार आदित्य सिन्हा तीसरे लेखक के किरदार या यूं कहें कि सूत्रधार की भूमिका में हैं। किताब का शुरुआती हिस्सा यही परतें खोलता है कि कैसे दोनों दिग्गज इसके लिए एक साथ आए।

हालांकि यह जासूसी की दुनिया से पर्दा उठाने वाली किताब नहीं, बल्कि विभिन्न विषयों पर दुलत और दुर्रानी के नजरियों का सार है। इसमें निजी जिंदगी के किस्सों से लेकर जासूसी, कश्मीर, अफगानिस्तान, आतंकवाद, मुंबई हमले, उड़ी, पठानकोट, सर्जिकल स्ट्राइक और डीप स्टेट जैसे विभिन्न मसलों से लेकर नरेंद्र मोदी, अजीत डोभाल, नवाज शरीफ, परवेज मुशर्रफ और डोनाल्ड ट्रंप जैसी तमाम हस्तियों के बारे में भी अलग-अलग संदर्भों में टिप्पणियां हैं। भारत-पाकिस्तान संबंधों पर वैसे तो किताबों की भरमार है, लेकिन यह पुस्तक द्विपक्षीय संबंधों के कई अहम पहलुओं पर एक नई दृष्टि डालती है।

इसमें लेखकों का एक-दूसरे के प्रति परस्पर सम्मान का भाव प्रकट होता है, जो शायद दोनों के बीच जुड़ाव की एक अहम कड़ी भी है। भारत-पाक के बीच सबसे बड़ी पहेली कश्मीर के मामले में यह साफ दिखता है, जहां दुर्रानी मानते हैं कि कश्मीर को लेकर दुलत की समझ बहुत स्पष्ट और उपयुक्त है। वहीं दुलत कश्मीर को लेकर वार्ता में आइएसआइ के दुर्रानी जैसे लोगों को जोड़ने की पैरवी करते हैं। दुलत कहते हैं कि कश्मीर समस्या को समझते हुए मुझे लगा कि अफगानिस्तान और कश्मीर के हालात एक जैसे हैं। कश्मीर का मसला सुलझाकर अफगान समस्या भी सुलझाई जा सकती है।

इसमें दुलत-दुर्रानी चुहलबाजी से भी परहेज नहीं करते। अमूमन खुफिया एजेंसियां अपने देश में कम विख्यात और दुश्मन देश में कहीं ज्यादा कुख्यात होती हैं। इसकी तस्दीक करते हुए दुर्रानी कहते हैं कि हिंदुस्तान में कुछ भी गलत होता है तो फौरन उसका इल्जाम आइएसआइ के माथे मढ़ दिया जाता है। इस पर समकालीन दौर के संदर्भ में कटाक्ष करते हुए दुलत कहते हैं कि वक्त बदल गया है और अब हमारे देश में लोग लिबरल-बुद्धिजीवियों को भी गड़बड़ी का दोषी मानने लगे हैं। वहीं लंदन में जब एक पत्रकार दुर्रानी पर भारत में घुसपैठिये भेजने का आरोप लगाते हैं तो वह जवाब देते हैं कि हम किसी को नहीं भेजते, असल में आपकी

> **रॉ और आइएसआइ के पूर्व प्रमुखों की बातचीत को आधार बनाकर तैयार हुई यह किताब कोई सनसनी नहीं फैलाती, बल्कि विभिन्न विषयों पर विचारों में साम्य दर्शाती है...**

पुस्तक : रॉ, आईएसआई और शांति का भ्रम
लेखक : एएस दुलत, असद दुर्रानी और आदित्य सिन्हा
प्रकाशक : मंजुल प्रकाशन
मूल्य : 399 रुपये

वीजा नीतियां ही बहुत सख्त हैं। दोनों के बीच यह बातचीत इस्तांबुल, काठमांडू और बैंकाक जैसे शहरों में परवान चढ़ी। इस किताब में उन्होंने जासूसी की दुनिया का कोई भेद नहीं खोला है। किसी सनसनी की उम्मीद लगाने वालों को यह मायूस ही करती है। फिर समझ नहीं आता कि पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान किताब को लेकर दुर्रानी पर इतना आग-बबूला क्यों हो गया?

साफगोई के भी इसमें तमाम वाकये हैं। जैसे मुंबई हमलों को लेकर दुर्रानी का आक्रोश या लादेन की हत्या को लेकर दुलत का दृष्टिकोण कि यह पाक की शह पर ही हुआ, क्योंकि वह भी लादेन से पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन यदि अपने स्तर पर कुछ करता तो घरेलू मोर्चे पर उसकी कड़ी प्रतिक्रिया हो सकती थी। वहीं कश्मीर में दखल को लेकर आइएसआइ की पहल पर भी दुर्रानी स्वीकार करते हैं कि उन्हें अंदाजा नहीं था कि मामला इतना बेकाबू हो जाएगा। पाकिस्तान में सक्रिय डीप स्टेट को लेकर पलटवार की मुद्रा में वह अमेरिका की मिसाल देते हुए बताते हैं कि कैसे सीआइए, पेंटागन, विदेश विभाग और कुछ अन्य तबके मिलकर वहां भी राजनीतिक नेतृत्व को असहाय बना देते हैं। भारत-पाक को वार्ता की सलाह देते हुए दोनों यह भी सुझाव देते हैं कि अगर रॉ-आइएसआइ के पूर्व मुखिया बातचीत कर सकते हैं तो फिर दोनों देश क्यों नहीं? दोनों की बातचीत को सिन्हा बखूबी आगे बढ़ाते हुए किताब को सही आकार देते हैं। इसका अनुवाद और सुगम होता तो यह और बेहतर बन सकती थी।

स्मृतियों से निसृत कथा

संजय श्रीवास्तव

कथाकार अमिता सक्सेना का उपन्यास 'अनकही' वे बातें कहता है जो घर-परिवारों या समाज में अक्सर अनकही ही रह जाती हैं। कहानी बीती सदी के 40-50 के दशक से शुरू होती है, जहां से अब तक आते हुए जीवनशैलियां और जीवनमूल्य पूरी तरह बदल चुके हैं। इसकी कहानी सामूहिक परिवारों की है जिसमें सदस्यों के बीच एक खास राग-रंग व रिश्ता है। कहानी जिस परिवार व समय के साथ शुरू होती है, उससे अब तक आते हुए सभी कुछ बदल चुका है। बड़े परिवारों की जगह अब सिंगल फैमिलीज अस्तित्व में आ गई हैं। चिट्ठियों की जगह इंटरनेट, ई-मेल और सोशल मीडिया ले चुका है।

यह उन महिलाओं की कहानी है, जो कुछ दशक पहले तक शिक्षित होने के बाद भी घर के दायरे में रहती थीं। उनकी प्राथमिकताएं अलग होती थीं। उनके अंतर्द्वंद्व और पारिवारिक संतुलन के तरीके अलग होते थे, शिक्षा के साथ उन्हें कुछ अलग तरह की व्यावहारिकताओं और प्रवीणताओं की जरूरत पड़ती थी। हवेलियां जनानखाने और मर्दानखाने में विभक्त थीं, जिसे एक ड्योढ़ी जोड़ती थी। पुरुष खांसते-खंखारते या किसी का नाम पुकारते ड्योढ़ी से जनानखाने में दाखिल होते थे। महिलाएं सतर्क होकर अपना घूंघट खींच लेतीं। दिन भर महिलाएं घरेलू कामकाज में व्यस्त रहतीं। घर-घर में चक्की-मूसल आदि अनेक तरह के यंत्र होते, जिन कामों के लिए आजकल सुविधापूर्ण उपकरण आ चुके हैं। घरों में बिजली आने के पहले तिदरी (ढिबरी) और कोठों के दोनों

किताब : अनकही
लेखिका : अमिता सक्सेना
प्रकाशक : ब्लूरोज पब्लिशर्स, दिल्ली
मूल्य : 149 रुपये (पेपरबैक)

किनारों पर बेलन के सहारे दो बड़े झलने वाले पंखे लगे होते थे, जिन्हें सेवादार झलते थे। कोठारों में अनाज, दालें और तेल-घी रखे जाते थे, रसोईघर के पास कमरे में लकड़ी और गोबर के उपले भरे होते थे।

'अनकही' की केंद्रीय भूमिका में एक शिक्षित महिला है जो इस माहौल में अंतर्द्वंद्व के उतार-चढ़ाव से गुजरती है। परिवार के मायने समझती है। उनके साथ जुड़ती है। प्रतिकूल हालात से तालमेल बिठाने की कोशिश करती है। पुराने समय का यह अंतर्द्वंद्व आज भी प्रासंगिक है। हालांकि छह दशक पहले की और आज की महिलाओं में पर्याप्त बदलाव आया है, पर इसमें कही गई कई बातें आज भी अनकही हैं।

जागरण जनमत कल का परिणाम

रमा देवी के खिलाफ टिप्पणी के लिए आजम खां को निलंबित कर दिया जाना चाहिए?

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

भ्रामक विज्ञापन करने वाली हस्तियों पर शिकंजा कसने से उपभोक्ता संरक्षण को बल मिलेगा?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर POLL लिखें, स्पेस देकर Y, N या C लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, N-नहीं, C-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

कहकर बच्चू फंस गए मिले न कोई राह,
बड़बोलेपन में किया फिर से एक गुनाह।
फिर से एक गुनाह न होगी बिल्कुल काफी,
अगर सदन में आय मांग लें आजम माफी।
कुढ़ता नारी वर्ग बोल उनके कटु सहकर,
आहत करते आप उन्हें कुछ भद्दा कहकर।
– ओमप्रकाश तिवारी

आशीष व्यास
संपादक, मध्य प्रदेश, नई दुनिया

मध्य प्रदेश डायरी

कमलनाथ के स्ट्रोक से सियासी सन्नाटा!

मध्य प्रदेश में इस बार का सावन दल-बदल की बौछारों के साथ आया है। बरसते पानी ने कई चेहरों पर चढ़ा निष्ठा का पानी उतार दिया है, तो कुछ किरदारों की प्रतिष्ठा भी गहरे तक प्रभावहीन कर दी है। हंगामेदार रहे विधानसभा के पावस सत्र में 'आया राम-गया राम' जैसे मुहावरे भी नए अर्थों के साथ सामने आ गए। इससे न केवल भाजपा-कांग्रेस के रणनीतिकारों की परंपरागत धारणाएं ध्वस्त हो गई हैं, बल्कि अब वे नए सिरे से, नई राजनीति पर काम करने के लिए भी विवश हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक नारायण त्रिपाठी और शरद कोल द्वारा अचानक कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग करने के बाद से दल-बदल की नई-नई कहानियों ने प्रदेश के राजनीतिक तापमान को भी बढ़ा दिया है। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के बाद से ही कमलनाथ के करीबी दोनों विधायकों के संपर्क में थे और उपेक्षा-असंतोष पर नजर रखते हुए, लगातार इस मौके की तलाश में थे कि जैसे ही अवसर मिले पाला बदलने की कवायद पूरी कर ली जाए।

भाजपा-कांग्रेस की खुली खींचतान का परिणाम चाहे अब सामने आया हो, लेकिन इसकी शुरुआत विधानसभा चुनाव परिणाम के साथ ही हो गई थी। भाजपा के छोटे-बड़े नेता सार्वजनिक रूप से लगातार यह बयान दे रहे थे कि कमलनाथ सरकार 'जुगाड़' का नया फार्मूला है। कर्नाटक में कांग्रेस- जेडीएस सरकार गिरने के बाद कमलनाथ सरकार की अस्थिरता की बात शुरू हुई। राज्य में भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने बयान दिया है कि अगर हमारे नंबर एक या नंबर दो का आदेश हुआ तो कांग्रेस सरकार 24 घंटे भी नहीं चलेगी!

ऐसे में मुख्यमंत्री कमलनाथ का पलटवार भी मंझे हुए राजनीतिज्ञ की तरह सामने आया। उन्होंने कहा, 'आपके ऊपर वाले नंबर एक और नंबर दो समझदार हैं, इसलिए आदेश नहीं दे रहे हैं। आप चाहें तो अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं।' विवाद-विरोध की राजनीतिक पृष्ठभूमि में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कई अवसरों पर अपने बयानों से सियासी गर्माहट पैदा की है। कर्नाटक घटनाक्रम के तुरंत बाद शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया, 'कांग्रेस के नेता अपनी सरकारों के पतन के लिए खुद जिम्मेदार हैं। हम मध्य प्रदेश सरकार के पतन का कारण नहीं बनेंगे।' शिवराज सिंह चौहान इस तरह के बयान देते हुए शायद यह भूल गए कि तर्क-कुतर्क के साथ अपने असंतोष को अवसर में बदलने वाले नेता छोटे-छोटे राजनीतिक फायदे के लिए कभी-कभी बड़ा राजनीतिक नुकसान कर देते हैं।

माना यह भी जा रहा है कि विंध्य अंचल में विख्यात रहे श्रीनिवास तिवारी और उनके बेटे सुंदरलाल तिवारी के निधन के बाद से कांग्रेस में ब्राह्मण नेताओं की कमी है। कभी प्रदेश की राजनीतिक धुरी का केंद्र रहा यह इलाका कांग्रेस में ब्राह्मण राजनीति का भी गढ़ था। नारायण त्रिपाठी के पंक्ति-परिवर्तन के पीछे क्षेत्र का निर्विवाद ब्राह्मण नेता बनने की इच्छाएं भी टटोली जा रही हैं। हालांकि त्रिपाठी के बयानों में इस तरह की कोई बात अब तक तो नजर नहीं आ रही है, क्योंकि उन्होंने अपने असंतोष और भाजपा से असहमति की जिम्मेदारी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर डाल दी है। त्रिपाठी का मानना है, 'विधानसभा चुनाव के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने ढेरों घोषणाएं कर दी थीं, लेकिन वे पूरी नहीं हो पाईं। अधूरी घोषणा से उनकी छवि खराब हो रही है और वे सीधे तौर पर जनता के विरोध की वजह बन रहे हैं।'

बहरहाल, भाजपा के लिए यह झटका इतना बड़ा है कि इसकी गूंज दिल्ली में सुनाई दी और सन्नाटा मध्य प्रदेश में छा गया है। मौके-बेमौके अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले भाजपा के कद्दावर नेता अचानक मौन में चले गए हैं। प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि भाजपा आलाकमान नाराज हैं और प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कारण पूछा जा रहा है। यह कवायद इसलिए भी की जा रही है कि भाजपा में अलग-अलग इलाकों से अंसतोष के कुछ सुर सुनाई दे रहे हैं। जानकारों का यह भी कहना है कि भाजपा चुप नहीं बैठेगी, नई रणनीति के साथ लौटेगी। ऐसा कुछ होगा या नहीं, यह तो समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल कमलनाथ सरकार का मास्टर स्ट्रोक भाजपाइयों के साथ साथ कुछ 'कांग्रेसियों' का भी मुंह बंद करने के लिए काफी है।

'मिलावट' का दूधिया कारोबार!

राजनीति में 'मिलावट' लोकतंत्र की सेहत के लिए खराब हो न हो, लेकिन सिंथेटिक दूध व नकली मावा लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। ग्वालियर और चंबल संभाग में पकड़े गए नेटवर्क ने जो राज उगले, वे काफी डराने वाले हैं। एक लीटर दूध में एक लीटर रिफाइंड ऑइल और 10 ग्राम डिटरजेंट फेंटने के बाद आठ लीटर पानी मिलाया जाता है। इससे 10 लीटर सिंथेटिक दूध तैयार हो जाता है! इसी नकली दूध में शैंपू, डिटर्जेंट, घटिया क्वालिटी का तेल मिलाकर मावा व पनीर तैयार कर लिया जाता है! चौंकाने वाला तथ्य यह भी है कि भिंड-मुरैना जिले से रोजाना चार लाख लीटर सिंथेटिक दूध टैंकरों से धौलपुर, आगरा और दिल्ली तक पहुंच रहा है। इसी तरह 1,200 क्विंटल मावा और 100 क्विंटल पनीर की सप्लाई ग्वालियर से लेकर इंदौर, उज्जैन, भोपाल सहित छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र तक हो रही है। स्थानीय प्रशासन की गहरी नींद से तैयार हुए इस मिलावटी गठजोड़ ने रेल नेटवर्क का उपयोग भी बड़े पैमाने पर किया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से सबसे अधिक माल भेजा जा रहा है। यह ट्रेन मावा व पनीर को दुर्ग, भिलाई, रायपुर, बिलासपुर के बाद महाराष्ट्र व नागपुर तक लेकर जाती है। उत्कल एक्सप्रेस के जरिये मिलावटी जहर ओडिशा तक की यात्रा करता है। पंजाब एक्सप्रेस द्वारा भोपाल, इटारसी तक सप्लाई है। मध्य प्रदेश शासन-प्रशासन चाहे स्वीकार न करे, लेकिन भिंड में सिंथेटिक दूध से मावा व पनीर बनाने के लिए करीब सवा सौ भट्टियां संचालित हो रही हैं! इनका मावा व पनीर निजी वाहन से जालौन, झांसी, इटावा, उरई, ग्वालियर, धौलपुर व आगरा तक भेजा जाता है। हाल ही में हुई धरपकड़ के बाद से लग तो रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार जागी है। दोषियों के खिलाफ उम्रकैद की सजा लाने की बात भी कर रही है, लेकिन इस सवाल का जवाब अभी भी शेष है कि इतना बड़ा कारोबार आखिर किसकी शह पर खड़ा कर लिया गया?

जेपी इन्फ्राटेक का नुकसान गहराया

नई दिल्ली, प्रेट्र : कर्ज के बोझ तले दबी जेपी इन्फ्राटेक को चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून, 2019) में 448.09 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में कंपनी का घाटा 319.82 करोड़ रुपये रहा था। हालांकि समीक्षाधीन अवधि में कंपनी की कुल आय बढ़कर 669.56 करोड़ रुपये पर पहुंच गई। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में इस मद में कंपनी को 432.31 करोड़ रुपये हासिल हुए थे। कंपनी इस वक्त इन्सॉल्वेंसी प्रक्रिया से गुजर रही है।

देश में इलेक्ट्रिक वाहन क्रांति को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक और साहसिक कदम उठाया है। अब हमें इस दिशा में काम आगे बढ़ाना चाहिए।

— पवन गोयनका
एमडी, महिंद्रा एंड महिंद्रा

कारपोरेट हलचल

एयर इंडिया की नजर युवा यात्रियों पर

एयर इंडिया ने युवा यात्रियों को लुभाने के लिए अपनी लंबी दूरी की उड़ानों में विशेष प्रबंध करने का एलान किया है। एयरलाइन अपनी ऐसी सभी उड़ानों में दो से 12 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को मैगजीन व वर्कबुक उपलब्ध करायेगी ताकि वे उड़ान के दौरान अपनी सृजनात्मकता को बनाये रखते हुए समय बिता सकें। इसके अतिरिक्त ऐसे सभी यात्रियों को स्मृति चिन्ह और अन्य उपहार देने की भी योजना है।

'दिव्य कला शक्ति' का आयोजन

सामाजिक न्याय व आधिकारिता मंत्रालय के तहत दिव्यांगजन आधिकारिता विभाग ने पिछले दिनों एक कार्यक्रम 'दिव्य कला शक्ति' का आयोजन किया जिसमें दिव्यांग बच्चों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद भी उपस्थित थे और उन्होंने दिव्यांग बच्चों के इस प्रदर्शन को देखा व सराहा। इनके अलावा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी उपस्थित थे।

एनएसआइसी करेगा ईवी उद्योग की मदद

तेलंगाना सरकार की तरफ से इलेक्ट्रिक व्हीकल पर आयोजित एक समिट में एनएसआइसी के निदेशक (पी एंड एम) पी. उदयकुमार ने विशेष अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया। अपने संबोधन में उदयकुमार ने कहा कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल उद्योग में भारी संभावनाओं को देखते हुए एनएसआइसी लघु व मझोले उद्योग क्षेत्र में भी इसके लिए आवश्यक इकोसिस्टम तैयार करने में मदद करेगा।

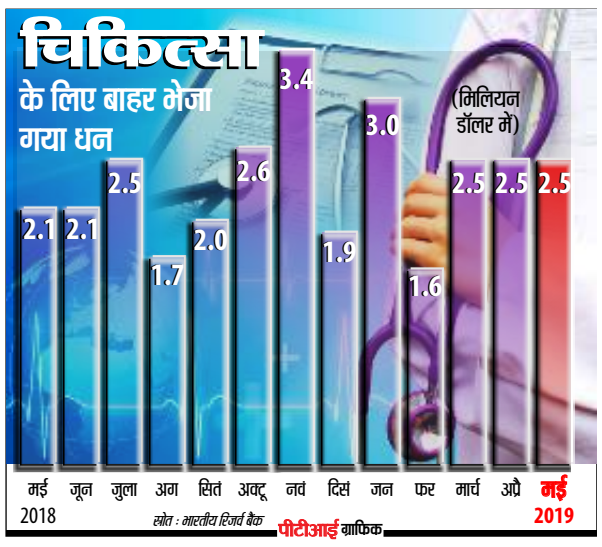

बढ़ते कदम ▶ टेलीकॉम ऑपरेटरों के साथ संचार मंत्री की बैठक, सरकार स्वस्थ स्पर्धा के पक्ष में

वंचित गांवों में एक वर्ष में देंगे टेलीकॉम सेवा

प्रसाद ने उद्योग से 5जी लागू करने में मजबूत भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वह टेलीकॉम क्षेत्र में किसी तरह के एकाधिकार को स्वीकार नहीं करेगी। सरकार इस क्षेत्र की सभी कंपनियों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की हिमायती है। सरकार ने देश को पांच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में टेलीकॉम कंपनियों से सहयोग मांगा है। इसके लिए सरकार ने सभी टेलीकॉम कंपनियों से कहा है कि वे सेवा की गुणवत्ता में सुधार और 5जी को लागू करने में ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करें। सरकार ने कंपनियों को एक वर्ष में उन सभी गांवों को दूरसंचार सेवाओं के दायरे में लाने का काम सौंपा है, जहां अभी तक ये सुविधाएं नहीं हैं।

टेलीकॉम ऑपरेटरों के साथ बैठक में केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी तथा कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कंपनियों को सरकार के पूरे समर्थन का भरोसा भी दिया। उन्होंने कहा कि शुल्क में कटौती और रिफंड जैसे बकाया मुद्दों पर सरकार का पूरा समर्थन है। प्रसाद ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, 'मैंने कंपनियों से कहा है कि 5जी में इनोवेशन, स्टार्ट-अप और उत्पादों के सृजन पर जोर दें, ताकि देश आधारित पेटेंट तैयार हो सके। पांच लाख करोड़ डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने में कम से कम 25 फीसद हिस्सेदारी टेलीकॉम कंपनियों की होनी चाहिए।'

प्रसाद के साथ हुई बैठक में भारती एयरटेल के सीईओ गोपाल विट्टल, वोडाफोन आइडिया के बालेश शर्मा, रिलायंस जियो के बोर्ड के सदस्य महेंद्र नाहटा और बीएसएनएल चेयरमैन पीके पुरवार मौजूद थे। संचार मंत्री का कार्यभार संभालने के बाद प्रसाद की उद्योग के साथ यह पहली बैठक थी। बैठक को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि टेलीकॉम उद्योग इस वक्त सात लाख करोड़ रुपये के कर्ज के साथ भारी वित्तीय दबाव का सामना करना रहा है।

प्रसाद ने कहा कि वह इनपुट टैक्स क्रेडिट और जीएसटी की दरों को नीचे लाने जैसे मुद्दों पर पहले ही विचार कर चुके हैं और इस संबंध में उन्होंने वित्त मंत्रालय के साथ चर्चा भी की है। उन्होंने कहा कि यूएसओ फंड पर शुल्क की दर में कमी का प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन है।

संचार मंत्री ने कहा कि मौजूदा समय में देश में 43000 गांव दूरसंचार नेटवर्क के दायरे से बाहर हैं। प्रसाद ने बताया, 'मैंने कंपनियों से कहा है कि वे अपने संसाधनों को साझा करें ताकि एक साल के भीतर हम ऐसे सभी गांवों तक पहुंच सकें। सभी कंपनियों ने इस प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है।' प्रसाद ने कंपनियों से केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे धार्मिक स्थलों पर भी कनेक्टिविटी में सुधार और डिजिटल इकोसिस्टम तैयार करने का काम करे। बैठक के दौरान कंपनियों ने सेवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए टेलीकॉम टावरों की संख्या बढ़ाने पर भी सहमति जताई।

देशभर के करीब 43,000 गांवों में अभी तक नहीं पहुंच सकी है टेलीकॉम सेवा, कंपनियों ने गुणवत्ता सुधार के लिए टावर बढ़ाने पर सहमति जताई। प्रेट्र

ट्रंप की धमकी के आगे नहीं झुकेगा फ्रांस

पेरिस, एपी : फ्रांस ने कहा है कि वह गूगल और फेसबुक जैसी दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनियों पर डिजिटल टैक्स लगाने की अपनी योजना पर आगे बढ़ेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एक ट्वीट के माध्यम से फ्रांस को ऐसे किसी कदम की सूरत में अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। ट्रंप ने कहा था कि अगर फ्रांस ने ऐसा कोई कदम उठाया, तो अमेरिका इसके जवाब में फ्रांस से आयातित वाइन पर जवाबी शुल्क लगाएगा। लेकिन फ्रांस के वित्त मंत्री ब्रुनो ली मायर ने शनिवार को कहा कि अंजाम चाहे जो भी हो, फ्रांस अपनी योजना पर आगे बढ़ेगा।

फ्रांस का तीन फीसद का यह टैक्स इसी सप्ताह प्रभावी हो चुका है। यह टैक्स मुख्य रूप से उन कंपनियों को प्रभावित करता है, जो ऑनलाइन विज्ञापन के लिए अपने ग्राहकों के डाटा का इस्तेमाल करती हैं। दिग्गज कंपनियां यूरोप के ऐसे देशों में मुख्यालय स्थापित कर लेती हैं जहां टैक्स दरें बेहद कम हैं। फ्रांस का यह कदम कंपनियों की इसी गतिविधि को रोकना है।

वर्तमान में गूगल, अमेजन, फेसबुक, एपल, एयरबीएनबी तथा उबर जैसी कंपनियां बड़े कारोबार के बावजूद फ्रांस में बहुत कम टैक्स का भुगतान कर रही हैं। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि फ्रांस का यह कदम अमेरिकी कारोबार के खिलाफ भेदभाव वाला है। लेकिन मायर ने कहा कि डिजिटल गतिविधियों पर दुनियाभर में समान टैक्स एक बड़ा मुद्दा है, और सभी देशों के लिए यह चुनौती का विषय बना हुआ है।

संपत्ति बिक्री प्रक्रिया के नियम हुए संशोधित

नई दिल्ली, प्रेट्र : इन्सॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया (आइबीबीआइ) ने कंपनियों की इन्सॉल्वेंसी समाधान प्रक्रिया और संपत्ति बिक्री प्रक्रिया से जुड़े नियमों को संशोधित किया। इन संशोधनों के तहत कर्जदाताओं की समिति (सीओसी) के गठन और अन्य परिस्थितियों के पहले आवेदन की वापसी की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। सीओसी के गठन के बाद लेकिन अभिरुचि पत्र आमंत्रित करने की निविदा जारी किए जाने से पहले और अभिरुचि पत्र आमंत्रित करने की निविदा जारी कर दिए जाने के बाद आवेदन वापस लेने को लेकर भी प्रक्रिया में बदलाव किए गए हैं।

शुक्रवार को जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक ताजा बदलाव के बाद सीओसी को संपत्ति बिक्री की लागत को पूरी करने से संबंधित योगदान से जुड़ी योजना को मंजूरी देना होगा। उसे कर्जदार कंपनी की चालू हालत में उसकी बिक्री या उसके कारोबार की बिक्री की सिफारिश करनी होगी और लिक्विडेटर के लिए शुल्क तय करना होगा।

जहां तक संपत्ति बिक्री की प्रक्रिया की बात है, तो ताजा बदलाव में चालू हालत में कर्जदार कंपनी की बिक्री की प्रक्रिया और लिक्विडेशन प्रक्रिया से गुजर रही कंपनी के कारोबार की बिक्री की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

भारत में कई नीतिगत बदलाव चाहती है एपल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- एमईआइएस में प्रोत्साहन की दर पांच-छह फीसद करने की मांग
- स्मार्टफोन के निर्यात को बढ़ावा देने वाले नियमों की पक्षधर है कंपनी

चीन के स्थान पर मैन्यूफैक्चरिंग को पूरी तरह भारत स्थानांतरित करने से पहले अमेरिकी टेक्नोलॉजी दिग्गज एपल कुछ नीतिगत बदलाव चाहती है। एपल ने सरकार से मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम (एमईआइएस) में बदलाव की मांग की है। इसके अलावा कंपनी अपने कांट्रैक्ट मैन्यूफैक्चर्स के उत्पादन और आयात की गणना एपल के ही खाते में करने की स्वीकृति भी सरकार से मांगी है।

दो सप्ताह पहले केंद्र सरकार के तीन वरिष्ठ मंत्रियों के साथ एपल इंडिया के प्रबंध निदेशक विराट भाटिया ने कंपनी के भारत में मैन्यूफैक्चरिंग शुरू करने की योजना पर चर्चा की। सूत्र बताते हैं कि इसी बैठक में एपल इंडिया के प्रबंधन ने सरकार से कुछ नीतिगत बदलाव करने की मांग की। एपल की मांग है कि एमईआइएस के तहत निर्यातकों को जो प्रोत्साहन मिलता है उसकी दर कम से कम सात-आठ साल के लिए पांच से छह फीसद सुनिश्चित रहनी चाहिए। एपल का कहना है कि यह विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के नियमों के भी अनुकूल होगा। हालांकि अभी सरकार मोबाइल हैंडसेट के लिए एमईआइएस के तहत चार फीसद प्रोत्साहन देती है।

एपल ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी के तहत एक सतत, लंबी अवधि की प्रोत्साहन आधारित नीति की मांग की है ताकि भारत से स्मार्टफोन के निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक एपल ने यह भी स्पष्ट किया है कि उसे कोई विशेष रियायत नहीं चाहिए। लेकिन देश की नीति इस सेक्टर को लेकर ऐसी बने जिससे स्मार्टफोन के निर्यात को प्रोत्साहन मिले।

जहां तक सिंगल ब्रांड रिटेल का सवाल है, तो एपल की योजना दो तीन फिजिकल स्टोर और एक ऑनलाइन सिंगल ब्रांड रिटेल स्टोर खोलने की है। एपल का मानना है कि भारत में उत्पादन शुरू करने के बाद उसके खाते में कंपनी के कांट्रैक्ट मैन्यूफैक्चरर्स के उत्पादन और आयात को भी शामिल करने की इजाजत मिलनी चाहिए। साथ ही कंपनी 30 फीसद लोकल सोर्सिंग के नियम में निर्यात को भी शामिल करवाना चाहती है।

एपल यह भी चाहती है कि सरकार नीतिगत बदलाव तभी लागू करे, जब वह अपने पूरे ग्लोबल इकोसिस्टम को भारत स्थानांतरित कर ले। इस काम में उसे दो से तीन वर्ष लगेंगे। जबकि भारत में पहले से मौजूद कंपनियां बीते सात-आठ साल से मैन्यूफैक्चरिंग कर रही हैं। एपल का यह भी कहना है कि भारत में निर्मित मोबाइल के घरेलू बाजार में बिक्री और निर्यात के लिए नियम अंतरराष्ट्रीय टैरिफ के मुताबिक होने चाहिए।

एपल फिलहाल चीन में 220 अरब डॉलर मूल्य के उत्पादों का उत्पादन करती है। लेकिन अमेरिका और चीन में कारोबारी तनाव के बाद एपल अपनी पूरी मैन्यूफैक्चरिंग को भारत स्थानांतरित करना चाहती है। हालांकि साल 2017 से एपल ने भारत में उत्पादन शुरू कर दिया है और करीब दो साल में कंपनी का निर्यात 50 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है। सरकार का मानना है कि अगर एपल अपनी 20 फीसद मैन्यूफैक्चरिंग और निर्यात को भारत स्थानांतरित करती है तो भारत के कुल निर्यात में 12 फीसद की वृद्धि होगी।

भारत में निर्मित मोबाइल के निर्यात के नियम अंतरराष्ट्रीय टैरिफ के मुताबिक चाहती है कंपनी। फाइल

पंजाब ईवी पर जीएसटी घटाने के खिलाफ, बिहार ने किया समर्थन

हरिकिशन शर्मा, नई दिल्ली

जीएसटी काउंसिल की 36वीं बैठक में शनिवार को इलेक्ट्रिक वाहनों पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) घटाने का फैसला वैसे तो बहुमत से हो गया। लेकिन केंद्र के इस प्रस्ताव का पंजाब ने कड़ा विरोध किया। वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई काउंसिल की बैठक में पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने कहा कि इस निर्णय के चलते राजस्व की जो हानि होगी, उसकी भरपाई कैसे की जाएगी। बादल ने कहा कि काउंसिल के इस निर्णय से ऑटोमोबाइल उद्योग पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है जो पहले ही मंदी की मार से जूझ रहा है। हालांकि बिहार के उप मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी घटाने के प्रस्ताव का जोरदार समर्थन किया और इसे जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने की दिशा में जरूरी कदम करार दिया।

बैठक के बाद बादल ने सिर्फ एक एजेंडा को लेकर जीएसटी काउंसिल की बैठक बुलाने की सरकार की जल्दबाजी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जीएसटी संग्रह की चार महीने से समीक्षा नहीं हुई है और जीएसटी के नेटवर्क को लेकर दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन ऐसे विषयों को काउंसिल के एजेंडे में शामिल करना मुनासिब नहीं समझा गया। उन्होंने यह भी पूछा कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी की दर घटाने से राजस्व की जो हानि होगी, उसकी भरपाई कैसे की जाएगी। फिलहाल राज्यों के खजाने में बड़ा हिस्सा पेट्रोल और डीजल पर वैट के रूप में आता है, आगे चलकर इस पर भी असर पड़ सकता है। काउंसिल को दीर्घकालिक सोच के साथ निर्णय लेना चाहिए।

बिहार का मत

- जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने को इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना जरूरी
- पंजाब ने सिर्फ एक मुद्दे को लेकर बैठक बुलाने की जल्दबाजी पर उठाया सवाल

सूत्रों के मुताबिक मोदी ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी घटाने का जोरदार समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। इससे अगर राजस्व की कुछ हानि होती है तो भी यह सूखा और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के चलते होने वाली धन-जन क्षति के मुकाबले काफी कम होगी। मोदी ने इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ-साथ इनके चार्जर भी जीएसटी की दर घटाकर पांच फीसद करने का समर्थन किया। बताया जाता है कि वित्त मंत्रालय के अधिकारी इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन पर जीएसटी की दर 18 से घटाकर 12 फीसद करना चाहते थे। लेकिन मोदी तथा दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने इसे पांच फीसद करने की बात कही।

सूत्रों का कहना है कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी दरों पर शनिवार को हुए बदलाव से सरकार के खजाने पर बमुश्किल 60 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। सूत्रों ने बताया कि पश्चिम बंगाल ने इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ-साथ हाइब्रिड कारों और बीएस-6 मानकों को पालन करने वाले वाहनों को भी जीएसटी में छूट देने की वकालत की। हालांकि उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों को छूट के मद्देनजर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में भी चिंता जताई।

पंजाब, बंगाल ने छूट के मद्देनजर उद्योग पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर चिंता जताई। फाइल

आइसीआइसीआइ बैंक को 2,513 करोड़ रुपये का लाभ

- स्टैंडअलोन आधार पर बैंक का लाभ 1,908 करोड़ रुपये रहा
- एनपीए के मद में बैंक ने 2,200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया

मुंबई, प्रेट्र : निजी क्षेत्र के दूसरे सबसे बड़े कर्जदाता आइसीआइसीआइ बैंक की संपत्ति गुणवत्ता में सुधार दिख रहा है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून, 2019) में बैंक का कंसोलिडेटेड शुद्ध मुनाफा बढ़कर 2,513.69 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में बैंक का यह मुनाफा महज 4.93 करोड़ रुपये रहा था। समीक्षाधीन अवधि में बैंक का स्टैंडअलोन शुद्ध मुनाफा 1,908 करोड़ रुपये रहा। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में बैंक को स्टैंडअलोन आधार पर 119 करोड़ रुपये का घाटा उठाना पड़ा था।

चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में आइसीआइसीआइ बैंक की शुद्ध ब्याज आय 26.8 फीसद बढ़कर 7,737 करोड़ रुपये पर पहुंच गई। पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में बैंक की शुद्ध आय मार्जिन 3.19 फीसद रही थी, जो इस वर्ष समान अवधि में बढ़कर 3.61 फीसद पर पहुंच गई।

नतीजों के बाद कांफ्रेंस कॉल में बैंक के नामित एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संदीप बत्रा और मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) राकेश झा ने कहा कि समीक्षाधीन अवधि में बैंक का फंसा कर्ज (एनपीए) घटा है, और ब्याज चुकाने वाली संपत्ति में इजाफा हुआ है। इसी के चलते बैंक की शुद्ध ब्याज मार्जिन में इजाफा हुआ है। समीक्षाधीन अवधि में बैंक का एनपीए 2,779 करोड़ रुपये बढ़ा, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में इसमें 3,547 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ था। बैंक ने यह भी कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के मद में उसे 452 करोड़ रुपये का घाटा हुआ।

विशेषज्ञों की नहीं, निवेश के मामले में खुद की विशेषज्ञता पर भरोसा कीजिए

धीरेन्द्र कुमार, सीईओ
वैल्यू रिसर्च

बोनस

हम अमूमन विशेषज्ञों पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करते हैं। हर बात में विशेषज्ञों की सुनना और जानना चाहते हैं। लेकिन क्या हमने कभी यह जानने की कोशिश की है कि विशेषज्ञता आखिर है क्या बला? जो विशेषज्ञ हैं, वे कितने विशेषज्ञ हैं और उनकी विशेषज्ञता क्या है? जहां तक बचत और निवेश का प्रश्न है, तो बचतकर्ताओं की राय पर कितना भरोसा किया जाना चाहिए? यह इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि बचतकर्ता और निवेशक आमतौर पर विशेषज्ञों की राय को महत्व देते ही हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि अपनी बचत और निवेश के बारे में आप उन पर विश्वास करें। सच तो यह है कि विशेषज्ञ मानते हैं कि आप उनपर हर चीज में आंख मूंदकर विश्वास करें।

जब मैं गूगल पर 'विशेषज्ञों के मुताबिक' खोजता हूं, तो मुझे 83 लाख नतीजे मिलते हैं। इससे ऐसा लगता है कि विशेषज्ञों पर कुछ ज्यादा ही भरोसा किया जा रहा है। ऐसा लगता है मानो जो लोग इंटरनेट और वेब की दुनिया में कुछ लिख-पढ़ रहे हैं, वे 'विशेषज्ञों के मुताबिक' पर मेहरबान हैं। इसके बावजूद हम पर इल्जाम यह लगाया जाता है कि हम ऐसे दौर में पहुंच गए हैं जब 'विशेषज्ञों' के दिन लद गए से लगते हैं, जब विशेषज्ञता हासिल करने से लोगों का विश्वास उठता सा जा रहा है। क्या 'विशेषज्ञ' वाकई विशेषज्ञ होते हैं?

कुछ दिनों पहले मैंने एक अंडरकवर अर्थशास्त्री टिम हार्फोर्ड की एक किताब पढ़ी। उसमें उन्होंने एक खोजकर्ता को याद किया है। वह खोजकर्ता इस बात का विश्लेषण करना चाह रहा था कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति की भावी घटनाओं के बारे में 'विशेषज्ञ' कितना सटीक अंदाजा लगाते या लगा पाते हैं।

वह 1984 का दौर था, जब शीत युद्ध अपने निर्णायक दौर में प्रवेश कर रहा था। अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन उन दिनों शीत युद्ध के प्रति बेहद आक्रामक रुख का प्रदर्शन कर रहे थे। इस आक्रामकता पर रूस की संभावित प्रक्रियाएं क्या-क्या हो सकती थीं, इसका पता लगाने की जिम्मेदारी अमेरिका ने यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के युवा मनोवैज्ञानिक फिलिप टेटलॉक को दी। टेटलॉक ने इस मामले में अंतरराष्ट्रीय संबंधों की जानकारी रखने वाले हर उस विशेषज्ञ से बात की, जिन तक वह पहुंच सकता था। लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। इसकी वजह यह थी कि विशेषज्ञ ही किसी राय पर एकमत नहीं थे। राय चाहे जो भी हो, एक-दो विशेषज्ञ उसके पक्ष खड़े हो ही जाते थे।

टेटलॉक ने इसे लंबी अवधि वाली और बेहद सावधानी से की गई खोज की परियोजना बना दी। उसने विशेषज्ञों से कहा कि वे सवालों के वैसे जवाब दें जिन्हें कसौटी पर परखा जा सके, जिनके सही होने का सुबूत खोजा जा सके। वह 20 वर्षों तक इस काम में लगा रहा। उसके बाद उसने बताया कि विशेषों की भविष्यवाणियां कभी सही नहीं हो सकतीं।

इस पूरी कहानी का दिलचस्प पहलू यह है कि अध्ययन करते-करते टेटलॉक ने यह भी पाया कि विशेषज्ञों की राय पूरी तरह बेकार भी नहीं थी। किसी भी अन्य शोधकर्ता की तरह टेटलॉक का भी गैर-विशेषज्ञों का एक कंट्रोल ग्रुप था। उसने पाया कि हालांकि गैर-विशेषज्ञों के कंट्रोल ग्रुप की तुलना में विशेषज्ञों की राय ज्यादा काम की थी। लेकिन इतनी भी बेहतर नहीं थी कि काम की साबित हो सके। सच तो यह है कि टेटलॉक ने ज्यादा मशहूर विशेषज्ञों को ज्यादा निष्प्रभावी पाया। लेकिन यह उनकी प्रसिद्धि की विफलता थी, विशेषज्ञता की नहीं।

टेटलॉक की खोज का कुल सार यह है कि हालांकि विशेषज्ञता अनुपयोगी नहीं है, लेकिन यह भविष्य से जुड़े सवालों के काम लायक और निश्चित जवाब देने की ओर बहुत दूर तक नहीं ले जाता। अगर कोई यह चाहता है कि उसे विशेषज्ञ से किसी सवाल का तत्काल जवाब मिले, तो बहुत संभव है कि विशेषज्ञ के पास उसका जवाब नहीं होगा। एक और बात है। जो खुद को जितना बड़ा विशेषज्ञ समझता और दावा करता है, वह इस तरह की भविष्यवाणी में उतना ज्यादा विफल साबित होता है।

ऐसे में, बचत और निवेश के मामले में विशेषज्ञों की राय लेने का मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब यह है कि क्या होगा, इसकी भविष्यवाणी के लिए आपको विशेषज्ञों के पास जाने की जरूरत नहीं है। और यह बात मैं इस सच्चाई से अवगत होते हुए कह रहा हूं, कि एक विशेषज्ञ के तौर पर मैं भी कभी-कभी ऐसे विचार व्यक्त कर देता हूं जिसे लोग भविष्यवाणी समझ सकते हैं। इसका अनिवार्य तौर पर मतलब यह है कि हर किसी को अपने बारे में खुद सोचना चाहिए, कम से कम थोड़ा तो सोचना ही चाहिए। विशेषज्ञ सिर्फ यह कर सकता है कि वह एक ऐसा फ्रेमवर्क मुहैया करा दे, निवेशक जिसके अंदर काम कर सके। यह वास्तव में 'भविष्यवाणी बनाम सिद्धांत' की बात है। भविष्यवाणियां काम नहीं आतीं, सिद्धांत काम आते हैं।

इन दोनों में भेद करना बेहद आसान है। जब आप निवेश पर सलाह मांगने जाते हैं, तो अमूमन आपको ऐसे सलाह मिलते हैं कि अमुक कंपनी का ईपीएस अगले वर्ष 17 फीसद की दर से बढ़ेगा और मैं उम्मीद करता हूं कि इसका शेयर भाव 400 रुपये पर पहुंच जाएगा। इस तरह के बयानों की कोई कमी नहीं होती। म्यूचुअल फंड्स और कमोडिटी जैसी संपत्तियों के बारे में भी कमोबेश इसी तरह की भविष्यवाणियां की जाती हैं। इन्हें आप 'टेटलॉक वर्ग के विशेषज्ञ' कह सकते हैं।

इसलिए भविष्यवाणियों की सत्यता और शुद्धता का मतलब ही यही है कि वे विशेषज्ञता को सही ठहराने के ऐसे दावे हैं जो असल में अस्तित्व में होते ही नहीं। इसकी वजह यह है कि किसी भी विशेषज्ञ को सबसे पहले विशेषज्ञता की सीमाओं की पहचान होनी चाहिए।

ऐसी भविष्यवाणियों के साथ दिक्कत यह है कि वे न केवल गलत होते हैं, बल्कि गलत उम्मीदें भी स्थापित करने की कोशिश करते हैं। इसलिए वे कई बार कुछ ऐसा कह जाते हैं जिससे आभास होता है कि यह किसी बड़े विशेषज्ञ ने कहा है। बचतकर्ताओं के साथ दिक्कत यह है कि वे नहीं जानते कि भविष्यवाणी कैसे की जाए, लिहाजा उन्हें विशेषज्ञों पर ही निर्भर रहना चाहिए।

इनमें से कुछ भी सही नहीं है। किसी को खुद के लिए विशेषज्ञ होना है, तो उसे सामान्य ज्ञान के अलावा ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अब यह सामान्य ज्ञान क्या है, इसके बारे में चर्चा फिर कभी।

ट्रंप के राजनीतिक भविष्य की दीवार

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को राहत देते हुए मेक्सिको से लगने वाली सीमा पर दीवार बनाए जाने के लिए पेंटागन के हिस्से के फंड का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है। अमेरिका और मेक्सिको को विभाजित करने वाली दीवार का निर्माण, 2016 के चुनाव के दौरान ट्रंप का प्रमुख वादा था।

कई बार बदली योजना

2016 में चुनाव अभियान के दौरान ट्रंप ने कहा था कि अगर वो सत्ता में आए तो अमेरिका-मेक्सिको सीमा पर एक बड़ी, खूबसूरत कंक्रीट की दीवार का निर्माण कराएंगे। लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्होंने स्टील से बने अवरोध के बारे में बात करना शुरू कर दिया, ताकि सीमा पर तैनात सुरक्षाकर्मी इसके माध्यम से देख सकें। अक्टूबर 2017 में ट्रंप प्रशासन ने 18 और 30 फीट के बीच लंबी दीवार का प्रोटोटाइप सामने रखा। जो कि कंक्रीट और धातु का एक संयोजन था। दिसंबर, 2017 के बाद से ट्रंप ने कहा कि वह एक ठोस दीवार का निर्माण नहीं करना चाहते हैं। बल्कि उसकी जगह स्टील स्लेट्स का निर्माण कराना चाहते हैं। इस साल की शुरुआत में, उन्होंने स्टील स्लेट बैरियर के डिजाइन की एक तस्वीर ट्वीट की।

दीवार की लागत

आधिकारिक और अनौपचारिक निकायों द्वारा दीवार के निर्माण की लागत 12 अरब डॉलर से 70 अरब डॉलर के बीच लगाई गई है। सीमा की आधी लंबाई को कवर करने वाली दीवार के निर्माण की लागत ट्रंप प्रशासन ने 8 अरब डॉलर से 12 अरब डॉलर लगाई है। पूर्व राष्ट्रपति बुश के कार्यकाल के दौरान 650 मील लंबी बाड़ लगाने में 7 अरब डॉलर का खर्च आया था। इस साल की शुरुआत में ट्रंप ने कहा कि वह 1.7 अरब डॉलर के अतिरिक्त 5 .7 अरब डॉलर चाहते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने पहले अनुमान लगाया था कि आधी सीमा तक दीवार की कीमत 25 अरब डॉलर होगी, लेकिन अब उसने कहा है कि वह अभी भी कीमत का पता लगाने के लिए विकल्पों को देख रही है। यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन का कहना है कि, औसतन, एक नई सीमा दीवार बनाने या मौजूदा बाड़ को बदलने के लिए लगभग .6 .5 डॉलर प्रति मील खर्च होता है।

उद्देश्य: राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार देश की सुरक्षा, मेक्सिको से आने वाले अवैध अप्रवासी और मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए यह दीवार बहुत महत्वपूर्ण है।

ब्रेक्जिट ब्रिटेन के लिए बड़ा आर्थिक अवसर

मैनचेस्टर, एएफपी : यूरोप के प्रमुख औद्योगिक शहर मैनचेस्टर पहुंचकर ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा, ब्रेक्जिट देश के लिए आर्थिक तरक्की का बड़ा मौका है, लेकिन पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री टेरीजा मे ने इसे विपरीत हालात वाला मौका बनाकर पेश किया।

जॉनसन ने शनिवार को यहां जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, वह देश में निवेश को बढ़ावा देंगे। ब्रेक्जिट (यूरोपीय यूनियन से अलगाव) के बाद नए व्यापार सौदों को गति देंगे और अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए बंदरगाहों को शुल्क मुक्त बनाएंगे। उन्होंने कहा, जब लोगों ने यूरोपीय यूनियन को छोड़ने के लिए वोट दिया तो उन्होंने सिर्फ ब्रसेल्स के खिलाफ ही वोट नहीं दिया था बल्कि लंदन के खिलाफ भी वोट दिया था। क्योंकि लंदन यूरोपीय यूनियन से जुड़कर देश के सारे फैसले कर रहा था। जॉनसन ने वादा कि वह स्थानीय निकायों को ज्यादा अधिकार देंगे। तेज इंटरनेट और यातायात व्यवस्था स्थापित करेंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा, यूरोपीय यूनियन छोड़ने के बाद हमारे लिए आर्थिक विकास के तमाम अवसर पैदा होंगे। हम वह सब कर पाएंगे जो दशकों से नहीं कर पा रहे थे। हम विकास के लिए उन सभी तरीकों को अपनाएंगे, जो आवश्यक होंगे। जॉनसन ने एक बार फिर वादा किया कि 31 अक्टूबर को वह हर हालत में देश को यूरोपीय यूनियन से बाहर लाएंगे। चाहे इसके लिए उन्हें बिना शर्तों वाला समझौता करना पड़े।

ट्रंप पर महाभियोग चलाने के रास्ते तलाश रही न्यायिक समिति

बढ़ी परेशानी ▶ समिति ने मुलर की रिपोर्ट से जुड़ी जानकारियां उजागर करने को कहा

न्यूयॉर्क टाइम्स से

राष्ट्रपति चुनाव में रूसी दखल का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा

वाशिंगटन : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की परेशानियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। 2016 के राष्ट्रपति चुनावों में रूसी दखल का मामला उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। इस मामले की जांच करने वाले विशेष वकील रॉबर्ट मुलर की रिपोर्ट आने के बाद से ही विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद राष्ट्रपति ट्रंप पर महाभियोग चलाने की मांग कर रहे हैं। अब अमेरिकी संसद के निचले सदन की न्यायिक समिति भी ट्रंप पर महाभियोग चलाने के रास्ते तलाशने में जुट गई है।

न्यायिक समिति ने जस्टिस बेरिल ए हॉवेल से विशेष वकील मुलर की रिपोर्ट से जुड़ी सभी जानकारियां उजागर करने को कहा है। जस्टिस हॉवेल, मुलर की जांच रिपोर्ट से संबंधित ग्रांड जूरी की अध्यक्षता कर रहे हैं। दरअसल ट्रंप पर महाभियोग चलाया जाए या नहीं, इसको लेकर समिति ने छानबीन शुरू कर दी है। समिति का कहना है कि रिपोर्ट के माध्यम से ही यह तय हो पाएगा कि संविधान के किन प्रावधानों के आधार पर ट्रंप पर महाभियोग की कार्रवाई की जा सकती है। शुक्रवार को समिति ने कहा कि न्याय नीति विभाग के पास मौजूदा राष्ट्रपति के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश देने का अधिकार नहीं है। केवल संसद के निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में ही ट्रंप को उनके क्रियाकलापों के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। ऐसा करने के लिए समिति को उन सभी साक्ष्यों तक पहुंचने की जरूरत है, जो रॉबर्ट मुलर ने जुटाए हैं।

वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के ओवल आफिस में एक कार्यक्रम के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। एएफपी

डेमोक्रेट्स को है रिपोर्ट उजागर होने की उम्मीद

विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों को उम्मीद है कि न्यायिक समिति की मांग से जस्टिस हॉवेल सहमत होंगे। उनका भरोसा है कि जिस तरह 1974 में राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के वाटरगेट कांड से संबंधित रिपोर्ट की जानकारी कमेटी को दी गई थी। इसी आधार पर इस मामले में भी मुलर की रिपोर्ट कमेटी को सौंपी जाएगी।

मेक्सिको सीमा पर दीवार बनवाने को रक्षा बजट से धन खर्च करेंगे ट्रंप

वाशिंगटन, आइएएनएस : अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मेक्सिको सीमा पर दीवार बनाने के लिए रक्षा विभाग के बजट आवंटन में से 2.5 अरब डॉलर (करीब 17 हजार करोड़ रुपये) की धनराशि खर्च करने को हरी झंडी दे दी है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि सीमा पर दीवार बनाना देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक है।

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने 5-4 के बहुमत से कैलीफोर्निया की अदालत के उस फैसले को बदल दिया जिसमें कहा गया था कि संसद द्वारा स्वीकृत धनराशि की मद को सरकार नहीं बदल सकती। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2016 के अपने चुनाव अभियान में मेक्सिको सीमा पर दीवार बनाने का वादा किया था। चुनाव जीतने के बाद उनकी कोशिश का काफी विरोध भी हुआ लेकिन ट्रंप टस से मस नहीं हुए और अरबों डॉलर के व्यय से दीवार बनने का काम जारी है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ट्रंप ने बड़ी जीत बताया है। दीवार निर्माण के पीछे ट्रंप का तर्क है कि इससे मेक्सिको से होने वाली अवैध घुसपैठ और नशीले पदार्थों की तस्करी रुकेगी। ट्रंप के अनुसार ज्यादातर ये घुसपैठिये ही अमेरिका में अपराध करते हैं और समस्याओं को बढ़ाते हैं। विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने कहा है कि दीवार बनने से सीमा पर आपातस्थिति जैसे हालात बन गए हैं। उसने दीवार बनाने को धन की बर्बादी करार दिया है। संसद से दीवार को पूरा करने के लिए अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत न होने पर ट्रंप ने रक्षा विभाग को आवंटित धन से दीवार बनवाने का फैसला किया लेकिन कैलीफोर्निया कोर्ट की रोक के बाद प्रक्रिया रुक गई थी। इसी के बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले पर मुहर लगाई

प्रतीकात्मक

हांगकांग में पुलिस ने चलाईं रबर बुलेट तो जवाब में चले पत्थर

हांगकांग के यूएन लोंग कस्बे में प्रदर्शन करते लोग। एएफपी

हांगकांग, एएफपी : चीनी सीमा के नजदीक स्थित हांगकांग के कस्बे में शनिवार को जमकर बवाल हुआ। लोकतंत्र समर्थकों को प्रतिबंध तोड़कर जनसभा करने से पुलिस ने जब रोका तो टकराव हो गया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और रबर बुलेट चलाईं तो आंदोलनकारियों ने पथराव किया। टकराव में नौ लोगों के घायल होने की खबर है जिनमें पांच की हालत गंभीर है। आंदोलनकारी बीते हफ्ते चीन सीमा के नजदीक लोकतंत्र समर्थकों की पिटाई पर विरोध जता रहे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

चीनी सीमा के नजदीक स्थित यूएन लोंग कस्बे दोपहर से शुरू हुआ टकराव रुक-रुककर शाम तक जारी रहा। इस दौरान पुलिस ने आंदोलनकारियों को तितर-बितर करने के लिए कई बार आंसू गैस के गोले छोड़े और रबर बुलेट चलाईं। इलाके में तनाव बना हुआ है। कई स्थानों पर लोगों ने पुलिस की गाड़ियों को घेर रखा है। कस्बे के रेलवे स्टेशन पर भी आंदोलनकारियों ने कब्जा कर रखा है। पिछले सात हफ्तों से जारी प्रदर्शनों और हिंसा में 45 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। आर्थिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र हांगकांग में हफ्तों से बनी अशांति के कारण वहां की पहचान प्रभावित हो रही है। यहां के युवा चीनी शासन का विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग स्वतंत्रता और ज्यादा अधिकारों की है।

चीनी सीमा के नजदीक लोकतंत्र समर्थकों का आंदोलन

बीते रविवार को शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे लोकतंत्र समर्थकों की जब लाठी-डंडों से लैस सफेद टीशर्ट पहने युवकों के दल ने पिटाई की, तो लोगों में गुस्सा फैल गया। इसके बाद पुलिस के कोई कार्रवाई न करने से आंदोलन भड़क उठा। लोगों ने इस पिटाई के लिए चीन समर्थक तत्वों को जिम्मेदार माना। उपनगरीय इलाके में छिड़ा यह आंदोलन हांगकांग शहर में चल रहे चीन विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ ही माना जा रहा है।

इमरान सरकार के विरोध में रैली

पाकिस्तान में इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ देशव्यापी अभियान के दौरान विपक्षी दलों के समर्थकों ने 'ब्लैक दिवस' मनाया और रैलियां निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। आर्थिक संकट से जूझ रही इमरान सरकार को लेकर लोगों में जबरदस्त नाराजगी है। यहां जरूरी चीजों की कीमतों में असहनीय वृद्धि हो गई है। रायटर

ब्रिटेन में भारतीय गैंगस्टर को मिली 18 साल की सजा

लंदन, प्रेट्र : भारतीय मूल के गैंगस्टर बलजिंदर कांग और उसके दाहिने हाथ सुखजिंदर पूनी को ब्रिटिश कोर्ट ने क्रमशः 18 व 16 साल के कारावास की सजा सुनाई है। दोनों नशीले पदार्थों की तस्करी और करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा अवैध रूप से अन्य देशों में भेजने के दोषी पाए गए हैं।

बलजिंदर और उसके गिरोह के सदस्यों को हाल के महीनों में 50 किलोग्राम केटामाइन और कोकीन बेचने का दोषी पाया गया है। केटामाइन और कोकीन तेज नशा करने वाले पदार्थ हैं। पुलिस जांच में पता चला कि बलजिंदर (31) एशो-आराम की जिंदगी जीने का अभ्यस्त है। वह महंगे ब्रांड वाले कपड़े पहनता था, महंगी डिजायनर घड़ियां पहनता था, महंगी कारों में चलता था और अक्सर अय्याशी के लिए संयुक्त अरब अमीरात का दौरा करता था। इसी के लिए वह नशे का अवैध कारोबार करता है। उसे एयरपोर्ट जाते समय गिरफ्तार किया गया था, जहां से उसे दुबई रवाना होना था। बलजिंदर को 18 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। 34 वर्षीय पूनी गिरोह चलाने में बलजिंदर की मदद करता था। किंग्सटन क्राउन कोर्ट ने उसे 16 साल की जेल की सजा सुनाई गई है।

भूकंप के झटकों से दहला फिलीपींस आठ लोगों की जान गई, 60 घायल

5.4 से 5.9 के बीच थी भूकंप की तीव्रता। इसका अनुमान अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक बताया गया है। मौसम विभाग ने अभी सुनामी की कोई चेतावनी नहीं जारी की है।

मनीला, आइएएनएस : शनिवार सुबह लगातार आए भूकंप के झटकों से फिलीपींस दहल उठा। उत्तरी बटानिस द्वीप पर आए भूकंप के झटकों से आठ लोगों की मौत हो गई और 60 घायल हुए हैं। स्थानीय प्रशासन ने लोगों को घर में ही रहने की चेतावनी दी है।

अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 5.4 से 5.9 के बीच थी। सबसे पहला झटका बटानिस स्थित इतबायत शहर में स्थानीय समयानुसार तड़के 4 बज कर 16 मिनट पर महसूस किया गया। फिर सुबह 9.24 बजे 5.7 तीव्रता का एक और भूकंप आया। इस बीच में कई बार भूकंप के हल्के झटके भी महसूस किए। मौसम विभाग ने अभी सुनामी की कोई चेतावनी नहीं जारी की है।

भूकंप के कारण कई चर्च और रिहायशी बिल्डिंग में दरारें आ गई हैं। यहां सक्रिय रेड क्रॉस संस्था ने भूकंप की तस्वीरें भी जारी की है। इन तस्वीरों में इतबायत स्थित चर्च दिख रहा है, जो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। चर्च के बाहर बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए थे। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, बचाव कार्य के लिए प्रभावित इलाकों में सेना को तैनात कर दिया गया है। बता दें कि फिलीपींस भूकंप के लिहाज से अतिसंवेदनशील प्रशांत के 'रिंग ऑफ फायर' क्षेत्र में पड़ता है। इसी के चलते यहां भूकंप के झटके आमतौर पर आते रहते हैं। इससे लोगों को जान-माल का नुकसान उठाना पड़ता है।

उत्तरी बटानिस द्वीप पर आए भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्य में जुटे फिलीपीस कोस्ट गार्ड के जवान और स्थानीय लोग। भूकंप से इतबायत शहर में भारी तबाही हुई है। एपी

ब्रिक्स राष्ट्रों ने की आतंक के वित्तपोषण को रोकने की अपील

रियो डी जेनेरियो, प्रेट्र: भारत ने अन्य ब्रिक्स राष्ट्रों के साथ शुक्रवार को सभी देशों से आतंकी नेटवर्क के वित्तपोषण और अपने क्षेत्रों से आतंकवादी गतिविधियों को रोकने की अपील की। साथ ही सभी देशों से आर्थिक भगोड़ों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। बता दें कि ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) राष्ट्रों के विदेश मामलों/अंतरराष्ट्रीय संबंधों के मंत्रियों की बैठक हो रही है। भारत की तरफ से सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्यमंत्री जनरल (सेवानिवृत्त) वीके सिंह प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

बैठक के दौरान पांचों देशों ने संयुक्त राष्ट्र के तहत अंतरराष्ट्रीय कानून के आधार पर आतंकवाद से लड़ने के लिए ठोस प्रयास करने का आह्वान किया। सभी तरह के आतंकवाद की निंदा करते हुए पांचों देशों ने आतंकवाद को रोकने और उसका मुकाबला करने में देशों तथा उनके सक्षम निकायों की प्राथमिक भूमिका को रेखांकित किया। इन देशों के मंत्रियों ने संकल्प व्यक्त करते हुए

भारत ने आर्थिक भगोड़ों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग दोहराई

कहा कि आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी परिणाम सुनिश्चित करने के लिए व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। बैठक के बाद जारी एक बयान में कहा गया कि व्यापक दृष्टिकोण में कट्टरता, आतंकियों की भर्ती, विदेशी आतंकवादियों के मूवमेंट, आतंक के वित्तपोषण के स्रोतों और माध्यमों को प्रतिबंधित करना, आतंकी ठिकानों को नष्ट करना तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से आतंकी संस्थाओं को इंटरनेट का दुरुपयोग करने से रोकना शामिल होना चाहिए। विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी जैसे आर्थिक भगोड़ों के संबंध में वीके सिंह ने कहा कि ब्रिक्स राष्ट्रों को ऐसे मामलों में मिलकर काम करने की जरूरत है। इस दौरान सिंह ने पीएम मोदी के उन 9-बिंदुओं वाले एजेंडे को दोहराया, जो उन्होंने अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में हुए जी-20 शिखर सम्मेलन 2018 में आर्थिक भगोड़ों की संपत्ति जब्त करने के संबंध में दिया था।

ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक रिया डे जेनेरियो में हुई। इस अवसर पर (बाएं से दाएं) चीन के विदेश मंत्री वांग यी, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, ब्राजील के विदेश मंत्री अर्नेस्टो अरुजो, भारत के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री वीके सिंह और दक्षिण अफ्रीका के अंतरराष्ट्रीय मामले एवं सहयोग मंत्री ग्रेस नलदेई मंदिसा पंडोर। एएफपी

अफगानिस्तान की अगुवाई वाली शांति प्रक्रिया के समर्थन की बात दोहराई

ब्रिक्स राष्ट्रों ने अफगानिस्तान की अगुआई वाली शांति प्रक्रिया के समर्थन के लिए अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रयासों के समर्थन की बात एक बार फिर से दोहराई है। बैठक के दौरान अफगान सुरक्षा बलों, सरकारी अधिकारियों और आम लोगों पर बढ़ते हमले पर भी चिंता व्यक्त की गई।

खाड़ी संकट पर बातचीत का आग्रह

भारत के साथ ही ब्रिक्स सदस्य देशों ने खाड़ी क्षेत्र में बढ़ रहे तनाव पर चिंता व्यक्त की है। सदस्य देशों ने संबंधित पक्षों से इस मुद्दे पर आपस में बातचीत करने का आग्रह किया। बता दें कि कुछ दिनों पहले ईरान और ब्रिटेन ने एक-दूसरे के तेल टैंकरों को पकड़ लिया था।

पाक के 50 फीसद परिवारों को दोनों वक्त का खाना नसीब नहीं

कराची, प्रेट्र : पाकिस्तान में कराए गए अपनी तरह के पहले सर्वेक्षण में पता चला है कि देश के आधे से ज्यादा परिवारों को दिन में दोनों वक्त का खाना भी नसीब नहीं है। जिसकी वजह से उनकी पोषण जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं और बड़ी संख्या में बच्चे भी कुपोषित हो रहे हैं।

'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' के मुताबिक राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा मंत्रालय द्वारा कराए गए नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे में पता चला है कि पाकिस्तान के 40.2 फीसद बच्चे कुपोषण और अवरुद्ध विकास के शिकार हैं। इसके मुताबिक 36.9 फीसद पाकिस्तानी परिवारों को खाना मिलने या नहीं मिलने को लेकर असुरक्षा का भाव रहता है। इसमें यह भी पता चला कि 48.4 फीसद पाकिस्तानी महिलाएं ही अपने शिशुओं को स्तनपान कराती हैं।

इस सर्वे में 1,15,600 परिवारों को शामिल किया गया। इनमें 1,45,324 महिलाएं, 76,724 पांच साल से कम उम्र के बच्चे और 1,45,847 10-19 साल के नाबालिग शामिल हैं। इस दौरान सर्वे करने वाली टीमों ने सर्वे में हिस्सा लेने वालों के खून और पेशाब के नमूने लिए। साथ ही उनके घरों के आस-पास पानी की गुणवत्ता और सीवेज की स्थिति की जांच भी की। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ के चेयरमैन प्रो. जमाल रजा ने हालात को चिंताजनक बताया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में 24 साल पहले भी इतने ही प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार थे।

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की पोशाक पर विवाद

इस्लामाबाद, प्रेट्र : अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात के दौरान पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा पहनी गई पोशाक को लेकर विवाद पैदा हो गया है। एक बड़े डिजाइनर ने दावा किया है कि उस पोशाक को उन्होंने बनाया था। इमरान ने ह्वाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात के दौरान नेवी ब्ल्यू सलवार-कमीज और अपनी पसंदीदा पेशावरी चप्पल पहन रखी थी। प्रवासी पाकिस्तानियों के लिए नियुक्त इमरान के सहायक जुल्फी बुखारी ने इस दावे को खारिज किया है।

मैंने राजस्थान में पहली बार कोई फुटबॉल अकादमी देखी है और यहां जिंक अकादमी में विश्व स्तरीय सुविधा मौजूद है। – सुनील छेत्री, कप्तान भारतीय फुटबॉल टीम

बांग्लादेश के स्पिन कोच बने डेनियल विटोरी

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ने न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान डेनियल विटोरी को स्पिन गेंदबाजी का कोच नियुक्त किया है। इसके साथ ही बांग्लादेश बोर्ड ने दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज चार्ल्स लैंगवेल्ट को भी टीम का तेज गेंदबाजी कोच बनाया है। लैंगवेल्ट दो वर्ष तक टीम के साथ जुड़े रहेंगे, वहीं विटोरी 2020 में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी-20 विश्व कप तक टीम के साथ जुड़े रहेंगे।

विवाद ▸ खिलाड़ी से 'ऑल इज वेल' कहलवाना चाहता है सीओए, सोशल मीडिया पर लिखवानी थी एकता की बात

नहीं सुलझ पा रहा है टीम इंडिया का विवाद

टीम इंडिया के प्रदर्शन पर असर डाल सकता है विवाद

नई दिल्ली, आइएएनएस : भारत की वनडे टीम के सीनियर खिलाड़ियों के बीच मनमुटाव बढ़ता जा रहा है। बीसीसीआइ के एक सीनियर प्रशासक ने कोशिश की थी कि कोई खिलाड़ी सोशल मीडिया पर टीम में एकता की बात को कहता हुआ एक पोस्ट लिखे, लेकिन इस पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि प्रशासकों की समिति (सीओए) ने खिलाड़ियों से बात की और सोशल मीडिया पर टीम में 'सब कुछ सही है' जैसी पोस्ट करने को कहा।

अधिकारी ने कहा, 'हर कोई जानता है कि खिलाड़ियों के बीच मनमुटाव है। हालांकि सीओए प्रमुख विनोद राय ने मीडिया में इस तरह की खबरों को सिरे से खारिज किया है, लेकिन सीओए के एक सदस्य ने टीम के लिए सीनियर खिलाड़ी से इस मामले पर सकारात्मक संदेश भेजने को कहा था, लेकिन इस मामले में ज्यादा प्रगति नहीं हुई है।'

दूसरी ओर, सीओए के एक सदस्य ने कहा कि वह तब तक इस मामले में नहीं पड़ेंगे जब तक खिलाड़ी इस मुद्दे को लेकर नहीं आते। सदस्य ने कहा, 'सीओए मीडिया में आने वाली खबरों पर प्रतिक्रिया नहीं दे सकती। अगर खिलाड़ियों को कोई शिकायत है तो उन्हें हमारे पास आना चाहिए। जहां तक समिति की जानकारी की बात है तो जब तक खिलाड़ी हमारे पास नहीं आते तब तक हमारे लिए कोई विवाद नहीं है।' सीओए इस मुद्दे में तब आई जब रोहित शर्मा ने कप्तान विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा को इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया था।

टीम इंडिया के उप कप्तान रोहित शर्मा, कप्तान विराट कोहली, मुख्य चयनकर्ता एमएसके प्रसाद और कोच रवि शास्त्री। फाइल फोटो

गेंदबाजों को लगी थी फटकार : टीम में विवाद विश्व कप में लीग मैच में इंग्लैंड के खिलाफ मिली हार के बाद से शुरू हुआ था। इस मामले से संबंध रखने वाले एक सूत्र ने कहा, 'हार के बाद गेंदबाजों को फटकार लगी थी और उनको लगता था कि यह सिर्फ खराब गेंदबाजी की बात नहीं है। साथ ही सुधार करने के लिए और भी क्षेत्र हैं। सिर्फ गेंदबाजों को निशाना बनाया जाए इससे बेहतर है कि बाकी की जगहों पर भी सुधार किया जाए।' बोर्ड के एक और अधिकारी ने कहा कि टीम में विवाद की खबरों पर ध्यान दिया जाना चाहिए और इससे पहले ही इससे टीम के प्रदर्शन पर फर्क पड़े, इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए।

मामला मीडिया की उपज तो तवज्जो क्यों? : बोर्ड के अधिकारी ने कहा, 'यह किसी कामकाजी जगह में होने वाले विवाद की तरह है, जिससे टीम के प्रदर्शन पर असर पड़ सकता है। अगर इसे तुरंत नहीं सुलझाया गया तो यह काफी खतरनाक हो सकता है और इससे टीम भावना पर असर पड़ सकता है।' अधिकारी ने कहा, 'आपकी टीम के दो कप्तान नहीं हो सकते और उनकी मैनेजमेंट कंपनियां एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप का खेल नहीं खेल सकतीं। टीम में विवाद है इसमें कोई शक नहीं है। वहीं सीओए विनोद राय कह रहे हैं कि यह मीडिया की उपज है। अगर यही बात है तो मीडिया की उपज को तवज्जो क्यों दी जा रही है।'

टेंडर प्रक्रिया पर उठे सवाल

नई दिल्ली : बीसीसीआइ के कार्यकारियों ने फैसला किया है कि टीम के प्रमुख प्रायोजक के लिए टेंडर प्रक्रिया 29 जुलाई को शुरू होगी और यह एम जंक्शन के साथ मिलकर आयोजित की जाएगी। हालांकि बोर्ड के अधिकारी इससे खुश नहीं हैं कि नीलामी प्रक्रिया के आवेदन ऑनलाइन खरीदे और दाखिल की जाएगी। इसमें ई-नीलामी तभी होगी जब इसकी जरूरत होगी। उनका मानना है कि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं है। बीसीसीआइ के एक सीनियर अधिकारी ने कहा है कि ई-नीलामी की जो प्रक्रिया मीडिया राइट्स के समय लागू की गई थी उसमें अचानक से बदलाव करना लोढ़ा समिति के प्रस्ताव के खिलाफ है। अधिकारी ने कहा, 'लोढ़ा समिति ने जो पहली चीज प्रस्तावित की थी वो पारदर्शिता थी और अब सीओए की आंख के नीचे यह सब हो रहा है जिसके प्रमुख पूर्व में सीएजी रह चुके हैं। हमें इस पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि भारतीय क्रिकेट के मीडिया अधिकारों की नीलामी के समय जिस ई-नीलामी प्रक्रिया का पालन किया गया था वो अलग थी। प्रक्रिया में बदलाव क्यों? आपके हिसाब से पहले वित्तीय नीलामी की जाएगी और फिर अगर जरूर पड़ी तो ई-नीलामी की जाएगी। इस प्रक्रिया पर शक होना स्वाभविक है। यह हैरान करने वाली बात है कि प्रक्रिया अचानक से बदल दी गई और किसी को जानकारी नहीं।

टेस्ट क्रिकेट के लायक नहीं लॉर्ड्स की पिच : जो रूट

क्रिकेट डायरी

लंदन, एएनआइ : आयरलैंड के खिलाफ टेस्ट जीतने के बाद इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने लॉर्ड्स की पिच को टेस्ट के लायक नहीं बताया है। उनके मुताबिक यहां बल्ले और गेंद के बीच साफ-सुथरा मुकाबला नहीं हुआ।

रूट ने कहा कि मैं यह कहना नहीं चाहता लेकिन कहना पड़ेगा कि यह विकेट टेस्ट के लायक नहीं है। मुझे लगता है कि यह अच्छी पिच नहीं थी। यहां पर गेंद और बल्ले के बीच साफ-सुथरा मुकाबला नहीं हुआ। इंग्लैंड यहां पहली पारी में 85 रन पर ढेर हो गई थी और आयरलैंड के टिम मुर्टाघ ने पांच विकेट लिए थे। आयरलैंड की टीम 207 रन बनाने में कामयाब हुई और 122 रनों की बढ़त ले ली, लेकिन इंग्लैंड दूसरी पारी में 303 रन बना गई और इससे आयरलैंड को 182 रनों का लक्ष्य मिला। आयरलैंड की टीम इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकी और 38 रनों पर ढेर हो गई। जीत से अलग रूट ने कहा कि टीम अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं खेली। रूट ने कहा कि हम पूरी तरह से सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट नहीं खेले। हमने कुछ हिस्सों में अच्छा किया। हमें आयरलैंड ने दबाव में ला दिया था। उन्होंने पहले दिन की सुबह परिस्थितियों का अच्छे से इस्तेमाल किया, लेकिन हमें मैच जीतने का रास्ता मिल गया। पहली पारी में और आखिरी पारी में जब आप ऐसे स्कोर बनाते हो तो यह सारी कहानी खुद बयां कर देता है। इंग्लैंड की टीम को अब एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया का सामना करना है। इस पर रूट ने कहा कि एशेज क्रिकेट हमेशा से ही खास रहता है और खिलाड़ी अब इसके लिए तैयार हैं।

सैम और लीच की रैंकिंग में सुधार

दुबई : आयरलैंड के खिलाफ एकमात्र टेस्ट जीतने के बाद इंग्लैंड के खिलाड़ियों सैम और जैक लीच की टेस्ट रैंकिंग में सुधार हुआ हे। लीच ने दूसरी पारी में 92 रन बनाए थे और वह 57 स्थानों की छलांग लगाते हुए 117वें स्थान पर पहुंच गए हैं। इसके अलावा सैम तीन स्थान की छलांग लगाकर 52वें स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं मैच में सात विकेट लेने वाले स्टुअर्ट ब्रॉड गेंदबाजों की रैंकिंग में एक स्थान ऊपर 18वें स्थान पर पहुंच गए हैं। इसके अलावा वोक्स 33वें स्थान पर पहुंच गए हैं।

बैगी ग्रीन मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है : बेनक्राफ्ट

लंदन : बॉल टेंपरिंग मामले में नौ महीने का प्रतिबंध झेलने वाले कैमरन बेनक्राफ्ट ने आखिरकार राष्ट्रीय टीम में वापसी कर ली है। बेनक्राफ्ट का नाम इंग्लैंड में एशेज सीरीज खेलने वाले 17 सदस्यीय टेस्ट टीम में शामिल किया गया है। बेनक्राफ्ट फिलहाल इस खबर से काफी खुश हैं लेकिन प्रतिबंध के दौरान और उसके कुछ समय बाद तक, जबकि वो टीम से बाहर थी, उन्होंने काफी मुश्किल समय बिताया। हालांकि इस दौरान जिस चीज ने उन्हें लगाकर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी वो थी ऑस्ट्रेलिया की बैगी ग्रीन टोपी। ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज ने रहस्योद्घाटन किया कि डरहम के लिए काउंटी क्रिकेट खेलते समय भी वह इस टोपी को अपने बैग में हमेशा रखते थे। यह ऐसी चीज है जिस पर आपको काफी गर्व होता है। यह बहुत कीमती चीज है।

टिके रहने के लिए मैच विजेता होना जरूरी : लसिथ मलिंगा

वनडे से संन्यास लेने वाले श्रीलंका के तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा। फाइल फोटो

कोलंबो, प्रेट्र : वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने वाले श्रीलंका के महान तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा ने कहा कि क्रिकेट में टिके रहने के लिए आपका मैन विजेता होना जरूरी है। मलिंगा ने शुक्रवार को बांग्लादेश के खिलाफ अपना आखिरी वनडे मैच खेला। आखिरी मुकाबले में भी मलिंगा ने धारदार गेंदबाजी की और 38 रन देकर तीन विकेट चटकाए। मेजबान टीम ने 91 रनों से मुकाबला जीतकर मलिंगा को दमदार विदाई दी।

मैच के बाद मलिंगा ने कहा कि मेरे कप्तान मुझसे विकेट लेने की उम्मीद करते हैं। मैंने अपने पूरे करियर में अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि युवा गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करेंगे क्योंकि क्रिकेट में हर कोई आगे नहीं जा सकता। आपको मैच विजेता बनना पड़ेगा। मलिंगा ने कहा कि मैं भविष्य में यही देखना चाहता हूं। इन युवा गेंदबाजों को मैच जीतने वाला प्रदर्शन करना होगा जिससे लोगों को कहना पड़े कि यह एक मैच विजेता गेंदबाज है। हमारे पास कुछ गेंदबाज हैं और हमें उनकी देखभाल करनी होगी।

वनडे क्रिकेट में तीन हैट्रिक लेने वाले मलिंगा एकलौते गेंदबाज हैं। उन्होंने इस प्रारूप में 226 मैचों में कुल 338 विकेट लिए हैं। उन्होंने 2004 में श्रीलंका के लिए पहला मैच खेला था। मलिंगा ने घरेलू दर्शकों के सामने संन्यास लेने का फैसला किया और उनके इस फैसले का सम्मान करते हुए हजारों दर्शक अपने इस चहेते खिलाड़ी को विदाई देने पहुंचे।

> अगर मुझे मुंबई इंडियंस के लिए पिछले एक दशक में किसी एक मैच मैच विनर को चुनना हो तो यह शख्स उसमें टॉप पर होगा। एक कप्तान के तौर पर वह मुझे तनावग्रस्त स्थिति में आराम देते हैं और हमेशा उम्मीदों पर खरे उतरते है। टीम में उनकी भूमिका ऐसी ही थी। मलिंगा आपको भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं।
> –रोहित शर्मा

> मलिंगा की शानदार गेंदबाजी। आपने क्रिकेट के लिए जो कुछ किया उसके लिए धन्यवाद। मैंने हमेशा आपसे सीखा है और आगे भी ऐसा करता रहूंगा।
> –जसप्रीत बुमराह

मलिंगा ने कहा कि मैंने पिछले 15 साल श्रीलंका के लिए खेला। देश के लिए खेलना सम्मान की बात है और मेरा समर्थन करने वाले इन लोगों एवं दर्शकों के लिए खेलकर मैं वास्तव में बहुत खुश हूं। मुझे लगता है कि अब मुझे आगे बढ़ने होगा क्योंकि हमें 2023 विश्व कप के लिए टीम बनानी है और इसलिए मुझे एहसास हुआ कि ठीक है मेरा समय खत्म हो गया है और मुझे जाना चाहिए। मलिंगा ने इस साल आइपीएल फाइनल में शानदार गेंदबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस को चौथी बार विजेता बनाया था। चेन्नई सुपर किंग्स को आखिरी ओवर में आठ रन बनाने थे लेकिन मलिंगा की गेंदबाजी के आगे सीएसके के बल्लेबाज पस्त हो गए थे।

आमिर ने मांगी ब्रिटेन की नागरिकता, पाक के लिए नहीं खेलना चाहते

टेस्ट से संन्यास लेने पर पाकिस्तानी दिग्गज अपने तेज गेंदबाज पर भड़के

कराची, एएफपी : पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मुहम्मद आमिर ने शुक्रवार को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करके सबको चौंका दिया। शोएब अख्तर, वसीम अकरम और रमीज राजा जैसे दिग्गज क्रिकेटरों ने उनके इस फैसले को हैरान करने वाला बताया। हालांकि टेस्ट से संन्यास लेने के बाद आमिर ने कहा है कि वह वनडे और टी-20 के लिए उपलब्ध रहेंगे। उनका तात्कालिक लक्ष्य अगले साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी20 विश्व कप के लिए खुद को तैयार करना है।

आमिर के करीबी क्रिकेटरों का दावा है कि आमिर अब पाकिस्तान के लिए नहीं खेलना चाहते हैं। उन्होंने ब्रिटेन की नागरिकता के लिए आवेदन दिया है। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार आमिर ब्रिटेन में मकान भी खरीदने वाले हैं ताकि स्थायी रूप से वहीं रह सकें। आमिर ने 2016 में ब्रिटिश नागरिक नरगिस मलिक से शादी की थी। पाकिस्तान के अखबार 'द ट्रिब्यून' के मुताबिक, आमिर ने स्पाउस वीजा (पत्नी की नागरिकता के आधार पर मिलने वाला वीजा) के लिए आवेदन किया है। शुरुआत में यह 30 महीने के लिए मिलाता है। बाद में संबंधित व्यक्ति अगर तय मानकों को पूरा करता है तो उसे स्थायी नागरिकता और ब्रिटिश पासपोर्ट भी मिल सकता है। स्पाउस वीजा मिलने के बाद आमिर ब्रिटेन में आजीविका के लिए काम भी कर सकते हैं। फिलहाल, वह लंदन में घर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं।

पाक के तेज गेंदबाज आमिर। फाइल फोटो

> मेरे लिए आमिर का टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेना थोड़ा आश्चर्य की बात है क्योंकि आप 27–28 की उम्र में शिखर पर हैं और टेस्ट क्रिकेट में आपको सर्वश्रेष्ठ के खिलाफ आंका जाता है। ऐसे समय आपने संन्यास ले लिया।
> –वसीम अकरम, पूर्व पाकिस्तानी गेंदबाज

आमिर को स्थायी ब्रिटिश नागरिकता मामले में एक परेशानी आ सकती है। दरअसल, स्पॉट फिक्सिंग मामले में ब्रिटिश कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया था। इस मामले में ब्रिटिश जेल में सजा भी काट चुके हैं। गृह विभाग इस मामले में आपत्ति दर्ज करा सकता है। वहीं, एक पक्ष ये भी है कि सजा काटने के बाद कई बार आमिर ब्रिटेन जा चुके हैं। वहां उन्होंने काउंटी क्रिकेट भी खेला है। लिहाजा, ये भी मुमकिन है कि अच्छे बर्ताव को आधार मानते हुए फिक्सिंग मामला रोड़ा न बने।

रिपोर्ट में कहा गया है कि आमिर के साथ पाकिस्तान के लिए खेलने वाले कई खिलाड़ी आमिर के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की खबर से हैरान नहीं हैं। दरअसल, ये खिलाड़ी अच्छी तरह ये जानते हैं कि ये तेज गेंदबाज अब न तो पाकिस्तान में रहना चाहता है और न ही पाक टीम से खेलना चाहता है। वह इंग्लैंड और दुनियाभर की टी-20 लीग में खेलना चाहता है। पाकिस्तान को अगली सीरीज श्रीलंका के खिलाफ यूएई में खेलना है। वहां की पिच तेज गेंदबाजों के लिए मददगार नहीं हैं। आमिर ने इस सीरीज से पहले ही टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है।

टी–20 व वनडे में भी नहीं खिलाना चाहिए : अख्तर

लाहौर : पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने कहा कि स्पॉट फिक्सिंग में प्रतिबंध के बाद पाकिस्तान ने उन्हें खेलने का मौका दिया और अब आमिर के लिए उसका बदला चुकाना का समय था। मैं इस बात से पूरी तरह से निराश हूं कि आमिर उस उम्र में संन्यास ले रहे हैं जहां ये खिलाड़ी अपने करियर के चरम पर है। उन्होंने कहा कि आमिर के लिए पाकिस्तान का बदला चुकाने का समय आ गया था। जब टेस्ट मैचों में पाकिस्तान की जीत का प्रतिशत खराब है तो टीम को आमिर के सहयोग की जरूरत थी। उन्हें पाकिस्तान को कुछ सीरीज जीतने में मदद करनी चाहिए थी जैसे मैंने इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में पाकिस्तान को सीरीज जीतने में मदद की थी। अगर मैं पाकिस्तान चयन बोर्ड का हिस्सा होता तो मैं इस लड़के को किसी भी प्रारूप में खेलने की अनुमति नहीं देता। कई बार ऐसा होता है जब आपको पैसा कमाना चाहिए लेकिन यह वह समय है जब पाकिस्तान को आपकी जरूरत है। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान बोर्ड से इस मामले को देखने का अनुरोध करता हूं। आमिर सिर्फ 27 साल के हैं और उनके संन्यास से हमें खिलाड़ियों की मानसिकता का पता चलता है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए इस मामले को देखने का समय है ताकि वे गतिशील और ऊर्जावान लोगों को टीम में ला सकें। ये सभी खिलाड़ी सिर्फ टी–20 गेंदबाज बनना चाहते हैं।

भारत–ए की जीत में चमके नदीम

अनाधिकारिक टेस्ट

▸ वेस्टइंडीज–ए को दी पहले टेस्ट में छह विकेट से शिकस्त

▸ स्पिनर शाहबाज ने दूसरी पारी में भी झटके पांच विकेट

नार्थ साउंड, प्रेट्र : शहबाज नदीम (47/5) और मुहम्मद सिराज (38/3) की शानदार गेंदबाजी के दम पर भारत-ए ने यहां सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में खेले जा रहे पहले अनाधिकारिक टेस्ट मैच के चौथे दिन भारत-ए ने वेस्टइंडीज-ए को छह विकेट से शिकस्त दे दी। इसी के साथ भारत-ए ने तीन अनाधिकारिक टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है।

भारत-ए को जीत के लिए 97 रनों का लक्ष्य मिला था। चौथे दिन एक विकेट पर 29 रन से आगे खेलते हुए भारत-ए ने इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तीन और विकेट गंवा दिए और 30 ओवर में चार विकेट के नुकसान पर 97 रन बनाकर मैच जीत लिया। भारत-ए के लिए अभिमन्यु ईश्वरन ने 35 गेंद पर 27, जबकि श्रीकर भरत ने 40 गेंद पर 28 रन बनाए। वेस्टइंडीज की ओर से रकीम कॉर्नवाल ने सबसे ज्यादा दो विकेट लिए। इससे पहले मैच के तीसरे दिन गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत-ए ने वेस्टइंडीज-ए को उसकी दूसरी पारी में 180 रन पर ढेर कर दिया था। वहीं, पहली पारी में वेस्टइंडीज ने 228 रन बनाए थे।

भारत-ए ने अपनी पहली पारी में 312 रन का स्कोर बनाया था। टीम के लिए शिवम दुबे ने 71, रिद्धिमान साहा ने 66, प्रियांक पांचाल ने 49, शुभमन गिल ने 40 और कप्तान हनुमा विहारी ने 31 रन बनाए। वेस्टइंडीज-ए की तरफ से मिग्युएल कमिंस ने चार विकेट अपने नाम किए। जोमेस वैरिकन, चेमार होल्डर और रहकीम कॉर्नवाल ने दो-दो विकेट लिए।

एशेज के लिए इंग्लैंड टीम में शामिल हुए आर्चर

एशेज

लंदन, रायटर : ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज सीरीज के पहले टेस्ट के लिए इंग्लिश टीम की घोषणा हो गई है। 14 सदस्यीय टीम में इंग्लैंड को विश्व चैंपियन बनाने वाले तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को पहली बार शामिल किया गया है। वह एक अगस्त से बर्मिंघम में होने वाले पहले टेस्ट में खेल सकते हैं। बेन स्टोक्स और जोस बटलर की टीम में वापसी हुई है।

टीम की कमान जो रूट के पास है तो स्टोक्स को उपकप्तान बनाया गया है। इस टीम में आयरलैंड के खिलाफ जीत के हीरो रहे लेविस ग्रेगरी और मैन ऑफ द मैच जैक लीच को भी शामिल किया गया है। लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर आयरलैंड के खिलाफ खेले गए मैच की दूसरी पारी में छह विकेट झटकने वाले क्रिस वोक्स को भी मौका मिला है।

इंग्लैंड टीम : जो रूट (कप्तान), मोइन अली, जिमी एंडरसन, जोफ्रा आर्चर, जॉनी बेयरस्टॉ, स्टुअर्ट ब्रॉड, रोरी बर्न्स, जोस बटलर, सैम करन, जो डेनली, जेसन रॉय, बेन स्टोक्स, ऑली स्टोन, क्रिस वोक्स।

ऑस्ट्रेलिया : टिम पेन (कप्तान), कैमरन बेनक्राफ्ट, पैट कमिंस, मार्कस हैरिस, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, उस्मान ख्वाजा, मारनस लाबुस्चग्ने, नाथन लियोन, मिशेल मार्श, माइकल नेसेर, जेम्स पैटिंसन, पीटर सिडल, स्टीव स्मिथ, टार्क, मैथ्यू वेड और डेविड वॉर्नर।

इंजेक्शन लगाकर विश्व कप में खेले जोफ्रा आर्चर

लंदन : इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने बताया कि विश्व कप के दौरान उन्हें बहुत दर्द झेलना पड़ा और वह टूर्नामेंट के दूसरे चरण में बिना दवाइयों (पेन किलर) के एक मुकाबला भी नहीं खेल पाए। आर्चर ने विश्व कप में इंग्लैंड के लिए कुल 20 विकेट लिए और मेजबान टीम को पहली बार खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई। आर्चर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल मुकाबले में सुपर ओवर में भी गेंदबाजी की थी। टूर्नामेंट के पांचवें मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ आर्चर को चोट लगी थी।

कैरी को नहीं चुनने पर नाराजगी

सिडनी : एशेज सीरीज के लिए चुनी गई ऑस्ट्रेलियाई टीम में एलेक्स कैरी को नहीं शामिल करने से ऑस्ट्रेलिया के पूर्व महान खिलाड़ी मार्क वॉ और शेन वॉर्न ने हैरानी जताई जबकि मार्क टेलर ने कहा कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि जो बर्न्स और कुर्टिस पैटरसन को नहीं चुना गया। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ पांच टेस्ट मैचों की सीरज के लिए शुक्रवार को 17 सदस्यीय टीम का चयन किया था। 128 टेस्ट खेलने वाले वॉ ने ट्वीट किया, 'एलेक्स कैरी नहीं है, यह मजाक तो नहीं। विश्व कप के प्रदर्शन को देखते हुए यह बहुत हैरानी की बात है।'

फुटबॉल डायरी

एटलेटिको ने चिर प्रतिद्वंद्वी रीयल मैड्रिड को बड़े अंतर से रौंदा

कोस्टा के चार गोल की मदद से 7–3 से जीता एटलेटिको मैड्रिड, दोस्ताना मैच में डिएगो और कर्वाजल को मिला रेड कार्ड

न्यूयॉर्क, एएफपी : डिएगो कोस्टा के चार गोल की मदद से स्पेनिश फुटबॉल क्लब एटलेटिको मैड्रिड ने अपने चिर प्रतिद्वंद्वी रीयल मैड्रिड को मेटलाइफ स्टेडियम में खेले गए एक दोस्ताना मुकाबले में 7-3 से करारी शिकस्त दी।

आलम यह था कि हाफ टाइम तक कोस्टा (पहले, 28वें, 45वें और 51वें मिनट) हैट्रिक लगाकर अपनी टीम को 5-0 की बढ़त दिला चुके थे और दूसरे हाफ में रेड कार्ड मिलने से पहले उन्होंने इस मुकाबले का अपना चौथा गोल दागा। यूरोप के बाहर खेला गया यह मुकाबला रीयल के मैनेजर जिनेदिन जिदान के लिए बेहद परेशान करने वाला रहा। इस दौरान रीयल के लुका जोविक की एटलेटिको के कीपर जैन ओबलाक के साथ गंभीर टक्कर देखने को मिली जिसने जिदान को सकते में डाल दिया। हाल ही में बेनफिका को छोड़कर स्पेनिश क्लब से जुड़े 19 वर्षीय जोआओ फेलिक्स (आठवें) ने एटलेटिको के लिए अपना पहला गोल दागा। इसके अलावा एंजेल कोरिया (19वें मिनट) और विटोलो (70वें मिनट) ने भी मैनेजर डिएगो सिमोन की टीम के लिए स्कोर किया। मुकाबले में बड़े अंतर से पिछड़ रही रीयल मैड्रिड को नाचो (59वें मिनट) ने ईडन हेजार्ड की मदद से गोल करके वापसी कराई। इसके कुछ ही देर बाद कोस्टा और रीयल के डानी कर्वाजल के बीच में मैदान पर भिड़ंत हो गई जिसके बाद दोनों को रेफरी ने रेड कार्ड दिखाकर बाहर किया। करीम बेंजमा (85वें मिनट) ने पेनाल्टी किक जबकि जेवियर हर्नांडेज (89वें मिनट) ने एकल प्रयास से गोल करके रीयल के हार के अंतर को थोड़ा कम किया लेकिन फिर भी एटलेटिको ने एक बड़ी जीत दर्ज की। विवादों में चल रहे रीयल के स्टार स्ट्राइकर गेरेथ बेल को दूसरे हाफ में जिदान ने मैदान में उतारा लेकिन वह अपनी चमक नहीं बिखेर सके।

मैच में हैट्रिक लगाने वाले एटलेटिको के डिएगो कोस्टा। एपी

जिदान और रामोस निराश : उधर रीयल की इस करारी हार से उसके मैनेजर जिदान निराश दिखे। उन्होंने कहा कि एटलेटिको हमसे हर मामले में अच्छा खेली। अब बात करने के लिए कुछ बचा नहीं है। हम एक सत्र के लिए तैयारी कर रहे हैं और हमें शांत रहना होगा। हमें 17 अगस्त को होने वाले पहले लीग मुकाबले के लिए तैयार रहना होगा। अभी के लिए हममें काफी कमी दिख रही है। वहीं रीयल के कप्तान सर्जियो रामोस ने कहा कि वाकई में हम अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। कई तरीके से इंसान हारता है लेकिन ऐसे नहीं हारता जैसा हम हारे।

प्रति सप्ताह एक मिलियन पाउंड का करार कर सकते हैं बेल

पेरिस : एक रिपोर्ट के मुताबिक रीयल मैड्रिड के स्टार स्ट्राइकर गेरेथ बेल चाइनीज सुपर लीग के क्लब जिआंगसु सनिंग के साथ एक मिलियन पाउंड (करीब साढ़े आठ करोड़ रुपये) प्रति सप्ताह का करार कर सकते हैं। वेल्स के 30 वर्षीय स्ट्राइकर बेल द्वारा उनके मौजूदा स्पेनिश क्लब को छोड़ने की खबरें काफी समय से चल रही हैं। रीयल के मैनेजर जिनेजिन जिदान ने यह भी कह दिया है कि वह उनकी भविष्य की योजनाओं में शामिल नहीं हैं। स्पेनिश मीडिया के मुताबिक अगर जिआंगसु के साथ बेल का करार होता है तो उन्हें चीन में खेलने के बदले प्रति सत्र 22 मिलियन यूरो (करीब एक अरब 68 करोड़ रुपये) मिलेंगे। चाइनीज ट्रांसफर विंडो अगले बुधवार को बंद हो रही है। ऐसे में संभावना है कि बेल उससे पहले करार की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। बेल 2013 में इंग्लिश क्लब टॉटनहम को छोड़कर रीयल मैड्रिड से जुड़े थे। पिछले दिनों जिदान ने बेल पर आरोप लगाया था कि उन्होंने बायर्न म्यूनिख के खिलाफ हुए मुकाबले में मैदान में उतरने से इन्कार कर दिया था।

प्रणीत की हार के साथ भारतीय चुनौती समाप्त

टोक्यो, प्रेट्र : भारत के बी साई प्रणीत को यहां जारी जापान ओपन के पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में शिकस्त झेलनी पड़ी। विश्व नंबर एक जापान के केंतो मोमोता ने प्रणीत को सीधे गेमों में 21-18, 21-12 से पराजित करते हुए टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। यह मुकाबला 45 मिनट तक चला।

प्रणीत की हार के साथ ही प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती समाप्त हो गई है। स्टार शटलर पीवी सिंधू और एचएस प्रणय पहले ही हारकर बाहर हो गए थे। क्वार्टर फाइनल में प्रणीत ने इंडोनेशिया के टॉमी सुगियार्तो को हराया था। मोमोता के खिलाफ भारतीय खिलाड़ी की शुरुआत अच्छी रही और उन्होंने 3-1 की बढ़त बना ली। हालांकि, मोमोता ने वापसी की और 11-8 से आगे हो गए। प्रणीत ने अपने खेल को बेहतर करने का प्रयास किया, लेकिन वह वापसी करने में कामयाब नहीं हो पाए और 23 मिनट में गेम हारकर मुकाबले में पिछड़ गए। दूसरे गेम में भी प्रणीत शुरुआत में 9-6 से आगे थे, लेकिन शीर्ष वरीय जापानी खिलाड़ी ने वापसी की और 12-9 की बढ़त बना ली।

14 लाख करोड़ रुपये है उत्तराखंड की तीन वन सेवाओं की स्टाक वैल्यू। ग्रीन अकाउंटिंग और सस्टेनेबल एनवायरनमेंटल परफॉरमेंस इंडेक्स के लिए तैयार की गई अध्ययन रिपोर्ट ने यह जानकारी दी गई है।

पहल ▶ परिक्रमा पथ की धुलाई में रोजाना इस्तेमाल होने वाले पानी की हो रही हार्वेस्टिंग

स्वर्ण मंदिर में अब हर रोज बचेगा सात लाख लीटर पानी

लगाया गया है आधुनिक रेन वाटर रीसाइकिलिंग और हार्वेस्टिंग प्लांट

पंकज शर्मा, अमृतसर

विश्व को मानवता की सेवा का संदेश देने वाला श्री हरिमंदिर साहिब अब जल बचाने का भी संदेश रहा है। श्री हरिमंदिर साहिब के परिक्रमा पथ की धुलाई में इस्तेमाल होने वाले लाखों लीटर पानी को व्यर्थ होने से बचाया जा रहा है। इसके लिए रेन वाटर रीसाइकिलिंग और हार्वेस्टिंग प्लांट स्थापित किया गया है।

जल संरक्षण

परिक्रमा पथ की धुलाई के लिए रोजाना करीब सात लाख लीटर पानी का इस्तेमाल होता है। यह पानी सीवरेज में व्यर्थ ही बह जाता था। हार्वेस्टिंग प्लांट लग जाने से अब इस पानी को साफ कर दोबारा जमीन के अंदर भेजा जाने लगा है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी (एसजीपीसी) ने पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के सहयोग से यह प्लांट श्री हरिमंदिर साहिब कांप्लेक्स में स्थापित किया है।

श्री हरमंदिर साहिब में जल बचाने के लिए बनाए गए टैंक। जागरण

प्लांट ने काम करना शुरू कर दिया है। परिक्रमा पथ के पानी के साथ-साथ कांप्लेक्स में जमा होने वाले बारिश के पानी को भी इसके तहत दोबारा भूमि में भेजा जाएगा। इससे सीवरेज में अधिक पानी आने के कारण सीवरेज ब्लॉक की समस्या भी खत्म हो जाएगी।

प्रोजेक्ट से जुड़ी वरुण मित्रा कंपनी के अधिकारी अरुण नरियाल ने बताया कि श्री हरिमंदिर साहिब के परिक्रमा पथ की धुलाई में हर रोज करीब सात लीटर पानी बर्बाद हो जाता था। अब इसी पानी को दोबारा उपयोग में लाया जा सकेगा। इस प्रोजेक्ट में दुनिया की आधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया है। इसमें डेप्थ फिल्ट्रेशन मॉड्यूलर टैंक सिस्टम स्थापित है। आधुनिक मशीनरी युक्त तीन तरह के टैंक बनाए गए हैं। पहले टैंक में परिक्रमा की धुलाई व बारिश का पानी आता है। उसमें लगे हुए विशेष दो तरह के विशाल आधुनिक फिल्टर पानी से मिट्टी व अन्य तरह की ठोस गंदगी को पानी से अलग करके साफ पानी को दूसरे टैंक में भेजते हैं। दूसरा टैक फिल्ट्रेन टैंक है। इसमें चार तरह के फिल्टर हैं, जो पानी में से हानिकारक तत्व, कार्बन व अन्य खतरनाक तत्वों को अलग करते हैं। इसके बाद पानी डिफिल्ट्रेशन रीचार्ज चैंबर में चला जाता है। वहीं से डबल फिल्ट्रेशन के बाद दोबारा धरती के अंदर चला जाएगा। इसके चार चैंबर हैं, जो सौ-सौ फीट गहरे हैं। इन चैंबरों में प्रति घंटे तीन लाख लीटर पानी साफ होकर दोबारा भूमि में समा जाएगा। प्रोजेक्ट पर पांच लाख से अधिक का खर्च आया है। पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के निर्देशक काहन सिंह पन्नू ने बताया कि विभाग ने पर्यावरण और जल संरक्षण के मद्देनजर यह प्रोजेक्ट श्री हरिमंदिर साहिब में स्थापित किया है। सरकार ऐसे सभी प्रोजेक्टों को स्थापित करने में पूरा सहयोग देगी। एसजीपीसी के मुख्य सचिव डॉ. रूप सिंह ने बताया, जल ही जीवन का संदेश सारी दुनिया तक फैलाने के लिए श्री हरिमंदिर साहिब में इस प्रोजेक्ट को स्थापित किया गया है। जल की एक बूंद भी अब इस परिसर में व्यर्थ नहीं जाने दी जाएगी। यह हमारे लिए गौरव की बात है।

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/positive-news

सत्तर पार, हौसला बेशुमार, उपलब्धियां अपार

संडे बॉक्स जरा हटके...

- सपनों से मिली प्रेरणा, कायम किए 16 लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड
- अमृतसर निवासी सुरिंदर सिंह का हौसला दे रहा युवाओं को प्रेरणा

रविंदर शर्मा, अमृतसर

कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट से वर्ष 2002 में सेवानिवृत्त हुए 77 वर्षीय सुरिंदर सिंह आजाद ने सपने देखने के बाद एक-दो नहीं पूरे 16 कीर्तिमान लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज करा दिए। वे रिकार्डों का शतक बनाने का दम भरते हैं। उनके नाम सबसे पहला लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड नौ इंच छाती फुलाने का रहा। इसके लिए उन्हें 1990 में लिम्का बुक की ओर से सर्टिफिकेट जारी किया गया था। आजाद सिंह का सीना बिना फुलाए 32 इंच का था, जबकि फुलाने के बाद 41 इंच हो जाता था।

सपने में दिखी राह : अमृतसर निवासी सुरिंदर सिंह आजाद ने बताया कि सेंट्रल कस्टम एक्साइज में बतौर लोअर डिवीजन क्लर्क नौकरी शुरू की थी। उन्हें 49 साल पहले एक रात सपन आया, जिसमें उन्हें कोई कह रहा था कि उनके नाम कई वर्ल्ड रिकॉर्ड होंगे। इसके लिए अपने अंदर की शक्तियां पहचाननी होंगी, अपनी क्षमता का इस्तेमाल करना होगा...। बकौल आजाद, इसके बाद वे सोचने लगे कि वे क्या क्या कर सकते हैं। रिकॉर्ड बनाने की सोचने लगे। जब ठान ली तो लक्ष्य हासिल भी होने लगे। पत्नी और परिवार के सभी सदस्यों ने हमेशा मेरा उत्साह बढ़ाया।

चार पीढ़ियों संग मतदान का रिकॉर्ड : लोकसभा चुनाव 2019 में उन्होंने

अमृतसर निवासी 77 वर्षीय सुरिंदर सिंह 29 साल में अर्जित अपने कीर्तिमानों के साथ। जागरण

102 वर्षीय पिता पिशौरा सिंह, बेटे हरमिंदर सिंह और पोते तेजिंदर सिंह के साथ एक बूथ पर वोट डाल कर चार पीढ़ियों के साथ मतदान का रिकॉर्ड बनाया। आजाद ने बताया कि पिछले दो वर्षों के दौरान हुए विधानसभा, नगर निगम और दो बार लोकसभा चुनाव में एक साथ चारों पीढ़ियां मतदान कर चुकी हैं। यहां तक कि कई साल पूर्व ही उनकी चार पीढ़ियों ने आंखें दान करने के लिए एक साथ फार्म भरने का भी रिकॉर्ड बनाया है।

बनाए ये रिकॉर्ड : नौ इंच छाती फुलाना। एक घंटे में 12,178 बार ताली बजाना। 534 किलोमीटर की दूरी स्कूटर को चौथे गियर में चलाते हुए तय करना। एक घंटे में 11,510 बार चुटकी बचाना। एक मिनट में 292 बार चुटकी बजाना। एक मिनट में 136 बार बाजू घुमाना। एक मिनट में बंद मुट्ठी को कलाई से 292 बार गोल-गोल घुमाना। अंगुली को एक मिनट में 278 बार खींचना... सहित ऐसे ही दिलचस्प रिकॉर्ड आजाद ने बनाए हैं।

दादा की उपलब्धियों पर पोतों को गर्व : पोते तेजिंदर सिंह, सर्बजीत सिंह, हरप्रीत सिंह और हर्षप्रीत सिंह कहते हैं कि उन्हें इस बात पर गर्व है कि उनके दादा के नाम इतने रिकॉर्ड हैं।

बर्फ होती सांसों को बचाने वाला साहसी इंजीनियर

रोहतांग दर्रे में फंसे वाहनों को निकालने के लिए इंजीनियर प्रशांत सिंह राणा रास्ते से बर्फ हटाते हैं। जागरण

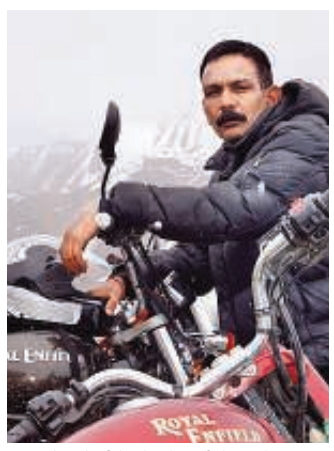

मध्य प्रदेश से सीमेंट टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा किया है प्रशांत सिंह राणा ने। जागरण

जीना इसी का नाम है

हंसराज सैनी, मंडी

- बीते पांच सालों में बर्फीले तूफान में फंसे सैकड़ों पर्यटकों की बचा चुके हैं जान
- जहां सारे प्रबंध हुए फेल, वहां से प्रशांत ही उम्मीद की किरण

अपने लिए जीने वाले दुनिया में कम नहीं हैं। लेकिन सही मायनों में इंसान वही है, जो दूसरों के लिए जान भी लुटाने को तैयार रहे। आइये मिलते हैं मंडी, हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट निवासी प्रशांत सिंह राणा से। प्रशांत पांच साल में बारालाचा से रोहतांग के बीच बर्फीले तूफान में फंसे सैकड़ों पर्यटकों को नई जिदंगी दे चुके हैं।

45 वर्षीय प्रशांत ने मध्य प्रदेश से सीमेंट टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा किया है। इसके बाद सरकाघाट में ऑटोमोबाइल का शोरूम खोला। सफलता नहीं मिली तो मंडी में बीमा कंपनी में काम करने लगे। सात साल यहां रहने के बाद 2011 में मनाली में कैब सर्विस शुरू कर दी। मनाली से लेह और लाहुल-स्पीति जैसे मुश्किल रास्तों में वाहन चलाने में महारत हासिल की और पर्यटकों की पहली पसंद बन गए।

प्रशांत के साहस के किस्से : प्रशांत ने 2014 में रोहतांग दर्रे पर फंसे 30 विदेशियों व पांच स्थानीय चालकों को रेस्क्यू किया था। 31 मई 2014 को वह लाहुल से मनाली आ रहे थे। कोकसर रेस्क्यू पोस्ट पर पुलिस ने बर्फीला तूफान होने के कारण प्रशांत और उनके साथ आ रहे पर्यटकों को रोक लिया। देर शाम सूचना मिली कि रोहतांग दर्रे में कुछ विदेशी फंसे हैं। पुलिस के पास मात्र बाइक थी।

प्रशांत से आग्रह किया तो वह गाड़ी लेकर रोहतांग दर्रे के लिए निकल पड़े। करीब तीन घंटे में सभी को सुरक्षित निकाल लिया। इसके बाद यह सिलसिला चल पड़ा। जहां कहीं भी प्रशांत की जरूरत पड़ती, तुरंत पहुंच जाते। दिसंबर में रोहतांग दर्रा घूमने गए 14 लोग बर्फीले तूफान में फंस गए थे। इस तूफान में लगभग 2000 लोग फंस गए थे। बेहद फिसलन और तीखी ढलान होने के कारण लोगों को मुश्किल आ रही थी। प्रशांत ने लगभग 200 लोगों को सुरक्षित निकालने में मदद की। सितंबर 2018 में बर्फबारी में फंसे सैकड़ों लोगों को सुरक्षित निकालने का काम भी प्रशांत ने कर दिखाया।

प्रशांत को हालांकि कोई तकनीकी विशेषज्ञता हासिल नहीं है, लेकिन अपने जज्बे और अनुभव के बूते वह लोगों की जान बचाने का काम कर रहे हैं। बकौल प्रशांत, वर्षों से लेह व लाहुल-स्पीति आना-जाना होता है। भगवान की कृपा से बर्फ में वाहन चलाने की महारत भी हासिल है। क्षेत्र की भौगोलिक हालात से भलीभांति वाकिफ हूं। 2014 में रोहतांग दर्रे से बर्फीले तूफान में फंसे विदेशी सैलानियों को सुरक्षित निकालने से नई ऊर्जा मिली। इसी ऊर्जा की लौ से मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करता आया हूं। ऐसे लोगों के आशीर्वाद से दूसरों के काम आने में सफल रहा हूं। कोशिश यही रहती है कि हर किसी के काम आऊं।

कॉफी की चुस्कियों से बनेगी झीरम घाटी की नई पहचान

बड़ा कदम ▶ जहां नक्सली बोते थे आतंक के बीज, अब वहां वैज्ञानिकों ने रोपे कॉफी के पौधे

रविवार विशेष

पंकज दुबे, रायपुर

कभी नक्सलियों के लिए कुख्यात रही झीरमघाटी अपनी नई पहचान बनाने को आतुर है। जहां नक्सली आतंक के बीज बोते थे, वहां अब वैज्ञानिकों ने कॉफी के पौधे रोपे हैं। स्थानीय किसान इन पौधों की देखभाल कर रहे हैं। जल्द ही देश-दुनिया के लोग यहां तैयार हुए बीजों से बनी कॉफी की चुस्कियां लेंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 350 किलोमीटर दूर घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र झीरम घाटी के दरभा में कृषि वैज्ञानिकों ने कॉफी की बगिया खिला दी है। तीन साल पहले इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. एसके पाटिल ने दरभा की पहचान बदलने का बीड़ा उठाया। क्षेत्र में कॉफी की खेती चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन मजबूत इरादों से काम आसान होता गया।

लगाए 27 हजार कॉफी के पौधे : बस्तर जिले के जगदलपुर हार्टिकल्चर कॉलेज के इन वैज्ञानिकों ने पहले चरण में 22 सौ कॉफी के पौधे लगाए। ये पौधे दक्षिण भारत से मंगवाए गए थे। उसके बाद दूसरे चरण में 25 हजार कॉफी के पौधे रोपे गए हैं। कॉफिया रोबेस्टा की एक और सीएसआर, अरबिका की तीन किस्म लगाई गई हैं। दो एकड़ से शुरू हुई कॉफी की खेती 20 एकड़ तक पहुंच गई है। अब तक 50 किसान इस मुहिम से जुड़ चुके हैं। योजना यह है कि यहां से प्राप्त बीज किसानों को निशुल्क दे दिया जाएगा।

झीरम घाटी में कॉफी की खेती का निरीक्षण करता इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का दल।

झीरम घाटी स्थित दरभा में 20 एकड़ में तैयार हो रही कॉफी की फसल। जागरण

किसान बिना किसी अवरोध के 25 साल तक ले सकते हैं पैदावार

एक बार की जाने वाली इस खेती का फायदा किसानों को 25 साल तक बिना किसी अवरोध के मिलेगा। इसमें हर साल उत्पादन की मात्रा बढ़ती जाएगी। कॉफी के पौधों में फल सालभर के बाद आने लगते हैं। कॉफी प्रोजेक्ट के प्रमुख वैज्ञानिक केपी सिंह के अनुसार अनुमान है कि दरभा में 150 क्विंटल पैदावार होगी। इस खेती पर करीब 48 लाख रुपए खर्च किए गए हैं।

नक्सल प्रभावित क्षेत्र दरभा को एक नई पहचान देने के साथ किसान की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए योजना शुरू की गई है। नतीजा सकारात्मक रहा है। – **डॉ. एसके पाटिल, कुलपति इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़।**

शुरुआती राह कठिन : शुरू में झीरम घाटी में तीन इलाके देखे गए, मंजूरी केवल दरभा के लिए मिली। कॉलेज डीन डीएस ठाकुर ने बताया कि समुद्र तल से करीब 623 फीट की ऊंचाई पर बसे दरभा का वातावरण इस फसल के लिए अनुकूल है।

कुख्यात रही है झीरम घाटी : 25 मई 2013 को बस्तर जिले के झीरम घाटी में नक्सलियों ने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर ताबडतोड़ हमला कर 29 नेताओं और कार्यकर्ताओं को मौत को घाट उतार दिया था। यह देशभर की चर्चित नक्सली घटना थी।

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/jagran-special

यहां खूंटे में बांध कर रखी जाती हैं मछलियां

रस्सी में मछली बांधकर पानी में डालता मछुआरा।

तरुण वागी, रामगढ़

खूंटे में बांध कर गाय, बैल, भैंस, बकरियों को रखते सुना होगा, लेकिन मछलियों को खूंटे में बांधकर रखा जाना अजूबे सा लगता है। हालांकि झारखंड के रामगढ़ में यह कोई अजूबा नहीं है। यहां पतरातू डैम में दो किलो से अधिक की मछलियों को जाल से फंसाने के बाद बांस के खूंटे से रस्सी के सहारे बांध कर पानी में छोड़ दिया जाता है। मछली के शौकीन लोगों को मछुआरे रस्सी में बंधी मछलियों को पानी से निकालकर जिंदा हालत में देने के लिए ऐसा करते हैं। पतरातू डैम में कतार में खूंटे से बंधी मछलियां बेचते लोग देखने को मिल जाएंगे।

प्रकृति की हसीन वादियों और सुरम्य घाटियों के बीच स्थित रामगढ़ के पतरातू डैम को झारखंड सरकार पर्यटक स्थल के रूप में विकसित कर रही है। यहां आने वाले पर्यटक यह नजारा देख

अपना देस खुशबू माटी की

- मछली फंसाने के बाद रस्सी से खूंटे के सहारे बांधकर वापस डैम में छोड़ दी जाती हैं मछलियां

और भी रोमांचित होते हैं। सरकार के मत्स्य विभाग द्वारा पतरातू डैम के तटवर्ती गांव के रैयत ग्रामीणों व स्थानीय लोगों को रोजगार का साधन देने के उद्देश्य से समय-समय पर मछली का बीज छोड़ा जाता है। हाल में ही मत्स्य विभाग ने डैम में विभिन्न प्रजातियों के करीब 25 लाख बीज छोड़े हैं। यहां के मछुआरे जाल या कांटा लगाकर मछलियों को फंसाते हैं। इसके बाद बड़े साइज की मछलियों मृगाल, कतला व रेहू आदि के मुंह से रस्सी डाल कर गलफड़े से निकालकर बांध देते हैं। इसके बाद डैम के किनारे लकड़ी या बांस का खूंटा गाड़कर मछलियों को रस्सी सहित वापस डैम में ही छोड़ देते हैं। डैम में आने वाले पर्यटक और स्थानीय लोग मछुआरों से एकदम जिंदा मछली खरीदकर ले जाते हैं। कुछ मछली खाने के शौकीन लोग तो अपने घर तक मछली को जिंदा ले जाने जाने के लिए मछलियों को पानी भरे किसी बर्तन में डालकर ले जाते हैं।

वर्षों से पतरातू डैम में खूंटे में बांध कर जिंदा मछलियां बेचने वाले मछुआरे शमसुद्दीन व जियाउल कहते हैं कि इससे ग्राहकों को जिंदा मछली खरीदने की संतुष्टि मिलती है और उन्हें मछली का सही दाम आसानी से मिल जाता है। यहां रेहू, कतला, ग्रास कॉर्प व मृगाल प्रजाति की मछलियां प्रतिदिन औसतन एक से डेढ़ क्विंटल तक निकालते हैं। जिंदा मछलियां के प्रजाति व वजन के हिसाब से 130 रुपये से लेकर 150 रुपये प्रतिकिलो आसानी से मिल जाते हैं।

जंगल में शोध का ब्योरा वन विभाग को देना अनिवार्य

राज्य ब्यूरो, देहरादून: सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्र के तमाम नामी संस्थान, शिक्षण व शोध संस्थाएं और शोधार्थी राज्य के जंगलों में शोध तो कर रहे, मगर इनके नतीजों की जानकारी वन विभाग को नहीं दे रहे। नतीजतन इनका लाभ प्रदेश को नहीं मिल पा रहा। इसे देखते हुए यह अनिवार्य किया गया है कि जंगल में किए जाने वाले किसी भी प्रकार के शोध के परिणाम से वन विभाग को अनिवार्य रूप से अवगत कराना होगा।

प्रमुख मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) के इस आदेश के क्रम में वन संरक्षक अनुसंधान संजीव चतुर्वेदी ने चार नामी संस्थानों भारतीय वन्यजीव संस्थान, वन अनुसंधान संस्थान, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण (बीएसआइ) और जीबी पंत विवि को पत्र भेजा है। इन संस्थाओं से राज्य में पिछले दो दशक में वनों से संबंधित शोध का ब्योरा मांगा गया है।

कीमत बताती है दुर्लभ डाक टिकटों की कहानी

कृष्ण बहादुर रावत, वाराणसी : लिफाफे पर चिपके साधारण से दिखने वाले डाक टिकट की भी अपनी कहानी होती है। हम उस छुपी हुई कहानी को खोज सकें तो वह टिकट हमारे सामने ज्ञान की रहस्यमय दुनिया का नया पन्ना साबित होता है। डाक टिकट किसी भी देश की विरासत की चित्रमय कहानी भी बताता है। कुछ इन्हीं कहानियों को बताने के लिए वाराणसी के आर्य महिला डिग्री कॉलेज में डाक विभाग की ओर से दो दिवसीय काशी पेक्स प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। समारोह के समापन अवसर पर आम दर्शकों की सबसे अधिक भीड़ वहां जुटी, जहां महात्मा गांधी से जुड़े चार दुर्लभ टिकट थे। चारों एक सीरीज में प्रदर्शित थे। इसकी खासियत यह है कि महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद 15 अगस्त 1948 को जारी इन टिकटों की सीरीज स्विट्जरलैंड में मुद्रित की गई थी।

टिकटों के ऊपर हिंदी और उर्दू में बापू लिखा है। उस समय चारों टिकटों की कीमत 10 रुपये से कुछ अधिक थी। आज सीरीज की सही कीमत देने वाला कोई नहीं है। प्रवर डाक अधीक्षक देवव्रत त्रिपाठी ने बताया कि 1952 में बनारस की विभूतियों तुलसी दास व कबीर पर भी डाक टिकट जारी किया गया था। उस समय उसकी कीमत नौ पैसे थी। आज टिकट की कीमत हजारों रुपये है। इसकी काफी मांग भी है।

बैल की जगह महिला रखती है कंधे पर हल

यशवंतसिंह पंवार, झाबुआ

मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के ग्राम उमरकोट के भाबोर-बीड फलिये (आदिवासी क्षेत्र में छोटा रहवासी क्षेत्र) में रहने वाली रामली पत्नी रतन भाबोर बैल की जगह खुद हल खींचकर खेत की जुताई कर रही है। पांच छोटे बच्चों के साथ जीवन-यापन का संघर्ष जारी है। हालांकि, मामला प्रकाश में आने पर प्रशासन और सांसद ने मदद की बात कही है।

बैल जोड़ी 25 हजार में आती है। बैल नहीं होने से रामली को बच्चों की मदद से स्वयं बैल बनकर खेती करनी पड़ रही है। वह कहती है कि किराये पर बैल मिलता है, लेकिन पैसे ज्यादा लगते हैं। एक हजार रुपये प्रतिदिन देने की उसकी हैसियत नहीं है। खेतों की जुताई में पांच बच्चों में सबसे बड़ी बेटी 12 वर्षीय कविता उसकी मदद करती है। अशिक्षित होने और जानकारी के अभाव में रामली किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं ले सकी।

मौसम विशेष

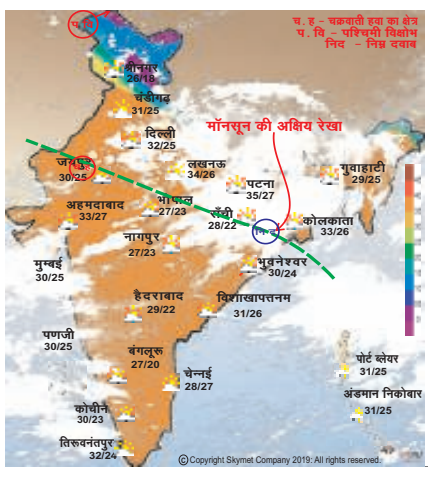

जम्मू-कश्मीर व हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा जारी रहेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा उत्तरी राजस्थान के तापमान में हल्की वृद्धि होगी। कुछ स्थानों पर गरज और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा जारी रहेगी। दक्षिण राजस्थान में भारी वर्षा होगी।

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	31/26/आंबा	अहमदाबाद	32/26/आंबा
कोलकाता	35/27/व	बड़ौदा	28/25/व
चेन्नई	38/29/व	नागपुर	28/23/आंबा
हैदराबाद	27/21/व	इन्दौर	27/24/व
बंगलूरू	28/21/व	रांची	33/25/व
त्रिवेन्द्रम	32/25/आंबा	पटना	34/27/व
गुवाहाटी	29/24/व	जमशेदपुर	33/26/आंबा
गंगटोक	15/09/आंबा	पुणे	23/22/व

साप्ताहिक राशिफल

रविवार 28 जुलाई, 2019 से शनिवार 3 अगस्त, 2019 तक

पं. बी. बी. शास्त्री 'देवेश'

मेष (चू,चे,चो,ला,ली,लू,ले,लो,आ)
व्यापार, नौकरी, उद्योग कार्य में सफलता, अर्थ साधन में प्रयास, नई कार्यशैली से चलें, सामाजिक कार्य योग, भूमि कार्य में अवरोध, अति विश्वास से बचें, संतान के लिए समय दें, ईर्ष्या से बचें, दांपत्य में सुख, राज्य पक्ष से लाभ, एकाएक कार्य संपन्न, आय में वृद्धि, शुभ अंक 2

वृष (इ,ऊ,ए,ओ,पा,वी,वू,वे,वो)
धनागम में सफलता, व्यवसायिक क्षेत्र में स्पर्धा, रचनात्मक कार्य का योग, पारिवारिक सहयोग, चिंता का समाधान, साधनों में वृद्धि, कार्यशैली में सुधार, अध्ययन में अवरोध, त्वचा नेत्र विकार, योग, प्रणय में सुख, वाहन में सावधानी, राजनीतिक अपयश, व्यय अधिक, शुभ अंक 4

मिथुन (का,की,कू,घ,ड,छ,के,को,हा)
अर्थ साधन में सुधार, सलाह से निर्णय करें, महिला का सहयोग, विदेश से समाचार, भवन निर्माण का योग, संतान से सहयोग, अध्ययन में रुचि, शत्रुपक्ष से सावधान, वाद-विवाद का योग, वाहन में सावधानी, जीवन साथी का मिलन, यंत्र स्थापन योग, राज्य पक्ष से लाभ, शुभ अंक 2

कर्क (ही,हू,हे,हो,डा,डी,डू,डे,डो)
अर्थ साधन में सुधार, बदलाव से बचें, धन निवेश के लिए योजना, विदेश कार्य में प्रगति, प्रयास की दिशा में परिवर्तन करें, संतान के लिए योजना, वाणी पर नियंत्रण, प्रणय में सुख, जीवन साथी का मिलन, वाहन में सावधानी, स्थान परिवर्तन प्रभावी, व्यय अधिक, शुभ अंक 3

सिंह (मा,मी,मू,मे,मो,टा,टी,टू,टे)
अर्थ साधन अच्छा, विशेष व्यक्ति से मिलन, ऊर्जा से पूर्ण, कूटनीति का सहयोग करें, विदेश कार्य में सुधार, पारिवारिक सुख, भौतिक साधनों की पूर्ति, मित्रों का सहयोग, अधिकारी से सहयोग, कुछ परिस्थिति विचलित कर सकती है, अच्छे समाचार की प्राप्ति, व्यय अधिक, शुभ अंक 5

कन्या (टो,पा,पी,पू,ष,ण,ठ,पे,पो)
व्यापार, नौकरी, उद्योग कार्य में श्रम से सफलता, धनागम में अधिक प्रयास, निर्णय सोच-विचार कर करें, धन के आवागमन में सावधानी, अति विश्वास से बचें, निर्माण में देरी, अध्ययन में एकाग्रता, कुसंग से बचे, जीवन साथी का मिलन, राज्य पक्ष से सावधान, भ्रमण के अवसर, शुभ अंक 6

तुला (रा,री,रू,रे,रो,ता,ती,तू,ते)
प्रतिस्पर्धा योग, साझेदारी में अनबन, मतभेदों को भूलने का प्रयास करें, भूमि कार्य में देरी, संतान की प्रगति, चयन में सफलता, मित्रों से सहयोग, सिर-नेत्र पीड़ा योग, प्रणय में सुख, नए साथी का मिलन, रक्षा साधन कार्य में प्रगति, राजनीति में सफलता, शुभ अंक 5

वृश्चिक (तो,ना,नी,नू,ने,नो,या,यी,यू)
व्यापार, नौकरी, उद्योग कार्य में सफलता, धनागम अच्छा, निर्णय से पूर्व विचार करें, विदेश से समाचार, निजी कार्य से संतुष्ट, स्वास्थ्य सुधार, संतान के लिये योजना, शिक्षा में व्यवधान, चयन में देरी, विपरीत परिस्थिति में भी सुधार, राजनीतिक कार्य में सफलता, स्थान-पद परिवर्तन, शुभ अंक 2।

धनु (ये,यो,भा,भी,भू,धा,फा,ढा,भे)
अर्थ साधन अच्छा, दिनचर्या व्यस्तता, निजी समस्या का समाधान, अपने लक्ष्य तथा कार्य पर ध्यान दें, संतान के प्रति योजना, चयन में सफलता, वाद में विजय, कुछ परिस्थितियां विचलित कर सकती हैं, प्रणय में सुख, एकाएक स्थान परिवर्तन, शुभ अंक 11

मकर (भो,जा,ज,खी,खू,खे,खो,गा,गी)
व्यापार, नौकरी, उद्योग कार्य में सहयोग से सफलता, धनागम में सुधार, साझेदारी में सावधानी, सामाजिक-राजनीतिक यश, महिला से सहयोग, परिणाम चिंता का समाधान, अध्ययन में रुचि, खान-पान का ध्यान रखें, जीवन साथी का मिलन, अधिकारी से सहयोग, व्यय अधिक शुभ अंक 4

कुम्भ (गू,गे,गो,सा,सी,सू,से,सा,दा)
व्यापार, नौकरी, उद्योग कार्य में सफलता, अर्थ साधन में प्रयास, विदेश व्यापार से सफलता, साहस की वृद्धि, नए संपर्क क्षेत्र, रचनात्मक कार्य का योग, साधनों की पूर्ति, संतान से सहयोग, त्वचा-नेत्र विकार, जीवन साथी का मिलन, रुके कार्य संपन्न, व्यय अधिक, शुभ अंक 5

मीन (दी,दू,थ,झ,ञ,दे,दो,चा,ची)
व्यापार, नौकरी, उद्योग कार्य में सफलता, धनागम में सफलता, प्रतिस्पर्धा से चिंता, नए कार्य की रूपरेखा, विदेश कार्य में सफलता, चिंता का समाधान, वाद-विवाद से बचें, जीवन साथी का मिलन, एकाएक स्थान पद परिवर्तन, राजनीतिक अपयश, शुभ अंक 5

राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
आजकल
रविवार 28 जुलाई 2019
14
www.jagran.com

प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई

1914 में आज ही प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। 52 माह तक चला यह युद्ध यूरोप, एशिया व अफ्रीका तीन महाद्वीपों के बीच समुद्र, धरती और आकाश में लड़ा गया था। इस विश्व युद्ध में भारत प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं था, लेकिन देश के जवानों ने बड़ी भूमिका निभाई थी।

चीन में आया 20वीं सदी का सबसे बड़ा भूकंप

1976 में आज ही चीन के बीजिंग में 8 .3 की तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें बीजिंग के उत्तर पूर्व में स्थित तांगशान शहर तहस-नहस हो गया था। करीब ढाई लाख लोग मारे गए थे। मौतों के लिहाज से इसे 20वीं सदी का सबसे बड़ा भूकंप माना जाता है।

विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाने की शुरुआत हुई

1925 में आज ही हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज करने वाले तथा वायरस के लिए टीका विकसित करने वाले डॉक्टर बारुक ब्लमर्ग का जन्म हुआ था। नोबेल पुरस्कार विजेता ब्लमर्ग अमेरिकी चिकित्सक थे। उन्होंने संक्रमक रोगों की उत्पत्ति और उनके निदान के लिए कई शोध किए। इसलिए 28 जुलाई को उनके जन्मदिन के सम्मान में विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को हेपेटाइटिस के लिए जागरूक करना है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक हेपेटाइटिस से हर साल 14 लाख लोगों की जान चली जाती है। हेपेटाइटिस से लीवर की बीमारी होती है और समय पर उपचार न मिलने पर लोगों की जान चली जाती है। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई संक्रामक रोगों का समूह है।

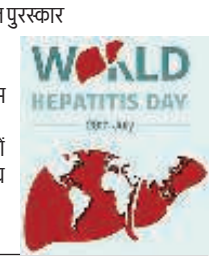

इधर-उधर की

पहला अंडरवाटर मिलिट्री म्यूजियम

अम्मान, एजेंसी : जॉर्डन के अकाबा में दुनिया का पहला अंडरवाटर मिलिट्री म्यूजियम बनाया गया है। 19 सैन्य अवशेषों वाले इस म्यूजियम को आधिकारिक तौर पर अकाबा में लांच किया है। यह लाल सागर में आठ फीट की गहराई में बना है। सेना ने यहां युद्ध टैंक, सैन्य एंबुलेंस, हेलिकॉप्टर, युद्धक विमान, क्रेन और एंटी एयरक्राफ्ट समेत 19 तरह के सैन्य उपकरण रखे हैं। खास बात यह है कि इसे सिर्फ सात दिन में बनाकर तैयार किया गया है। सतह से नीचे 15 से 20 मीटर दूरी पर आठ सैन्य अवशेषों को लगाया गया। जबकि अन्य 11 को 20 से 28 मीटर की दूरी पर लगाया गया। वहां के प्रशासन ने समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव उपाय किए गए हैं।

काम के तनाव से जल्दी आ जाता है बुढ़ापा

न्यूयॉर्क टाइम्स से

वाशिंगटन : आज के समय में सफल कॅरियर बनाना इतना जरूरी है कि लोग बस उसकी भागमभाग में जुटे रहते हैं। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, शेफ हो या फिल्म जगत से जुड़ा कोई व्यक्ति हो, सफल होने के लिए सभी दिन या रात देखे बिना अपने काम में लगे रहते हैं। इन सबके चलते कई बार उन्हें तनाव हो जाता जिसका सीधा असर उनके स्वास्थ्य पर दिखाई देने लगता है।

मिशिगन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं का कहना है कि काम के चलते होने वाले तनाव और ठीक ढंग से नींद ना ले पाने से व्यक्ति की शारीरिक क्षमता घटने लगती है और उनमें

प्रतीकात्मक

उम्र से पहले ही बुढ़ापे के लक्षण दिखने लगते हैं। कई लोगों के बाल सफेद होने लगते हैं तो कुछ का पाचन तंत्र व आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है। ऐसे में जरूरी है कि वे रात-दिन की उल्टी-पुल्टी शिफ्ट में घंटों काम करने से बचें।

छह गुना तेजी से बूढ़े होने लगते हैं लोग : शोधकर्ता ने अपने अध्ययन में पाया कि काम को लेकर तनाव में रहने वाले लोग अन्य के मुकाबले छह गुना अधिक तेजी से बूढ़े होते हैं। अपनी बात पुष्ट करने के लिए उन्होंने 250 युवा डॉक्टरों पर शोध किया। उन सभी के टेलोमेरेस की लंबाई का पता लगाने के लिए उनके सलाइवा का नमूना इकट्ठा किया गया था।

टेलोमेरेस क्रोमोजोम के सिरे पर मौजूद रहकर डीएनए को सुरक्षित रखते हैं। युवा व बच्चों में तनाव बढ़ने से इनकी लंबाई छोटी होती जाती है। टेलोमेरेस की लंबाई का कम होना डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर व हृदय संबंधी रोगों के साथ ही समय से पहले बूढ़े होने का भी कारक है। शोध में वैज्ञानिकों ने पाया कि घंटों काम करने और तनाव के चलते टेलोमेरेस की लंबाई तेजी से घटती जाती है।

सुधार की जरूरत

शरीर को स्वस्थ रखने और बुढ़ापे के लक्षणों को कम करने के लिए जीवनशैली में सुधार किया जाना बेहद जरूरी है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में प्रोफेसर डॉ. सिरीजन सेन ने कहा, 'व्यक्ति को घंटों लगातार काम करने से बचना चाहिए। खानपान में बदलाव के साथ दिन में छह-आठ घंटे की नींद लेना भी जरूरी है।'

फिल्म रिव्यू

न कॉमेडी बन पाई, न ड्रामा

अर्जुन पटियाला

निर्देशक : रोहित जुगराज
कलाकार : दिलजीत दोसांझ, कृति सैनन, वरुण शर्मा, मुहम्मद जीशान अय्यूब, रोनित रॉय, सीमा पाहवा
समय : 1 घंटे 46 मिनट

उम्दा कलाकारों की मौजूदगी में इस फिल्म से मस्ती और बेहतरीन कॉमेडी की अपेक्षाएं थीं, पर फिल्म ने निराश किया। पटकथा बेहद कमजोर है। 'फोर्स', 'डी डे', 'कमांडो', 'पिंक' जैसी धीर-गंभीर फिल्मों का लेखन करने वाले रितेश शाह ने पहली बार कॉमेडी में हाथ आजमाया है। उन्होंने कहा था कि यह प्रयोग है। भविष्य में उन्हें ऐसे प्रयोगों से बचना चाहिए।

फिल्म की शुरुआत एक स्क्रिप्ट लेखक द्वारा निर्माता को अपनी फार्मूला कहानी सुनाने से होती है। कहानी एक पुलिस अधिकारी, उसके मातहत कर्मचारी, ग्लैमरस टीवी रिपोर्टर और दबंग विधायक को लेकर मिर्च-मसाला के साथ गढ़ी गई है। पुलिस अधिकारी अर्जुन पटियाला (दिलजीत दोसांझ) की नियुक्ति फिरोजपुर में होती है। उसके मातहत ओनिडा (वरुण शर्मा) है। अर्जुन पहली नजर में टीवी रिपोर्टर रितु रंधावा (कृति सैनन) को अपना दिल दे बैठता है।

वह अपने डीसीपी गिल (रोनित रॉय) के अपराधमुक्त जिले के सपने को पूरा करना चाहता है। उसके लिए अपराधियों को ही आपस में भिड़ा देता है। हालांकि अपराधमुक्त जिले के पीछे का असल खेल कुछ और है। बेईमान विधायक प्राप्ति मक्कड़ (सीमा पाहवा) अचल संपत्ति के गैरकानूनी सौदों के लिए कुख्यात है। वह पुलिस का प्रयोग करती है और अर्जुन उसे चकमा देता है। बेजोड़ कलाकारों की जमात कमजोर पटकथा, लचर स्क्रीनप्ले और घिसे-पिटे संवादों तले दब जाती है। दृश्यों का फिल्मांकन बेहद कमजोर है।

फिल्म की शुरुआत में निर्माता बने पंकज त्रिपाठी की दिलचस्पी कहानी सुनने से ज्यादा उन चीजों को जानने में होती है, जो कहानी को सफल बनाते हैं। मसलन आइटम सांग, रोमांस, विलेन की मौजूदगी। यही सब फिल्म में शुमार किया गया है, जबकि यह दौर कंटेंट सिनेमा का है। ऐसे में कॉमेडी के नाम पर ऐसी फूहड़ फिल्में सिनेमा का स्वाद खराब कर रही हैं।

स्मिता श्रीवास्तव

★★★★★ उत्कृष्ट ★★★★ बहुत अच्छी ★★★ अच्छी ★★ औसत ★ औसत से कम

लिवर में चर्बी बढ़ा रहा सीसे का विषैलापन

शोध ▶ आइआइटी मंडी के शोधकर्ताओं ने लिवर को प्रभावित करने वाली प्रक्रिया खोजी

देश की 32 फीसद आबादी फैटी लिवर की समस्या से परेशान है

जागरण संवाददाता, मंडी

सीसायुक्त चीजों के विषैलेपन से लिवर (यकृत) में चर्बी बढ़ रही है। इससे लोग तेजी से फैटी लिवर बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। देश की 32 फीसद आबादी इस समस्या से परेशान है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) मंडी के शोधकर्ताओं ने पहली बार उस प्रक्रिया को सामने रखा है, जिसमें सीसे से लिवर में चर्बी बढ़ने का खतरा रहता है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज (एनएएफएलडी) नई पीढ़ी की खतरनाक महामारी बन गई है। इसका सीधा संबंध मेटाबॉलिक समूह की बीमारियों मोटापे और डायबिटीज आदि से है। इसमें लिवर में बहुत अधिक चर्बी जमा हो जाती है।

स्कूल ऑफ बेसिक साइंसिज के सहायक प्रोफेसर डॉ. प्रोसेनजीत मोंडल का कहना है सीसे व फैटी लिवर डिजीज के बीच संबंध पहले से ज्ञात है। वास्तविक प्रक्रिया का अब तक पता नहीं था, जिसकी वजह से सीसे से फैटी लिवर की समस्या बढ़ती है।

ज्यादा कार्बोहाइड्रेट से समस्या : मनुष्य में वसा यानी चर्बी को कार्बोहाइड्रेट में बदलने की क्षमता मौजूद नहीं है। आहार में कार्बोहाइड्रेट के बढ़ते सेवन व डे नोवो लिपोजेनेसिस (डीएनएल) पर नियंत्रण के अभाव में यह समस्या सामने आ रही है। रक्त प्रवाह में मौजूद कार्बोहाइड्रेट के वसा में बदल जाने की जटिल प्रक्रिया है। डीएनएल के नियंत्रण में अभाव से ज्यादा चर्बी बनती है, जो लिवर और अन्य अंदरूनी अंगों में जमा हो जाती है। सीसा विषैला होने के कारण पर्यावरण के लिए गंभीर संकट पैदा करता है। यह देखा गया है कि इसकी वजह से चर्बी बनने और लिवर में जमा होने पर नियंत्रण नहीं रह पाता है। देश में लोग पेंट, कीटनाशक, पैकेजिंग और बीयर आदि कई चीजों की वजह से सीसे और इसके साल्ट की चपेट में आ रहे हैं। शरीर में अवशोषित लेड साल्ट कोमल उत्तक के रूप में जमा होता है।

आइआइटी मंडी के स्कूल ऑफ बेसिक सांइस के सहायक प्रोफेसर डॉ. प्रोसेनजीत मोंडल। जागरण

कई संस्थानों के विशेषज्ञ हुए शोध में शामिल

शोध वैज्ञानिक एवं औद्योगिक शोध परिषद (सीएसआइआर) भारतीय विषविज्ञान शोध संस्थान लखनऊ और रसायन एवं जीवन विज्ञान विभाग जामिया हमदर्द नई दिल्ली के शोधार्थियों के सहयोग से किया गया।

क्या है फैटी लीवर

फैटी लिवर एक ऐसी बीमारी है, जो शरीर में बहुत ज्यादा फैट बनने के कारण होती है। इससे आपका लिवर डैमेज हो सकता है।

डीएनएल में गड़बड़ी से समस्या : कार्बोहाइड्रेट रिस्पांसिव एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन लिवर की कोशिकाओं में चर्बी बनने के लिए जिम्मेदार नियंत्रक एंजाइम को सक्रिय करता है। इसके परिणामस्वरूप लिवर में ज्यादा चर्बी बनने लगती है। डॉ. मोंडल व उनकी टीम ने सीसे से उत्पन्न लिवर की बीमारियों की प्रक्रिया बताने के साथ ऐसे केमिकल्स भी बताए हैं, जो बाइंडिंग प्रोटीन पर वार कर सकते हैं। इससे सीसे से उत्पन्न लिवर की बीमारियों के उपचार के लिए उचित दवा की खोज और तैयार करना आसान होगा।

शोध अनुसंधान

डायबिटीज से बढ़ जाता है पैंक्रियाज के कैंसर का खतरा

डायबिटीज के मरीजों में पैंक्रियाज (अग्नाशय) के कैंसर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। दक्षिण कोरिया के शोधकर्ताओं ने 'जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंडोक्राइनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म' में छपे शोध में यह जानकारी दी है। उनका कहना है कि पैंक्रियाज के कैंसर का जल्द पता लगाना मुश्किल है। इसकी पहचान आखिरी स्टेज में हो पाती है। उस वक्त कैंसर शरीर के अन्य अंगों में पहुंच चुका होता है। शोध के दौरान 2.5 करोड़ लोगों के रक्त में ग्लूकोज के स्तर और पैंक्रियाज कैंसर के संबंध का विश्लेषण किया गया। अध्ययन में पाया गया कि रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ने से पैंक्रियाज कैंसर का खतरा भी बढ़ता जाता है। शोध के बाद वैज्ञानिक चेओर-यंग ने कहा, 'डायबिटीज इस कैंसर का प्रमुख कारक है। हालांकि, डायबिटीज के मरीजों के साथ उन लोगों को भी सचेत रहना चाहिए, जो डायबिटीज से ग्रस्त तो नहीं है, लेकिन उनके खून में शुगर का स्तर बढ़ने लगा है।' (एएनआइ)

गर्भावस्था में कॉफी का सेवन शिशु के लिए नुकसानदेह

महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान अत्यधिक चाय या कॉफी के सेवन से बचना चाहिए। इन दोनों पेय पदार्थ में मौजूद कैफीन उनके शिशु में विकसित हो रहे लिवर को नुकसान पहुंचाता है। बड़े होने पर उस बच्चे के लिवर की बीमारी से ग्रसित होने का खतरा बढ़ जाता है। चूहों पर किए प्रयोग के बाद शोधकर्ताओं ने यह निष्कर्ष निकाला है। शोध के दौरान गर्भवती चुहियों को कैफीन दिया गया था। वैज्ञानिकों का कहना है कि कैफीन के कारण नवजात चूहों का वजन बहुत कम हो गया और उनके लिवर का विकास भी रुक गया था। चीन की वुहान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर यिनजियान वेन ने बताया, 'गर्भावस्था के दौरान रोजाना दो या तीन कप कॉफी पीने से गर्भवती में तनाव से संबंधित हार्मोन बहुत बढ़ जाता है। इसका सीधा असर गर्भ में विकसित हो रहे भ्रूण के लिवर पर पड़ता है।' उन्होंने कहा कि शोध से स्पष्ट है कि गर्भावस्था के दौरान कैफीन लेना होने वाले बच्चे के लिए नुकसानदेह होगा। इंसानों पर हालांकि पुष्टि नहीं हुई है। (आइएएनएस)

वाट्सएप बना रहा नया डेस्कटॉप वर्जन, बिना फोन के करेगा काम

सैनफ्रांसिस्को, आइएएनएस : फेसबुक के स्वामित्व वाली कंपनी वाट्सएप अपने एप के डेस्कटॉप वर्जन पे काम कर रही है, ताकि यूजर्स अपने मोबाइल को इंटरनेट से कनेक्ट करे बिना इस मैसेजिंग एप का इस्तेमाल अपने कंप्यूटर पर कर सकें। एप के वेब वर्जन को 2015 में वाट्सएप ने लांच किया था। इसके जरिए कंप्यूटर पर चैट को मॉनिटर किया जा सकता है, लेकिन इसके इस्तेमाल के लिए यूजर्स को पहले अपने फोन को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना पड़ता है।

वाट्सएप लीकर अकाउंट डब्ल्यूएबीटाइंफो ने शुक्रवार को ट्वीट में जानकारी दी कि कंपनी एक यूनिवर्सल विंडोज प्लेटफॉर्म (यूडब्ल्यूपी) एप विकसित कर सकती है। साथ ही कंपनी एक नए मल्टी-प्लेटफॉर्म सिस्टम पर भी काम कर रही है, जो आपके फोन के बंद होने पर भी काम करेगा। खबरों के मुताबिक, इसके अलावा वाट्सएप मल्टीप्लेटफॉर्म सिस्टम पर भी काम कर रहा है, जिसकी मदद से यूजर्स एक ही वक्त में कई डिवाइस के माध्यम से अपनी चैट और प्रोफाइल में एक्सेस कर सकेंगे।

मोबाइल को बिना इंटरनेट से कनेक्ट करे इस्तेमाल कर सकेंगे एप

प्राचीन केनटोनी ओपेरा की जीवंत प्रस्तुति

सिंगापुर के क्रेटा पीपुल्स थियेटर में 'यंग वायस सेलीब्रेटी सिंगापुर-केनटोनी ओपेरा चैरिटी नाइट' के मौके पर भावपूर्ण प्रस्तुति देते आर्टिस्ट। यह सदियों पुरानी पारंपरिक कला है, जो दक्षिणी चीन में आज भी काफी लोकप्रिय है। इसके अलावा ग्वांगडोंग, गुआंग्सी, हांगकांग, मकाऊ और दक्षिण पूर्व एशिया में चीनी समुदाय के लोगों के बीच काफी पसंद की जाती है। एजेंसी

मुखौटों का उत्सव

पश्चिमी मेक्सिको के कई गांवों में तीन शताब्दियों से अधिक की परंपरा को लोग आज भी जीवित रखे हुए हैं। प्रतिवर्ष जैलिसा स्टेट के सैंटो सैंटियागो में लोग विचित्र प्रकार के मुखौटे पहनकर वार्षिक उत्सव 'टोस्टोनेस' में हिस्सा लेते हैं। टेस्टोनेस स्वदेशी पूर्व-कोलंबियन शब्द है, जिसका अर्थ होता है नेता। यह उत्सव स्पेनिस आक्रमण के खिलाफ स्वदेशी लड़ाई की याद दिलाता है। एएफपी

स्क्रीन शॉट

शादी के बाद भी नहीं बदले प्रियंका और निक

कहावत है कि आटे-दाल का भाव शादी के बाद पता चलता है। बात की जाए प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास के रिश्तों की, तो वक्त के साथ वह और बेहतर होता जा रहा है। यह बताया उनका चचेरी बहन परिणीति चोपड़ा ने। पिछले दिनों परिणीति अपनी मिमि दीदी यानी प्रियंका चोपड़ा का जन्मदिन मनाने के लिए अमेरिका गई थीं। प्रियंका और परिणीति एक-दूसरे के काफी करीब हैं। प्रियंका में शादी के बाद क्या बदलाव आए हैं? पूछने पर परिणीति ने बताया, 'मिमि दीदी बिल्कुल वैसी ही हैं, जैसे पहले थीं। सफल शादी का संकेत यही होता है कि दपंती के बीच कुछ नहीं बदले। उनकी जिंदगी में भी कुछ नहीं बदला है।' परिणीति बताती हैं कि जब वह पहली बार निक से मिली थीं, तब से अब तक उनमें भी कोई बदलाव नहीं है। दोनों दंपती के तौर पर और बेहतर हो रहे हैं। यानी उनकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी चल रही है। निक ने प्रियंका के जन्मदिन की तैयारियां एक महीने पहले से ही शुरू कर दी थीं। उसके लिए मुझे 22 घंटे की लंबी फ्लाइट लेकर वहां पहुंचना पड़ा। परिणीति अपने लिए भी ऐसा ही रिश्ता चाहती हैं। बकौल परिणीति, 'अगर मैं शादी करूंगी, तो यही चाहूंगी कि हम दोनों वैसे ही रहें, जैसे पहले थे।' फिल्मों की बात की जाए तो प्रियंका चोपड़ा की फिल्म 'द स्काई इज पिंक' बनकर तैयार है और हाल ही में इस फिल्म को टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में टॉप 20 फिल्मों में शामिल किया गया है।

संजय दत्त की बायोग्राफी अभी नहीं...

फिल्म 'संजू' में संजय दत्त की जिंदगी को लोगों को करीब से जानने का मौका मिला था। हालांकि उनके जीवन के कई ऐसे पहलू हैं, जिन्हें एक फिल्म में समेट पाना मुश्किल था। यही वजह है कि संजय दत्त अपनी बायोग्राफी लाने की तैयारी में हैं। खबरें थी कि संजय दत्त की यह किताब अपने जन्मदिन 29 जुलाई पर रिलीज करेंगे। इस दिन संजय साठ साल के हो जाएंगे। लेकिन उनके प्रशंसकों को अभी और इंतजार करना होगा। फिलहाल, संजय अपनी होम प्रोडक्शन की फिल्म 'प्रस्थानम' में व्यस्त हैं। 'प्रस्थानम' तेलुगु फिल्म की हिंदी रीमेक है। अपने जन्मदिन पर वह फिल्म का ट्रेलर लॉन्च करेंगे। वह फिल्म 'पानीपत', 'शमशेरा', 'सड़क 2' और 'भुज' की शूटिंग में व्यस्त हैं। ऐसे में वह अपनी किताब के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं। इस साल रिलीज 'कलंक' में वह अर्से बाद माधुरी दीक्षित के साथ स्क्रीन पर नजर आए थे। 'प्रस्थानम' 20 सितंबर को रिलीज होगी। जबकि संजय दत्त प्रोडक्शन की मराठी फिल्म 'बाबा' दो अगस्त को रिलीज होगी।

चिंताजनक

जलवायु परिवर्तन की वजह से बढ़ता तापमान मस्तिष्क पर डाल रहा प्रभाव, नेचर क्लाइमेट चेंज जर्नल में प्रकाशित किया गया है अध्ययन

जलवायु परिवर्तन बढ़ा रहा है अवसाद

न्यूयॉर्क, आइएएनएस : एक नए अध्ययन में चौंकाने वाला दावा किया गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण लोगों में अवसाद बढ़ रहा है। इस वजह से आत्महत्या के मामले भी बढ़ रहे हैं। अध्ययन में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण गर्म हो रहे मौसम की वजह से लोगों के व्यवहार में अचानक बदलाव देखने को मिला है। लोग सोशल मीडिया पर भी अवसादग्रस्त पोस्ट लिखते हैं। शोधकर्ताओं ने 50 करोड़ ट्वीट्स का विश्लेषण करके यह अध्ययन किया है।

यह अध्ययन नेचर क्लाइमेट चेंज जर्नल में प्रकाशित किया गया है। इसमें बताया गया कि जलवायु परिवर्तन आर्थिक मंदी की तरह विनाशकारी है। जिस तरह से आर्थिक मंदी के समय लोगों में हताशा बढ़ती है और आत्महत्या दर बढ़ जाती है। उसी तरह से जलवायु परिवर्तन भी लोगों को प्रभावित कर रहा है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर मार्शल बर्क ने बताया कि 2050 में अनुमानित तापमान बढ़ने से अमेरिका और मेक्सिको में प्रतिवर्ष 21,000 अधिक खुदकशी के मामले सामने आएंगे। शोधकर्ता सदियों से इस बात को मान्यता देते आए हैं कि गर्मियों के मौसम में आत्महत्या के सर्वाधिक मामले सामने आते हैं। उन्होंने बताया कि आत्महत्या के मामले बढ़ने में तापमान के अलावा अन्य कारक भी होते हैं जैसे- नौकरी की टेंशन, घर में झगड़ा आदि। केवल तापमान किस तरह से लोगों को प्रभावित करता है इसके लिए शोधकर्ताओं ने कई दशकों तक अमेरिका और मेक्सिको के शहरों में बढ़ते तापमान और आत्महत्या के आकड़ों की तुलना की। इसके साथ ही शोधकर्ताओं ने अलग-अलग भाषाओं के करीब आधे अरब ट्वीट्स का भी विश्लेषण किया, ताकि यह जाना जा सके कि जलवायु परिवर्तन की वजह से बढ़ता तापमान किस तरह से लोगों का मस्तिष्क प्रभावित करता है।

इस तरह किया अध्ययन : शोधकर्ताओं ने गर्मी के मौसम में किए गए ट्वीट्स में पाया कि उनमें 'लोनली', 'ट्रैप्ड' या 'सुसाइडल' शब्द का सर्वाधिक इस्तेमाल किया गया। शोधकर्ताओं ने बढ़ते तापमान और बढ़ते आत्महत्या के मामलों में गहरा संबंध पाया।

भविष्य में और बढ़ेगी यह समस्या

शोधकर्ताओं ने बताया कि उन्होंने भविष्य में बढ़ते तापमान के मस्तिष्क पर पड़ने वाले प्रभाव जानने के लिए वैश्विक जलवायु मॉडल के अनुमानों का इस्तेमाल किया। इस दौरान पाया कि 2050 तक अमेरिका में आत्महत्या के मामले 1.4 प्रतिशत और मेक्सिको में 2.3 प्रतिशत बढ़ जाएंगे।

शोधकर्ताओं ने 50 करोड़ ट्वीट्स का किया विश्लेषण। प्रतीकात्मक

हॉलीवुड फिल्म के लिए तैयारी कर रहे अली

फिल्म 'फास्ट ऐंड फ्यूरियस' की सातवीं किस्त 'फ्यूरियस 7' और 'विक्टोरिया ऐंड अब्दुल' में काम कर चुके अली फजल अब एक हॉलीवुड फिल्म की शूटिंग नवंबर में शुरू करेंगे। इसके अलावा वह अफगानिस्तान युद्ध पर आधारित एक और अंतरराष्ट्रीय फिल्म में भी काम कर रहे हैं। हॉलीवुड फिल्म की शूटिंग लंदन में होनी है। उनकी वेब सीरीज 'मिर्जापुर' के दूसरे सीजन की शूटिंग बनारस में चल रही है। वह अपने हिस्से की शूटिंग जल्द पूरी करेंगे, ताकि अपने हॉलीवुड प्रोजेक्ट के लिए वक्त पर काम शुरू कर सकें। उससे पहले वह अपने किरदार की तैयारियों में जुटेंगे।

अपने स्टंट की कोरियोग्राफी में योगदान करेंगे टाइगर

टाइगर श्रॉफ कैमरे के सामने एक्शन, डांस में ही कमाल नहं करते, कैमरे के पीछे भी सक्रिय रहते हैं। खबर है कि फिल्म 'बागी 3' के लिए टाइगर खुद अपने स्टंट को कोरियोग्राफ करेंगे। इस बारे में टाइगर ने कहा, 'इस बात में आधी सच्चाई है। मैं फिल्म के कुछ स्टंट सीन के लिए रेफरेंस की व्यवस्था करूंगा।' टाइगर ने कहा कि आज भारतीय दर्शक 'एवेंजर्स', 'जॉन विक', 'मिशन इंपॉसिबल' आदि में बेहतरीन एक्शन देख रहे हैं। हमें भी उसी स्तर के एक्शन सीन लाने की आवश्यकता है। टाइगर ने बताया, 'बागी 3' में कुछ ऐसे सीन होंगे, जिन्हें पहले नहीं देखा गया। मैं वही कर रहा हूं, जिसे टीम के सदस्य को करना चाहिए।'